भारतीय कानून रिपोर्ट

पूर्ण बेंच

माननीय न्यायमूर्ति डी. के. महाजन, प्रेम चंद पंडित, गुरदेव सिंह, आर. एस. नरूला और बाल राज तुली, के समक्ष

गुरदास सिंह बादल - याचिकाकर्ता

बनाम

भारत का चुनाव आयोग और अन्य - उत्तरदाता।

1971 की सिविल रिट संख्या 1258।

18 मई, 1971।

निर्वाचन संचालन नियम (1961) - नियम 93 - भारत का संविधान (1950)- अनुच्छेद 327 और 329 - नियम 93, चुनाव आयोग को मतपत्रों के निरीक्षण का आदेश देने की शक्ति प्रदान करना - क्या संविधान के अनुच्छेद 327 और 329 के अधिकारातीत है - अनुच्छेद 329 (बी) के (1962)1 तहत कार्यवाही की रोक - पूरी की जाने वाली शर्तेंनियम के अधीन शक्ति- चाहे वह अर्ध-न्यायिक हो या प्रशासनिक प्रकृति की- निरीक्षण का आदेश पारित करने से पहले लौटे हुए उम्मीदवार को सूचना देना—चाहे आवश्यक हो—न्यायालय और निर्वाचन आयोग द्वारा निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग— सामान्य तत्व और मुख्य अंतर— के बीच कहा गया है—ऐसी शक्ति—चाहे वह न्यायालय या अधिकरण के साथ सह-टर्मिनस हो—का उद्देश्य निर्वाचन आयोग को मतपत्रों के निरीक्षण की अनुमति देने का अधिकार - कहा गया है - इस तरह का निरीक्षण - क्या किसी प्राधिकारी के समक्ष लंबित चुनाव से संबंधित किसी कार्यवाही के अभाव में या चुनाव याचिका के लिए साक्ष्य एकत्र करने के लिए अनुमति दी जा सकती है - "चुनाव याचिका के उद्देश्य के लिए" अभिव्यक्ति - मतपत्रों के निरीक्षण की अनुमति देने वाले चुनाव आयोग के आदेश की व्याख्या - इस तरह के आदेश की सामग्री क्या केवल निरीक्षण के लिए आवेदन में आरोपों की गंभीरता पर पारित की जा सकती है।

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 (i) के तहत चुनाव आयोग की शक्ति को पवित्र बनाया गया है, और अनुच्छेद 327 के तहत अपने विधायी कार्यों का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा उस पर किसी भी संभावित अतिक्रमण से बचाया गया है। हालांकि, अनुच्छेद 324 में निहित कुछ भी चुनाव आयोग में निहित या सौंपे जाने वाले कुछ अतिरिक्त शक्तियों या कार्यों के रास्ते में बाधा नहीं है। अनुच्छेद 324 यह नहीं कहता है कि इसमें अनुच्छेद द्वारा आयोग को प्रदान किए गए कार्यों के अलावा कोई अन्य कार्य निहित नहीं होगा। इसलिए 31 मार्च, 1962 से चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93 में संशोधन, चुनाव आयोग को मतपत्रों के निरीक्षण का आदेश देने का अधिकार देना किसी भी तरह से नहीं है। अल्ट्रा वाइरस संविधान का अनुच्छेद 327 (पैरा 14)

(पूर्ण पीठ के अनुसार), कि किसी को भी चुनाव बुलाने के लिए नहीं माना जाता है जब तक कि वह वापस आए उम्मीदवार को मुद्दों के परीक्षण के लिए तलब करने की प्रार्थना नहीं करता है, जिसका निर्णय अंततः चुनाव के परिणाम को लागू करने के लिए प्रासंगिक हो सकता है। नियम 93 में संशोधन से अधिकार नहीं

निर्वाचन आयोग किसी ऐसे प्रश्न या मुद्दे के निर्णय के लिए किसी भी दावे पर विचार कर सकता है जिसके निर्णय पर चुनाव को रद्द किया जा सकता है या शून्य घोषित किया जा सकता है। न ही यह प्रावधान किसी को भी इस तरह के किसी भी निर्णय या निर्णय का दावा करने का अधिकार देता है। इसलिए नियम 93 चुनाव आयोग को चुनाव की वैधता के खिलाफ आरोपों के गुण-दोष पर कोई निर्णय दिए बिना दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति देने का अधिकार देता है, किसी भी तरह से संविधान के अनुच्छेद 329 (बी)) के विपरीत नहीं है। (पैरा 17)

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 329 के खंड (बी) द्वारा किसी याचिका, आवेदन या कार्यवाही को केवल तभी रोक दिया जाएगा जब निम्नलिखित चार शर्तों को पूरा किया जाता है: - (i) आवेदन एक चुनाव याचिका के अलावा अन्य है, जिसे निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित तरीके से प्रस्तुत किया गया है, (ii) चुनाव कार्यवाही से संबंधित मामलों पर आवेदन में हमला किया गया है, (iii) हमला उस निर्णय पर होता है जिसके निर्णय पर चुनाव याचिका की सुनवाई करने के लिए सक्षम न्यायालय चुनाव को रद्द कर सकता है या इसे शून्य घोषित कर सकता है, और (iv) उपरोक्त खंड (iii) में निर्दिष्ट चुनाव कार्यवाही से संबंधित मामले पर प्राधिकरण या न्यायाधिकरण का अधिनिर्णय आवेदक द्वारा लागू किया जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि प्राधिकरण को इस मामले पर निर्णय लेने का अधिकार है या नहीं। (पैरा 16)

(न्यायमूर्ति महाजन और नरूला,) के अनुसार, चुनाव आयोग से नियम 93 के तहत एक आवेदन पर अपना निर्णय देते समय, अर्ध-न्यायिक तरीके से कार्य करने की उम्मीद की जाती

है क्योंकि वह औचित्य या नीति पर विचार करते हुए निरीक्षण के लिए आवेदन की अनुमति नहीं दे सकता है, लेकिन उसके समक्ष रखी गई सामग्री पर निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना चाहिए, और कारणों के साथ आदेश का समर्थन करने के लिए बाध्य है। नियम 93 के तहत आयोग का कार्य अर्ध-न्यायिक होने के कारण, ऑडी अल्टरनेटम पार्टम का प्राकृतिक न्याय का प्रसिद्ध नियम लागू होगा और आयोग द्वारा लौटाए गए उम्मीदवार को प्रस्तावित आदेश के खिलाफ कारण दिखाने का अवसर दिए बिना दिया गया कोई भी निर्णय मान्य नहीं होगा। (पैरा 38 और 52)

(न्यायमूर्ति पंडित और तुली, के अनुसार) कि चुनाव आयोग के लिए यह स्वीकार्य है कि वह किसी आवेदक को नियमों के नियम 93 के तहत निरीक्षण की अनुमति दे सकता है यदि आयोग प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि वोटों का स्वागत या अस्वीकृति उचित नहीं थी या वोटों की गिनती ठीक से नहीं की गई थी। नियम के अनुसार उन्हें निरीक्षण की अनुमति देने से पहले कारणों को रिकॉर्ड करना होता है, जिसका अर्थ है कि उन्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा और विवेकपूर्ण तरीके से आदेश पारित करना होगा। इस मामले में चुनाव आयोग द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति प्रशासनिक है न कि अर्ध-न्यायिक जिसे कारणों को दर्ज करने के बाद विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना है। निस्संदेह, इसके कारण चुनाव के सिद्धांतों और चुनाव कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए। कारणों को दर्ज करना चुनाव आयोग द्वारा शक्ति के मनमाने प्रयोग के खिलाफ एक सुरक्षा उपाय है। (पैरा 95 और 96)

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चुनाव आयोग द्वारा पारित नियमों के नियम 93 में उल्लिखित चुनाव पत्रों के निरीक्षण या उत्पादन का आदेश किसी भी पार्टी के अधिकारों को निर्धारित नहीं करता है, क्योंकि न तो कोई

इन पत्रों के निरीक्षण या उत्पादन का दावा करने का अधिकार है और न ही उक्त कागजात किसी व्यक्ति से संबंधित हैं। आयोग के पास मतपत्रों की वैधता या अन्यथा पर फैसला करने का कोई अधिकार नहीं है। चूंकि आयोग पार्टियों के बीच मुद्दे में किसी भी बिंदु पर फैसला नहीं करता है, इसलिए लौटाए गए उम्मीदवार को कोई नोटिस आवश्यक नहीं है और इसलिए, चुनाव आयोग द्वारा पारित निरीक्षण की अनुमति देने वाला आदेश एक प्रशासनिक चरित्र का है और यह अर्ध-न्यायिक नहीं है और इसे पारित करने से पहले लौटाए गए उम्मीदवार या किसी अन्य उम्मीदवार को कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण पर लागू मानक आयोग पर लागू नहीं होते हैं, जब वह नियम 93 के तहत आदेश पारित करता है। (पैरा 112)

न्यायमूर्ति गुरदेव सिंह ने कहा कि नियम 93 चुनाव आयोग को लौटाए गए उम्मीदवार या किसी अन्य उम्मीदवार को निरीक्षण के लिए आवेदन का नोटिस देने का अधिकार नहीं देता है। इस प्रकार, विपरीत पक्ष को नोटिस जारी करने के लिए कानून के मामले के रूप में कोई दायित्व नहीं है। हालांकि, जहां आवेदक के अलावा इच्छुक दलों, विशेष रूप से लौटे या हारे हुए उम्मीदवारों को इस तरह के नोटिस जारी करने का समय है, प्राकृतिक न्याय के नियमों के लिए आवश्यक है कि इस तरह के नोटिस जारी किए जाएं और निरीक्षण का आदेश देने से पहले संबंधित पक्ष को सुना जाए। इसके अलावा, चूंकि चुनाव आयोग को कारणों को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है यदि वह निरीक्षण की अनुमति देता है तो यह ऐसी शक्ति के उचित प्रयोग के लिए अनुकूल होगा यदि वह अन्य उम्मीदवारों को सुनवाई देता है जहां उन्हें सूचित करने का समय होता है। (पैरा 145)

(न्यायमूर्ति नरूला,) के अनुसार, भले ही चुनाव आयोग मतपत्र के निरीक्षण की अनुमति देते समय प्रशासनिक रूप से कार्य करता है, लेकिन जहां निरीक्षण की अनुमति देने की आवश्यकता इतनी तत्काल या इतनी दबाव और तत्काल प्रकृति की नहीं है कि लौटाए गए उम्मीदवार को बुलाने या सुनने की अनुमति न दी जाए, और ऐसी कोई तात्कालिकता नहीं है जो वापस आए उम्मीदवार को अवसर दिए जाने पर निरीक्षण के उद्देश्यों को विफल कर दे, यह न केवल समीचीन बल्कि उचित होगा कि लौटाए गए उम्मीदवार को निरीक्षण के लिए आवेदन की सूचना जारी की जानी चाहिए ताकि उसे अभ्यावेदन देने का अवसर मिल सके और निरीक्षण की अनुमति देने से पहले मुद्दे पर विचार करने के लिए उसे सुना जा सके। (पैरा 65)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि नियम 93 के परंतुक की भाषा से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विधायिका का इरादा यह नहीं था कि चुनाव आयोग को निरीक्षण के लिए आदेश पारित करने से पहले लौटे हुए उम्मीदवार या किसी अन्य उम्मीदवार को सुनना चाहिए। उस स्तर पर, मामला निरीक्षण के लिए आवेदक और चुनाव आयोग के बीच का होता है और कोई अन्य व्यक्ति इसमें नहीं आता है। चुनाव आयोग को निश्चित रूप से लौटाए गए उम्मीदवार को नोटिस देने या सुनने या किसी प्रकार की जांच करने से वंचित नहीं किया जाता है यदि वह खुद को संतुष्ट करने के लिए ऐसा चाहता है कि निरीक्षण की अनुमति देने का प्रथम दृष्टया मामला है क्योंकि उसे इसके समर्थन में कारण दर्ज करना होगा, लेकिन इसे कानून के मामले के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि उसे यह करना चाहिए, सभी मामलों में, लौटाए गए उम्मीदवार या किसी अन्य उम्मीदवार को नोटिस दें और निरीक्षण के लिए आदेश पारित करने से पहले उसकी बात सुनें या किसी प्रकार की जांच करें। चुनाव आयोग के पास इस संबंध में कोई राय व्यक्त करने का कोई अधिकार क्षेत्र या शक्ति नहीं है।

स्वीकृत या अस्वीकृत मतपत्रों की वैधता या अन्यथा न तो वह इसके संबंध में कोई राहत दे सकता है। इसलिए, निरीक्षण की अनुमति देने से वापस आए उम्मीदवार के चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और न ही यह चुनाव की प्रक्रिया के किसी भी हिस्से के संबंध में किसी भी मामले पर फैसला करता है जिसे केवल चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है और इसलिए, लौटाए गए उम्मीदवार या किसी अन्य उम्मीदवार को यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि निरीक्षण के लिए आदेश देने से पहले उसे सुना जाना चाहिए। यदि चुनाव पत्रों के निरीक्षण के परिणामस्वरूप कोई सामग्री एकत्र की जाती है, तो उस पर चुनाव याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा, यदि उस सामग्री के साथ चुनाव याचिका दायर की गई है और उस स्थिति में लौटाए गए उम्मीदवार के पास इसे रोकने या खंडन करने का पर्याप्त अवसर होगा। उन्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि चुनाव याचिका में आधार के समर्थन में सबूत इकट्ठा करने के एक निश्चित तरीके को चुनाव याचिकाकर्ता को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें केवल इतना ही हक है कि चुनाव के संबंध में मामले पर निर्णय होने से पहले उनका पक्ष सुना जाना चाहिए। वह सुनवाई उन्हें तब मिलेगी जब चुनाव याचिका दायर की जाएगी। नियम द्वारा प्रदान किए गए तरीके से साक्ष्य एकत्र करने को किसी भी तरह से लौटे उम्मीदवार के चुनाव को पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है। बेशक, यदि निरीक्षण की अनुमति देने वाला आदेश नियम 93 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो लौटाए गए उम्मीदवार को उस आदेश को चुनौती देने का अधिकार है, लेकिन उसे यह शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है कि वह आदेश उसे नोटिस के बिना पारित किया गया था। इसलिए चुनाव आयोग नियम 93 के तहत निरीक्षण के लिए आदेश पारित करने से पहले लौटे हुए उम्मीदवार या किसी अन्य उम्मीदवार को नोटिस जारी करने या सुनने के लिए किसी भी दायित्व के तहत नहीं है। केवल इसलिए कि निरीक्षण के लिए आवेदन पर निर्णय लेने से पहले लौटे उम्मीदवार को नोटिस जारी करने के लिए पर्याप्त समय है, यह मानने का

कोई आधार नहीं है कि आदेश पारित करने से पहले लौटे उम्मीदवार को सुनने में चुनाव आयोग की विफलता उस आदेश को दूषित करती है। यह निर्वाचन आयोग का कार्य है कि वह इन मामलों के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार करे जब नियमों में कोई प्रक्रिया प्रदान नहीं की गई है और नियम के अनुसार यह आवश्यक है कि उसे निरीक्षण के लिए आवेदन की अनुमति देने के कारणों को बताना होगा। यदि वह आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो आदेश हमले से प्रतिरक्षा है।

(पैरा 97, 98 और 102)

(न्यायमूर्ति नरूला,) के अनुसार, न्यायालय और निर्वाचन आयोग द्वारा नियमों के नियम 93 के तहत मतपत्रों के निरीक्षण का आदेश देने की शक्ति के प्रयोग के आवश्यक सामान्य तत्व और विशेषताएं इस प्रकार हैं: (i) नियम 93 के तहत आवेदन केवल ऐसे व्यक्ति के कहने पर अनुमति दी जा सकती है जिसकी निरीक्षण द्वारा एकत्र की जाने वाली जानकारी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण रुचि है; (ii) ऐसे आवेदन की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि उसमें किसी ऐसे मामले पर निश्चित आरोप न लगाए गए हों, जिसके साथ न्यायालय या आयोग, जैसा भी मामला हो; (iii) आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए जब तक कि न्यायालय या आयोग संतुष्ट न हो कि सामग्री और प्रासंगिक आरोपों में कम से कम कुछ प्रथम दृष्टया सच्चाई है; (iv) निरीक्षण के आवेदनों से निपटने में दोनों प्राधिकरणों द्वारा न्यायिक और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए; (v) केवल साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। हालांकि, सबूत इकट्ठा करने के लिए निरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है। जिसके बारे में आवेदक को पहले से ही यह बताते हुए खुलासा करना होगा कि वह गुप्त कागजात में वास्तव में क्या देखने जा रहा है; (vi) संतुष्टि होनी चाहिए, जिसके द्वारा समर्थित

कारण, क्यों निरीक्षण को न्याय के हित में माना जाता है और किसी दिए गए मामले की परिस्थितियों में अपरिहार्य रूप से आवश्यक माना जाता है; (vii) निस्संदेह निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए; (viii) न्यायालय या आयोग द्वारा किसी भी निरीक्षण की अनुमति इस तरह से नहीं दी जा सकती है जिससे मतपत्र की गोपनीयता का उल्लंघन हो। (पैरा 20)

यह अभिनिर्धारित किया गया है है कि न्यायालय और आयोग द्वारा नियम 93 के अधीन शक्ति के प्रयोग के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित हैं - (क) न्यायालय लंबित कार्यवाहियों जैसे (i) चुनाव याचिका या (ii) आपराधिक अभियोजन के अलावा निरीक्षण की अनुमति नहीं दे सकते हैं। आयोग निरीक्षण की अनुमति दे सकता है, भले ही उसके समक्ष कोई कार्यवाही लंबित न हो; (ख) न्यायालय की आवश्यक विशेषताएं और विशेषताएँ, जो उनके साथ एक निश्चित निर्णय पर आने का पारंपरिक तरीका रखती हैं, आयोग के मामले में वांछित हैं; (ग) जबकि न्यायालय की संतुष्टि नियमित रूप से कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा प्राप्त की जाएगी, आयोग साक्ष्य और सिविल प्रक्रिया के नियमों द्वारा निरंकुश मामले की परिस्थितियों द्वारा मांगे गए किसी भी निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से निरीक्षण की अनुमति देने के कारणों के अस्तित्व के बारे में खुद को संतुष्ट कर सकता है; (घ) जबकि न्यायालय के पास नियम 93 को लागू किए बिना भी निरीक्षण की अनुमति देने की अंतर्निहित शक्ति है, आयोग के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है और वह उस नियम के अलावा निरीक्षण की अनुमति नहीं दे सकता है। (पैरा 21)

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चुनाव पत्रों के उत्पादन और निरीक्षण की अनुमति देने में चुनाव आयोग की शक्ति सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण की शक्ति के साथ सह-समाप्त नहीं है या एक ही उद्देश्य के लिए है और समान सीमाओं द्वारा संरक्षित है। निर्वाचन आयोग अथवा सक्षम न्यायालय अथवा अधिकरण के कार्यक्षेत्र का निर्धारण आवश्यक रूप से उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कृत्यों और शक्तियों के आधार पर किया जाना है। दूसरे शब्दों में, चुनाव पत्रों के निरीक्षण और उत्पादन की अनुमति देने की शक्ति उस प्राधिकरण के कार्यों से रंग लेना है जिसे वह शक्ति सौंपी गई है। जिन परिस्थितियों में उस शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, वे भी समान नहीं हो सकते हैं। (पैरा 90)

(न्यायमूर्ति नरूला,) के अनुसार, नियम 93 के तहत निरीक्षण की अनुमति देने के लिए चुनाव आयोग को सशक्त बनाने का उद्देश्य (i) चुनाव ट्रिब्यूनल द्वारा निरीक्षण के लिए आवेदन पर निर्णय देने से पहले उपयोग किए गए मतपत्रों को नष्ट करने की संभावना की विशिष्ट आकस्मिकता को पूरा करना था; (ii) एक गंभीर चुनाव-याचिकाकर्ता, सामान्यतः पराजित उम्मीदवार को उसके पास मौजूद साक्ष्य या सूचना की शुद्धता की जांच करने में सक्षम बनाना, या उपयोग किए गए मतपत्रों की अधिक सावधानीपूर्वक जांच करना ताकि उसके द्वारा पहले से ही रखी गई जानकारी सुनिश्चित हो सके और यदि आवश्यक हो तो उन मतपत्रों की सटीक गणना प्राप्त करने के लिए जो अवैध रूप से स्वीकार या अस्वीकार किए गए पाए जा सकते हैं; (iii) निर्वाचन अपराधों के विचारण के प्रयोजन राथ या चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के प्रयोजन राथ निर्वाचन याचिका के निपटान के पश्चात् भी तब तक उपलब्ध प्रयुक्त मतपत्रों आदि के निरीक्षण की अनुमति देना; और (iv) आयोग को उपयुक्त मामलों में निरीक्षण की अनुमति देने के लिए एक व्यापक शक्ति देना, जिसे बाद में इस तरह से प्रयोग किए जाने के एकान्त रक्षोपाय के अधीन कर दिया गया था जो आयोग द्वारा दर्ज किए गए कारणों से उचित प्रतीत होता है।

(पैरा 29)

(न्यायमूर्ति गुरदेव सिंह) के अनुसार, चुनाव आयोग मतपत्रों आदि के उत्पादन और निरीक्षण का

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।

(नरूला, जे। ;

आदेश देने की अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है, जब कोई कार्यवाही, जिसमें ऐसे कागजात की जांच आवश्यक है, उसके समक्ष लंबित नहीं है। चूंकि इसी प्रावधान के अनुसार निर्वाचन आयोग, अधिकरण और न्यायालयों को मतपत्रों को खोलने, प्रस्तुत करने और निरीक्षण करने की अनुमति देने का अधिकार है और चूंकि अधिकरण या न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग तब नहीं किया जा सकता जब उनके समक्ष कोई कार्यवाही लंबित न हो, निर्वाचन आयोग के पास किसी भी समय निरीक्षण की अनुमति देने की व्यापक शक्ति नहीं है। .» वह ऐसा तभी कर सकती है जब उसके समक्ष और चुनाव के संबंध में कुछ कार्यवाही लंबित हो। (पैरा 124)

(न्यायमूर्ति गुरदेव सिंह) के अनुसार, यद्यपि कार्यवाही की प्रकृति जिसमें निरीक्षण या दस्तावेजों आदि के उत्पादन की अनुमति देने के लिए अदालत, न्यायाधिकरण या चुनाव आयोग से संपर्क किया जा सकता है, अलग-अलग होगी, फिर भी मूल नियम यह है कि सबूत खोजने या चुनाव याचिका के उद्देश्य से जांच करने के लिए निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अर्थात्, निर्वाचन आयोग, न्यायालय और अधिकरण, एक याचिका पर विचार करते समय मतपत्रों आदि की जांच करते हैं। जब तक इस नियम का पालन नहीं किया जाता है, तब तक जांच का आदेश देने या सबूत ो ं को बाहर निकालने के लिए जो शरारत की जाती है, वह की जाएगी। नियम 93 में "चुनाव याचिका के उद्देश्य से" शब्द का अर्थ "चुनाव याचिका को स्थापित करने या बनाए रखने के उद्देश्य से" के समान नहीं पढ़ा जा सकता है। इस नियम की सही व्याख्या यह है कि यदि मतपत्रों के संबंध में किए गए अपराध के संबंध में निरीक्षण की आवश्यकता है, तो संबंधित पक्ष को न केवल अभियोजन को बनाए रखने के लिए बल्कि इसे स्थापित करने के लिए भी सक्षम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, लेकिन जहां तक चुनाव याचिका का संबंध है, इसे उच्च न्यायालय द्वारा केवल तभी अनुमति दी जानी चाहिए जब चुनाव याचिका लंबित हो और उसमें निहित आरोपों की आवश्यकता हो। मतपत्रों, काउंटरफॉइल आदि का उत्पादन या निरीक्षण ताकि चुनाव याचिका में उत्पन्न होने वाले मामलों का निपटारा किया जा सके।

(पैरा 127 और 1311)

(न्यायमूर्ति नरूला,) के अनुसार, निरीक्षण की अनुमति देने वाले वैध आदेशों में दोहराए जाने के लिए किसी भी जादू संकेत को निर्धारित करना न तो संभव है और न ही उचित है। चीजों की प्रकृति में प्रत्येक मामले को अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए। निरीक्षण के क्रम में कोई विशिष्ट शब्द मौजूद होने की आवश्यकता नहीं है। आदेश में प्रथम दृष्टया विचार की गई सामग्री, उन आरोपों के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्टि दिखाई जानी चाहिए जिन्हें निरीक्षण की अनुमति देने को उचित ठहराने के लिए माना गया है और इस तरह के औचित्य के कारण हैं। उन कारणों को आदेश से ही स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए, न कि किसी औपचारिक आदेश से जो बाद में इसके आधार पर तैयार किया जा सकता है। निरीक्षण के लिए आवेदन में लगाए गए आरोप का केवल बयान, * गंभीर होने के कारण, नियम 93 (1) के तहत निरीक्षण की अनुमति देने के लिए कानून की नजर में कोई कारण नहीं है। (पैरा 47)

नियम 93 की भाषा से पता चलता है कि यह चुनाव आयोग की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर निर्भर करता है, कि निरीक्षण के लिए एक मामला बनाया गया है और वह निरीक्षण की अनुमति देने वाला आदेश पारित कर सकता है। जब उसे ऐसी राय बनानी होती है, तो उसे अपने सामने रखी गई सामग्री पर विचार करना होता है, इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए उचित सामग्री का गठन करना होता है। बस यह देखा जाना है कि जिस सामग्री पर विचार किया गया है वह उस आदेश के लिए प्रासंगिक और जर्मन है जो पारित होने जा रहा है। निर्वाचन आयोग के आदेश को इस आधार पर लागू नहीं किया जा सकता है कि यह आवेदक द्वारा लगाए गए तथ्य के आरोपों को निर्धारित नहीं करता है जिन्हें चुनाव आयोग द्वारा गंभीर माना गया था और जिसके विश्वास पर वह खुद को संतुष्ट करता है कि मांगी गई चुनाव पत्रों के निरीक्षण की अनुमति देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। निरीक्षण के लिए आवेदन में विचार के चरण में, चुनाव आयोग को निरीक्षण के लिए आवेदन में लगाए गए आरोपों तक खुद को सीमित रखना

पड़ता है और मामले में आगे कोई जांच नहीं कर सकता है। वह केवल आरोपों की प्रकृति, सार और गुणवत्ता पर अपना मन बना सकते हैं और उसके आधार पर अपना आदेश पारित कर सकते हैं। निरीक्षण की अनुमति देने का कारण लगाए गए आरोपों की गंभीरता या अन्यथा को संदर्भित करना है। (पैरा 103 और 106)

मैं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में अनुरोध किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 12के आदेश को रद्द करने के लिए प्रमाणपत्र, परमादेश, निषेध या किसी अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश की रिट। 1. भारत निर्वाचन आयोग और निर्वाचन अधिकारी को प्रतिवादी इकबाल सिंह को निरीक्षण के लिए मतपत्र आदि उपलब्ध कराने से प्रतिबंधित किया जाए और आगे प्रार्थना की जाए कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादियों को भारत के निर्वाचन आयोग के आदेशों का पालन करने से रोका जाए।

एच.एल. सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता, एम.बी. शर्मा, एस.सी. सिब्बल, नरोत्तम सिंह और आर एन। नरूला, वकील, याचिकाकर्ता के लिए।

अशोक सेन, वरिष्ठ अधिवक्ता, और जी.एल. सांची, भागीरथ दास, हर-भगवान सिंह, आर.एल. शर्मा, अमरजीत चौधरी, गोबिंदर सिंह संधू, पी.एस. दौलता, वी. जी. डोगरा और श्रीमती आदर्श, अधिवक्ता,प्रतिवादी नंबर 3 के लिए ।

निर्णय

न्यायमूर्ति नरूला -चुनाव आयोग के 15 मार्च, 1971 के आदेश की वैधता और वैधता, जिसमें प्रतिवादी नंबर 3 इकबाल सिंह को फाजिल्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में 5 मार्च, 1971 को हुए मध्यावधि चुनाव में सफल उम्मीदवार गुरदास सिंह बादल के पक्ष में डाले गए खारिज और गिने गए मतपत्रों का निरीक्षण करने की अनुमति दी गई थी। उपर्युक्त वापस आए उम्मीदवार द्वारा इस रिट याचिका में निम्नलिखित आधारों पर प्रश्न में बुलाया गया है: –

1. चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93 में किया गया संशोधन, 31 मार्च, 1962 से प्रभावी है, जो चुनाव आयोग को निरीक्षण का आदेश देने का अधिकार देता है अप्रयुक्त और प्रयुक्त मतपत्रों की संख्या और मतदाता सूची आदि की चिह्नित प्रति क्या है? *अल्ट्रा वाइरस* उक्त अनुच्छेद के रूप में संविधान के अनुच्छेद 327 को अनुच्छेद 324 के प्रावधानों के अधीन पढ़ा जाना चाहिए; ^

2. नियम 93 का विवादित संशोधन संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) के विपरीत है क्योंकि यह चुनाव आयोग को चुनाव याचिका के बजाय किसी अन्य तरीके से चुनाव की प्रक्रिया में कदम उठाने की अनुमति देने का अधिकार देता है;

3. यहां तक कि अगर निरीक्षण की अनुमति देने के लिए चुनाव आयोग में निहित शक्ति संवैधानिक और वैध है, तो उक्त शक्ति का उपयोग केवल परिस्थितियों में और केवल उन सीमाओं के अधीन किया जा सकता है जो उसी नियम के तहत निरीक्षण की अनुमति देने के लिए अदालत या ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र पर लागू होती हैं। दूसरे शब्दों में, नियम 93 के तहत चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र उस नियम के तहत न्यायालय के साथ सह-व्यापक है और उससे बड़ा या व्यापक नहीं है। चुनाव आयोग द्वारा इस मामले में पारित आदेश इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सकारात्मक और नकारात्मक परीक्षणों को पूरा नहीं करता है और इसलिए, रद्द किया जाना चाहिए;

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।

. (नरूला, जे। ;

4. नियम 93 के तहत निर्वाचन आयोग को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग केवल उस नियम के परंतुक के अधीन करने की अनुमति है, अन्यथा नहीं। नियम 93 के तहत चुनाव आयोग द्वारा पारित कोई भी आदेश मान्य नहीं होगा यदि यह किसी भी कारण से समर्थित नहीं है। निरीक्षण के आदेश की वैधता को बनाए रखने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि चुनाव आयोग द्वारा दिए गए कारण (नियम 93 के परंतुक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए) निरीक्षण की अनुमति देने के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक हैं; *

5. वर्तमान मामले में लागू आदेश किसी भी कारण से समर्थित नहीं है, क्योंकि केवल यह कहना कि निरीक्षण के लिए आवेदन में लगाए गए आरोप, यदि सही हैं, तो गंभीर होंगे, कानून की नजर में कोई कारण नहीं है। अन्यथा चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत रिकॉर्ड से पता चलता है कि विवाद में रहे मामले में आयोग ने पूरी तरह से दिमाग नहीं लगाया है; और

6. लागू आदेश भी रद्द करने योग्य है क्योंकि यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया है और, यह आदेश गंभीर रूप से पूर्वाग्रह और याचिकाकर्ता के लोकसभा के सदस्य के रूप में बने रहने के संवैधानिक अधिकार को ग्रहण करता है।

2. उपर्युक्त दलीलों से निपटने से पहले, इस स्तर पर उन प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान दिया जा सकता है जिनके कारण यह याचिका दायर की गई है।

3. फाजिल्का संसदीय क्षेत्र से मध्यावधि चुनाव के लिए मतदान 5 मार्च, 1971 को हुआ था। इस निर्वाचन क्षेत्र में आठ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। हालांकि चुनाव में आठ उम्मीदवार थे, लेकिन असली मुकाबला एक तरफ याचिकाकर्ता और दूसरी तरफ प्रतिवादी नंबर 3 के बीच था। उपायुक्त। फिरोजपुर, जो संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिला चुनाव अधिकारी थे, को निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। तीसरे प्रतिवादी के आवेदन पर, चुनाव आयोग ने श्री आरडी शर्मा, अवर सचिव, को इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया था। यह विवादित नहीं है कि उन्होंने मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया और मतगणना की निगरानी भी की। उन्होंने तीसरे प्रतिवादी द्वारा की गई मौखिक शिकायत पर भी विचार किया और निर्णय लिया। 12 मार्च, 1971 की पर्यवेक्षक की रिपोर्ट और तीसरे प्रतिवादी की शिकायत पर निर्णय की एक प्रति याचिका के अनुलग्नक 'सी' में दी गई है।

4. वोटों की गिनती 10 से 12 मार्च, 1971 तक की गई थी, अंतिम दिन केवल डाक मतपत्रों की गिनती के लिए समर्पित था। मतगणना के समापन पर, 12 मार्च, 1971 को चुनाव का परिणाम घोषित किया गया, जिसमें दिखाया गया कि याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा डाले गए 1,47,277 वोटों के मुकाबले 1,52,653 वोट हासिल किए थे। गिनती के समापन पर और इसके परिणाम की घोषणा से पहले, प्रतिवादी प्रतिवादी ने रिटर्निंग अधिकारी को एक आवेदन (रिट याचिका का अनुलग्नक 'ए') दिया, जिसमें उसने विभिन्न आधारों पर पुनर्मतगणना के लिए प्रार्थना की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद, उसी दिन रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश (कॉपी अनुलग्नक 'बी') द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। 15 मार्च, 1971 को प्रतिवादी ने चुनाव आयोग को एक आवेदन दिया (चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी की वापसी के लिए अनुबंध आर-एक्स की प्रति) जिसमें उन्होंने सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में सभी बैलोबपेपर और अन्य प्रासंगिक चुनाव रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति देने के लिए प्रार्थना की, जो निरीक्षण के लिए खुले हो सकते हैं ताकि वह उचित अदालत में कानूनी उपाय प्राप्त कर सकें।

चुनाव याचिका। उन्होंने किसी भी संभावित शरारत से बचने के लिए आवेदन पर तत्काल आदेश पारित करने की प्रार्थना की। उस आवेदन पर, श्री एस पी सेन वर्मा, निर्वाचन आयोग ने उसी दिन एक आदेश पारित किया जिसे नीचे प्रस्तुत किया गया है:-

"एस. इकबाल सिंह द्वारा आवेदन में लगाए गए आरोप, यदि सही हैं, तो निस्संदेह गंभीर हैं। मैं समझता हूं कि निर्वाचन संचालन नियमावली, 1961 के नियम 93 के उप-नियम (1) में उल्लिखित दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति दी जाए। सर्वप्रथम, प्रयुक्त और अप्रयुक्त मतपत्रों का निरीक्षण किया जा सकता है और इस तरह के निरीक्षण के बाद यदि आवेदक निर्वाचक नामावली की अंकित प्रति के निरीक्षण की मांग करता है, तो उस दस्तावेज के निरीक्षण की भी अनुमति दी जा सकती है। नियम 93 (1) के परंतुक के अनुसार एक औपचारिक आदेश तैयार किया जा सकता है और जिला निर्वाचन अधिकारी को विस्तृत निर्देश और निर्देश दिए जा सकते हैं।

अवर सचिव श्री आरडी शर्मा, जिन्हें फाजिल्का संसदीय क्षेत्र में मतपत्रों की गिनती के समय आयोग से पर्यवेक्षक के रूप में भेजा गया था, फिरोजपुर जा सकते हैं और निरीक्षण के समय उपस्थित रह सकते हैं।

5. उपर्युक्त आदेश को श्री वर्मा "डी.ई.सी.(जे)" द्वारा चिह्नित किया गया था। इससे पहले कि कागजात उनके कार्यालय से आगे बढ़ पाते, श्री वर्मा ने आवेदन पर एक और आदेश पारित किया, जिसके विवरण के साथ हम चिंतित नहीं हैं क्योंकि इसका उद्देश्य केवल श्री आर डी शर्मा, अवर सचिव के नाम के स्थान पर श्री के वी विश्वनाथन, अवर सचिव का नाम बदलना था। पहली बार में पारित आदेश में दिया गया है। मामले को फिर से डीईसी (जे) को चिह्नित किया गया था। इसके बाद श्री केवी विश्वनाथन ने 16 मार्च, 1971 को आयोग के सचिव को अनुमोदन के लिए औपचारिक आदेश का एक मसौदा प्रस्तुत किया। इसके बाद मामला डीईसी (जे) (सचिव के माध्यम से) के पास गया, जिन्होंने फाइल पर इस आशय का आदेश दिया कि मसौदा बिहार (मुंगेर) के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा अनुमोदित मॉडल पर था। इसके बाद 16 मार्च, 1971 के औपचारिक आदेश (रिट याचिका के अनुलग्नक 'डी') को जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित किया गया। आदेश का ऑपरेटिव हिस्सा (इलाहाबाद उच्च न्यायालय के कुछ पिछले फैसलों के संदर्भ के अलावा और प्रतिवादी द्वारा आवेदन करने से संबंधित उद्धरण के अलावा) निम्नलिखित शब्दों में था: –

"और जबकि आवेदक ने कहा है कि उसे सक्षम करने के लिए इन दस्तावेजों का निरीक्षण आवश्यक है

एक चुनाव याचिका द्वारा उचित न्यायालय में अपने कानूनी उपचार की मांग करें;

और जबकि उक्त आवेदन में, आवेदक ने आरोपलगाया है कि गिनती के दौरान बड़ी संख्या में मतपत्र पाए गए थे, जिन पर कानून के तहत आवश्यक पीठासीन अधिकारी का कोई विशिष्ट चिह्न या हस्ताक्षर नहीं था और 6,000 से अधिक वैध वोट गलत तरीके से खारिज कर दिए गए थे;

अब, इसलिए, निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 93 के उप-नियम (1) के उप-नियम (1) के प्रावधानों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग इस बात से संतुष्ट हो गया है कि आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार निरीक्षण आवश्यक है ताकि एक ही

समय में मतपत्र की गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके। —

1. पंजाब राज्य में फिरोजपुर जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी उक्त फाजिल्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों के संबंध में श्री इकबाल सिंह के अलावा अन्य सभी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के पक्ष में डाले गए मत पत्रों और अस्वीकृत मतों वाले पैकेटों को खोलेंगे और आवेदक या उसके विधिवत अधिकृत एजेंट को उनकी उपस्थिति में उनका निरीक्षण करने की अनुमति देंगे। यदि लौटा हुआ उम्मीदवार आवेदक के पक्ष में डाले गए मतों के एक साथ उद्घाटन और निरीक्षण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित में आवेदन करता है, तो इसे भी अनुमति दी जाएगी;
2. पूर्वोक्त निरीक्षण पूरा होने के बाद और मतपत्रों के पैकेटों का इस्तेमाल, निविदा या अस्वीकृत किया जाता है और अप्रयुक्त मतपत्रों वाले पैकेटों को नीचे उप-पैरा (iv) में निर्देशित के अनुसार सील और सुरक्षित किया जाता है, यदि आवेदक फाजिल्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी या सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों के संबंध में मतदाता सूची की चिह्नित प्रति के निरीक्षण की मांग करता है तो उस दस्तावेज के निरीक्षण की भी अनुमति दी जा सकती है;
3. कि जिला निर्वाचन अधिकारी अन्य चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके विधिवत उम्मीदवारों को उचित अवसर देगा।

ऐसे उद्घाटन और निरीक्षण के समय अधिकृत एजेंट उपस्थित रहें। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को लिखित में उचित नोटिस दिया जाना चाहिए जिसमें निरीक्षण की तारीख, समय और स्थान का उल्लेख हो। चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को इस तरह के उद्घाटन और निरीक्षण में उपस्थित होने के लिए केवल एक विधिवत अधिकृत एजेंट नियुक्त करने की अनुमति दी जा सकती है। इस तरह के निरीक्षण के दौरान, किसी भी व्यक्ति को मतपत्र को छूने या संभालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी उपस्थित व्यक्तियों में से किसी को भी मतपत्रों की संख्या को नोट करने की अनुमति दे सकता है, जिसे वह अनुचित रूप से स्वीकार या अनुचित रूप से अस्वीकार कर देता है। इस तरह के उद्घाटन और पैकेट ों के निरीक्षण के समय जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी प्रदान की जाएगी; और

(iv) निरीक्षण पूरा होने के बाद, उपयोग किए गए, प्रस्तुत या अस्वीकृत किए गए सभी मतपत्र, अप्रयुक्त मतपत्र, और निर्वाचक नामावली की अंकित प्रति को संबंधित पैकेटों में प्रतिस्थापित किया जाएगा और ऐसे पैकेटों को जिला निर्वाचन अधिकारी की मुहर के साथ उनकी उपस्थिति में और निरीक्षण के समय उपस्थित व्यक्तियों की मुहर के साथ फिर से सील किया जाएगा। चुनाव आयोग की मुहर। सभी पैकेटों को एक स्टील बॉक्स या अन्य कंटेनर में डाल दिया जाएगा, जिसे पूर्वोक्त तरीके से बंद और सील किया जाएगा और इसे सुरक्षित हिरासत के लिए ट्रेजरी में रखा जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ न की जाए।

6. यह दोनों पक्षों का स्वीकार किया गया मामला है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का आदेश याचिकाकर्ता को किसी भी नोटिस के बिना पारित किया गया था और इसी तरह औपचारिक आदेश (अनुबंध 'डी') एकतरफा तैयार किया गया था और अनुपालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा गया था। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतपत्रों आदि के निरीक्षण की अनुमति देने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित तिथि (31 मार्च, 1971) का नोटिस प्राप्त होने पर, याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने उपायुक्त के कार्यालय से चुनाव आयोग के आदेश की एक प्रति प्राप्त की है। उन्होंने इसकी प्रति अनुलग्नक 'डी' के रूप में दायर की है। इस बीच, याचिकाकर्ता ने 17 मार्च, 1971 को लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली थी। औपचारिक की प्रति प्राप्त करने के बाद

याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत यह याचिका दायर की, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा पारित आदेश के रिकॉर्ड को थिग कोर्ट में पेश करने और चुनाव आयोग के आदेश (अनुबंध 'डी') को रद्द करने की प्रार्थना की गई। आगे यह प्रार्थना की गई कि रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष रिकॉर्ड भी मंगाए जाएं और चुनाव आयोग के साथ-साथ रिटर्निंग ऑफिसर को निरीक्षण के लिए मतपत्र आदि उपलब्ध कराने से प्रतिबंधित किया जाए। चुनाव आयोग के आक्षेपित आदेश को रद्द करने और प्रतिवादियों को चुनाव आयोग के आदेश का पालन करने से रोकने के लिए एक विशिष्ट अनुरोध किया गया था। आक्षेपित आदेश के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने का भी अनुरोध किया गया था।

7. 30 मार्च, 1971 को मोशन बेंच ने याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए कहा कि विवाद में मामले किसी भी प्रत्यक्ष प्राधिकरण द्वारा कवर नहीं किए गए थे और महत्वपूर्ण होने के कारण, मामले को 5 अप्रैल, 1971 को पूर्ण पीठ द्वारा सुना जा सकता है। चुनाव आयोग को 31 मार्च, 1971 के लिए निर्धारित निरीक्षण को रोकने के लिए एक अंतरिम निर्देश जारी किया गया था। यह निर्देश दिया गया था कि यदि याचिका विफल हो जाती है, तो निरीक्षण उस तारीख के अगले दिन होगा जिस दिन उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था। यह प्रस्ताव पीठ के उपर्युक्त आदेश के अनुसरण में था कि पांच न्यायाधीशों की इस पूर्ण पीठ का गठन मेरे प्रभु, मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया गया था।

8. पहले दो प्रतिवादियों (चुनाव आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी) ने न तो पेश होने का फैसला किया है और न ही कोई जवाब दाखिल किया है। याचिका को अकेले प्रतिवादी नंबर 3 इकबाल सिंह ने चुनौती दी है। उन्होंने अपना रिटर्न दाखिल किया जिसके साथ उन्होंने 29 मार्च, 1971 को लोकसभा में सदन के पटल पर कानून मंत्री द्वारा दिए गए बयान की एक प्रति (अनुलग्नक आर-1 के रूप में) प्रस्तुत की है, जो चंडीगढ़ के एक गोदाम से कुछ मुद्रित अप्रयुक्त मतपत्रों की बरामदगी से संबंधित है; मुख्य चुनाव आयुक्त और पर्यवेक्षक तथा अन्य प्राधिकारियों को 11 मार्च, 1971 को भेजे गए उनके टेलीग्राम की एक प्रति और 20 फरवरी से 8 मार्च, 1971 के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त और उप मुख्य निर्वाचन आयुक्त (अनुलग्नक आर-III से आर-9) को सौंपे गए उनके विभिन्न आवेदनों की प्रतियां भी शामिल हैं। रिटर्न के अनुबंध आर-एक्स के रूप में, उन्होंने 15 मार्च, 1971 के अपने आवेदन की एक प्रति दायर की है, जिस पर आक्षेपित आदेश पारित किया गया था। अदालत की अनुमति के साथ, याचिकाकर्ता ने अपना प्रस्तुत किया

लिखित बयान के जवाब में प्रतिकृति जिसमें उन्होंने कुछ अतिरिक्त बिंदुओं को उठाया, जिन्हें इस फैसले के शुरुआती भाग में याचिकाकर्ता की ओर से दी गई प्रस्तुतियों की गणना में भी शामिल किया गया है।

9. याचिका की सुनवाई शुरू होने पर, हम में से एक (न्यायमूर्ति गुरदेव सिंह) ने देखा और बताया कि आदेश अनुलग्नक 'डी' आयोग के आदेश की सच्ची प्रति नहीं हो सकती है क्योंकि यह दिखाया गया था कि आयोग के सचिव द्वारा अपने अधिकार में हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, बल्कि "आदेश द्वारा" व्यक्त किए गए थे। इसका मतलब यह था कि अनुबंध 'डी' संभवतः आयोग के आदेश के अनुसरण में सचिव द्वारा तैयार किए गए केवल औपचारिक आदेश या संचार की एक प्रति थी। इस मुद्दे पर थोड़ी चर्चा के बाद, दोनों पक्षों (याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हीरा लाल सिब्बल और प्रतिवादी के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक सेन) ने आयोग के मूल आदेश वाले रिकॉर्ड के लिए एक संयुक्त अनुरोध किया। तदनुसार, हमने आयोग को उक्त रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उस आदेश के अनुसरण में, आयोग की फाइल जिसमें 15 मार्च, 1971 को चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी का मूल आवेदन था, इसके अनुलग्नक और चुनाव आयोग के मूल आदेश के साथ, और नोटिंग जिसका संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है (जिला निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग के बीच कुछ पत्राचार के अलावा) 16 अप्रैल को हमारे सामने रखा गया था। 1971. इसके बाद दोनों पक्षों द्वारा इस आधार पर दलीलें दी गईं कि वास्तविक क्रम जिसकी वैधता निर्धारित की जानी है, वह मुख्य चुनाव आयुक्त का है, दिनांक 15 मार्च, 1971, श्री अशोक सेन ने निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से कहा कि उनका मामला या तो श्री एसपी सेन वर्मा के आदेश को बरकरार रखेगा या अन्यथा होगा। दिनांक 15 मार्च, 1971. बाद में श्री सिब्बल ने याचिका में संशोधन करने के लिए अनुमति के लिए मौखिक अनुरोध तक किया ताकि औपचारिक आदेश अनुलग्नक 'डी' पर हमला करने के बजाय आयोग के 15 मार्च, 1971 के आदेश को सीधे तौर पर लागू किया जा सके। हालांकि, उस समय प्रतिवादी की ओर से पेश हुए वकील सांघी ने स्पष्ट किया कि वह इस तरह की किसी तकनीकी पर भरोसा नहीं करते हैं, और हम पार्टियों द्वारा उठाए गए तर्कों पर इस धारणा पर फैसला सुना सकते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त के मूल आदेश के साथ-साथ औपचारिक आदेश अनुलग्नक 'डी' को रिट याचिका में लागू किया गया है। इसलिए इस संबंध में याचिका में संशोधन करने के श्री सिब्बल के अनुरोध पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

10. उल्लेख कुछ हद तक प्रारंभिक प्रकृति के एक अन्य मामले का भी किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के वकील ने याचिकाकर्ता को नियम 93 के प्रावधानों को चुनौती देने की अनुमति देने पर आपत्ति जताई क्योंकि रिट याचिका में इस तरह के किसी विशिष्ट आधार का उल्लेख नहीं किया गया था। तथापि, इस आपत्ति पर तब जोर नहीं दिया गया जब यह देखा गया कि इस मुद्दे को व्यापक रूप से प्रतिकृति में उठाया गया है, और जब, यह बताया गया कि ऐसे बिंदु जो आयोग के अधिकार क्षेत्र की जड़ तक जाते हैं, उन्हें न्यायालय द्वारा ही उठाया जा सकता है बशर्ते कि प्रतिवादियों को उन बिंदुओं को पूरा करने का अवसर दिया जाए।

11. पार्टियों के प्रतिद्वंद्वी विवादों से निपटने से पहले नियम 93 के विकास का पता लगाया जा सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (1951 का 43) (इसके बाद 1951 अधिनियम कहा जाता है)

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(नरूला, जे।

में कोई भी प्रावधान किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण को स्वीकार किए गए और अस्वीकृत मतपत्रों या मतदाता सूची की चिह्नित प्रति के निरीक्षण की अनुमति देने का अधिकार नहीं देता है। दूसरी ओर, मतदान की गोपनीयता से संबंधित 1951 के अधिनियम की धारा 94 और 128 *प्रथम दृष्टया ऐसे* दस्तावेजों के खिलाफ प्रतीत होती हैं, जिन्हें पराजित उम्मीदवार द्वारा निरीक्षण करने की अनुमति दी जा रहीहै। 1951 अधिनियम की धारा 169 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) (एच) के तहत सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद नियम 93 तैयार किया गया है। उप-धारा (1) केंद्र सरकार को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने के लिए अधिकृत करती है। उप-धारा (2) का खंड (एच) सरकार को निम्नलिखित मामलों के लिए ऐसे नियमों द्वारा प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है: —

"मतपेटियों, मतपत्रों और अन्य चुनाव पत्रों की सुरक्षित हिरासत, जिस अवधि के लिए ऐसे कागजात संरक्षित किए जाएंगे और ऐसे कागजात का निरीक्षण और उत्पादन।

नियम 93(1) जैसा कि यह मार्च, 1962 से पहले था, निम्नलिखित शब्दों में था -

"चुनाव पत्रों का उत्पादन और निरीक्षण। _____

1. रिटर्निंग ऑफिसर की हिरासत में रहते हुए-

(अ) अप्रयुक्त मतपत्रों के पैकेट;

(आ)प्रयुक्त मतपत्रों के पैकेट चाहे वे वैध हों, निविदा किए गए हों या अस्वीकार किए गए हों;

(इ) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के पैकेट या, जैसा भी मामला हो, धारा 152 की उपधारा (1) या उप-धारा (2) के तहत रखी गई सूची; और

(ई) निर्वाचकों द्वारा घोषणाओं के पैकेट और उनके हस्ताक्षरों का सत्यापन; इसे नहीं खोला जाएगा और उनकी सामग्री का निरीक्षण किसी सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश के अलावा किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जाएगा या उसके समक्ष पेश नहीं किया जाएगा।

31 मार्च, 1962 की अधिसूचना द्वारा, "चुनाव आयोग" को अधिकारियों (सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण) की सूची में जोड़ा गया था जो नियम 93 के उप-नियम (1) के तहत निरीक्षण की अनुमति दे सकते थे। 7 सितंबर, 1962 की अधिसूचना द्वारा, नियम 93 (1) में निम्नलिखित परंतुक जोड़े गए: –

"बशर्ते कि -

(अ) जहां निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसा कोई आदेश दिया जाता है, वहां आयोग उसे बनाने से पहले उसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा; और

(आ)ऐसे कोई पैकेट नहीं खोले जाएंगे, न ही उनकी सामग्री का चुनाव आयोग के ऐसे किसी आदेश के तहत किसी व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण किया

जाएगा, या उनके समक्ष पेश नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस व्यक्ति या प्राधिकरण नेउम्मीदवारों या उनके विधिवत अधिकृत एजेंटों को इस तरह के उद्घाटन, निरीक्षण या उत्पादन में उपस्थित होने का अवसर नहीं दिया है।

दिसंबर, 1966 तक किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप, अंतिम आकार जिसमें पूरा नियम 93 अब उभरा है (और प्रासंगिक समय पर लागू था) नीचे दिखाया गया है: –

"चुनाव पत्रों का उत्पादन और निरीक्षण।

1. जिला निर्वाचन अधिकारी की हिरासत में रहते हुए-

(अ) अप्रयुक्त मतपत्रों के पैकेट;

(आ)इस्तेमाल किए गए मतपत्रों के पैकेट चाहे वे वैध हों, निविदा किए गए हों या अस्वीकार किए गए हों;

(इ) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के पैकेट या जैसा भी मामला हो, धारा 152 की उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत रखी गई सूची; और

(ई) चुनावों द्वारा घोषणाओं के पैकेट और उनके हस्ताक्षरों का सत्यापन;

चुनाव आयोग या सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश के अलावा किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा उनकी सामग्री का निरीक्षण नहीं किया जाएगा, या उनके समक्ष पेश नहीं किया जाएगा।

बशर्ते कि -

(अ)जहां निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसा कोई आदेश दिया जाता है, वहां आयोग उसे बनाने से पहले उसके कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा; और

(आ)ऐसे कोई पैकेट नहीं खोले जाएंगे और न ही उनकी सामग्री का निर्वाचन आयोग के ऐसे किसी आदेश के तहत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जाएगा या उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस व्यक्ति या प्राधिकारी ने उम्मीदवारों या उनके विधिवत अधिकृत एजेंटों को इस तरह के उद्घाटन, निरीक्षण या उत्पादन में उपस्थित होने का उचित अवसर नहीं दिया हो।

2. निर्वाचन से संबंधित अन्य सभी कागजात ऐसी शर्तों के अधीन सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे और ऐसे शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान के लिए, जैसा कि निर्वाचन आयोग निदेश दे।

3. नियम 64 के तहत या नियम 84 के उपनियम (3) के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अग्रेषित रिटर्न की प्रतियां संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसी प्रत्येक प्रति के लिए दो रुपये के शुल्क के भुगतान पर प्रस्तुत की जाएंगी।

12. अब पक्षों के वकीलों द्वारा उठाए गए विभिन्न तर्कों को पकड़ने के लिए मंच तैयार है। श्री सिब्बल द्वारा दिए गए पहले दो तर्कों की सराहना करने के लिए, संविधान के भाग XV से अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 327 और अनुच्छेद 329 के खंड (1) को पुन: प्रस्तुत करना आवश्यक है (जो भाग

चुनावों से संबंधित है):

324 (1) संसद और प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के सभी निर्वाचनों और इस संविधान के अधीन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने और उनके संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा (जिसे इस संविधान में निर्वाचन आयोग के रूप में संदर्भित किया गया है)।

327. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संसद समय-समय पर विधि द्वारा निर्वाचक नामावलियों की तैयारी, निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन और ऐसे सदन या सदनों के यथोचित गठन को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अन्य सभी विषयों सहित संसद के किसी सदन या सदन के निर्वाचनों से संबंधित या उनके संबंध में उपबंध कर सकेगी।

329. इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी-

(अ) अनुच्छेद 327 या अनुच्छेद 328 के तहत बनाए गए या बनाए जाने वाले निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित किसी भी कानून की वैधता पर किसी भी अदालत में सवाल नहीं उठाया जाएगा;

(आ) संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन के लिए कोई निर्वाचन ऐसे प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत निर्वाचन याचिका के अलावा और ऐसी रीति से नहीं बुलाया जाएगा जो उपयुक्त विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन उपबंधित की जाए।

13. श्री सिब्बल का पहला निवेदन यह है कि जहां तक अनुच्छेद 327 को स्पष्ट रूप से "इस संविधान के प्रावधानों के अधीन" बनाया गया है, संसद को उस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त विधायी शक्ति अनुच्छेद 324 के अधीन है। ऐसा प्रतीत होता है कि कानून के इस प्रस्ताव के साथ कोई झगड़ा नहीं है। विवाद वास्तव में उस परिणाम से उत्पन्न होता है जो श्री सिब्बल उपर्युक्त कानूनी स्थिति से प्राप्त करना चाहते हैं। उनका कहना है कि अनुच्छेद 324 (1) के तहत आयोग का अधिकार क्षेत्र चुनावों के लिए मतदाता सूची तैयार करने के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण (i) तक ही सीमित है; और (ii) संसद आदि के सभी निर्वाचनों के संचालन के संबंध में, निर्वाचन आयोग को ऐसे किसी कार्य के साथ कानूनी रूप से निहित नहीं किया जा सकता है जो चुनाव पश्चात की अवधि से संबंधित हो। श्री सिब्बल के अनुसार, अनुच्छेद 324 में होने वाले "चुनाव" शब्द को उस शब्द के व्यापक अर्थ को सुप्रीम कोर्ट के उनके न्यायमूर्ति द्वारा एन *पी पोन्नुस्वामी* बनाम *सुप्रीम कोर्ट में दिया गया था।निर्वाचन अधिकारी, नटनाक्कल निर्वाचन क्षेत्र, नमक्कल, सलेम जिला; और अन्य*[1]। यह तर्क दिया गया था कि उस अर्थ के अनुसार, संसदीय

अपने व्यापक अर्थों में चुनाव 1951 अधिनियम की धारा 14 के तहत जारी अधिसूचना के साथ शुरू होता है, और 1961 के नियमों के नियम 64 के तहत चुनाव के परिणाम की घोषणा के साथ समाप्त होता है। तर्क यह है कि अनुच्छेद 324 (1) के तहत आयोग का अधिकार क्षेत्र "चुनावों के संचालन" तक ही सीमित होने के कारण इसके परिणाम की घोषणा के साथ समाप्त होता है, संसद द्वारा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता है, और संसद द्वारा कोई नियम नहीं बनाया जा सकता है, और केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 327 या 1951 के अधिनियम की धारा 169 के तहत कोई नियम नहीं बनाया जा सकता है। धारा 67 में उल्लिखित चरण के बाद के चुनावों के संबंध में आयोग। निर्वाचन अधिकारी द्वारा फॉर्म 20 में परिणाम पत्र में प्रविष्टियां करने के साथ चुनाव का संचालन समाप्त हो जाता है , जिसमें इसके विवरण का उल्लेख होता है। इसके बाद मतपत्रों को

[1] ए.आई.आर. 1952 एस.सी. 64 = (1952) S.C.R. 2218

सील कर दिया जाता है और उनकी हिरासत रिटर्निंग अधिकारी से जिला निर्वाचन अधिकारी को पास हो जाती है।

14. कहा जाता है कि चुनाव का संचालन 1951 के अधिनियम के भाग V के अध्याय V के तहत कार्यवाही की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाता है, यानी मतदान के परिणाम के प्रकाशन के साथ। हमारा ध्यान "चुनाव" शब्द के दायरे की ओर भी आकर्षित किया गया था, जिसे 1951 के अधिनियम की धारा 2 (डी) में परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है " _संसद के किसी भी सदन में एक सीट या सीटों को भरने के लिए चुनाव। यह तर्क दिया गया था कि सीट भरने के साथ चुनाव की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, भले ही चुनाव के संबंध में विवादों को निपटाने की कार्यवाही निकट हो या लंबित हो। इसी तरह, धारा 67 ए की भाषा से यह बताया गया था कि किसी उम्मीदवार के चुनाव की तारीख वह तारीख है जिस दिन उसे निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचित घोषित किया जाता है। विचाराधीन मुद्दे पर निर्णय लेने के उद्देश्य से, मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद चुनाव के संबंध में जो कुछ भी होता है, वह सख्ती से "चुनाव का संचालन" अभिव्यक्ति के दायरे में नहीं आ सकता है, लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। अनुच्छेद 327 की भाषा वास्तव में बहुत व्यापक है। यह प्रावधान संसद को न केवल "मतदाता सूची तैयार करने" या "संसद के सभी चुनावों के संचालन आदि" से संबंधित मामलों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। (अनुच्छेद 324 की विषय-वस्तु)। लेकिन "चुनावों से संबंधित सभी मामलों" या "चुनावों के संबंध में सभी मामलों" के संबंध में कोई कानून बनाने के लिए भी। इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि नियम 93 के अंतर्गत आने वाले मामले चुनावों से संबंधित हैं या उनका कम से कम चुनावों से कोई संबंध है। अनुच्छेद 327 के तहत शक्ति को नियंत्रित करने के लिए अनुच्छेद 324 को केवल एक सीमा तक कहा जा सकता है कि बाद के प्रावधान के तहत बनाया गया कोई भी कानून संविधान के अनुच्छेद 324 (1) द्वारा चुनाव आयोग में निहित शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए या किसी भी तरह से कम नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 324 (1) के तहत आयोग की शक्ति को पवित्र बनाया गया है, और अनुच्छेद 327 के तहत अपने विधायी कार्यों का प्रयोग करते हुए संसद द्वारा उस पर किसी भी संभावित अतिक्रमण से बचाया जाता है। हालांकि, अनुच्छेद 324 में निहित कुछ भी चुनाव आयोग में निहित या सौंपे जाने वाले कुछ अतिरिक्त शक्तियों या कार्यों के रास्ते में बाधा नहीं है। इस संबंध में याचिकाकर्ता के तर्क में कुछ दम हो सकता है यदि अनुच्छेद 324 में कहा गया था कि आयोग को कोई अन्य कार्य नहीं सौंपा जाएगा, और अनुच्छेद द्वारा आयोग को प्रदान की गई शक्तियों के अलावा इसमें कोई अन्य शक्ति निहित नहीं होगी। अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 327 की भाषा से इस तरह के किसी भी प्रतिबंध को स्पष्ट करना असंभव है। इसलिए, मैं श्री सिब्बल के पहले तर्क में कोई आधार खोजने में असमर्थ हूं और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि नियम 93 का आक्षेपित भाग किसी भी तरह से *संविधान के अनुच्छेद 327* के विपरीत नहीं है।
15. दूसरे बिंदु का भाग्य इस प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है कि क्या किसी व्यक्ति को 1961 के नियमों के नियम 93 (1) में उल्लिखित दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए चुनाव आयोग को केवल आवेदन देकर संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) के अर्थ के भीतर चुनाव बुलाया जा सकता है। इस मामले में आवेदन संसद के सदन में एक सीट के चुनाव से संबंधित है। यह चुनाव याचिका

के माध्यम से नहीं किया गया था। इसे चुनाव याचिका की सुनवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था और इसे 1951 के अधिनियम की धारा 81 से 83 द्वारा प्रदान किए गए तरीके से दायर नहीं किया गया था। अनुच्छेद 329 के खंड (ख) की अन्य सभी शर्तों पर कोई विवाद नहीं है, सिवाय ऊपर दिए गए प्रश्न के। तो अनुच्छेद 329 (बी) में "प्रश्न में कहा गया" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ है? इस संबंध में श्री सिब्बल ने *एन पी पोन्नुस्वामी के मामले* (1) (सुपरा) में उच्चतम न्यायालय की हेराफेरी पर बहुत जोर दिया। पोन्नुस्वामी के नामांकन पत्र को खारिज करने के निर्वाचन अधिकारी के एक आदेश की वैधता को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 329 (बी) द्वारा इस आधार पर रोक दिया था कि उक्त अनुच्छेद "चुनावी मामलों के संबंध में सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को बाहर करने या बाहर करने और चुनाव को चुनौती देने के एकमात्र तरीके को समाप्त करने के उद्देश्य से था"।

यह तब हुआ जब रिट याचिका दायर की गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संविधान के भाग XV में "चुनाव" शब्द का व्यापक अर्थों में उपयोग किया गया था और इसके दायरे में चुनाव की प्रक्रिया में सभी चरणों और नामांकन पत्र दाखिल करने और मतदान के परिणाम की घोषणा के बीच उस प्रक्रिया के सभी चरणों को शामिल किया गया था। इसलिए, श्री सिब्बल का यह कहना सही है कि अनुच्छेद 329 (बी) द्वारा बनाई गई रोक चुनाव के परिणाम की घोषणा के बाद शुरू की गई कार्रवाइयों या याचिकाओं या आवेदनों तक ही सीमित नहीं है। अनुच्छेद के दायरे में आने वाली कोई भी याचिका, आवेदन या कार्रवाई पर रोक लगा दी जाएगी, चाहे वह मतदान से पहले या बाद में शुरू या बाद में प्रस्तुत की गई हो। इसलिए, "चुनाव पर सवाल उठाने" का मतलब यह नहीं है कि चुनाव के परिणाम को दरकिनार करने के लिए प्रार्थना करें। सर्वोच्च न्यायालय ने आधिकारिक रूप से कहा है (i) कि अनुच्छेद 329 सभी चुनावी मामलों को कवर करता है; और (ii) कि कोई भी मामला जो चुनाव को प्रभावित करता है, उसे चुनाव याचिका के माध्यम से अदालत के समक्ष नहीं लाया जा सकता है। प्रतिवादी द्वारा निरीक्षण के लिए अपने आवेदन में लगाए गए आरोप 1951 अधिनियम की धारा 100 (एल) (डी) (iii) द्वारा पूरी तरह से कवर किए गए हैं, जो उच्च न्यायालय को लौटाए गए उम्मीदवार के चुनाव को शून्य घोषित करने का कर्तव्य देता है, यदि यह राय है कि किसी भी वोट के अनुचित स्वागत, इनकार या अस्वीकृति या किसी भी वोट के स्वागत से जो शून्य है, जहां तक चुनाव का परिणाम वापस आए उम्मीदवार से संबंधित है, भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है। यदि प्रतिवादी ने एक सक्षम अदालत या ट्रिब्यूनल को आवेदन दिया था जो वोटों के कथित अनुचित स्वागत या अस्वीकृति के बारे में उसकी शिकायत पर फैसला कर सकता था या फैसला कर सकता था, तो वह वास्तव में रिट-याचिकाकर्ता के चुनाव को सवालों के घेरे में बुला लेता। हालांकि, एक महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या अनुच्छेद 329 (बी) द्वारा केवल चुनाव पर सवाल उठाना प्रतिबंधित है या केवल ऐसी कार्यवाही में चुनाव को प्रश्न में बुलाया जाना प्रतिबंधित है, जिसके परिणाम से यह पूर्व-निर्धारित हो सकता है कि चुनाव याचिका न्यायालय द्वारा उचित कार्यवाही में अंततः क्या पाया जाना है? श्री सिब्बल ने अनुच्छेद 32'9 के खंड (क) और खंड (ख) में अपनाई गई भाषा में मौखिक अंतर की ओर ध्यान दिलाया जहां तक खंड (क) केवल 'किसी भी न्यायालय में' प्रश्न पूछने पर रोक लगाता है, लेकिन खंड (ख) से अनुपस्थित रहने के कारण 'किसी भी न्यायालय में' शब्द स्पष्ट हैं। उस आधार पर यह प्रस्तुत किया गया था कि यद्यपि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आवंटन से संबंधित किसी भी कानून आदि की वैधता पर रोक केवल किसी भी न्यायालय में कार्यवाही के लिए है, चुनाव (जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया है) को किसी भी न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के अलावा अन्य कार्यवाही में भी प्रश्न में बुलाने की अनुमति नहीं है। इस संबंध में यह देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने *पोन्नुस्वामी के मामले* (1) में यह स्पष्ट कर दिया कि अनुच्छेद 329 के खंड (बी) को उस अनुच्छेद के खंड (ए) के पूरक के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि "किसी भी न्यायालय में" शब्दों को खंड (बी) से केवल इसलिए हटा दिया गया है ताकि टॉटोलॉजी से बचा जा सके, और यह कि उन शब्दों के बिना भी इरादा निर्णय देने के लिए सक्षम न्यायालयों या ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को रोकना है और नागरिकों या उम्मीदवार को निजी या सार्वजनिक संचार में या यहां तक कि उन अधिकारियों को दिए गए आवेदनों और याचिकाओं में चुनाव पर सवाल उठाने से रोकना नहीं है जो न तो कर सकते हैं और न ही दावा कर सकते हैं। चुनाव की पूछताछ से संबंधित किसी भी मामले को तय करें और किन अधिकारियों को ऐसा कोई निर्णय देने के लिए भी नहीं कहा जा सकता है। *हरि विष्णु कामथ*

बनाम अहमद इशाक और अन्य[2] मामले में सुप्रीम कोर्ट की घोषणा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए , इस आशय का कि अनुच्छेद 329 (बी) आवश्यक रूप से चुनाव को रद्द करने के लिए कार्यवाही शुरू करने तक सीमित नहीं है। यह अपने दायरे में उन कार्यवाहियों को भी शामिल करता है जो चुनाव को दरकिनार करने के लिए नहीं हैं। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने भी हमारा ध्यान हल्सबरी के इंग्लैंड के कानूनों के पृष्ठ 243 पर पैराग्राफ 426 में निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया। तीसरा संस्करण, खंड 14 (साइमंड्स संस्करण): –

> "किसी भी संसदीय चुनाव और संसद में वापसी पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है, सिवाय एक याचिका के, जिसे संसदीय चुनाव याचिका कहा जाता है, जिसमें अनुचित चुनाव या रिटर्न की शिकायत की जाती है जो वैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की जाती है।

और प्रस्तुत किया कि 1.951 अधिनियम की धारा 80, जो संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) के अनुरूप है, का उद्देश्य कुछ भी अलग प्रदान करना नहीं है। अंग्रेजी मतपत्र अधिनियम और अंग्रेजी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1949 और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लेख करते हुए, श्री सांघी ने पार्कर के चुनाव एजेंट और रिटर्निंग ऑफिसर, पांचवें संस्करण के पृष्ठ 221 पर पैराग्राफ की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें यह कहा गया है कि खारिज किए गए मतपत्रों का निरीक्षण हाउस ऑफ कॉमन्स के आदेश के साथ-साथ उच्च न्यायालय या काउंटी कोर्ट के आदेश से प्राप्त किया जा सकता है। और इसी तरह गिने गए मतपत्रों के निरीक्षण के आदेश सदन से प्राप्त किए जाएं।

कॉमन्स या किसी अदालत से। यह तर्क दिया गया था कि अंग्रेजी नियमों की वैधता या वैधता पर कभी सवाल नहीं उठाया गया था, हालांकि अनुच्छेद 329 (बी) जैसे वैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ गोपनीयता से संबंधित कानून इंग्लैंड में भारत के समान हैं।

16. मेरी राय में किसी याचिका, आवेदन या कार्यवाही को अनुच्छेद 329 के खंड (ख) द्वारा केवल तभी रोका जाएगा जब निम्नलिखित चार शर्तें पूरी की जाती हैं:-

    1. आवेदन एक चुनाव याचिका के अलावा है, जिसे निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है;
    2. चुनाव कार्यवाही से संबंधित मामलों पर आवेदन में हमला किया जाता है;
    3. हमला उस फैसले पर होता है जिसके फैसले पर चुनाव याचिका की सुनवाई करने के लिए सक्षम अदालत चुनाव को रद्द कर सकती है या इसे शून्य घोषित कर सकती है; और
    4. उपर्युक्त खंड (iii) में उल्लिखित चुनाव कार्यवाही से संबंधित मामले पर प्राधिकरण या न्यायाधिकरण का अधिनिर्णय आवेदक द्वारा लागू किया जाता है, इस तथ्य के बावजूद कि प्राधिकरण को इस मामले पर निर्णय लेने का अधिकार है या नहीं।

[2] A.I.R 1955 S.C 233

17. जब उपरोक्त सिद्धांतों को इस मामले के तथ्यों पर लागू किया जाता है, तो यह स्पष्ट है कि हालांकि पहले तीन संतुष्ट हैं, चौथा एक पूरा नहीं हुआ है। हालांकि 1951 के अधिनियम की धारा 100 (एल) (आई) (iii) के तहत आने वाले निरीक्षण के लिए अपने आवेदन में प्रतिवादी द्वारा सीधा हमला किया गया था, लेकिन उस संबंध में आरोपों की शुद्धता या अन्यथा के बारे में निर्णय देने के लिए चुनाव आयोग से कोई अनुरोध नहीं किया गया था, न ही आयोग ऐसी किसी भी प्रार्थना पर विचार कर सकता था। यह महत्वपूर्ण है कि किसी उम्मीदवार को ढोल की थाप से यह कहने पर कोई रोक नहीं है कि चुनाव में भ्रष्ट आचरण किया गया है, न ही निजी या सार्वजनिक संचार में, या यहां तक कि समाचार पत्रों में भी कानून की सीमा के भीतर इस तरह के आरोप लगाए जाने पर कोई रोक नहीं है। इसलिए, अनुच्छेद 329 (बी) द्वारा बनाई गई रोक किसी ऐसी चीज के उच्चारण या लेखन के लिए नहीं है जो एक वैध हमले के बराबर हो सकती है, जिसके प्रमाण पर याचिका अदालत द्वारा चुनाव को रद्द किया जा सकता है, लेकिन यह रोक केवल ऐसे किसी भी प्रश्न पर निर्णय या निर्णय का दावा करने के लिए है। हमें वेबस्टर के न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी (दूसरा संस्करण) के पृष्ठ 320 पर दिए गए वाक्यांश "कॉल इन क्वेश्चन" के शब्दकोश अर्थ का उल्लेख किया गया था। वहां यह कहा गया है कि "प्रश्न में बुलाने" का अर्थ है "परीक्षण या परीक्षा के लिए बुलाना; इसलिए चुनौती देने के लिए निर्दिष्ट करें; महाभियोग लगाना; संदेह करना; जांच करने के लिए; सिब्बल ने कहा कि अनुच्छेद 329 में जिस अर्थ में अभिव्यक्ति का इस्तेमाल किया गया है, वह "संदेह पैदा करने के लिए" है। दूसरी ओर यह सुझाव दिया गया था कि शब्दकोश में दिए गए विभिन्न वैकल्पिक अर्थों में से, वाक्यांश पर लागू होने वाला एकमात्र उपयुक्त अर्थ जिस संदर्भ में यह होता है वह है "परीक्षण के लिए तलब करना। मुझे लगता है कि किसी को भी तब तक चुनाव नहीं माना जाएगा जब तक कि वह रिटर्निंग उम्मीदवार को मुद्दों के परीक्षण के लिए बुलाने की प्रार्थना नहीं करता है, जिसका निर्णय अंततः चुनाव के परिणाम पर सवाल उठाने के लिए प्रासंगिक हो सकता है। जहां तक चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी ने चुनाव की वैधता के सवाल पर चुनाव आयोग से ऐसे किसी फैसले का दावा नहीं किया, प्रतिवादी को यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने याचिकाकर्ता के चुनाव को सवालों के घेरे में बुलाया है। नियम 93 में किया गया संशोधन चुनाव आयोग को किसी ऐसे प्रश्न या मुद्दे के निर्णय के लिए किसी भी दावे पर विचार करने का अधिकार नहीं देता है, जिसके निर्णय पर चुनाव रद्द किया जा सकता है या शून्य घोषित किया जा सकता है। न ही यह प्रावधान किसी को भी इस तरह के किसी भी निर्णय या निर्णय का दावा करने का अधिकार देता है। इसलिए, यह माना जाता है कि चुनाव की वैधता के खिलाफ आरोपों के गुण-दोष पर कोई निर्णय दिए बिना दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति देने के लिए चुनाव आयोग को अधिकार देने वाले नियम 93 का विवादित संशोधन किसी भी तरह *से* संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) के विपरीत नहीं है। इसलिए, श्री सिब्बल का दूसरा तर्क भी विफल हो जाता है।

18. यह मुझे नियम 93 के तहत चुनाव आयोग की शक्ति के दायरे में ले जाता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत प्रस्ताव यह है कि उक्त शक्ति का उपयोग आयोग द्वारा केवल उसी तरीके से और उन्हीं सीमाओं और सुरक्षा उपायों के अधीन किया जा सकता है जो उसी नियम के तहत एक अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा प्रयोग किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, हमें यह मानने के लिए कहा जाता है कि नियम 93 में नामित तीन पदाधिकारियों

की प्रकृति के बीच विशाल और महत्वपूर्ण अंतर के बावजूद, उन सभी को निरीक्षण के लिए आवेदन पर निर्णय लेने के लिए एक समान तरीके से कार्य करना चाहिए। विभिन्न मामलों के दौरान उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा कुछ सकारात्मक और नकारात्मक परीक्षण निर्धारित किए गए हैं, जिनके लिए दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों द्वारा हमारे समक्ष विस्तृत और बार-बार संदर्भ दिया गया था, जो नियम 93 के तहत निरीक्षण की अनुमति देने की अदालत की शक्ति की सीमाओं से संबंधित था। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा क्या निर्णय दिया गया है, इस पर कोई विवाद नहीं होने के कारण, मैं केवल कानून के उन प्रस्तावों को गिना सकता हूं जो जबर सिंह बनाम *गेंदा लाल*[3], *राम सेवक यादव* बनाम *हुसैन कामिल किदवई और अन्य*[4], और *जितेंद्र बहादुर सिंह* वी। *कृष्णा बिहारी और अन्य*[5] मामले में न्यायमूर्ति के निर्णयों से निकलते *हैं* : –

1. यहां तक कि 1961 के नियमों के नियम 93 से स्वतंत्र रूप से, एक अदालत या एक न्यायाधिकरण के पास चुनाव याचिका के परीक्षण के दौरान विचाराधीन दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति देने की शक्ति और अधिकार क्षेत्र है। न्यायालय का यह क्षेत्राधिकार सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XI की संकीर्ण सीमाओं तक सीमित नहीं है;
2. भले ही यह न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग हो या नियम 93 द्वारा निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, न्यायालय निश्चित रूप से प्रयुक्त मतपत्रों आदि के निरीक्षण की अनुमति नहीं दे सकता है। केवल यह तथ्य कि मतपत्र न्यायालय के समक्ष उपलब्ध हैं या उनकी हिरासत रखने वाले अधिकारी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं, किसी भी पक्ष को उनके निरीक्षण का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है;
3. निरीक्षण की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब चुनाव याचिका में उन भौतिक तथ्यों का पर्याप्त विवरण हो जिस पर याचिकाकर्ता अपने मामले के समर्थन में भरोसा करता है; और इस तरह के निरीक्षण के बाद याचिकाकर्ता को उन भौतिक तथ्यों को साबित करने में सक्षम बनाने के लिए निरीक्षण आवश्यक है। किसी याचिका में की गई अस्पष्ट दलीलों का समर्थन करने के लिए निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो भौतिक तथ्यों द्वारा समर्थित नहीं है;
4. नियम 93 के उप-नियम (1) में उल्लिखित दस्तावेजों के निरीक्षण को केवल अस्पष्ट दलीलों का समर्थन करने के लिए सबूत निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। याचिकाकर्ता के मामले को भौतिक तथ्यों के कथनों द्वारा समर्थित सटीकता के साथ निर्धारित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता द्वारा संदेह करने या विश्वास करने का आरोप कि वोटों का अनुचित स्वागत, इनकार या अस्वीकृति हुई है, अदालत को निरीक्षण की अनुमति देने का अधिकार नहीं देगा;
5. न्यायालय द्वारा निरीक्षण की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब वह संतुष्ट हो कि विवाद का फैसला करने और पार्टियों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए, मतपत्रों का निरीक्षण आवश्यक है;

[3] A.I.R 1964 S.C. 1200 (1964)6 S.C.R 54
[4] A.I.R 1964 S.C 1249 (1964) 6 S.C.R 238
[5] A.I.R 1970 S.C. 276

6. असफल उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वोटों की अवैध अस्वीकृति के आरोप के संबंध में एक आवेदन में, यह याद रखना चाहिए कि उम्मीदवारों या उनके चुनाव एजेंटों के लिए संबंधित मतपत्रों के सीरियल नंबर नोट करना काफी आसान है। इसलिए, यदि चुनाव याचिका मतपत्रों के निरीक्षण के बारे में चुप है या क्या मतगणना एजेंटों ने उन मतपत्रों के सीरियल नंबर नोट किए थे, या क्या उन एजेंटों ने उन मतपत्रों की वैधता के संबंध में कोई आपत्ति उठाई थी; यदि हां, तो वे एजेंट कौन हैं, और मतपत्रों के सीरियल नंबर क्या हैं, जिन पर उनमें से प्रत्येक ने अपनी आपत्ति व्यक्त की है, बताए जाने वाले भौतिक तथ्य संतुष्ट नहीं हैं, और इसलिए मतपत्रों की जांच का आदेश नहीं दिया जाना चाहिए; और

7. अदालत को मतपत्रों की गोपनीयता पर कानून के आग्रह (1951 अधिनियम की धारा 94 और 128) का ध्यान रखना चाहिए।

19. निरीक्षण की अनुमति देने के लिए न्यायालय की शक्ति पर सीमाओं के दायरे के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के विश्लेषण से पता चलता है कि न्यायालय को आवश्यक रूप से किसी प्रकार की प्रारंभिक जांच शुरू करने की आवश्यकता है, जिसके आधार पर वह निरीक्षण की अनुमति देने से *पहले कुछ बिंदुओं पर प्रथम दृष्टया* निर्णय ले सकता है। श्री सिब्बल ने कहा कि नियम 93 में तीनों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया है। इसमें नामित पदाधिकारी। उनमें से प्रत्येक की शक्ति को नियम द्वारा समान रूप से निर्बाध और बंधनमुक्त होने के लिए छोड़ दिया गया है। न तो इसका प्रयोग करने का तरीका और न ही किन परिस्थितियों में निरीक्षण की अनुमति दी जानी है, नियम में दर्शाया गया है। इस संबंध में न्यायालय की शक्ति को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया है, यह तर्क दिया जाता है कि हमें नियम 93 के तहत चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में उसी कानून को आवश्यक रूप से लागू करना चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने पृष्ठ 161 पर क्रेज़ एन क़ानून कानून (पांचवें संस्करण) में की गई टिप्पणियों के आधार पर जोरदार तर्क दिया कि नियम 93 में आयोग की शक्तियों के प्रयोग के लिए कोई अलग नियम निर्धारित नहीं करके, 'नियम बनाने वाले प्राधिकारी को उधार दिया गया माना जाता है।

निरीक्षण की शक्ति की न्यायिक व्याख्या को विधायी मान्यता, और इसलिए, हमें यह मानना चाहिए कि आयोग भी निरीक्षण की अनुमति नहीं दे सकता है जब तक कि ऊपर उल्लिखित सभी शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है। मैं इस निवेदन से सहमत होने में असमर्थ हूं। इस मामले में न्यायिक व्याख्या की विधायी मान्यता का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि चुनाव आयोग को अधिकार प्रदान करने के लिए 1962 में नियम में संशोधन किया गया था और न्यायिक फैसले 1964 और 1970 के बीच बहुत बाद में आए थे। मेरा यह भी मत है कि यदि एक ही नियम द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों को एक ही शक्ति प्रदान की जाती है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि उन प्राधिकारियों में से प्रत्येक द्वारा शक्ति का प्रयोग बिल्कुल उसी तरीके से किया जाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, जब किसी उच्च न्यायालय में कोई नई शक्ति निहित होती है/यह हमेशा समझा जाता है, इस संबंध में कोई विशिष्ट घोषणा किए बिना, कि ऐसी नई शक्ति का प्रयोग उसी तरीके से किया जाएगा, और उसी नियम और सीमाओं के अधीन किया जाएगा, जैसा कि उस न्यायालय द्वारा पहले से ही प्रयोग की जा रही अन्य शक्तियों के अधीन है। मैं नियम 93 के तहत एक तरफ अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा और दूसरी तरफ चुनाव आयोग द्वारा शक्ति के प्रयोग के बीच दो बुनियादी और भौतिक अंतरों को नजरअंदाज करने में असमर्थ हूं। पहला अंतर दो अधिकारियों की प्रकृति में निहित है। चुनाव आयोग के पास करने के लिए दो प्रकार के कार्य हैं, अर्थात्, प्रशासनिक और अर्ध-न्यायिक। कुछ समय के लिए यह मान लिया जाए कि नियम 93 के तहत इसकी शक्तियों का प्रयोग अर्ध-न्यायिक तरीके से किया जाना है, तब भी उसे न्यायालय के समान कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय की आवश्यक विशेषताएं, जैसा कि अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण से अलग है; सुप्रीम कोर्ट ने *वीरेंद्र कुमार सत्यवादी* बनाम *पंजाब राज्य*[6] *मामले में निम्नलिखित शब्दों में इसका उल्लेख किया था:-*

> "यह व्यापक रूप से कहा जा सकता है कि एक अदालत को अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण से अलग करने वाली बात यह है कि उस पर न्यायिक तरीके से विवादों का फैसला करने और एक निश्चित निर्णय में पार्टियों के अधिकारों की घोषणा करने का कर्तव्य है। न्यायिक तरीके से निर्णय लेने के लिए यह शामिल है कि पक्षकार अपने दावे के समर्थन में सुनवाई के अधिकार के मामले के रूप में हकदार हैं और इसके प्रमाण में सबूत जोड़ना चाहते हैं।
>
> और यह प्राधिकरण की ओर से एक दायित्व भी आयात करता है कि वह पेश किए गए सबूतों पर विचार करने और कानून के अनुसार मामले का फैसला करे। जब एक सवाल

(दो) ए.आई.आर. 1956 एस.सी. 153.

---

[6] A.I.R 1956 S.C. 153

इसलिए यह उठता है कि क्या किसी अधिनियम द्वारा बनाया गया प्राधिकरण एक अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण से अलग एक न्यायालय है, यह तय किया जाना है कि क्या अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में इसमें अदालत के सभी गुण हैं।

यद्यपि एक अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण में न्यायालय की शक्तियां हो सकती हैं, लेकिन इसे आवश्यक रूप से न्यायालय के सभी प्रसिद्ध गुणों के साथ श्रेय नहीं दिया जा सकता है।

20. दूसरा अंतर प्रकृति या कार्यवाही में निहित है। जबकि न्यायालय या न्यायाधिकरण को उसके समक्ष जारी मामलों पर निर्णय देने के उद्देश्य से निरीक्षण की अनुमति देने का अधिकार है, चुनाव आयोग के समक्ष ऐसा कोई विचार प्रासंगिक नहीं है। आयोग को विवाद के गुण-दोष पर कोई निर्णय देने का न तो अधिकार है और न ही उससे कोई अपेक्षा की जाती है। यह स्पष्ट है कि यद्यपि नियम 93 के तहत प्रयोग की जाने वाली शक्ति न्यायालय के साथ-साथ चुनाव आयोग के लिए भी समान है, निरीक्षण के लिए आवेदन पर विचार करने और निर्णय लेने का कार्य आवश्यक रूप से निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं है, और वास्तव में, कुछ मामलों में, आयोग द्वारा उसी तरह से नहीं किया जा सकता है जैसा कि न्यायालय द्वारा किया जाता है। यद्यपि शक्ति समान हो सकती है, इसके प्रयोग का तरीका पदाधिकारी की आवश्यक विशेषताओं और कार्यवाही की प्रकृति और उद्देश्य के साथ भिन्न होता है जिसके दौरान शक्ति का उपयोग किया to.be है। न्यायालय के साथ-साथ आयोग द्वारा विचाराधीन शक्ति के प्रयोग के आवश्यक सामान्य तत्व और विशेषताएं इस प्रकार हैं -

    1. नियम 93 के तहत एक आवेदन को केवल ऐसे व्यक्ति के उदाहरण पर अनुमति दी जा सकती है जिसके पास 'निरीक्षण द्वारा एकत्र की जाने वाली जानकारी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण रुचि है;
    2. इस तरह के आवेदन को तब तक अनुमति नहीं दी जा सकती जब तक कि उन मामलों पर निश्चित आरोप नहीं लगाए जाते हैं जिनके साथ न्यायालय या आयोग, जैसा भी मामला हो;
    3. आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए जब तक कि न्यायालय या आयोग संतुष्ट न हो जाए कि *मटेरिया 1 और प्रासंगिक आरोपों में* कम से कम कुछ प्रथम दृष्टया सच्चाई है;
    4. निरीक्षण के आवेदनों से निपटने में दोनों प्राधिकरणों द्वारा न्यायिक और वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए;

5. केवल साक्ष्य जुटाने के लिए निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती। हालांकि, सबूत इकट्ठा करने के लिए निरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है, जिसके बारे में आवेदक को पहले से ही यह बताते हुए खुलासा करना होगा कि वह गुप्त कागजात में वास्तव में क्या देखने जा रहा है;
6. इस बात पर संतोष होना चाहिए कि क्यों निरीक्षण को न्याय के हित में माना जाता है और किसी दिए गए मामले की परिस्थितियों में अपरिहार्य रूप से आवश्यक माना जाता है;
7. निश्चित रूप से निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए; और
8. अदालत या आयोग द्वारा किसी भी निरीक्षण की अनुमति इस तरह से नहीं दी जा सकती है जिससे मतपत्र की गोपनीयता का उल्लंघन हो।

21. दूसरी ओर न्यायालय और आयोग द्वारा इस शक्ति के प्रयोग के बीच निम्नलिखित मुख्य अंतर हैं -
    1. अदालतें लंबित कार्यवाही के दौरान निरीक्षण की अनुमति नहीं दे सकती हैं जैसे कि (i) चुनाव याचिका, या (ii) आपराधिक अभियोजन। आयोग निरीक्षण की अनुमति दे सकता है भले ही उसके समक्ष कोई कार्यवाही लंबित न हो ;
    2. एक न्यायालय की आवश्यक विशेषताएं और विशेषताएं जो उनके साथ एक निश्चित निर्णय पर आने का पारंपरिक तरीका रखती हैं, आयोग के मामले में वांछित हैं;
    3. जबकि न्यायालय की संतुष्टि नियमित रूप से कानूनी रूप से स्वीकार्य साक्ष्य द्वारा प्राप्त की जाएगी, आयोग साक्ष्य और नागरिक प्रक्रिया के नियमों द्वारा निर्बाध मामले की परिस्थितियों द्वारा मांगे गए किसी भी निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से निरीक्षण की अनुमति देने के कारणों के अस्तित्व के बारे में खुद को संतुष्ट कर सकता है;
    4. जबकि न्यायालय के पास नियम 93 को लागू किए बिना भी निरीक्षण की अनुमति देने की अंतर्निहित शक्ति है, आयोग के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है और उस नियम के अलावा निरीक्षण की अनुमति नहीं दे सकता है।
22. प्रासंगिक कानूनी स्थिति के इस विश्लेषण से पता चलता है कि अनुमति देने को नियंत्रित करने वाले कुछ सिद्धांत एक तरफ अदालत या ट्रिब्यूनल द्वारा और दूसरी तरफ चुनाव आयोग द्वारा चुनाव रिकॉर्ड समान नहीं हैं। यह आगे दर्शाता है कि निरीक्षण की अनुमति देने की चुनाव आयोग की शक्ति एक तरह से अदालत या न्यायाधिकरण की तुलना में व्यापक है, क्योंकि यह अदालत द्वारा उस शक्ति के प्रयोग के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित सभी शर्तों से बंधी नहीं है। इसलिए, मैं श्री सिब्बल की इस बात से सहमत होने में असमर्थ हूं कि इस संबंध में आयोग की शक्ति न्यायालय की शक्ति के साथ बिल्कुल व्यापक और सह-टर्मिनस है, और उन सभी सीमाओं के अधीन है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं समझा जा सकता है कि नियम 93 द्वारा आयोग में निहित शक्ति या तो मनमानी या काल्पनिक है या पूरी तरह से निरंकुश है। मैं श्री सिब्बल के चौथे और पांचवें तर्क पर चर्चा करते हुए मामले के इस पहलू पर चर्चा करूंगा। उन प्रस्तुतियों के संबंध में जो कुछ कहा जा रहा है, उसके अधीन रहते हुए, मैं मानता हूं कि निर्वाचन आयोग के आक्षेपित आदेश को केवल इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता है कि निरीक्षण की अनुमति देने के लिए न्यायालय या अधिकरण की शक्तियों के संबंध में उच्चतम

न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किए बिना आयोग द्वारा शक्ति का प्रयोग किया गया है।

23. पक्षकारों के वकीलों के बीच इस बुनियादी बिंदु पर शायद ही कोई विवाद था कि नियम 93 के दायरे से चुनाव आयोग को प्रदत्त शक्ति का उस प्राधिकरण द्वारा उस नियम के परंतुक के अनुपालन के बिना कानूनी रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। श्री अशोक सेन ने कई शब्दों में स्वीकार किया कि आयोग का एक आदेश जो कारणों से समर्थित नहीं है, टिक नहीं सकता है और इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। हालांकि श्री संगबी ने बाद में यह तर्क देने की कोशिश की कि परंतुक की आवश्यकताएं केवल निर्देशिका थीं और अनिवार्य नहीं थीं, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि ऐसा कहकर उन्होंने यह सुझाव नहीं दिया कि बिना किसी कारण के आयोग के आदेश को अनुच्छेद 226 के तहत रिट कार्यवाही में समर्थन दिया जा सकता है। जिस सवाल पर दोनों पक्षों को विस्तार से बहस करनी थी, वह यह था कि क्या इस मामले में आयोग का आक्षेपित आदेश परंतुक की आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं।

24. एक प्रारंभिक मामला जिसमें आक्षेपित आदेश की वैधता से निपटने से पहले विचार करने की आवश्यकता होती है, इस सवाल से संबंधित है कि क्या आयोग का आदेश वह है जो 15 मार्च, 1971 को मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा पारित किया गया था, या जिसे आयोग के "आदेश द्वारा" सचिव द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था, और जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्राप्त किया गया था। जबकि श्री अशोक सेन ने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया था कि यह मुख्य चुनाव आयुक्त का आदेश है जो वास्तविक आदेश है जिसे कानून की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए और उस आदेश में किसी भी कमी को भरने के लिए, हम आयोग के कार्यालय द्वारा तैयार किए गए औपचारिक आदेश की मदद नहीं ले सकते हैं और जिला निर्वाचन अधिकारी को अग्रेषित कर सकते हैं। श्री संघी। बाद में प्रतिवादी की ओर से दलीलों की श्रृंखला को उठाते हुए उन्होंने तर्क दिया कि हालांकि वह इस संबंध में श्री सेन द्वारा उठाए गए रुख से पीछे नहीं हटना चाहते हैं?, * वह केवल यह जोड़ना चाहते हैं कि 16 मार्च, 1971 के औपचारिक आदेश को मुख्य चुनाव आयुक्त के आदेश का एक हिस्सा माना जाना चाहिए और इसे इसमें शामिल माना जाना चाहिए। जिस तरह से दो आदेश पारित किए गए थे, उसका विस्तृत विवरण मैंने इस फैसले के पहले भाग में मामले का इतिहास देते हुए पहले ही दिया था। हमारा ध्यान 1951 के अधिनियम की धारा 19क की ओर दिलाया गया था जो उप मुख्य निर्वाचन आयुक्त और आयोग के सचिव को भी संविधान, 1951 अधिनियम या 1961 के नियमों के तहत आयोग के सभी या किन्हीं कार्यों को करने के लिए अधिकृत करता है। इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी के आवेदन पर अंतिम आदेश तीनों में से किसी भी प्राधिकरण द्वारा पारित किया जा सकता था। हालांकि, मैं धारा 19ए से यह बताने में असमर्थ हूं कि तीनों में से किसी भी प्राधिकरण को उनमें से दूसरे द्वारा पारित आदेश में सुधार करने या चुनाव आयोग द्वारा पारित आदेश में छोड़ी गई किसी भी कमी को भरने की कोई शक्ति नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त अपना कोई आदेश पारित किए बिना आवेदन को उप मुख्य चुनाव आयुक्त या आयोग के सचिव के पास भेज सकते थे। जिस प्राधिकारी को आवेदन चिह्नित किया गया था, वह तब इस पर अपना निर्णय दे सकता था। हालांकि, एक बार जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने आवेदन

पर अपना आदेश पारित कर दिया था, तो कार्यालय केवल मुख्य चुनाव आयुक्त के आदेश में निर्देशित एक औपचारिक आदेश का मसौदा तैयार कर सकता था; जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त के आदेश के परिणामस्वरूप एक नियमित प्रकार के विस्तृत निर्देश शामिल हो सकते थे। तथापि, यह अकल्पनीय है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त आदेश पारित करेंगे और उप मुख्य निर्वाचन आयुक्त या सचिव इसके कारणों को लिखेंगे। मैंने पहले ही रिट याचिका के किसी भी औपचारिक संशोधन पर जोर दिए बिना दोनों पक्षों के वकीलों के बीच एक या दोनों आदेशों की वैधता पर हमारे निर्णय को आमंत्रित करने के लिए समझौते का उल्लेख किया है, जो सीधे और विशेष रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त के मूल आदेश को लागू करता है, जो स्वाभाविक रूप से रिट याचिका दायर किए जाने के समय याचिकाकर्ता के संज्ञान में नहीं था। मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, मेरा दृढ़ मत है कि इस याचिका का परिणाम मुख्य चुनाव आयुक्त के 15 मार्च, 1971 के मूल आदेश की वैधता या अन्यथा पर निर्भर करेगा। मेरी यह भी राय है कि जहां भी और जहां तक औपचारिक आदेश निरीक्षण की अनुमति के मामले में मूल आदेश से आगे निकलता है, औपचारिक आदेश की अनदेखी की जानी चाहिए। दोनों आदेशों (मुख्य चुनाव आयुक्त के 15 मार्च, 1971 के आदेश और आयोग के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित औपचारिक आदेश, दिनांक 16 मार्च, 1971) का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने पर उनके बीच अंतर के निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं का पता चलता है, जो यह भी दर्शाता है कि 16 मार्च, 1971 के औपचारिक आदेश ने मुख्य चुनाव आयुक्त के आदेश से परे जाकर उल्लंघन किया, दिनांक 15 मार्च, 1971, कुछ मामलों में:-

मुख्य चुनाव आयुक्त का 15 मार्च, 1971 का आदेश।

1. निरीक्षण की अनुमति "नियम 9 के उप-नियम (1) में उल्लिखित दस्त, जिसमें आवश्यक रूप से नियम 93 के उप-नियम (1) के दायरे के विषय (डी) के संदर्भ में "निर्वाचकों द्वारा घोषणाओं के पैकेट और उनके हस्ताक्षरों का सत्यापन" शामिल था;

2. लौटाए गए उम्मीदवार को इकबाल सिंह प्रतिवादी के पक्ष में डाले गए मतों का निरीक्षण करने की अनुमति देने वाला कोई आदेश पारित नहीं किया गया था;

की ओर से सचिव द्वारा हस्ताक्षरित औपचारिक आदेश आयोग, दिनांक 16 मार्च, 1971.

यद्यपि आदेश में निरीक्षण की अनुमति देने के निर्णय का संदर्भ दिया गया है - "जैसा कि आवेदक द्वारा अनुरोध किया गया है"- दस्तावेजों को निर्दिष्ट करते हुए कि किस निरीक्षण की वास्तव में अनुमति दी जानी थी और किस आदेश

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(नरूला, जे।

आयोग की ओर से सचिव द्वारा हस्ताक्षरित
औपचारिक आदेश दिनांक 16 मार्च, 1971

संदर्भ निरीक्षण की अनुमति देने के निर्णय के आदेश में किया गया है- जैसा कि आवेदक द्वारा प्रार्थना की गई है। किन दस्तावेजों को वास्तव में निरीक्षण की अनुमति दी जानी थी और किस आदेश में इसकी अनुमति दी जानी थी, यह विनिदष्ट करते समय नियम 93 (1) (डी) में उल्लिखित दस्तावेजों का कोई संदर्भ नहीं दिया जाता है और नियम 93 के उप नियम (1) के खंड (ए) से (सी) में विस्तृत दस्तावेजों का ही विशिष्ट उल्लेख किया जाता है।

यह निर्देश दिया गया था कि "यदि लौटा हुआ उम्मीदवार आवेदक के पक्ष में डाले गए वोटों के एक साथ उद्घाटन और निरीक्षण के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित में आवेदन देता है, तो इसे भी अनुमति दी जाएगी।

4. आम तौर पर प्रतिवादी द्वारा निरीक्षण के लिए अपने आवेदन में लगाए गए आरोपों की गंभीरता का संदर्भ दिया गया था, जिसमें किसी विशेष आरोप का विशिष्ट उल्लेख नहीं था;	की अनुमति देने की आवश्यकता थी। (क) मतपत्रों की स्वीकृति के संबंध में विशिष्ट आरोप जो विशिष्ट अंक धारण नहीं करते हैं और उन पर आयोग द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाते हैं। रिटर्निंग अधिकारी; और (बी) केवल इकबाल सिंह के पक्ष में डाले गए 6,000 मतपत्रों को गलत तरीके से खारिज करने का उल्लेख आदेश में किया गया था।
5. निरीक्षण के उस कथित उद्देश्य का कोई संदर्भ नहीं दिया गया जिसके लिए आवेदक ने आयोग से संपर्क किया था ; -सीएल।	जिस उद्देश्य के लिए निरीक्षण का दावा किया गया था (ताकि वह चुनाव याचिका द्वारा उपयुक्त न्यायालय में अपना कानूनी उपाय प्राप्त कर सकें) का संदर्भ दिया गया है।
6. आम तौर पर पूरे निरीक्षण की अनुमति देते समय मतपत्र की गोपनीयता की रक्षा के लिए कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिया गया था;	मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखने की वैधानिक शर्त जोड़ी गई थी।
7. निरीक्षण की अनुमति देने के लिए यह दिया गया था कि प्रतिवादी द्वारा लगाए गए आरोप साबित होने पर निस्संदेह गंभीर थे। आयोग ने यह नहीं कहा कि यह किसी भी मामले में संतुष्ट था या न्याय को निरीक्षण	इस बात से संतुष्ट हूं कि 'न्याय के अंत को आगे बढ़ाने के लिए' निरीक्षण आवश्यक था और प्रतिवादी द्वारा लगाए गए आरोपों के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था, यदि साबित हो जाता है, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे गंभीर हैं।

उपर्युक्त विश्लेषण से पता चलता है -

~

1. दो स्वतंत्र अलग-अलग दिमागों ने समस्या पर काम किया;
2. आदेश सामग्री विवरण में समान नहीं हैं;
3. औपचारिक आदेश न केवल मूल जे आदेश से भिन्न है, बल्कि कुछ विवरणों से भी अधिक है; और
4. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने स्थिति की वास्तविकताओं, लगाए गए विशिष्ट और भिन्न-भिन्न आरोपों, निर्णय लिए जाने वाले प्रश्न के लिए आरोपों की प्रासंगिकता के संबंध में और केवल एक विषय के रूप में अपना ध्यान रखे बिना यांत्रिक तरीके से आदेश पारित किया।

25. इनमें से प्रत्येक बिंदु का आक्षेपित आदेश की वैधता पर असर पड़ता है और जब भी

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(नरूला, जे।

और जहां भी मुझे ऐसा करना आवश्यक लगेगा, मैं मामले के इन पहलुओं का उल्लेख करूंगा।

26. यह मुझे मुख्य चुनाव आयुक्त के आदेश की वैधता के प्रश्न पर ले जाता है। इस आदेश को पहले ही वापसले लिया गया है। आदेश के समर्थन में एकमात्र कल्पनीय कारण यह दिया गया है कि "एस इकबाल सिंह द्वारा आवेदनों में लगाए गए आरोप, यदि सही हैं, तो निस्संदेह गंभीर हैं।हमें यह तय करने के लिए बुलाया गया है कि क्या आक्षेपित आदेश में उपरोक्त उद्धृत वाक्य नियम 93 के परंतुक (ए) की आवश्यकताओं को पूरा करता है या नहीं। दूसरे शब्दों में, प्रश्न यह है कि क्या सत्य या अन्यथा के बारे में आरोपों की गंभीरता, जिसमें *प्रथम दृष्टया* संतुष्टि का कोई प्रयास नहीं है, को नियम 93 के तहत उपयोग किए गए और अप्रयुक्त मतपत्रों और मतदाता सूची की चिह्नित प्रति के निरीक्षण की अनुमति देने के लिए कानून की नजर में एक कारण माना जा सकता है। इस मुद्दे पर पार्टियों द्वारा निम्नलिखित छह शीर्षों के तहत बहस की गई है -

1. मार्च, 1962 में आयोग को उक्त दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति देने का उद्देश्य क्या था;
2. सितंबर, 1962 में नियम 93 में किए गए संशोधन का उद्देश्य और उद्देश्य क्या था, जिसमें आयोग को निरीक्षण की अनुमति देने के लिए अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए एक शर्त के रूप में कारणों को दर्ज करने का वैधानिक कर्तव्य सौंपा गया था;
3. क्या नियम 93(1) के परंतुक (क) की आवश्यकता केवल निर्देशिका या अनिवार्य है;
4. क्या नियम 93 (1) के तहत किसी आवेदन पर निर्णय लेते समय आयोग से अर्ध-न्यायिक या विशुद्ध रूप से प्रशासनिक तरीके से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है;
5. क्या नियम 93(1) के तहत निरीक्षण की अनुमति देने के लिए आयोग के लिए औचित्य या नीति के विचार अच्छे आधार हैं? यदि नहीं, तो किस प्रकार के निष्कर्ष निरीक्षण के आदेश को सही ठहराएंगे और किस प्रक्रिया से आयोग से उन निष्कर्षों पर पहुंचने की उम्मीद है। दूसरे शब्दों में, किस प्रकार के कारणों को नियम के उद्देश्य के लिए जर्मन माना जा सकता है;
6. क्या मुख्य चुनाव आयुक्त के आक्षेपित आदेश में दिया गया एकमात्र कारण _("एस इकबाल सिंह द्वारा आवेदन में लगाए गए आरोप, यदि सही हैं, तो निस्संदेह गंभीर हैं") नियम 93 (1) के परंतुक (ए) की आवश्यकता को पूरा करता है।

अब मैं उपर्युक्त प्रत्येक मुद्दे को एक-एक करके उठाऊंगा।

27. जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, नियम 93 दो प्रकार के दस्तावेजों से संबंधित है, अर्थात् (i) उप-नियम (2) में उल्लिखित जिनका निरीक्षण निश्चित रूप से या अधिकार के मामले के रूप में किया जा सकता है, और (ii) वे दस्तावेज, जिनका निरीक्षण नामित अधिकारियों के आदेशों को छोड़कर उप-नियम (1) द्वारा निषिद्ध है। न तो हम पहली श्रेणी से संबंधित हैं और न ही उनके संबंध में कोई प्रश्न उठ सकता है। दूसरी श्रेणी में

आने वाले दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति देने का अधिकार मूल रूप से केवल न्यायालयों और न्यायाधिकरणों में निहित था। यह शक्ति पहली बार मार्च, 1962 में चुनाव पर प्रदान की गई थी। उस समय चुनाव आयोग के पास चुनाव याचिकाएं दायर करनी पड़ती थीं। आयोग को याचिका की जांच करनी थी और कुछ घटनाओं में इसे खारिज करना था। यदि कोई याचिका खारिज नहीं की जाती है, तो आयोग द्वारा उस पर मुकदमा चलाने के लिए एक न्यायाधिकरण का गठन किया जाना था। याचिका गठित होने के बाद इसे न्यायाधिकरण के पास भेजा गया था। ट्रिब्यूनल के गठन में कभी-कभी महीनों लग जाते थे। वैधानिक अवधि जिसके बाद निर्वाचन अधिकारी द्वारा निषिद्ध दस्तावेजों को सामान्य रूप से नष्ट किया जाना था, एक वर्ष था (नियम 94 (बी))। याचिका पर विचार होने के बाद चुनाव न्यायाधिकरण के पास निरीक्षण की अनुमति देने का अधिकार था और इस उद्देश्य के लिए उसके पास आवेदन किया गया था। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब तक ट्रिब्यूनल को दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, तब तक उन्हें नष्ट कर दिया जाएगा। यह सुझाव दिया गया है कि यह इस प्रकार की स्थिति को पूरा करने के लिए था कि आयोग को याचिका दायर करने से पहले भी निरीक्षण की अनुमति देने का अधिकार दिया गया था। सुझाव प्रशंसनीय है और बल के बिना नहीं है।

28. अंग्रेजी चुनाव कानून में (मतपत्र अधिनियम, 1872 की पहली अनुसूची में निहित नियमों का नियम 40, और नियम 57

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची में निहित संसदीय निर्वाचन नियम) हाउस ऑफ कॉमन्स और उस देश के उच्च न्यायालयों को सशक्त बनाने के उद्देश्य प्रासंगिक नियम में ही दिए गए हैं। इंग्लैंड में प्रयुक्त मतपत्रों के निरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है यदि निरीक्षण की आवश्यकता होती है (i) मतपत्रों के संबंध में किसी अपराध के लिए अभियोजन शुरू करने या बनाए रखने के उद्देश्य से; या (ii) चुनाव या वापसी पर सवाल उठाने वाली याचिका के उद्देश्य से, और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। हमारे नियम 93 में उन प्रयोजनों के बारे में कोई संकेत नहीं दिया गया है जिनके लिए निरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है। जहां तक न्यायालयों या अधिकरणों का संबंध है, उद्देश्य स्पष्ट है। एक आपराधिक न्यायालय द्वारा चुनाव अपराध के लिए अभियोजन शुरू करने या बनाए रखने के लिए निरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है। चुनाव याचिका में लगाए गए किसी भी निश्चित आरोप के संबंध में सबूत हासिल करने या जांचने के उद्देश्य से चुनाव याचिका की सुनवाई करने वाले न्यायालय द्वारा इसकी अनुमति दी जा सकती है। एक ओर इंग्लैंड में और दूसरी ओर भारत में निरीक्षण की अनुमति देने की शक्ति के बीच अंतर के बिंदु निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं: -

(अ) इंग्लैंड में अदालत याचिका दायर करने से पहले याचिका के प्रयोजनों के लिए निरीक्षण की अनुमति दे सकती है। भारत में ऐसा नहीं है।

(आ) इंग्लैंड में शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब अदालत शपथ पर साक्ष्य से संतुष्ट हो। भारत में ऐसी कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है; और

(इ) इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स को निरीक्षण की अनुमति देने का कोई कारण नहीं बताना है। भारत में चुनाव आयोग कारणों के साथ अपने आदेश का समर्थन करने के लिए बाध्य है।

जबकि श्री सिब्बल ने तर्क दिया कि लंबे समय तक अंग्रेजी शासन में इस तरह के विनिर्देश के सामने भारतीय शासन में निरीक्षण के उद्देश्यों के किसी भी उल्लेख का अभाव दर्शाता है कि चुनाव आयोग द्वारा निरीक्षण को उन उद्देश्यों के लिए अनुमति देने का इरादा नहीं था, जिनके लिए इंग्लैंड में इसकी अनुमति दी गई थी, यह प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि उद्देश्यों के गैर-विनिर्देश का उद्देश्य क्या है? भारतीय नियम निरीक्षण के दायरे को निर्दिष्ट उद्देश्यों तक सीमित करने के लिए नहीं है, बल्कि इसे यथासंभव व्यापक रखने के लिए है। प्रतिवादी के अनुसार, गैर-विनिर्देश नियम 93 द्वारा प्रदत्त शक्ति के दायरे को प्रतिबंधित नहीं करता है, बल्कि बढ़ाता है। श्री अशोक सेन के इस निवेदन के पीछे पर्याप्त तर्क प्रतीत होता है। यह याचिकाकर्ता की ओर से स्वयं दिए गए पहले सुझाव के अनुरूप भी है। यदि 1962 में आयोग को अनुमति देने का अधिकार दिया गया था

मतपत्रों के उपलब्ध होने से पहले संभावित चुनाव याचिकाकर्ता को सबूतों की जांच करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से, ऐसा कोई कारण नहीं है कि संबंधित प्रावधानों में संशोधन के बाद यह उद्देश्य समाप्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप चुनाव याचिका आयोग के समक्ष नहीं बल्कि उच्च न्यायालय में दायर करने की आवश्यकता थी। श्री सिब्बल ने तर्क दिया कि यदि उद्देश्य चुनाव याचिका के लिए सबूत एकत्र करने की अनुमति देना था, तो नियम में कहा गया होगा कि इस तरह के निरीक्षण की अनुमति केवल 45 दिनों के लिए दी जा सकती है, यानी, उस अवधि

तक सीमित है जिसके भीतर चुनाव याचिका दायर की जा सकती है। हालांकि तर्क पहली नजर में आकर्षक है, लेकिन इसमें शायद ही कोई सार है। श्री सिब्बल का यह तर्क अकाट्य होता यदि निरीक्षण की अनुमति देने का एकमात्र उद्देश्य चुनाव याचिका के लिए सबूत इकट्ठा करना होता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव याचिका दायर करने के बाद मतपत्रों के निरीक्षण की अनुमति देने का सवाल आम तौर पर चुनाव याचिका के प्रयोजनों के लिए नहीं उठता है क्योंकि अदालत मामले को देख लेगी, और यह अकेले अदालत है जिसके लिए निरीक्षण के लिए आवेदन किया जाएगा। चुनाव आयोग हालांकि चुनाव याचिका के फैसले के बाद भी निरीक्षण की अनुमति दे सकता है। यह चुनाव याचिका के लंबित रहने के दौरान भी चुनाव याचिका से जुड़े उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए निरीक्षण की अनुमति दे सकता है यदि निरीक्षण चुनाव याचिका न्यायालय के समक्ष जारी मामलों के लिए प्रासंगिक नहीं है।

29. चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी के वकील श्री जी. एल. सांघी का तर्क इस आशय का था कि चुनाव आयोग को निरीक्षण की अनुमति देने का अधिकार दिया गया था ताकि चुनाव याचिकाकर्ता याचिका दायर करने से पहले चुनाव के लिए प्रासंगिक चुनौती का निश्चित विवरण प्राप्त कर सके ताकि अदालत का समय और वादियों के खर्च को बचाया जा सके। बल के बिना भी नहीं है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ, जिन्होंने *रघुबीर सिंह यादव बनाम इलाहाबाद* उच्च न्यायालय के फैसले का फैसला सुनाया । *गजेंद्र सिंह और अन्य*[7], मैं इस बात से सहमत हूं कि "नियम का उद्देश्य मतगणना की निष्पक्षता के बारे में खुद को संतुष्ट करने की दृष्टि से एक पार्टी द्वारा निरीक्षण को सक्षम करना है। मेरी राय में, चुनाव आयोग को मतगणना की निष्पक्षता के बारे में चुनाव में एक पक्ष को संतुष्ट करने के लिए निरीक्षण की अनुमति देने का अधिकार नहीं दिया गया है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह सबूत ो ं का पता लगाने और उनका पता लगाने के उद्देश्य से चुनाव में किसी पक्ष को निरीक्षण की अनुमति दे ताकि वह हलफनामा दायर कर सके।

(सात) 1969 के ई.पी. संख्या 22 पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया 25 अगस्त 1969. .

[7] E.P. NO. 22 OF 1969 DECIDED BY ALLAHABAD HIGH COURT ON 25TH AUGUST 1959.

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(नरूला, जे।

निरीक्षण के दौरान उपयुक्त सामग्री मिलने पर निरीक्षण के लिए प्रासंगिक आधार पर चुनाव याचिका। इसी समय, एक तरफ मछली पकड़ने या शिकार के सबूत और दूसरी तरफ सबूत इकट्ठा करने या जांच करने के बीच का अंतर महत्वपूर्ण है। मामलों के दो सेटों के बीच अंतर प्रदर्शित करने के लिए, मैं चरम उदाहरणों का हवाला दे सकता हूं। यदि कोई आवेदक चुनाव आयोग को बताता है कि वह चुनाव याचिका दायर करना चाहता है और उसे यह पता लगाने में सक्षम बनाने के लिए कि क्या वह मतपत्रों की अवैध अस्वीकृति या स्वीकृति से संबंधित कुछ आधार ले सकता है, तो उसे वापस आए उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए सभी मतपत्रों के निरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है। वह सबूत निकालने की कोशिश कर रहे होंगे। यदि दूसरी ओर पराजित उम्मीदवार आयोग को दिए अपने आवेदन में यह लिखना चाहता था कि निर्दिष्ट स्टेशनों पर उसके मतगणना एजेंटों ने उसे सूचित किया था कि लौटे हुए उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए विशेष संख्या वाले मतपत्रों में वास्तव में पराजित उम्मीदवार के नाम के सामने कॉलम में मुहर का निशान था, और आवेदक निरीक्षण द्वारा उस तथ्य की जांच करना चाहता है क्योंकि ऐसे मतपत्रों की संख्या आवेदक के लिए गिने गए वोटों से अधिक लौटाए गए उम्मीदवार द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या से अधिक थी, यह सबूत निकालने का मामला नहीं होगा, बल्कि जांच या सबूत इकट्ठा करने का मामला होगा। जबकि पहले मामले में निरीक्षण के लिए आवेदन की अनुमति नहीं दी जा सकती है, यदि आयोग आवेदन में लगाए गए आरोपों से प्रत्यक्षतःसंतुष्ट है तो इसे संभवतः दूसरे मामले में अनुमति दी जा सकती है। इसलिए, मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि निरीक्षण की अनुमति देने के लिए आयोग को सशक्त बनाने का उद्देश्य (i) चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा निरीक्षण के लिए आवेदन पर निर्णय देने से पहले उपयोग किए गए मतपत्रों को नष्ट करने की संभावना की विशिष्ट आकस्मिकता को पूरा करना था; (ii) एक गंभीर चुनाव-याचिकाकर्ता, सामान्यतः पराजित उम्मीदवार को उसके पास मौजूद साक्ष्य या सूचना की शुद्धता की जांच करने में सक्षम बनाना या उपयोग किए गए मतपत्रों की अधिक सावधानी पूर्वक जांच करना ताकि उसके द्वारा पहले से ही रखी गई जानकारी सुनिश्चित हो सके और यदि आवश्यक हो तो उन मतपत्रों की सटीक गणना प्राप्त की जा सके जिन्हें अवैध रूप से स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है; (iii) चुनाव अपराधों के विचारण के प्रयोजनके लिए या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के प्रयोजन राथ निर्वाचन याचिका के निपटान के पश्चात् भी तब तक उपलब्ध प्रयुक्त मतपत्रों आदि के निरीक्षण की अनुमति देना; और (iv) आयोग को उपयुक्त मामलों में निरीक्षण की अनुमति देने के लिए एक व्यापक शक्ति देना, जिसे बाद में इस तरह से प्रयोग किए जाने के एकान्त रक्षोपाय के अधीन कर दिया गया था जो आयोग द्वारा दर्ज किए गए कारणों से उचित प्रतीत होता है।

30. उस संशोधन की आपत्ति, जिसके तहत नियम 93 में परंतुक (क) जोड़ा गया था, दूर की बात नहीं है। यद्यपि हमारे पास अपेक्षित सामग्री नहीं है जो यह दिखा सके कि आयोग को अधिकार दिए जाने के कुछ महीनों के भीतर संशोधन करने की आवश्यकता क्यों उत्पन्न हुई, यह संदेह से परे प्रतीत होता है कि अनुमति दिए जाने के मामले में कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता का उद्देश्य (और निरीक्षण से इनकार किए जाने के मामले में नहीं) यह सुनिश्चित करना था कि शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता है। निश्चित रूप से, और आयोग प्रत्येक आवेदन से निपटते समय यह महसूस करना जारी रख सकता है कि जिस मामले में निरीक्षण की अनुमति दी जानी थी, वह असाधारण प्रकृति का होना चाहिए। भगत *राजा* बनाम *भारत संघ और अन्य* [8], इस बात पर जोर दिया गया कि यदि खनिज रियायत नियम, 1960 के तहत एक पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के आदेश के समर्थन में कोई कारण नहीं दिया जाता है तो उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों को भी बहुत नुकसान होता है।

31. यह केवल तभी होता है जब कारण दिए जाते हैं कि उपयुक्त न्यायालय इस बात की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकता है कि दिए गए कारण निर्णय को बरकरार रखने के उद्देश्य के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। यह देखा गया कि यदि सरकार द्वारा दिए गए कारण रद्द या अस्पष्ट हैं, तो न्यायालय उचित निर्णय लेने में अक्षम है। आगे यह कहा गया कि यदि राज्य सरकार कई कारण बताती है, जिनमें से कुछ अच्छे हैं और कुछ नहीं हैं, और केंद्र सरकार केवल उन कारणों को निर्दिष्ट किए बिना राज्य सरकार के आदेश का समर्थन करती है जो उसके अनुसार राज्य सरकार के आदेश को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हैं, तो अपील में सुप्रीम कोर्ट को यह पता लगाने में मुश्किल हो सकती है कि वे कौन से आधार हैं जो केंद्र सरकार के पास हैं। राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखना। कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता यह है कि अदालतें आदेश या निर्णय से *प्रथम दृष्टया* यह पता लगा सकें कि क्या निर्णय से असंगत या जर्मन विचारों को निर्णय लेने वाले प्राधिकारी के साथ तौला गया है। एक आदेश में निहित कारण यह पता लगाने में भी मदद करते हैं कि निर्णय देने की शक्ति का उपयोग मन के पूर्व अनुप्रयोग के साथ या उसके बिना किया गया है या नहीं।

32. मैसर्स *त्रावणकोर रेयन्स लिमिटेड* बनाम *भारत संघ और अन्य*[9], सर्वोच्च न्यायालय के उनके न्यायमूर्ति द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय को अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, न केवल निर्णय, बल्कि इस निष्कर्ष को सही ठहराने वाली सामग्रियों का एक स्पष्ट प्रकटीकरण आवश्यक है कि उस संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विवाद पर न्यायिक विचार किया गया है। किसी भी प्रकार के दावे पर किसी भी प्राधिकारी द्वारा निर्णय के

[8] A.I.R 1967 S.C 1606
[9] C.A. No. 2252 of 1966 decided by Supreme Court on 28th October, 1969.

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(नरूला, जे।

समर्थन में कारणों को दर्ज करना यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय कानून के अनुसार लिया गया है और यह केवल नीति या औचित्य या किसी बाहरी आधार के आधार पर नहीं किया गया है। यह प्रशासनिक ज्यादतियों के खिलाफ एक पर्याप्त सुरक्षा उपाय है। कारण प्रदान करने का एक अन्य उद्देश्य चुनाव आयोग में चुनाव में उम्मीदवारों के विश्वास को प्रेरित करना है, जो इस तरह की कठोर शक्ति के साथ निहित है, जिसका दायरा मेरे द्वारा एक साधारण न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से अधिक व्यापक माना गया है। आयोग का आदेश किसी अपील के अधीन नहीं है। चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान इसे सवालों के घेरे में नहीं लाया जा सकता। वापस आए उम्मीदवार जो इससे गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं, उन्हें कानून द्वारा यह पता लगाने के लिए कोई अवसर नहीं दिया जाता है कि क्या यह मनमाने ढंग से या यांत्रिक तरीके से पारित किया गया था, या दिमाग के पूर्ण आवेदन के बाद। कारणों को दर्ज करना एकमात्र सुरक्षा है जो आदेश से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जिन कारणों ने आयोग को प्रेरित किया था, वे इसमें निहित शक्ति की सामग्री और दायरे के अनुरूप थे। *आर.एस. सेठ गोपीकिशन अग्रवाल बनाम आर.एन.सेन, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क रायपुर के सहायक कलेक्टर*[10] *मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला* श्री सांघी ने कारण बताने की आवश्यकता के प्रभाव के संबंध में भरोसा किया, इसका हमारे सामने मौजूद मुद्दे पर कोई सीधा प्रभाव नहीं है, क्योंकि सीमा शुल्क अधिनियम में प्रासंगिक प्रावधान जो *गोपीकिसान अग्रवाल*[11] *के मामले* में विचाराधीन था। को कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि केवल विश्वास के आधार की आवश्यकता थी। दो आवश्यकताएं मुझे समान नहीं लगती हैं। विश्वास के उचित आधार सूचना की प्रकृति और स्रोत के बारे में तथ्य के बयानों से संबंधित हो सकते हैं। किसी निर्णय के समर्थन में कारणों का उद्देश्य विचार किए गए मामलों, प्राप्त निष्कर्षों और मानसिक या तार्किक प्रक्रिया का खुलासा करना है जिसके द्वारा नीति या औचित्य के विचारों से प्रभावित हुए बिना निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। चूंकि निर्वाचन आयोग को एक व्यापक शक्ति प्रदान की गई थी और यह महसूस किया गया था कि न्यायालय या अधिकरण में ऐसी शक्ति निहित करके स्वचालित रूप से मौजूद सुरक्षा उपाय आयोग पर लागू हो सकते हैं, इसलिए अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित करना वांछनीय समझा गया।आयोग को निरीक्षण की अनुमति देने वाले आदेश केवल तभी पारित करने का अधिकार है जब ऐसे आदेशों *को प्रथम दृष्टया* कारणों से समर्थित किया जा सकता है। मेरी राय में, ये नियम 93 के उप-नियम (1) के दायरे में आयोग को प्रदत्त शक्ति बनाने के उद्देश्य थे, जो संशोधन द्वारा जोड़े गए परंतुक (ए) में निहित शर्त मिसाल को पूरा करने के अधीन थे।

33. मैं पहले ही संक्षेप में परंतुक (ए) की आवश्यकताओं के बारे में निर्देशिका या अनिवार्य होने के बारे में तर्क का उल्लेख कर चुका हूं। यद्यपि केवल "विल" शब्द का उपयोग निर्णायक नहीं है, जिस संदर्भ में प्रावधान किया गया है, जिस रूप में इसे रखा गया है, क़ानून की योजना या नियम जिसमें आवश्यकता निहित है, और प्रावधान का विधायी

[10] A.I.R 1967 S.C. 1298
[11] 1966 Curr. L.J. 1694

इतिहास हमेशा इस तथ्य को इंगित कर सकता है कि किसी दिए गए मामले में कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता केवल निर्देशिका या अनिवार्य है या नहीं। मैं उन दो तथ्यों को नजरअंदाज नहीं कर सकता जो इस संबंध में महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले, कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता को उप-नियम (1) (जो केवल उप-नियम आयोग को निरीक्षण की अनुमति देने का अधिकार देता है) के परंतुक के रूप में पेश किया गया है। दूसरे शब्दों में, जो आदेश कारणों से समर्थित नहीं हैं, उन्हें दायरे से बाहर कर दिया जाता है, और निरीक्षण की अनुमति देने वाले केवल ऐसे आदेशों को नियम 93 (1) के भीतर छोड़ दिया गया है जैसा कि कारणों द्वारा विधिवत समर्थित हैं। निरीक्षण की अनुमति देने की शक्ति को अध्यधीन बनाया गया है और कारणों की रिकॉर्डिंग के कारणों को दर्ज किए बिना निरीक्षण की अनुमति देने की शक्ति को परंतुक द्वारा छीन लिया गया है। दूसरे, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि नियम 93 (1) उसमें उल्लिखित दस्तावेजों को खोलने और किसी भी व्यक्ति द्वारा उनके निरीक्षण या किसी भी प्राधिकरण के समक्ष पेश करने पर प्रतिबंध लगाता है। यह सामान्य नियम है। इसके बाद केवल कुछ निर्दिष्ट अधिकारियों के आदेशों के तहत निरीक्षण आदि की अनुमति देने के लिए उक्त निषेध पर एक अपवाद बनाया जाता है। यह प्रतिबंध मतपत्रों की गोपनीयता के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए है, जिसके लिए अन्यथा कोई अपवाद नहीं बनाया गया है। जब किसी मामले को अपवाद के भीतर लाने के लिए उपयोग करने योग्य आयोग की शक्ति को रिकॉर्डिंग कारणों की आगे की सुरक्षा के अधीन बनाया जाता है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि आवश्यकता केवल निर्देशिका है। इस मामले के सभी पक्ष और विपक्ष पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, मेरा दृढ़ मत है कि प्रावधान की बनावट (नियम 93 के दायरे और परंतुक को एक साथ पढ़ा जाता है) और अधिनियम की योजना, और नियमों और मतपत्रों की गोपनीयता के समग्र विचार पर, कारणों की रिकॉर्डिंग उसके तहत निरीक्षण की अनुमति देने के लिए चुनाव आयोग की शक्ति के उद्भव के लिए एक शर्त मिसाल है। उप-नियम।

34. उच्चतम न्यायालय की नवीनतम घोषणाओं की प्रवृत्ति को देखते हुए, यह निर्धारित करना वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि नियम 93 (1) के तहत निरीक्षण की अनुमति देने के लिए आयोग में निहित शक्ति अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक है या नहीं। फिर भी इस मुद्दे पर लंबे तर्कों को संबोधित किया गया है, मैं इसे नोटिस करना पसंद करूंगा और इस बिंदु पर भी अपना निर्णय दर्ज करूंगा। जबकि श्री सिब्बल इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय को लिखते समय नगर समिति और अन्य बनाम पंजाब राज्य[12] मे की गई कतिपय टिप्पणियों के आधार पर बहस करना चाहते थे। पंजाब राज्य के बारे में कि कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता इस आदेश को अर्ध-न्यायिक बनाती है, श्री अशोक सेन द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा मुंगेर के कलेक्टर और अन्य[13] के मामले में की गई आज्ञाओं के अधिकार पर प्रस्तुत किया गया था। केशव प्रसाद गोयनका और अन्य लोगों का कहना है कि केवल कारणों को दर्ज करने

[12] 1966 curr. L.J 290
[13] A.I.R1962 S.C 1694

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(नरूला, जे।

की आवश्यकता अपने आप में एक प्रशासनिक आदेश को अर्ध-न्यायिक नहीं बनाती है। मैं इस बिंदु पर निर्णय लेने के लिए नगरपालिका समिति और अन्य के मामले में मेरे द्वारा कही गई किसी भी बात को प्रासंगिक नहीं मानता हूं।.हालांकि, *मुंगेर के कलेक्टर और अन्य (सुप्रा)* का मामला हाथ में लिए गए मामले से बहुत अलग हो सकता है (और श्री सिब्बल ने अंतर को इंगित करने में काफी समय लिया), इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि केवल कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता हमेशा निर्णायक रूप से साबित नहीं करेगी कि कारणों से समर्थित आदेश एक अर्ध-न्यायिक है। वास्तव में कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता वाला प्रावधान यह सुझाव देने के लिए एक लंबा रास्ता तय करता है कि आदेश अर्ध-न्यायिक हो सकता है। हालांकि, यह मामले का निर्णायक परीक्षण नहीं है। वर्तमान मामले में इस मुद्दे की प्रासंगिकता इस विचार तक ही सीमित है कि जबकि एक अर्ध-न्यायिक आदेश प्रमाण पत्र की रिट के लिए उत्तरदायी *है,* एक प्रशासनिक आदेश नहीं है। लेकिन संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में यह शायद ही सामग्री है। उस प्रावधान के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र इंग्लैंड और अमेरिका में जारी प्रसिद्ध उच्च विशेषाधिकार रिट के मुद्दे तक ही सीमित नहीं है। भारत में उच्च न्यायालय सर्टिओरारी की रिट जारी करने तक सीमित नहीं हैं, लेकिन "सर्टिओरारी की प्रकृति में" रिट जारी कर सकते हैं। फिर, उच्च न्यायालयों को विशेष रूप से ऐसी किसी भी रिट, आदेश या निर्देश जारी करने का अधिकार है, जो कि मंडामस, निषेध, क्वो-वारंटो और सर्टिओरारी की प्रसिद्ध रिट के अलावा है, जैसा कि किसी मामले की परिस्थितियां उचित ठहरा सकती हैं। इसलिए, यह शायद ही कोई तथ्य है कि नियम 93 के तहत चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र का उपयोग अर्ध-न्यायिक तरीके से किया जाना है या केवल एक प्रशासनिक निर्णय के माध्यम से।

35. *आर. बनाम मैनचेस्टर कानूनी सहायता समिति,*[14], यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य व्यापक रूप से अलग-अलग परिस्थितियों में उत्पन्न हो सकता है, जिसे व्यापक रूप से परिभाषित करने का प्रयास करना असंभव और वास्तव में अनुचित होगा। यह भी कहा गया कि "जहां निर्णय एक अदालत का है, जब तक, उदाहरण के लिए, मामले में, "उत्पाद शुल्क लाइसेंस देने वाले न्यायाधीशों का मामला, यह पूरी तरह से मंत्रिस्तरीय क्षमता में काम कर रहा है, यह स्पष्ट रूप से न्यायिक रूप से कार्य करने के कर्तव्य के तहत है। दूसरी ओर, जब निर्णय एक प्रशासनिक निकाय का होता है और नीति के प्रश्नों द्वारा पूरी तरह से या आंशिक रूप से कार्य किया जाता है, तो उस निर्णय पर पहुंचने के दौरान न्यायिक रूप से कार्य करने का कर्तव्य उत्पन्न हो सकता है।

36. जैसा कि ए. के. क्रैपक और अन्य बनाम *भारत संघ और अन्य*[15] (मामले *में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति द्वारा* यह अभिनिर्धारित किया गया है। अर्ध-न्यायिक शक्ति की अवधारणा, हाल के वर्षों में, एक आमूल-चूल परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। जिसे कुछ साल पहले प्रशासनिक शक्ति माना जाता था, उसे अब अर्ध-न्यायिक माना जा रहा है। के. एस. हेगड़े, जे., जिन्होंने उस मामले में उच्चतम न्यायालय का निर्णय तैयार किया था, ने कहा कि बढ़ते प्रशासनिक निकायों की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त शक्ति एक नई निरंकुशता न बन जाए, न्यायालय धीरे-धीरे उन सिद्धांतों को विकसित कर रहे हैं जिनका पालन प्रशासनिक कार्यों का प्रयोग करते समय किया जाना चाहिए। विद्वान न्यायाधीश ने आगे कहा कि इस तरह के मामलों में मिसालों के कठोर पालन से सार्वजनिक भलाई आगे नहीं बढ़ सकती है क्योंकि नई समस्याएं नए समाधानों की मांग करती हैं। उनके न्यायमूर्ति द्वारा यह आधिकारिक रूप से निर्धारित किया गया था कि अर्ध-न्यायिक शक्ति की सीमाओं को तय करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ए में फैसला सुनाया। *क्राइपक का मामला* कि चूंकि अर्ध न्यायिक और प्रशासनिक निकायों दोनों का उद्देश्य एक न्यायसंगत निर्णय पर पहुंचना है, इसलिए प्राकृतिक न्याय के नियम दोनों पर लागू होने चाहिए। किसी दिए गए मामले पर प्राकृतिक न्याय का कौन सा विशेष नियम लागू होना चाहिए, इस सवाल को विशेष मामले से संबंधित विभिन्न कारकों पर तय करने के लिए छोड़ दिया गया था। यह देखा गया कि भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में, जो कानून के शासन द्वारा विनियमित और नियंत्रित है, यह अपरिहार्य है कि प्रशासनिक निकायों का अधिकार क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कानून के शासन की अवधारणा अपनी जीवन शक्ति खो देगी यदि राज्य के साधनों को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से अपने कार्यों का निर्वहन करने का कर्तव्य नहीं सौंपा जाता है। यह निर्धारित किया गया था कि संक्षेप में न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता कुछ और नहीं

[14] (1952) 2 Q.B.D 413.
[15] A.I.R 1970 S.C 150.

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(नरूला, जे।

बल्कि न्यायसंगत रूप से कार्य करने की आवश्यकता है।

निष्पक्ष रूप से और मनमाने ढंग से या मनमाने ढंग से नहीं। कोई भी यह तर्क नहीं दे सकता है कि चुनाव आयोग से 1961 के नियमों के नियम 93 के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेते समय अन्यायपूर्ण, या अनुचित रूप से, या मनमाने ढंग से या मनमाने ढंग से कार्य करने की उम्मीद की जाती है। एक बार जब यह माना जाता है कि उसे न्यायसंगत और निष्पक्ष रूप से कार्य करना है और मनमाने ढंग से या मनमाने ढंग से कार्य नहीं करना है, तो इसका मतलब है, एके क्रैपक के मामले *में* सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार , आयोग को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार नियम 93 के तहत एक आवेदन पर निर्णय देने के अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा।

37. चंद्र भवन बोर्डिंग एंड लॉजिंग *में, बैंगलोर* बनाम बैंगलोर *मैसूर राज्य और एक अन्य* [16], यह दोहराया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रशासनिक शक्तियों के प्रयोग पर भी लागू होते हैं, हालांकि वे सिद्धांत सन्निहित नियम नहीं हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी दिए गए मामले पर प्राकृतिक न्याय का कौन सा विशेष नियम, यदि कोई हो, लागू होना चाहिए, काफी हद तक उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, कानून के ढांचे पर निर्भर करता है जिसके तहत जांच की जाती है और ट्रिब्यूनल या इस उद्देश्य के लिए नियुक्त व्यक्तियों के निकाय का गठन। इस मामले का सार यह है कि यदि किसी प्रशासनिक प्राधिकरण को न्यायिक रूप से कार्य करना है, तो *उसके* द्वारा प्रस्तावित आदेश अर्ध-न्यायिक है, लेकिन यदि उसका ऐसा कोई कर्तव्य नहीं है और कानून द्वारा औचित्य या नीति के विचार पर आगे बढ़ने की अनुमति दी जाती है, तो आदेश अर्ध-न्यायिक नहीं है, बल्कि एक प्रशासनिक है।

38. पूरे मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद और ऊपर उल्लिखित कानून के सिद्धांतों को लागू करने के बाद, मेरी राय है कि चुनाव आयोग से, नियम 93 के तहत एक आवेदन पर अपना निर्णय देते समय, अर्ध-न्यायिक तरीके से कार्य करने की उम्मीद की जाती है क्योंकि यह औचित्य या नीति पर विचार करने पर निरीक्षण के लिए आवेदन की अनुमति नहीं दे सकता है। लेकिन इसके सामने रखी गई सामग्री पर निष्पक्ष रूप से निर्णय लेना चाहिए, और कारणों के साथ आदेश का समर्थन करने के लिए बाध्य है।

39. यह मुझे उप-शीर्ष संख्या 11 पर ले जाता है। (v) श्री सिब्बल के चौथे मुख्य विवाद का ब्यौरा क्या है? मैंने पहले ही कहा है कि नियम 93 के तहत निरीक्षण की अनुमति देने वाला आयोग का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा यदि यह कारणों से समर्थित नहीं है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि निरीक्षण की अनुमति देने के उद्देश्य से ऐसे कारणों को लागू किया जाना चाहिए। बाहरी कारण कानून की नजर में कोई कारण नहीं हैं। इसी तरह अप्रासंगिक और अस्पष्ट कारणों को परंतुक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं माना जा सकता है। जब भी

[16] A.I.R 1970 S.C 2042

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(नरूला, जे।

कारणों के साथ किसी भी प्राधिकरण के आदेश का समर्थन करने के लिए एक वैधानिक आवश्यकता है, यह आदेश से ही प्रकट होना चाहिए । कम से कम उस सामग्री का संक्षिप्त संदर्भ जिस पर निष्कर्ष निकाला गया है और जिसके संबंध में आदेश का समर्थन करने के लिए सामग्री, कारण दिए गए हैं, आदेश में ही उपलब्ध होना चाहिए। प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा यह तर्क दिया गया था कि यह परिभाषित करना मुश्किल है कि एक अच्छा कारण क्या है जिस पर एक आदेश का समर्थन किया जा सकता है। इस तर्क के उत्तर में श्री सिब्बल ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रिज बनाम *बाल्डविन और अन्य* [17] मामले में 'प्राकृतिक न्याय' को परिभाषित करने में कठिनाई के संबंध में लॉर्ड रीड की प्रसिद्ध टिप्पणियों का उल्लेख *किया*, 'यह देखा गया था :-

> "आधुनिक समय में कभी-कभी इस आशय के विचार व्यक्त किए गए हैं कि प्राकृतिक न्याय इतना अस्पष्ट है कि व्यावहारिक रूप से अर्थहीन है। लेकिन मैं इन्हें बारहमासी भ्रम से दूषित मानता हूं कि क्योंकि किसी चीज को काटा और सुखाया नहीं जा सकता है या अच्छी तरह से तौला या मापा नहीं जा सकता है, इसलिए यह मौजूद नहीं है।

श्री सिब्बल ने आगे तर्क दिया कि केवल निष्कर्ष देने और उस मानसिक प्रक्रिया का खुलासा नहीं करने का मतलब कारण देना नहीं है जिसके द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है। उन्होंने गुजरात राज्य बनाम गुजरात मामले में उच्चतम न्यायालय के उनके न्यायमूर्ति के निर्णय की ओर भी हमारा ध्यान आकषत *किया* । *पटेल राघव नत्था और अन्य*[18], जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि विभिन्न तर्कों को पढ़ने के बाद एक अधिकारी अपने कारणों का खुलासा किए बिना अपने निष्कर्ष बताता है, तो वह कानून की आवश्यकता को पूरा नहीं करता है। न्यायालयों द्वारा बार-बार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि "यह न्याय के हित में समीचीन है" या "यह न्याय के अंत की सेवा करेगा" जैसे वाक्यांशों का उपयोग करना कानून की नजर में कोई कारण नहीं है। यह भी स्थापित कानून है कि एक आदेश जिसे कारणों से समर्थित करने की आवश्यकता होती है, उसे रद्द कर दिया जाना चाहिए यदि यह प्रथम दृष्टया इसका खुलासा नहीं करता है / यदि आदेश वैध कारणों से समर्थित नहीं है, तो इसकी वैधता को बनाए रखने के लिए उच्च न्यायालय को अपने स्वयं के तर्क को प्रतिस्थापित करना नहीं है। इस संबंध में हमारा ध्यान प्राग दास उमर वैश्य बनाम *भारत संघ और अन्य* [19] में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर आकृष्ट किया गया था। निस्संदेह श्री सिब्बल को इस संबंध में उच्चतम न्यायालय की आधिकारिक घोषणा का समर्थन प्राप्त है।

40. श्री सिब्बल का एक और निवेदन, जिस पर इस स्तर पर ध्यान दिया जा सकता है, यह है कि यदि कोई निर्णय प्रशासनिक है और एक से अधिक कारणों से समर्थित है, तो पूरा निर्णय रद्द कर दिया जाएगा यदि उन कारणों में से एक भी असंगत पाया

[17] (1964) A.C 40 at page 64.
[18] C.A. No.723of 1966 decided on 21st April, 1969.
[19] C.A. No. 657 of 1965 decided on 17th august, 1967.

जाता है, लेकिन यदि निर्णय अर्ध-न्यायिक है, भले ही उसके समर्थन में दिए गए विभिन्न कारणों में से एक अच्छा पाया जाए, और अन्य कारणों से बुरा होगा, आदेश कायम रहेगा। इन प्रस्तावों को सहेला राम बनाम *पंजाब राज्य*[20] मामले में पूर्ण पीठ के फैसले द्वारा समर्थित करने की मांग की गई थी ।

41. चौथे विवाद के अंतिम (छठे) उप-प्रमुख में ठीक वही मुद्दा शामिल है जो याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के पांचवें मुख्य विवाद में शामिल है। इसलिए, मैं श्री सिब्बल के पांचवें मुख्य निवेदन पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ता हूं जो इस आशय का है कि इस मामले में आक्षेपित आदेश कानून की नजर में किसी भी कारण से समर्थित नहीं है। विचार के लिए उठने वाला पहला मुद्दा यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष क्या सामग्री उपलब्ध थी जब उन्होंने आक्षेपित निर्णय दिया था। आदेश में निरीक्षण के लिए आवेदन (अनुबंध आर-एक्स) को छोड़कर किसी भी चीज का उल्लेख नहीं है। आयोग द्वारा भेजे गए मामले के मूल रिकॉर्ड में भी आवेदन, उस पर पारित आदेश, कार्यालय नोटिंग, सचिव द्वारा हस्ताक्षरित औपचारिक आदेश और आदेश के कार्यान्वयन से संबंधित आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी के बीच बाद के टेलीग्राफिक और डाक पत्राचार के अलावा कुछ भी नहीं है। बहस के दौरान प्रतिवादी के वकील ने सुझाव दिया कि हमें यह मान लेना चाहिए कि उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त के पास भी विभिन्न संचारों (टेलीग्राम और पत्रों) की प्रतियां थीं, जो प्रतिवादी द्वारा फरवरी से 12 मार्च, 1971 के दौरान आयोग को भेजी गई थीं। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं। हमारे पास यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि निरीक्षण के लिए आवेदन में लगाए गए आरोपों के अलावा चुनाव आयोग द्वारा क्या, संभावित सामग्री पर विचार किया जा सकता था। आयोग द्वारा लौटाए गए रिकॉर्ड और मुख्य चुनाव आयुक्त के मूल आदेश से वास्तव में संकेत मिलता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के समक्ष 15 मार्च, 1971 को निरीक्षण के लिए आवेदन में कुछ भी शामिल नहीं था, जब उन्होंने उसी दिन आक्षेपित आदेश पारित किया था। इसलिए, यदि यह माना जा सकता है कि चुनाव आयोग ने कुछ बातों पर विचार किया है

निरीक्षण के लिए आदेश पारित करने से पहले, यह कहा जा सकता है कि आयोग ने निरीक्षण के लिए आवेदन का अध्ययन किया। इसलिए जिस आधार पर आदेश पारित किया गया है, वह केवल "एस इकबाल सिंह द्वारा आवेदन में लगाए गए आरोप" हो सकते हैं। अब यह देखा जाएगा कि निरीक्षण के लिए आवेदन (अनुबंध आर-एक्स) में, निम्नलिखित बिंदुओं को आरोपों के रूप में उठाया गया था -

1. पंजाब सरकार की मशीनरी को पंजाब के मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल के भाई गुरदास सिंह बादल (याचिकाकर्ता) को लोकसभा के लिए याचिकाकर्ता के चुनाव में हर संभव अनुचित तरीके अपनाकर और मुख्यमंत्री के निपटान में सरकारी मशीनरी का अवैध रूप से उपयोग करके मदद करने के लिए काम

[20] I.L.R(1967) 1Pb. & Hr. 260

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(नरूला, जे।

किया गया था (पैराग्राफ 4);

2. चुनाव में अपनी सफलता के लिए याचिकाकर्ता द्वारा पंजाब सरकार की मशीनरी का उपयोग कैसे किया जा रहा था, इसका विवरण 20 फरवरी, 1971 और 27 फरवरी, 1971 की शिकायतों में दिया गया था, जिसकी प्रतियां निरीक्षण के लिए आवेदन के अनुलग्नक 'ए' और 'बी' थीं (पैराग्राफ 4); ----

3. पंजाब के मुख्यमंत्री ने चुनाव में अपने भाई की सफलता के लिए अपने पास मौजूद सभी साधनों का इस्तेमाल किया। प्रतिवादी ने 28 फरवरी, 1971 को आयोग को एक शिकायत की, जिसके संबंध में शिकायत की प्रति आवेदन के अनुलग्नक 'सी' (पैराग्राफ 5) थी;

4. मुख्यमंत्री, पंजाब ने चुनाव में अपने भाई की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसके लिए मतदान 5 मार्च, 1971 को हुआ था (पैराग्राफ 6);

5. 7 मार्च, 1971 को प्रतिवादी ने उप चुनाव आयुक्त से शिकायत की कि मतगणना की निगरानी के लिए किसी वरिष्ठ अधिकारी को तैनात किया जाए ताकि संबंधित नियमों के अनुसार मतगणना हो सके। इसी तरह का अभ्यावेदन उसी दिन चुनाव आयोग को भेजा गया था। उन शिकायतों की प्रतियां निरीक्षण के लिए आवेदन के अनुलग्नक 'डी' और 'ई' के रूप में संलग्न की गई थीं (पैराग्राफ 7);

6. 8 मार्च, 1971 को चुनाव आयोग को एक विस्तृत पत्र लिखा गया था, जिसमें चुनाव में याचिकाकर्ता की मदद करने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा किए गए कथित कदाचार का विवरण दिया गया था। (यह महत्वपूर्ण है कि 8 मार्च, 1971 की कथित शिकायत की प्रति, निरीक्षण के लिए आवेदन के साथ संलग्न भी नहीं की गई है। हमने मूल रिकॉर्ड देखा है। नहीं। उस शिकायत की प्रति आयोग के रिकॉर्ड में भी है जिसे हमें भेज दिया गया है)। (पैराग्राफ 8);

7. मतगणना के दौरान बड़ी संख्या में मतपत्र ऐसे पाए गए जिन पर पीठासीन या मतदान अधिकारी के हस्ताक्षर और/या विधानसभा/मतदान केंद्र की मुहर या उसकी संख्या नहीं थी। इस तरह के मतपत्रों की संख्या लगभग 15,000 से अधिक थी। इनके अलावा, चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी के पक्ष में डाले गए 6,000 से अधिक वैध वोटों को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। प्रधानमंत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और फाजिल्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के पर्यवेक्षक को इस आरोप की टेलीग्राफिक सूचना के बावजूद इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। टेलीग्राम की प्रतियों को अनुलग्नक 'एफ' और 'जी' (पैराग्राफ 9 और 12) चिह्नित किया गया था;

8. 12 मार्च, 1971 को 1961 के नियमों के नियम 63 और 64 के तहत रिटर्निंग अधिकारी को एक लिखित याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें फिर से गिनती के लिए कहा गया था, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने "बिना कोई वैध कारण बताए" प्रतिवादी की उक्त याचिका को खारिज कर दिया (पैराग्राफ 9);

9. निर्वाचन अधिकारी ने पुन: गणना के लिए प्रतिवादी के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह पंजाब के मुख्यमंत्री के प्रभाव में था और प्रतिवादी द्वारा पुनर्गणना का अनुरोध करने के बावजूद, याचिकाकर्ता को 5,323 मतों (पैराग्राफ 10, 11 और 13) के अंतर से निर्वाचित घोषित किया गया था; और

10. चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी को उचित आश्वासन था कि इस्तेमाल किए गए और अप्रयुक्त मतपत्रों और पीठासीन और मतगणना पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट और चुनाव से संबंधित अन्य कागजात के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है।

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(नरूला, जे।

42. निरीक्षण के लिए प्रतिवादी के आवेदन में लगाए गए आरोपों के रिज्यूमे से यह देखा जाएगा कि इसमें दस आरोप थे, जिनमें से केवल अंतिम तीन निषिद्ध दस्तावेजों के निरीक्षण के अनुरोध के साथ कुछ प्रासंगिक हो सकते हैं। आदेश में यह नहीं दिखाया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त अपना फैसला दर्ज करते समय केवल प्रासंगिक आरोपों या प्रासंगिक और अप्रासंगिक आरोपों के बारे में सोच रहे थे या केवल सभी अप्रासंगिक आरोपों के बारे में सोच रहे थे। यदि लागू किया गया आदेश पूरी तरह से प्रशासनिक है, तो इसे उस छोटे से आधार पर रद्द किया जा सकता है। तथापि, यदि यह एक अर्ध-न्यायिक आदेश है, जैसा कि मैंने पाया है, तो यह आदेश तब भी कायम रहेगा यदि संबंधित सामग्री के आधार पर भी निरीक्षण की अनुमति देने के लिए कुछ कानूनी कारण दिए गए हों। निरीक्षण के लिए आवेदन के पैराग्राफ 4 से 8 में निहित आरोपों का निरीक्षण के मामले में कोई प्रासंगिकता नहीं थी। प्रतिवादी की ओर से 8 मार्च, 1971 के प्रतिवादी के आवेदन में कथित तौर पर निहित बातों के आधार पर दलीलें दी गईं, जिसका संदर्भ निरीक्षण के लिए आवेदन के पैराग्राफ 8 में दिया गया है। हालांकि, उस आवेदन की कोई भी प्रति न तो आवेदन के साथ संलग्न की गई थी, या अन्यथा संबंधित समय पर मुख्य चुनाव आयुक्त को उपलब्ध होने के लिए दिखाया गया है।

43. यहां तक कि अगर यह माना जा सकता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने केवल प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखा और अप्रासंगिक सामग्री को नहीं, तो इससे इस मामले के फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। श्री सिब्बल द्वारा यह तर्क दिया गया था कि आरोपों की केवल गंभीरता (यहां तक कि प्रासंगिक भी) निरीक्षण के आदेश को पारित करने का औचित्य नहीं है। वकील के अनुसार, निषिद्ध दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति देने का कोई औचित्य नहीं होगा जब तक कि चुनाव आयोग यह न पाए कि (i) उसके समक्ष लगाए गए आरोप निरीक्षण की अनुमति देने के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक हैं; और (ii) आयोग उसके समक्ष रखी गई सामग्री से संतुष्ट है कि वे आरोप *प्रथम दृष्टया* सही हैं और तुच्छ या निराधार नहीं हैं। आक्षेपित आदेश स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने नियम 93 की आवश्यकताओं के दूसरे आवश्यक घटक पर अपना दिमाग नहीं लगाया, यानी संबंधित आरोप में *प्रथम दृष्टया* सच्चाई की संतुष्टि के बारे में। इसके विपरीत, मुख्य चुनाव आयुक्त ने आदेश में कहा है कि उन्होंने यह कहकर मामले के उस पहलू पर अपना दिमाग नहीं लगाया था कि आरोप

इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे केवल तभी गंभीर होंगे जब वे सच पाए जाएंगे। मुझे यह सुझाव देने के लिए समझा नहीं जा सकता है कि चुनाव आयोग से यह उम्मीद की जाती है कि वह चुनाव याचिका के परीक्षण के लिए आरोपों की सच्चाई या अन्यथा के बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष दर्ज करेगा। मेरी राय में, यदि आयोग उन आरोपों पर निषिद्ध दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति देता है जो *प्रथम दृष्टया* झूठे, तुच्छ या आधारहीन हो सकते हैं, चाहे वे कितने भी गंभीर क्यों न हों, तो रिकॉर्ड करने के कारणों की सुरक्षा पूरी तरह से भ्रामक और अस्पष्ट हो जाएगी। चूंकि यह भी तर्क नहीं दिया जा सकता है कि निरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है यदि आयोग संतुष्ट है कि आरोप झूठे या तुच्छ हैं, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि *संबंधित आरोपों में प्रथम दृष्टया* सच्चाई के बारे में आयोग की संतुष्टि आयोग को निरीक्षण की अनुमति देने के लिए योग्य बनाएगी। निरीक्षण के लिए आवेदन में अत्यंत गंभीर आरोप लगाए जा सकते हैं जो अप्रासंगिक हो सकते हैं या जो संभवतः सच नहीं हो सकते हैं। दोनों में से किसी भी स्थिति में निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

44. जहां तक प्रतिवादी की शिकायत पर पर्यवेक्षक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के आरोप का संबंध है, यह महत्वपूर्ण है कि 12 मार्च, 1971 की पर्यवेक्षक की विस्तृत रिपोर्ट (रिट याचिका के अनुलग्नक 'सी-' की प्रति) पर मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा लागू आदेश पारित करने से पहले विचार नहीं किया गया था। उस रिपोर्ट में श्री आर,। चुनाव आयोग के अवर सचिव डी. शर्मा ने कहा कि -

    1. उन्होंने 10 और 11 मार्च, 1971 (मतगणना तिथियों) को निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतगणना केंद्रों का दौरा किया था और उन्होंने पाया था कि मतगणना सुचारू रूप से की जा रही थी;

    2. लगभग सभी स्थानों पर सहायक रिटर्निंग अधिकारियों और निर्वाचन सुपर वाइजर्स को मतगणना के संबंध में उनके द्वारा दिए गए सभी निर्देशोंका सख्ती से पालन किया गया।

    3. उन्होंने विशेष रूप से दो मुख्य प्रतियोगियों (याचिकाकर्ता और चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी) और हर केंद्र पर उनके मतगणना एजेंटों से अनुरोध करने का ध्यान रखा था कि क्या उन्हें किसी भी प्रकार की शिकायत थी, और उनसे कोई गंभीर शिकायत नहीं की गई थी;

    4. अबोहर में लांबी निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुछ मतपत्रों पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और इसलिए, पर्यवेक्षक ने सावधानीपूर्वक जांच की।

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(नरूला, जे।

मतपत्रों का बंडल, जो कथित तौर पर मतपत्रों से भरा हुआ था, जिस पर पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए थे और पाया गया कि बंडल में मुश्किल से एक या दो ऐसे मतपत्र थे;

5. पर्यवेक्षक ने विचाराधीन मतपत्रों के सीरियल नंबरों को देखकर पुष्टि की कि सभी मतपत्र अधिकृत श्रृंखला के थे और एक या दो पत्रों पर चूक जानबूझकर नहीं की गई थी और इसलिए आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार उन मतपत्रों को खारिज नहीं किया जा सकता था;

6. मिलाप में प्रकाशित योगी राज सूर्य देव के मतगणना एजेंटों के बारे में एक मामूली शिकायत की भी जांच की गई और इसे निराधार पाया गया; और

7. एस. इकबाल सिंह (चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी) द्वारा की गई एकमात्र शिकायत 11 मार्च 1971 को मुक्तसर में फाजिल्का के जलालाबाद निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में मौखिक थी। उपायुक्त और पर्यवेक्षक तुरंत मामले को देखने गए और पाया कि शिकायत में कोई दम नहीं था और जब वे उस स्थान पर पहुंचे, तो मतगणना लगभग खत्म हो चुकी थी।

45. गौरतलब है कि ऑब्जर्वर की रिपोर्ट 12 मार्च, 1971 को बनाई गई थी कि मतगणना लगभग समाप्त होने के बाद की गई थी, कि मतगणना 12 मार्च, 1971 को समाप्त हो गई थी, कि 13 और 14 मार्च, 1971 को पंजाब में दूसरे शनिवार और रविवार के कारण सार्वजनिक अवकाश थे कि चुनाव आयोग का कार्यालय 15 मार्च को फिर से खुल गया। 1971 और मुख्य चुनाव आयुक्त का आदेश 15 तारीख को सुबह-सुबह पारित किया गया प्रतीत होता है जैसा कि आयोग की आधिकारिक फाइल में नोटिंग से स्पष्ट है। आक्षेपित आदेश में पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के बारे में कोई उल्लेख नहीं होने के कारण, मैं इन परिस्थितियों में यह मानना काफी सुरक्षित मानता हूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त के पास प्रतिवादी के आवेदन पर अपना निर्णय देने से पहले इसे देखने का कोई अवसर नहीं था।

46. प्रतिवादी ने अपने आवेदन में शिकायत की थी कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने बिना कोई वैध कारण बताए उसकी याचिका खारिज कर दी थी। जिला निर्वाचन अधिकारी (जो निर्वाचन अधिकारी भी थे) को उत्तरदाता की शिकायत की एक प्रति

निर्वाचन क्षेत्र) याचिका के लिए अनुलग्नक 'ए' है। उस शिकायत पर उसी दिन जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पारित विस्तृत आदेश की एक प्रति याचिका के अनुलग्नक 'बी' में दी गई है। उस आदेश में रिटर्निंग अधिकारी ने लिखा है कि उन्होंने याचिकाकर्ता, चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी और विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की उपस्थिति में और निर्वाचन आयोग के अवर सचिव श्री आरडी शर्मा की उपस्थिति में प्रतिवादी के आदेश में दिए गए विभिन्न आधारों पर विचार किया। आदेश में पंजाब के संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री केएस मान की उपस्थिति भी देखी गई है। श्री शर्मा द्वारा की गई टिप्पणियों की प्रति आदेश में संदर्भित की गई थी और उसे संलग्न किया गया था। शिकायत में बताए गए सटीक आधारों पर ध्यान दिया गया था, और यह कहा गया था कि प्रतिवादी को किसी भी विशिष्ट उदाहरण को उद्धृत करने के लिए कहा गया था जहां उसके द्वारा कथित अनियमितताएं की गई हों, लेकिन प्रतिवादी ने किसी विशिष्ट उदाहरण का हवाला नहीं दिया। आदेश में आगे कहा गया कि चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी से पूछा गया था कि क्या किसी विधानसभा क्षेत्र में उसने या उसके किसी एजेंट ने वोटों की फिर से जांच करने के लिए कहा था या सहायक निर्वाचन अधिकारी या पर्यवेक्षक के समक्ष आंकड़ों में कोई विसंगति बताई थी, जिन्होंने 10 और 11 मार्च को केंद्रों का दौरा किया था। 1971. और यह कि इकबाल सिंह ऐसे किसी विशिष्ट उदाहरण का हवाला देने में विफल रहे थे। आदेश में इकबाल सिंह के संसदीय क्षेत्र के किसी विशिष्ट विधानसभा क्षेत्र में डाले गए मतों की फिर से गिनती करने के निर्वाचन अधिकारी के सुझाव के जवाब में पूर्ण पुनर्मतगणना की बात दोहराने का भी उल्लेख किया गया है। मतपेटियों को अनुचित तरीके से सील करने के आरोप के संबंध में निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना में मुहरों की जांच पहला अभियान था और अगर मतपेटियों पर लगी कोई सील सही नहीं पाई जाती या 'अनुचित' पाई जाती तो मतगणना शुरू नहीं हो सकती थी। यह कहा गया था कि, किसी भी मतगणना केंद्र या किसी सहायक रिटर्निंग अधिकारी को ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई थी, और इसलिए, उस आरोप में कोई आधार नहीं था। तब नोटिस लिया गया था कि एक बंडल में केवल एक या दो मतपत्र पाए गए थे, जिन पर रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर या मुहर नहीं थी, और पर्यवेक्षक ने मतपत्रों के सीरियल नंबरों से पुष्टि की थी कि वे थके हुए रिटर्निंग अधिकारियों को इस आशय से दिए गए थे कि इस तरह के बैलोट-पेपर उत्पन्न होते हैं। आदेश में उल्लेख किया गया था कि निर्देशों (जिन पर निर्वाचन अधिकारी की मुहर और हस्ताक्षर नहीं थे) को खारिज नहीं किया जाएगा यदि मतपत्रों की वास्तविकता को चुनौती नहीं दी जाती है। इस तथ्य का विशेष उल्लेख किया गया था कि किसी भी केंद्र में कोई गैर-वास्तविक मतपत्र नहीं पाया गया था। गलत रिटर्न तैयार करने के आरोप का निपटारा इस टिप्पणी के साथ किया गया कि यह दिखाने के लिए किसी विशिष्ट मामले का हवाला नहीं दिया गया था कि मतगणना पर्यवेक्षकों या सहायक रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा गलत तरीके से कोई रिटर्न तैयार किया गया था। उपरोक्त निष्कर्षों के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि चुनाव लड़ने वाला प्रतिवादी *प्रथम दृष्टया* मामला बनाने में सक्षम नहीं था , जिसके लिए संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डाले गए सभी मतों की फिर से गिनती की आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्टेपनी[21] के *फैसले के आधार पर* चाडालावाडा सुभा राव बनाम कासू ब्रह्मानंद रेड्डी और अन्य[22] निर्णय में कतिपय

[21] (1866) O.M &H. 34.
[22] A.I.R 1967 A.P 155 at p. 176.

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(नरूला, जे।

टिप्पणियों का उल्लेख किया गया था। निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी का इरादा स्पष्ट रूप से पुनर्मतगणना कराना था ताकि किसी भी तरह की कुछ गलतियों का पता लगाया जा सके जो संभवतः उसे लाभ पहुंचा सकती हैं और इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। तदनुसार पुनर्मतगणना के आवेदन को खारिज कर दिया गया था। मेरा विचार है कि यदि जिला निर्वाचन अधिकारी (रिटर्निंग अधिकारी) के उपर्युक्त विस्तृत आदेश के संबंध में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को विश्वास में लिया गया होता, तो हो सकता है कि उन्होंने या तो निरीक्षण की अनुमति न दी होती या निर्वाचन अधिकारी द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न होने के कारण दिए होते। प्रेक्षक की रिपोर्ट और निर्वाचन अधिकारी के आदेश की विषय-वस्तु को देखने के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त क्या राय बना सकते थे, यह सुझाव देना मेरा काम नहीं है। यह उन पर निर्भर था कि वह उन दस्तावेजों में कही गई बातों के बावजूद निरीक्षण की अनुमति दें। लेकिन उस मामले में आदेश ने *प्रथम दृष्टया* यह दिखाया होगा कि उन्होंने उस सामग्री को ध्यान में रखा था और जिन कारणों से उन्होंने रिकॉर्ड किया होगा, उन्होंने अभी भी निरीक्षण की अनुमति देना आवश्यक या उचित माना।

47. हालांकि, आयोग के लिए सबूत लेना आवश्यक नहीं हो सकता है, निरीक्षण के लिए एक आवेदक को अपने हलफनामे या अन्य दस्तावेजी सबूतों द्वारा अपने आरोपों का समर्थन करने से नहीं रोका जाता है। यह उल्लेखनीय है कि चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी के आवेदन के साथ कोई हलफनामा नहीं था। हालांकि यह एक प्राधिकारी के लिए खुला हो सकता है कि वह किसी व्यक्ति द्वारा लगाए गए तथ्य की शपथ लिए बिना उस पर विश्वास कर सके। और उसके बावजूद दूसरे पर विश्वास न करना

हलफनामा देते हुए, एक आवेदक द्वारा अपने आरोपों की पूरी जिम्मेदारी लेने और हलफनामे में झूठे आरोप लगाने के लिए अभियोजन का जोखिम उठाने के महत्व को आसानी से दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इन सभी तथ्यों से पता चलता है कि लागू आदेश यांत्रिक तरीके से और चुनाव आयोग के दिमाग के उचित अनुप्रयोग के बिना पारित किया गया था। निरीक्षण की अनुमति देने वाले वैध आदेशों में दोहराए जाने के लिए न तो कोई जादुई संकेत निर्धारित करना संभव है और न ही उचित है। चीजों की प्रकृति में प्रत्येक मामले को अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए। निरीक्षण की अनुमति देने वाले आदेश में कोई विशिष्ट शब्द मौजूद होने की आवश्यकता नहीं है। आदेश में प्रथम दृष्टया विचार की गई *सामग्री, उन आरोपों के बारे* में प्रथम दृष्टया संतुष्टि दिखाई जानी चाहिए जिन्हें निरीक्षण की अनुमति देने को उचित ठहराने के लिए माना गया है और इस तरह के औचित्य के कारण हैं। उन कारणों को आदेश से ही स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए, न कि किसी औपचारिक आदेश से जो बाद में इसके आधार पर या किसी भी संचार से तैयार किया जा सकता है जिसके साथ उस आदेश को किसी अधीनस्थ प्राधिकारी को अग्रेषित किया जा सकता है। यदि आक्षेपित आदेश में दिए गए प्रकार के कारण को एक अच्छा कारण माना जाता है, तो ऐसे दस्तावेजों के निरीक्षण के निषेध के अपवाद के भीतर मामले को लाने के लिए नियम 93 के परंतुक द्वारा प्रदान की गई वैधानिक सुरक्षा पूरी तरह से विफल हो जाएगी। यदि तत्काल मामले में दिए गए कारण को एक अच्छा कारण माना जा सकता है, तो निरीक्षण के लिए एक आवेदक को केवल इतना करना है कि उन

आरोपों में कोई सच्चाई होने के बारे में प्रथम दृष्टया संतुष्टि देने की आवश्यकता के बिना गंभीर आरोप लगाना होगा । यदि नियम बनाने वाले प्राधिकारी का यह इरादा होता, तो नियम 93 के उप-नियम (2) में उल्लिखित दस्तावेजों की तरह संभावित चुनाव-याचिकाकर्ताओं को भी निषिद्ध दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति दी जाती। आयोग द्वारा पारित निरीक्षण के आदेश को एक रिट याचिका की प्रारंभिक सुनवाई में इस न्यायालय की मोशन बेंच द्वारा पारित आदेश के बराबर बताने की कोशिश करके इस बिंदु पर प्रतिवादी के मामले का समर्थन करने का एक चरण में प्रयास किया गया था। यह सुझाव दिया गया था कि हम किसी रिट याचिका को दूसरे पक्ष को बुलाए बिना सुनवाई के लिए स्वीकार करते हैं जब याचिका में *दुर्भावना* आदि के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं, बिना किसी कारण के याचिका को स्वीकार करने के हमारे फैसले का समर्थन किए बिना। समस्या के लिए यह दृष्टिकोण मुझे पूरी तरह से भ्रामक प्रतीत होता है। एक रिट याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते समय, यह न्यायालय मामले में आगे बढ़ने के अलावा कुछ भी तय नहीं करता है। निरीक्षण की अनुमति देते समय आयोग अंततः पूरे मामले का निपटान करता है।

रिट याचिका को स्वीकार करने का उद्देश्य दूसरे पक्ष को उपस्थित होने और उसका बचाव करने के लिए बुलाना है। नियम 93 के तहत एक याचिका में चुनाव आयोग के समक्ष ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। हम निश्चित रूप से किसी रिट याचिका को भी स्वीकार नहीं करते हैं, जिसमें *दुर्भावना* के आरोप हों , लेकिन याचिकाकर्ता के हलफनामे में कही गई बातों और यदि कोई दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं, तो उनके संदर्भ में आरोपों में प्रथम *दृष्टया* कुछ सच्चाई होने की संभावना के संदर्भ में खुद को संतुष्ट करते हैं। एक और अंतर जो मेरी राय में, अन्य सभी विचारों को दरकिनार करता है, इस तथ्य में निहित है कि उच्च न्यायालय को अपने संबंधित नियमों द्वारा एक रिट याचिका को सरसरी तौर पर उसी तरह से खारिज करने की अनुमति है जैसे उच्च न्यायालय किसी भी कारण से उस आदेश का समर्थन किए बिना एक शब्द "खारिज" लिखकर एक नियमित दूसरी अपील या संशोधन के लिए याचिका को खारिज कर सकता है। श्री सिब्बल के तीसरे मुख्य तर्क को दूर करने के उद्देश्य से मैंने पदाधिकारियों (एक तरफ उच्च न्यायालय और दूसरी ओर चुनाव आयोग) के बीच जो अंतर बताया है, उसे प्रतिवादी के मामले के समर्थन में दिए जाने वाले तर्क की वैधता को देखते हुए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

48. मैंने ऊपर जो कुछ कहा है, उसे ध्यान में रखते हुए, मेरा सुविचारित मत है कि मुख्य चुनाव आयुक्त का 15 मार्च, 1971 का आक्षेपित आदेश किन्हीं कारणों से समर्थित नहीं है और निरीक्षण के लिए आवेदन में लगाए गए आरोपों का केवल बयान, यदि सही है, तो गंभीर होने के नाते, नियम 93 (1) के तहत निरीक्षण की अनुमति देने के लिए कानून की नजर में कोई कारण नहीं है। मामले की परिस्थितियों से, जिसका संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है, मुझे यह भी प्रतीत होता है कि विवादित आदेश विवाद में वास्तविक मामलों पर आयोग के दिमाग को पूरी तरह से लागू नहीं करने से ग्रस्त है। आवेदन में लगाए गए प्रासंगिक और अप्रासंगिक आरोपों के बीच कोई अंतर नहीं किया गया था। नियम 93 के उप-नियम (1) के खंड (ए) टीक्यू (डी) में उल्लिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेजों को आवेदन में लगाए गए आरोपों से संबंधित उद्देश्यों के लिए खोला और निरीक्षण करना आवश्यक होगा, यह भी विचार नहीं किया गया है। यदि चुनाव आयोग ने इस संबंध में अपना दिमाग लगाया होता, तो नियम 93 (1) (डी)

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(नरूला, जे।
के तहत चुनौती दिए गए वोटों और घोषणाओं के निरीक्षण की अनुमति नहीं दी गई होती। इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया कि यदि हारे हुए उम्मीदवार को निरीक्षण की अनुमति दी जाती है, तो लौटाए गए उम्मीदवार से यह पूछना आवश्यक हो सकता है कि क्या वह इकबाल सिंह के पक्ष में डाले गए किसी मतपत्र का निरीक्षण करना चाहता है। जो भी हो

इस मामले पर विचार किया जाए, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 15 मार्च, 1971 का आदेश यांत्रिक तरीके से पारित किया गया था जैसे कि कुछ मामलों में निरीक्षण की अनुमति देना या न देना नीति या औचित्य का मामला था। इस स्तर पर यह देखा जा सकता है कि श्री सिब्बल ने हमें चुनाव आयोग द्वारा दी गई कथित जानकारी के आधार पर कुछ समाचार पत्रों की रिपोर्टों का उल्लेख किया जिसमें यह कहा गया था कि आयोग ने उन मामलों में निरीक्षण की अनुमति देने के लिए एक समान प्रथा अपनाई थी जहां लौटाए गए उम्मीदवार और सबसे अधिक पराजित उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए मतों के बीच का अंतर 40,000 से कम था और आयोग ने लगातार निरीक्षण से इनकार कर दिया था। ऐसे मामले जहां अंतर बड़ा था। हमें समाचार पत्रों की खबरों का न्यायिक नोटिस लेने के लिए कहा गया था। मुझे लगता है कि इस विवाद में पड़ना अनावश्यक है। हालांकि, यह स्पष्ट है कि यदि चुनाव आयोग द्वारा इस तरह के किसी भी मानदंड का पालन किया गया था, तो यह लागू आदेश को रद्द करने का एक और कारण होगा क्योंकि नियम 93 (1) के तहत आवेदनों को केवल नीति के आधार पर निपटाया नहीं जा सकता है।

49. यद्यपि मैंने यह माना है कि आयोग का वास्तविक और एकमात्र आदेश, जिसकी वैधता पर इस मामले का भविष्य निर्भर करता है, श्री एस पी सेन वर्मा का 15 मार्च, 1971 का आदेश है, मुझे 16 मार्च के औपचारिक आदेश की वैधता के प्रश्न पर भी संक्षेप में चर्चा करनी चाहिए। 1971 में, आयोग के "आदेश द्वारा" सचिव द्वारा हस्ताक्षरित आयोग के अवर सचिव द्वारा तैयार किया गया, क्योंकि उस बिंदु पर भी दोनों पक्षों द्वारा विकल्प में तर्कों को संबोधित किया गया था। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने औपचारिक आदेश को आयोग के आदेश के रूप में बुलाने के लिए प्राथमिकता दिखाई क्योंकि इसमें निरीक्षण के लिए आवेदन में लगाए गए दो आरोपों का विशिष्ट संदर्भ है और इसके ऑपरेटिव भाग में निम्नलिखित अभिव्यक्ति का भी उपयोग किया गया है: –

चुनाव आयोग इस बात से संतुष्ट है कि आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार निरीक्षण न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है।

मैं इस फैसले के पहले हिस्से में आदेश के प्रासंगिक हिस्से को शब्दश: उद्धृत कर चुका हूं। पहले दो अनुच्छेदों से ऐसा प्रतीत होता है :-

1. निरीक्षण के लिए आवेदन में प्रतिवादी के बयान का संदर्भ दिया गया था कि निरीक्षण आवश्यक है, ताकि वह एक चुनाव याचिका द्वारा उचित न्यायालय में उनका कानूनी उपचार की मांग कर सके।

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(नरूला, जे।

एक चुनाव याचिका द्वारा उचित न्यायालय में उनका कानूनी उपचार; और

2. यह महत्व उन आरोपों (ए) के साथ जुड़ा हुआ था, जो मतपत्रों पर डाले गए वोटों की अवैध स्वीकृति के बारे में थे, जिन पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर या मुहर नहीं थी और (बी) विशेष रूप से लगभग 6,000 मतपत्रों की "गलत" अस्वीकृति के बारे में।

50. यह विवादित नहीं था कि यह आदेश श्री विश्वनाथ ने श्री एसपी सेन वर्मा के आदेश के अनुसरण में तैयार किया था। अधिनियम में सचिव द्वारा आयोग के आदेश के प्रमाणीकरण को अधिकृत करने का कोई प्रावधान नहीं है- हालांकि सचिव स्वयं आदेश पारित कर सकता था, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से सचिव के रूप में अपनी व्यक्तिगत क्षमता में ऐसा नहीं किया, लेकिन आयोग के "आदेश द्वारा" स्पष्ट रूप से इसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए। मैंने पहले ही संकेत दिया है कि कानून की नजर में केवल यह कहने का कोई कारण नहीं है कि न्याय के अंत को आगे बढ़ाने के लिए निरीक्षण आवश्यक है या समीचीन है या न्याय के हित में है। आदेश से पता चलता है कि यहां तक कि आयोग के सचिव ने भी अवर सचिव द्वारा तैयार मसौदा आदेश को मंजूरी देते समय प्रतिवादी के आवेदन के अलावा उनके सामने कोई सामग्री नहीं थी। "औपचारिक आदेश" शब्द प्रिवी काउंसिल अभ्यास और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रासंगिक नियमों से उधार लिया गया प्रतीत होता है। औपचारिक आदेश को दूसरे शब्दों में एक अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले के ऑपरेटिव हिस्से के संदर्भ में एक अदालत द्वारा पारित डिक्री के बराबर किया जा सकता है। इस मामले में औपचारिक आदेश विभिन्न भौतिक विवरणों में मूल आदेश से बहुत आगे चला गया, जो इस फैसले के पहले भाग में मेरे द्वारा पहले ही इंगित किए जा चुके हैं। मुझे सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बात यह है कि औपचारिक आदेश तैयार करने वाले अधिकारी को यह एहसास नहीं था कि लौटे हुए उम्मीदवार को निरीक्षण की अनुमति देने की शक्ति आयोग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को नहीं सौंपी जा सकती है जैसा कि इस मामले में किया गया था। लौटाए गए उम्मीदवार को जिला रिटर्निंग अधिकारी को दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए आवेदन करने के लिए नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उस अधिकारी का नाम नियम 93 में नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि चुनाव आयोग को 1951 के अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के किसी प्रावधान के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि वह जिला निर्वाचन अधिकारी को निरीक्षण की अनुमति देने के अपने कार्यों को छोड़ दे। अधिकांश अन्य दोष जिन्हें मैंने इंगित किया है

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(नरूला, जे।

मुख्य चुनाव आयुक्त के आदेश के साथ संबंध सचिव द्वारा अनुमोदित औपचारिक आदेश में भी मौजूद है। इसलिए, यदि केवल औपचारिक आदेश (याचिका के अनुलग्नक 'डी') की वैधता पर ही सवाल उठाया जाता, तो मैं मानता कि यह मुख्य चुनाव आयुक्त के मूल आदेश के समान ही दोष से ग्रस्त है।

51. अब मैं श्री सिब्बल द्वारा आग्रह किए गए अंतिम मुद्दे पर आता हूं। बेशक याचिकाकर्ता को निरीक्षण के लिए आवेदन में एक पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया था। वास्तव में ऐसा करना आवश्यक नहीं हो सकता है। यह भी विवादित नहीं है कि हालांकि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाए गए थे, लेकिन चुनाव आयोग द्वारा उन्हें आवेदन का कोई नोटिस नहीं भेजा गया था। वास्तव में याचिकाकर्ता को याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए मतपत्रों के निरीक्षण की अनुमति देने के लिए प्रस्तावित आदेश के खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई अवसर नहीं दिया गया था, और आक्षेपित आदेश में संदर्भित अन्य दस्तावेजों के लिए। इस संबंध में, श्री सांघी द्वारा यह तर्क दिया गया था कि चुनाव में अन्य सभी उम्मीदवारों को दिए जा रहे वास्तविक निरीक्षण की सूचना के लिए नियम 93 (1) के परंतुक (बी) में किए गए प्रावधान से पता चलता है कि निरीक्षण की अनुमति देने के चरण में नोटिस की आवश्यकता को नियम बनाने वाले प्राधिकरण द्वारा निहित रूप से बाहर रखा गया है। मैं विद्वान वकील की इस दलील से सहमत होने में असमर्थ हूं। नियम 93 (1) के परंतुक (बी) में संदर्भित उचित अवसर स्पष्ट रूप से उम्मीदवारों या उनके विधिवत अधिकृत एजेंटों को "इस तरह के उद्घाटन, निरीक्षण या उत्पादन में उपस्थित होने" के लिए अधिकृत करने तक सीमित है। यह वापस आए उम्मीदवारों या निरीक्षण से प्रभावित होने वाले किसी अन्य व्यक्ति को निरीक्षण या उसके किसी भी हिस्से के लिए आदेश के तथ्य, वैधता या वैधता को चुनौती देने के लिए अधिकृत नहीं करता है। न ही परंतुक (बी) लौटाए गए उम्मीदवार को गोपनीयता के नियम के संभावित पालन को छोड़कर निरीक्षण की प्रक्रिया के किसी भी हिस्से पर आपत्ति करने के लिए अधिकृत करता है। आयोग के आदेश की वैधता पर दोनों पक्षों द्वारा इस आधार पर लंबी दलीलें दी गईं कि इससे गोपनीयता के नियम का उल्लंघन होने की संभावना है। इस तरह के उल्लंघन को प्रतिबंधित करने वाले वैधानिक प्रावधानों और औपचारिक आदेश में इस निर्देश के विशिष्ट उल्लेख को ध्यान में रखते हुए, हम यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि विचाराधीन दस्तावेजों के निरीक्षण से गोपनीयता का उल्लंघन होगा। चूंकि आयोग द्वारा प्रयुक्त मतपत्रों के साथ-साथ मतदाता सूची की चिह्नित प्रति के निरीक्षण की अनुमति दी गई है, इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि मतदाता सूची की चिह्नित प्रति को लापरवाही से संभालना, या चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी या उसके किसी भी प्रतिनिधि या किसी को भी अनुमति देना। अन्यथा उस निर्वाचक की पृष्ठ संख्या, नाम या क्रम संख्या को देखना, जिसके मतपत्र का निरीक्षण ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले ही किया जा चुका है, गोपनीयता के नियम का उल्लंघन करेगा। लेकिन हमें यह मानना होगा कि यदि और जब भी उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण की अनुमति दी जानी है, तो इसे इस तरह से अनुमति दी जानी चाहिए ताकि मतपत्र की गोपनीयता का उल्लंघन न हो।

52. यह मानते हुए कि पराजित उम्मीदवार के आवेदन पर निरीक्षण की अनुमति देने से पहले वापस आए उम्मीदवार को सुनवाई का अवसर दिया गया है, नियम 93 में निहित किसी भी चीज से या कहीं और निहित नहीं किया गया है, और ऐसा कोई व्यक्त बहिष्करण नहीं है, दो प्रश्न निर्णय के लिए कहते हैं, अर्थात्, (i) क्या नियम 93 (1) के तहत कार्यवाही पर प्राकृतिक न्याय के नियम लागू होते हैं और यदि हां, (ii) उस नियम के अंतर्गत कार्यवाहियों पर लागू संगत नियम क्या हैं। मैंने पहले कहा है कि नियम 93 के तहत आयोग का कार्य *अर्ध-न्यायिक है।* यदि यह निष्कर्ष सही है, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि *ऑडी अल्टरम पार्टम का* प्रसिद्ध सिद्धांत लागू होगा और आयोग द्वारा लौटाए गए उम्मीदवार को प्रस्तावित आदेश के खिलाफ कारण दिखाने का अवसर दिए बिना दिया गया कोई भी निर्णय मान्य नहीं होगा। आयोग के समक्ष कार्यवाही अर्ध-न्यायिक या अन्य होने के मामले में भिन्न दृष्टिकोण अपनाने जा रहे मेरे विद्वान भाइयों के प्रति मेरे मन में जो अत्यधिक सम्मान है और महसूस करता हूं, यह आवश्यक है कि मैं उन आधारों पर ध्यान दूं जिनके आधार पर मैं प्रभावित पक्ष को अवसर प्रदान करना आवश्यक समझता हूं, भले ही आयोग से अपनी प्रशासनिक क्षमता में निरीक्षण के प्रश्न पर निर्णय लेने की अपेक्षा की जाए।

53. श्री सिब्बल ने जिस विषय पर हमारा ध्यान आकषत किया है, उस पर सबसे पहला मामला आर्थर जॉन स्पैकमैन बनाम *प्लमस्टेड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऑफ वर्क्स*इंग्लैंड[23] मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का निर्णय है । संबंधित कानूनी प्रावधान में प्राधिकारी को ऐसे मालिक या कब्जेदार, इमारत या व्यक्ति के बारे में लिखित में आदेश देने का अधिकार दिया गया है, जिसमें ऐसी किसी भी इमारत को गिराने या उसके निर्माण का निर्देश दिया गया है, जो उपरोक्त सामान्य रेखा से परे हो सकता है। इमारतों की ऐसी सामान्य लाइन को अधीक्षण वास्तुकार द्वारा मेट्रोपॉलिटन बोर्ड ऑफ वर्क्स को कुछ समय के लिए तय किया जाना था। अर्ल ऑफ सेलबोर्न, एल.सी., मैन-नेर का उल्लेख करते हुए जिसमें वास्तुकार को निम्नानुसार देखी गई इमारतों की सामान्य रेखा को ठीक करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए: –

> "इसमें कोई संदेह नहीं है, विशेष प्रावधानों के अभाव में कि जिस व्यक्ति को निर्णय लेना है, उसे कैसे आगे बढ़ना है, कानून का अर्थ यह होगा कि न्याय की पर्याप्त आवश्यकताओं का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। वह शब्द के उचित अर्थों में न्यायाधीश नहीं है; लेकिन उन्हें पक्षकारों को उनके समक्ष अपनी बात रखने और अपना मामला और अपना दृष्टिकोण बताने का अवसर देना चाहिए। उसे नोटिस देना चाहिए कि वह मामले में कब आगे बढ़ेगा, और उसे ईमानदारी से और निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए और किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के आदेश के तहत नहीं, जिन्हें कानून द्वारा अधिकार नहीं दिया गया है। किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। कानून के अर्थ के भीतर कोई निर्णय नहीं होगा यदि न्याय के सार के विपरीत

[23] L.R 10 (1885) A.C 229.

ऐसा कुछ भी किया गया हो। लेकिन मुझे यह तर्क के साथ पूरी तरह से संगत प्रतीत होता है, कि क़ानून जानबूझकर फॉर्म प्रदान करने के लिए छोड़ सकता है, क्योंकि यह एक प्रकार का मामला नहीं है, जिसमें मुकदमेबाजी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल यह आवश्यक है कि पार्टियों को उस व्यक्ति को प्रस्तुत करने का अवसर होना चाहिए जिसके निर्णय से उन्हें बाध्य किया जाना है कि उनके निर्णय में उनके सामने लाया जाना चाहिए। उसे। जब ऐसा किया जाता है, तो मामले की प्रकृति से, पार्टियों को तलब करने के बारे में आगे की कार्यवाही नहीं होती है, या उस तरह का कुछ भी नहीं करना पड़ता है जो एक न्यायाधीश को करना पड़ सकता है।

54. निश्चित रूप से इमारतों की सामान्य लाइन को ठीक करते समय वास्तुकार कुछ भी *अर्ध-न्यायिक* नहीं कर रहा था। लॉर्ड चांसलर ने यह स्पष्ट किया कि यद्यपि वास्तुकार शब्द के उचित अर्थों में न्यायाधीश नहीं था, फिर भी उसे पार्टियों को अपने सामने सुनने और अपने मामले और उनके विचारों को बताने का अवसर देना चाहिए। इस बात पर जोर दिया गया कि यह रूप का मामला नहीं था, और इसलिए, भले ही क़ानून इस विषय पर चुप हो, पार्टियों को अभी भी उस व्यक्ति को प्रस्तुत करने का अवसर होना चाहिए जिसके निर्णय से उन्हें बाध्य होना है।

55. इसके बाद वकील ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स (लॉर्ड लोरेबम, एल.सी.) के शिक्षा बोर्ड बनाम *राइस* और अन्य[24] फैसले में प्रसिद्ध अंश का *उल्लेख किया*, जिसमें बहुत जोर दिया गया था

[24] L.R (1911) A.C 179 at p. 182

~ (I 23TL R- (191D A.C. I79 at P- 182-

प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह कुछ भी निर्णय ले और दोनों पक्षों की बातों को निम्नलिखित शब्दों में निष्पक्ष रूप से सुने-

"तुलनात्मक रूप से हाल के क़ानूनों ने, यदि वे उत्पन्न नहीं हुए हैं, तो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को तय करने या निर्धारित करने के कर्तव्य को राज्य के विभागों या अधिकारियों पर थोपने की प्रथा का विस्तार किया है। वर्तमान उदाहरण में, जैसा कि कई अन्य लोगों में है, निर्धारण के लिए जो आता है वह कभी-कभी विवेक से निपटाया जाने वाला मामला होता है, जिसमें कोई कानून शामिल नहीं होता है। यह, मुझे लगता है, आमतौर पर एक प्रशासनिक प्रकार का होगा; लेकिन कभी-कभी इसमें कानून के साथ-साथ तथ्य का मामला भी शामिल होगा, या यहां तक कि अकेले कानून के मामले पर निर्भर करेगा। ऐसे मामलों में शिक्षा बोर्ड को कानून का पता लगाना होगा और तथ्यों का भी पता लगाना होगा। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा करने में उन्हें अच्छे विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए और दोनों पक्षों को निष्पक्ष रूप से सुनना चाहिए, क्योंकि यह हर उस व्यक्ति का कर्तव्य है जो कुछ भी तय करता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे इस तरह के सवाल को इस तरह से लेने के लिए बाध्य हैं जैसे कि यह एक परीक्षण था। उनके पास शपथ दिलाने की कोई शक्ति नहीं है, और गवाहों से पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। वे किसी भी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो वे सबसे अच्छा सोचते हैं, हमेशा उन लोगों को उचित अवसर देते हैं जो विवाद में पक्ष हैं ताकि वे अपने विचार के प्रतिकूल किसी भी प्रासंगिक बयान को सही या विरोधाभासी कर सकें।

56. *न्यू प्रकाश ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड बनाम स्वर्णा ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड*[25] *में आर्थर जॉन स्पैकमैन* उपर्युक्त के मामले *में और शिक्षा बोर्ड बनाम राइस मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के निर्णयों से उपरोक्त उद्धृत अंश* (सुप्रा), को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदन के साथ उद्धृत किया गया था (पृष्ठ 109-110 पर)। *भारत संघ बनाम कर्नल जे. एन. सिन्हा और अन्य*[26], के. एस. हेगड़े, जे. ने मौलिक नियम 56 (जे) के तहत एक निर्णय के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को लागू करने के प्रश्न पर विचार करते हुए कहा, जो नियम सरकार को 55 वर्ष की आयु के बाद किसी भी कर्मचारी को लिखित में तीन महीने का नोटिस या ऐसे नोटिस के बदले तीन महीने का वेतन और भत्ते देकर सेवानिवृत्त करने के लिए अधिकृत करता है। निम्नानुसार देखा गया:-

"प्राकृतिक न्याय के नियम सन्निहित नियम नहीं हैं और न ही उन्हें मौलिक अधिकारों के स्थान पर बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि इस न्यायालय ने *क्रैपक बनाम भारत संघ* में कहा था,

"प्राकृतिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुरक्षित करना है या न्याय के गर्भपात को रोकने के लिए इसे नकारात्मक रूप से रखना है। ये नियम केवल उन

[25] (1957) s.c.r 98
[26] A.I.R 1971 S.C 40.

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(नरूला, जे।

क्षेत्रों में काम कर सकते हैं जो वैध रूप से बनाए गए किसी भी कानून द्वारा कवर नहीं किए गए हैं। दूसरे शब्दों में, वे कानून की जगह नहीं लेते हैं, बल्कि इसे पूरक करते हैं। यह सच है कि यदि किसी सांविधिक प्रावधान को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ लगातार पढ़ा जा सकता है, तो न्यायालयों को ऐसा करना चाहिए क्योंकि यह माना जाना चाहिए कि विधायिका और वैधानिक प्राधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने का इरादा रखते हैं। लेकिन, दूसरी ओर, यदि कोई सांविधिक प्रावधान या तो विशेष रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के किसी भी या सभी नियमों के आवेदन को शामिल नहीं करता है, तो न्यायालय विधायिका या वैधानिक प्राधिकरण के जनादेश की अनदेखी नहीं कर सकता है और संबंधित प्रावधान में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पढ़ सकता है। प्रदत्त शक्ति का प्रयोग प्राकृतिक न्याय के किसी सिद्धांत के अनुसार किया जाना चाहिए या नहीं, यह शक्ति प्रदान करने वाले प्रावधान के व्यक्त शब्दों, प्रदान की गई शक्ति की प्रकृति, जिस उद्देश्य के लिए इसे प्रदान किया गया है और उस शक्ति के प्रयोग के प्रभाव पर निर्भर करता है।

57. जे. एन. सिन्हा और अन्य (सुप्रा) के मामले *में सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक घोषणा का अनुपात* यह है कि यदि किसी वैधानिक प्रावधान को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ लगातार पढ़ा जा सकता है, तो न्यायालय को उन सिद्धांतों को ऐसे प्रावधान तक विस्तारित करना चाहिए क्योंकि यह माना जाना चाहिए कि कानून बनाने वाले प्राधिकरण का इरादा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने का है। उस नियम के लिए गढ़ा गया एकमात्र अपवाद एक ऐसे मामले का था जहां एक वैधानिक प्रावधान या तो विशेष रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा किसी भी या सभी नियमों, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के आवेदन को शामिल नहीं करता है। वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, ऐसा कोई बहिष्करण नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही देखा है कि नियम 93 के तहत आवेदन पर निर्णय किसी नीति के अनुसार या किसी प्रशासनिक औचित्य के कारण नहीं दिया जाना है, बल्कि प्रत्येक मामले में अपने गुण-दोष के आधार पर दिया जाना है। जैसे ही यह स्पष्ट हो जाता है कि निर्णय सामग्री और प्रासंगिक तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, मेरी राय में, संबंधित प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह निर्णय से प्रभावित होने वाले व्यक्ति को यह प्रदर्शित करने का अवसर दे कि जिन आरोपों पर निर्णय मांगा गया है, वे या तो निराधार या अस्तित्वहीन हैं या अन्यथा यह दिखाने के लिए कि यह उचित मामला नहीं है। विपरीत की प्रार्थना का अनुदान दावत। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होने के लिए यह न्यूनतम आवश्यक है।

58. *भारत संघ में और दूसरा* v. *पी. के. रॉय और अन्य* (26) ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की सीमा और अनुप्रयोग को एक कठोर सूत्र के सीधे जैकेट के भीतर कैद नहीं किया जा सकता है। सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रशासनिक प्राधिकरण को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र की प्रकृति, प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों के चरित्र, क़ानून की योजना और नीति और विशेष मामले में प्रकट अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। पी. *के. रॉय के पिंजरे* (26), (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस प्रस्ताव के लिए एक अधिकार है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत प्रशासनिक अधिकारियों के निर्णयों पर भी लागू होते हैं।

बेरियम केमिकल्स लिमिटेड में और एक अन्य बनाम *कंपनी लॉ बोर्ड और अन्य*[27], यह अभिनिर्धारित किया गया था कि हालांकि एक राय का गठन एक व्यक्तिपरक प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन प्रासंगिक अनुमान का सुझाव देने वाली परिस्थितियों के अस्तित्व को निष्पक्ष रूप से बनाया जाना चाहिए।

59. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने निम्नलिखित तीन मामलों में अंग्रेजी न्यायालयों द्वारा निर्धारित कानून पर बहुत जोर दिया, जिसके आधार पर यह तर्क दिया गया था कि जहां प्रासंगिक निर्णय केवल कुछ तथ्यों या परिस्थितियों की *प्रथम दृष्टया* संतुष्टि पर एक प्राधिकरण द्वारा दिया जाना है , ऐसे निर्णय से प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्ति को बुलाना आवश्यक नहीं है: —

    1. वाइसमैन *और एक और* बनाम *बोर्नमैन और! अन्य*[28]
    2. *पैरी-जोन्स* बनाम बनाम *कानून, समाज और अन्य*[29]
    3. वाइसमैन *और एक और* बनाम। *बोर्नमैन और अन्य*[30]

60. वाइसमैन के मामले में, (1967) 3 ऑल ईआर 1045, जो इस विषय पर मूल निर्णय है, ट्रिब्यूनल को वैधानिक घोषणा, प्रमाण पत्र और प्रति-कथन को ध्यान में रखना था और यह निर्धारित करना था कि क्या इस मामले में कार्यवाही के लिए *प्रथम दृष्टया* मामला है या नहीं। वादी का दावा

इसका मतलब यह था कि ट्रिब्यूनल उन्हें सबूत पेश करने और बहस करने का अवसर देने के लिए बाध्य था, इससे पहले कि ट्रिब्यूनल प्रथम *दृष्टया* निर्णय पर आए, मामले को खारिज कर दिया गया। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां एक न्यायाधिकरण को केवल यह निर्धारित करना था कि *"एक संभावित प्रतिवादी के जवाब देने के लिए" प्रथम दृष्टया* मामला था या नहीं , उसे सुनवाई का अवसर देना आवश्यक नहीं था क्योंकि संभावित प्रतिवादी के पास बाद में अपना मामला बनाने का ऐसा अवसर होगा। यह जोड़ा गया था कि अपील की अदालत के समक्ष मामले में, क़ानून ने उन सामग्रियों को निर्दिष्ट किया था जिन पर ट्रिब्यूनल के प्राथमिक निर्णय तक पहुंचा जाना चाहिए और अदालत को अन्य मामलों को ध्यान में रखने का दायित्व नहीं होना चाहिए। *वाइसवान के मामले* (28), और नियम 93 के तहत मामले के बीच का अंतर मुझे बहुत स्पष्ट प्रतीत होता है। सर्वप्रथम, वहां के संविधि में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया था कि प्रथम दृष्टया निर्णय लेने के लिए किन बातों पर विचार किया जाना चाहिए । नियम 93 में ऐसा कोई संकेत नहीं है। दूसरे, *वाइसमैन के मामले* (28) में ट्रिब्यूनल को केवल यह मानना था कि संभावित प्रतिवादी के जवाब देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला था या नहीं। इस तरह की राय बनने पर, प्रतिवादी को जवाब देने के लिए बुलाया जाना था और तब तक उसके लिए कोई पूर्वाग्रहपूर्ण कदम नहीं उठाया गया होगा। वर्तमान मामले में, निरीक्षण की अनुमति देने के संबंध में निर्णय अंतिम रूप से आयोग द्वारा नियम 93 (1) के तहत लिया जाना है। किसी भी कार्यवाही में बाद के चरण में लौटा हुआ

[27] A.I.R 1967 S.C. 295
[28] (1967) 3 A.E.R 1045.
[29] (1968) A.E.R. 177.
[30] (1969) 3 A.E.R. 275

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(नरूला, जे।

उम्मीदवार उस निर्णय की शुद्धता पर सवाल उठाने का हकदार नहीं है, या अपनी पीठ के पीछे अनुमत निरीक्षण के परिणाम और प्रभाव से बचने का हकदार है। तीसरा, वाइसमैन के मामले में ट्रिब्यूनल को केवल वाइसमैन की वैधानिक घोषणा, आदि पर विचार करना था, आयुक्तों के प्रमाण पत्र और प्रति-कथन पर विचार करना था और केवल यह निर्धारित करना था कि क्या इस मामले में कार्यवाही के लिए प्रथम दृष्टया मामला था। ऐसा करने में ट्रिब्यूनल अंततः कुछ भी तय नहीं करता है और कोई निष्पादन योग्य या ऑपरेटिव आदेश पारित नहीं करता है। नियम 93 (1) के तहत निषिद्ध दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति देने का निर्णय अंतिम और अपरिवर्तनीय है और इससे लौटे हुए उम्मीदवार को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है यदि किसी दिए गए मामले में वह आयोग को निरीक्षण की अनुमति न देने के लिए मनाने का हकदार है।

61. *पैरी-जोन्स के* मामले (29), (सुप्रा), *वाइसमैन के मामले* (28) में निर्धारित कानून का पालन किया गया था। कोर्ट ऑफ अपील के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या सॉलिसिटर लेखा नियमों के नियम 11 के तहत काम करने वाली लॉ सोसाइटी सॉलिसिटर को अपने बही-खातों आदि को प्रस्तुत करने का निर्देश देने से पहले उसे सुनने की हकदार थी। सॉलिसिटर ने तर्क दिया था कि जांच लेखाकार को कुछ दस्तावेजों का निरीक्षण करने का अधिकार नहीं था और सॉलिसिटर को देखने का अधिकार था।

रिकॉर्ड पेश करने से पहले उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई क्योंकि जांच यह थी कि क्या ***प्रथम दृष्टया*** मामला था, प्राकृतिक न्याय के नियम लागू नहीं होते थे, इसलिए मुझे सॉलिसिटर को दी जा रही शिकायत की सूचना की आवश्यकता होती है, और क्योंकि आवश्यक निरीक्षण न्यायिक या अर्ध-न्यायिक जांच नहीं थी, बल्कि एक जांच थी जिसे लॉ सोसाइटी की परिषद बिना किसी उकसावे के करने का हकदार थी। एक बार फिर ***पैरी-जोन्स के मामले*** में निर्धारित कानून, हमारे उद्देश्यों के लिए बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। सॉलिसिटर की पुस्तकों और रिकॉर्ड को सॉलिसिटर लेखा नियमों के तहत निरीक्षण करने का अधिकार था। यह नियम 93(2) में उल्लिखित दस्तावेजों के निरीक्षण जैसा मामला था। इसके अलावा, जिस स्तर पर पुस्तकों या दस्तावेजों को देखा जाना था, वह जांच का था और इस आशय के विशेष वैधानिक प्रावधान के अभाव में, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ किसी भी वैधानिक कार्रवाई के लिए आधिकारिक एजेंसी द्वारा एकत्र की जाने वाली किसी भी सामग्री पर कोई रोक नहीं है।

62. तीसरा मामला वाइसमैन के मामले ***में अपील की अदालत के फैसले के खिलाफ अपील पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का निर्णय था*** अपीलीय न्यायालय के निर्णय को इस टिप्पणी के साथ बरकरार रखा गया था कि वित्त अधिनियम, 1960 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए और करदाताओं को जवाबी बयान देखने और जवाब देने का अधिकार देने के लिए इसका विस्तार नहीं करते हुए, ट्रिब्यूनल अनुचित रूप से या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य नहीं कर रहा था। इस मामले के संबंध में आगे कुछ भी कहना आवश्यक नहीं है जो मेरे द्वारा वाइसमैन के मामले में अपील की अदालत के फैसले के संबंध में पहले ही देखा जा चुका ***है*** (28)। इसलिए, तीन अंग्रेजी मामलों में से कोई भी प्रतिवादी के लिए कोई फायदा नहीं है।

63. तत्पश्चात् यह आग्रह किया गया कि किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता जो कार्यवाही में पक्षकार नहीं है। यदि यह कानून होता, तो उस पक्ष को कार्यवाही में शामिल न करके प्राकृतिक न्याय के नियमों का उल्लंघन करना बहुत आसान होता, जिसके निर्णय से प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्यवाही के लिए आवश्यक पक्ष नहीं है, लेकिन किसी भी तरह से उसके निर्णय से प्रभावित होने की संभावना है, तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत एक बार में आकर्षित होंगे। एक स्पष्टवादी; खाया है बी। चुनाव आयोग के इस फैसले से कि उसके पक्ष में डाले गए मतपत्रों को किसी और को सौंप दिया जाए। यदि वह इस तरह के निरीक्षण से प्रभावित होने की संभावना नहीं थी, तो चुनाव दाखिल करने के प्रयोजनों के लिए निरीक्षण की अनुमति देने में कोई मज़ा नहीं होगा। वह

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(नरूला, जे।

जिस क्षण यह स्थापित हो जाता है कि वह इस तरह के निर्णय से प्रभावित होने की संभावना है और आरोपों के आधार पर निर्णय लिया जाना है, तो लौटाए गए उम्मीदवार को सुनवाई का अवसर देना नितांत आवश्यक हो जाता है _। प्रतिवादी के वकील ने आग्रह किया कि *ऑडी अल्टरनेटम पार्टम का सिद्धांत* ऐसे मामले में लागू नहीं होता है जिसमें दो पक्षों के बीच कोई विवाद नहीं है। पी. एल. लखनपाल बनाम *भारत संघ*[31] मामले में दिए गए फैसले को देखते हुए इस तर्क को नकारात्मक रूप दिया जाना चाहिए, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि भले ही कोई पारस्परिक संबंध न *हो और* प्रतियोगिता उस पक्ष के बीच हो जो कार्य करने के लिए दबाव डाल रहा है, और दूसरा इसका विरोध कर रहा है, प्राधिकरण का अंतिम निर्धारण अभी तक एक *अर्ध-न्यायिक* अधिनियम होगा बशर्ते प्राधिकरण को न्यायिक रूप से कार्य करने की आवश्यकता हो। इस विषय पर *ए.के. क्राइपक के मामले* में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून भी प्रासंगिक है। इसका विस्तृत संदर्भ पहले ही दिया जा चुका है।

64. ऊपर मेरे द्वारा जिस कानून का संदर्भ दिया गया है, उसे ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि आयोग का यह कर्तव्य था कि वह याचिकाकर्ता को यह दिखाने के लिए राजी करे कि वह निषिद्ध दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति न दे या तो यह दिखाकर कि प्रतिवादी द्वारा लगाए गए आरोपों में *प्रथम दृष्टया* कोई सच्चाई नहीं है या अन्यथा लंबे समय तक दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। मामले की जांच की जा रही है। मेरी यह भी राय है कि भले ही आयोग कानून के मामले के रूप में बाध्य नहीं है, फिर भी लौटाए गए उम्मीदवार या निरीक्षण की अनुमति देने वाले आदेश से सीधे प्रभावित होने की संभावना वाले किसी अन्य व्यक्ति को अवसर देना, इस मामले में आयोग का कर्तव्य था, और ऐसे अन्य मामलों में आयोग का कर्तव्य होगा जहां मामले पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय है। प्रश्न को निष्पक्ष रूप से तय करने के लिए लौटे उम्मीदवार को ऐसा अवसर देना। मैं इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के निर्णय से दृढ़ हूं, जिसमें क्षेत्रीय *परिवहन प्राधिकरण, पटियाला में और एक अन्य* बनाम *गुर-बचन सिंह*[32] वर्तमान मामले में मेरे चार विद्वान भाइयों में से तीन पक्षकार थे, क्षेत्रीय *परिवहन प्राधिकरण, पटियाला में और एक अन्य* प क्षकार थे।पूर्ण पीठ को भेजा गया सवाल यह था कि क्या मोटर वाहन अधिनियम (1939 का 4) की धारा 62 के तहत दिए जाने वाले अस्थायी स्टेज कैरिज परमिट के लिए आवेदक के अलावा अन्य व्यक्तियों को नोटिस देने की आवश्यकता है। पूर्ण पीठ (डीके महाजन, गुरदेव सिंह, बाल राज तुली और बी.एस.

ढिल्लों, जेजे और मैंने इस प्रश्न का सर्वसम्मत उत्तर नकारात्मक में देते हुए नीचे लिखा है: –

> पीठ ने कहा, "लेकिन यह धारा (मोटर वाहन अधिनियम की धारा 62) परिवहन प्राधिकरण को नोटिस जारी करने या इच्छुक पक्षों द्वारा दिए गए अभ्यावेदन, यदि

[31] A.I.R 1967 S.C 1507
[32] I.L.R. 1971 IT Pb. & Hr. 94.

कोई हो, पर विचार करने से नहीं रोकती है। हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि परमिट देने से संबंधित कार्यवाही *अर्ध-न्यायिक* प्रकृति की है और इसे प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप संचालित किया जाना चाहिए, जो नियम धारा 62 द्वारा बाहर नहीं किए गए हैं, उन मामलों में जहां अस्थायी आवश्यकता तत्काल नहीं है या तत्काल प्रकृति की है और मार्ग या क्षेत्र के साथ या उसके आसपास पहले से ही परिवहन सुविधाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों को सुनने का समय है। जो अस्थायी परमिट जारी करने का इरादा है, यह न केवल समीचीन है, बल्कि उचित है कि ऐसे व्यक्तियों को एक नोटिस जारी किया जाना चाहिए ताकि उन्हें अस्थायी परमिट देने से पहले अभ्यावेदन देने और उस पर विचार करने के लिए सुनवाई का अवसर मिल सके।

65. उपर्युक्त पूर्ण पीठ के निर्णय के अधिकार पर, मैं यह कहूंगा कि ऐसे मामलों में जहां निरीक्षण की अनुमति देने की आवश्यकता इतनी तत्काल या इतनी दबाव और तत्काल प्रकृति की नहीं है कि लौटाए गए उम्मीदवार को बुलाने या सुनने की अनुमति न दी जाए, और ऐसी कोई तात्कालिकता नहीं है जो निरीक्षण के उद्देश्यों को विफल कर दे यदि लौटा हुआ उम्मीदवार को अवसर दिया जाता है, यह न केवल समीचीन बल्कि उचित होगा कि लौटाए गए उम्मीदवार को निरीक्षण के लिए आवेदन की सूचना जारी की जानी चाहिए ताकि उसे अभ्यावेदन देने का अवसर मिल सके और निरीक्षण की अनुमति देने से पहले मुद्दे पर विचार करने के लिए उसे सुना जा सके। हाथ में मामला वह है जो उस नियम के भीतर आता है और उसके अपवाद के भीतर नहीं आता है। निरीक्षण 15 मार्च, 1971 के लिए लागू किया गया था। निरीक्षण का घोषित और स्वीकृत उद्देश्य चुनाव याचिका दायर करने के लिए सामग्री इकट्ठा करना था। चुनाव याचिका दायर करने की सीमा 26 अप्रैल, 1971 तक थी, वास्तव में याचिका केवल सीमा के अंतिम दिन दायर की गई है। याचिकाकर्ता को नोटिस देने में कुछ दिनों से अधिक समय नहीं लगता। लंबे समय तक जांच की जरूरत नहीं थी। श्री सिब्बल ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को अवसर दिया गया होता, तो वह आयोग ® के समक्ष रिटर्निंग ओसेर के आदेशों को रखता, और नियुक्त पर्यवेक्षक को भी सूचित करता।

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(नरूला, जे।

आयोग द्वारा और लगभग आधे घंटे के दौरान कुछ अन्य तथ्यों को इंगित किया होगा। याचिकाकर्ता को इस तरह के अवसर से भी वंचित किया गया है, जबकि निर्णय लेने के लिए पर्याप्त समय था, कम से कम खेद का विषय है।

66. एक स्तर पर श्री सिब्बल ने तर्क दिया था कि भले ही आयोग द्वारा कानूनी तरीके से निरीक्षण की अनुमति दी जाती है, लेकिन निरीक्षण, चाहे किसी भी कारण से, चुनाव याचिका दायर करने से पहले नहीं किया जाता है, आयोग का आदेश निष्पादन योग्य नहीं हो जाता है, और उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव याचिका पर विचार किए जाने के कारण, निरीक्षण का मामला अदालत पर छोड़ दिया जाना चाहिए और आयोग के आदेश को माना जाना चाहिए। कम हो गया है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि हालांकि नियम 93 में ऐसा कोई स्पष्ट निषेध नहीं है, लेकिन आयोग चुनाव याचिका दायर होने के बाद निरीक्षण की अनुमति नहीं दे सकता है। श्री सेन ने न केवल इस निवेदन की शुद्धता पर सवाल नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने कहा कि चुनाव याचिका लंबित होने के बाद निरीक्षण की अनुमति देना उच्च न्यायालय की अवमानना होगी। यद्यपि मैं इस प्रस्ताव की आगे और सावधानीपूर्वक जांच किए बिना उस हद तक जाने के लिए तैयार नहीं हो सकता हूं, मैं आयोग के आक्षेपित आदेश के कार्यान्वयन से पहले चुनाव याचिका दायर करने के प्रभाव पर विचार करता, अगर मैंने अन्यथा आदेश को अवैध और गैर-वैध नहीं माना होता । वर्तमान मामले में इस शैक्षणिक मामले में जाना अनावश्यक है।

67. अब निर्णय के लिए एकमात्र बिंदु श्री अशोक सेन द्वारा प्रस्तुत अंतिम तर्क है, जो प्रतिवादी के विद्वान वरिष्ठ वकील हैं, और उनके उत्तराधिकारी श्री जीएल सांघी, एडवोकेट द्वारा प्रबलित हैं। दोनों ने दलील दी कि भले ही यह पाया जाता है कि आयोग का आदेश या तो नियम 93 द्वारा अधिकृत नहीं है या अन्यथा प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन करने के कारण अमान्य है या कारणों से समर्थित नहीं होने के कारण अयोग्य पाया जाता है, फिर भी याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती है क्योंकि उसके किसी भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। आगे यह आग्रह किया गया कि भले ही प्रतिवादी के खिलाफ सब कुछ तय किया जाता है और यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता आयोग के आदेश से व्यथित व्यक्ति है, फिर भी याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि निरीक्षण के आदेश से कोई अन्याय नहीं हुआ है, याचिकाकर्ता के साथ तो बिल्कुल भी अन्याय नहीं हुआ है। इस संबंध में श्री सांघी ने जिस पहले मामले का उल्लेख किया है, वह उच्चतम न्यायालय का निर्णय है।

उड़ीसा राज्य बनाम मदन गोपाल रूंगटा[33] । जब
संविधान के अनुच्छेद 226 के दायरे से निपटते हुए, कानिया, सीजे, (जिन्होंने न्यायालय का निर्णय

[33] A.I.R 1952 S.C 12- (1952) S.C.R 28

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(नरूला, जे।

तैयार किया) ने कहा कि यद्यपि मौलिक अधिकारों के आधार पर रिट या निर्देश जारी करने के अलावा, उच्च न्यायालय के पास किसी अन्य उद्देश्य के लिए रिट जारी करने या समान निर्देश देने का भी अधिकार है; अनुच्छेद 226 के अंतिम शब्दों को उसी के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो उससे पहले है; और इसलिए, अधिकार का अस्तित्व उस अनुच्छेद के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग का आधार है।

68. इसके बाद उड़ीसा राज्य *बनाम राम* चंद्र देव आदि[34] *मामले में उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों पर भरोसा किया गया* कि यद्यपि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निस्संदेह बहुत व्यापक है और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी उस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय द्वारा उचित रिट जारी की जा सकती है। और इस अर्थ में, एक

जो पक्ष उच्च न्यायालय के विशेष अधिकार क्षेत्र का उपयोग करता है, वह केवल अपने ऐसे अधिकारों के अवैध अतिक्रमण के मामलों तक ही सीमित है, अनुच्छेद के अंतिम शब्दों से संकेत मिलता है कि इससे पहले कि किसी पार्टी के पक्ष में रिट या आदेश जारी किया जा सके, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि पार्टी के पास अधिकार है और उक्त अधिकार पर अवैध रूप से आक्रमण या धमकी दी गई है। यह उस संदर्भ में था कि यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एक अधिकार का अस्तित्व अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका की नींव है। श्री सांघी ने मंगनभाई ईश्वरभाई पटेल बनाम भारत संघ और एक अन्य[35] मामले में *उच्चतम न्यायालय के उनके न्यायमूर्ति के फैसले की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया* । उस मामले में, सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था। स्वाभाविक रूप से, इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट एक पार्टी के उदाहरण को छोड़कर एक रिट जारी करने से इनकार करता है, जिसके मौलिक अधिकारों पर सीधे और काफी हद तक आक्रमण किया जाता है या इस तरह से आक्रमण किए जाने का खतरा है। आगे यह देखा गया कि रिट-याचिकाकर्ताओं # उन्हें भविष्य में उनके मौलिक अधिकारों से वंचित किए जाने की केवल आशंका अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह मामला एक अंतरराष्ट्रीय संधि के आधार पर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद में दिए गए मध्यस्थता फैसले के अनुसरण में कच्छ क्षेत्र में पाकिस्तान को भूमि सौंपने से संबंधित है। उस मामले से निपटना आवश्यक है क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के दायरे में बहुत अंतर है।

एक तरफ और दूसरी तरफ अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का अधिक व्यापक अधिकार क्षेत्र है।

69. कलकत्ता गैस कंपनी (प्रोप्रायरी) लिमिटेड बनाम *पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य* [36]के *मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का भी उल्लेख किया गया*।, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रश्न सीधे विचार के लिए आता है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि उक्त अनुच्छेद उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए निर्देश

[34] A.I.R 1964 S.C 685
[35] A.I.R 1969 S.C 783
[36] A.I.R 1962 S.C. 1044

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(नरूला, जे।

और रिट जारी करने के लिए बहुत व्यापक शक्ति प्रदान करता है। आगे यह देखा गया कि अनुच्छेद 226 के तहत लागू किया जा सकने वाला कानूनी अधिकार आमतौर पर याचिकाकर्ता का अधिकार होना चाहिए जो अपने अधिकार के उल्लंघन की शिकायत करता है और राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है। उस संबंध में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "अनुच्छेद 226 के तहत लागू किया जा सकने वाला अधिकार आमतौर पर याचिकाकर्ता का व्यक्तिगत या व्यक्तिगत अधिकार भी होगा, हालांकि बंदी *प्रत्यक्षीकरण* या क्को-वारंटो *जैसी कुछ रिट के मामले में,* इस नियम को शिथिल या संशोधित करना पड़ सकता है। उस मामले में एक क़ानून के अधिनियमन द्वारा याचिकाकर्ता के अधिकार (एक समझौते के आधार पर) से वंचित करने को अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप को उचित ठहराने के लिए माना गया था।

70. उच्चतम न्यायालय का अंतिम निर्णय, जिस पर श्री सांघी ने हमारा ध्यान आकृष्ट किया था, वह था *दीनबंधु साहू* बनाम भारत *जदुमोनी मंगराज और अन्य*[37]। इस मामले पर श्री सांघी द्वारा बहुत जोर दिया गया था क्योंकि इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चुनाव की कार्यवाही में मुकदमेबाजी के तहत अधिकार सामान्य कानूनी अधिकार नहीं हैं, बल्कि ऐसे अधिकार हैं जो कानूनों के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी हैं और उन अधिकारों की सीमा उन विधियों के संदर्भ में निर्धारित की जानी चाहिए जो उन्हें बनाते हैं। हालांकि, उपर्युक्त टिप्पणियां याचिकाकर्ता के खिलाफ नहीं जाती हैं क्योंकि उन्होंने किसी भी सामान्य कानूनी अधिकारों का दावा नहीं किया है, बल्कि केवल यह दावा कर रहे हैं कि लागू आदेश आयोग द्वारा नियम 93 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र की सीमित सीमाओं के भीतर पारित नहीं किया जा सकता है। आदेश पर सवाल उठाने का उनका अधिकार वैधानिक नियम से आता है न कि इससे स्वतंत्र रूप से। जहां तक चुनाव याचिका दायर करने में देरी (पुरानी प्रक्रिया के तहत) को माफ करने से पहले आयोग द्वारा वापस आए उम्मीदवार को नोटिस देने की आवश्यकता का संबंध है, *दीनबंधु साहू के मामले* में सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे लिए कोई मददगार नहीं है क्योंकि यह मामला चुनाव न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया था। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी की देनदारियां या अधिकार क्षेत्र उसमें उत्पन्न हुए।

(71) न ही हम चुंडिकुली के अल्फ्रेड थंगराज दुरयप्पा बनाम *डब्ल्यू जे फर्नांडो और अन्य*[38] *में* प्रिवी काउंसिल के फैसले में प्रतिवादी के पक्ष में कुछ भी पा सकते हैं / इसके विपरीत रिज वी के मामले के संदर्भ में उनके न्यायमूर्ति की निम्नलिखित टिप्पणियां *हैं* । *बाल्डविन* (सुप्रा) महत्वपूर्ण हैं: –

"उस मामले में *रिज बनाम बाल्डविन* (16), कोई प्रयास नहीं किया गया था? उन मामलों का एक विस्तृत वर्गीकरण देने के लिए जहां सिद्धांत *ऑडी अल्टरम पार्टम लागू* किया जाना

[37] (1955) S.C.R 140
[38] (1967) 2 A.C 337

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।

(नरूला, जे।

चाहिए। उनके न्यायमूर्ति की राय में ऐसा करना गलत होगा। कार्यालय से बर्खास्तगी, वंचित जैसे बाहरी जाने-माने मामले

संपत्ति का निर्धारण और क्लबों से निष्कासन, एक विशाल क्षेत्र है जहां सिद्धांत केवल अधिकांश पर लागू किया जा सकता है।

सामान्य विचार।

प्रसिद्ध कक्षाओं के मामलों की कोई सामान्य नियम नहीं हो

प्रावधान की भाषा के अलावा सामान्य सिद्धांत के अनुप्रयोग के रूप में निर्धारित किया जाए। उनके न्यायमूर्ति की राय में तीन मामले हैं जिन्हें हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए जब यह विचार किया जाना चाहिए कि सिद्धांत को लागू किया जाना चाहिए या नहीं। ये तीन मामले हैं: पहला, संपत्ति की प्रकृति क्या है, पद धारण किया गया है, प्राप्त स्थिति या अन्याय के शिकायतकर्ता द्वारा की जाने वाली सेवाएं। दूसरे, किन परिस्थितियों में या किन अवसरों पर नियंत्रण के उपाय का उपयोग करने का हकदार होने का दावा करने वाला व्यक्ति हस्तक्षेप करने का हकदार है। तीसरा, जब हस्तक्षेप करने का अधिकार साबित हो जाता है, तो वास्तव में दूसरे पर क्या प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। इन सभी मामलों पर विचार करने के बाद ही सिद्धांत के अनुप्रयोग के प्रश्न को ठीक से निर्धारित किया जा सकता है।

(चौंतीस) (1967)2 ए.सी. 337. :

प्रिवी काउंसिल के न्यायमूर्ति ने जिन तीन मामलों को ध्यान में रखने का निर्देश दिया था, उनमें से कम से कम दो (दूसरा और तीसरा) तत्काल मामले में लागू होते हैं। सबसे पहले, याचिकाकर्ता किसी भी नियंत्रण उपाय का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा या बाद के किसी भी चरण में निरीक्षण के आदेश में हस्तक्षेप करने का हकदार नहीं होगा। दूसरे, आदेश एक प्रकार का है जिसे यदि इंटरसेप्ट नहीं किया जाता है तो लौटने वाले उम्मीदवार को अपूरणीय क्षति हो सकती है, जिसे बाद में ठीक करना संभव नहीं हो सकता है, भले ही यह कुछ उचित कार्यवाही में पाया जाए कि आदेश पारित नहीं किया जा सकता है:

72. फिरोजशाह गांधी *बनाम* ***एच*** *एम. सीरवई, महाराष्ट्र, बॉम्बे के एडवोकेट-जनरल*[39] मामले में फैसले के पैराग्राफ 12 में की गई टिप्पणियों के आधार पर आग्रह किया गया था कि याचिकाकर्ता निरीक्षण के लिए आवेदन पर निर्णय से निराश हो सकता है, लेकिन उसे उस आदेश के खिलाफ "पीड़ित व्यक्ति" नहीं कहा जा सकता है क्योंकि एक व्यक्ति केवल तभी पीड़ित हो सकता है जब वह उस लाभ से निराश हो जो उसे प्राप्त होता यदि आदेश दूसरे रास्ते पर चला जाता। यह तर्क मुझे पूरी तरह से बिना किसी सार के प्रतीत होता है। यदि निरीक्षण की अनुमति नहीं दी गई होती, तो याचिकाकर्ता को वास्तव में अपने पक्ष में डाले गए मतपत्रों को देखने की अनुमति नहीं देने का लाभ मिलता। तब यह प्रस्तुत किया गया था कि निरीक्षण के आदेश से याचिकाकर्ता को कानूनी शिकायत नहीं होती है क्योंकि उसे गलत तरीके से किसी भी चीज से वंचित नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता को उस पद के लिए चुने जाने के बाद पांच साल तक लोकसभा के सदस्य के रूप में बने रहने का अधिकार है, जब तक कि चुनाव याचिका में सक्षम न्यायालय द्वारा उसका चुनाव रद्द नहीं किया जाता है। निरीक्षण की अनुमति देकर, आयोग निश्चित रूप से उस अधिकार के शांतिपूर्ण आनंद को खतरे में डाल रहा है और धमकी दे रहा है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि यह सफलतापूर्वक कैसे तर्क दिया जा सकता है कि इन तथ्यों के बावजूद, याचिकाकर्ता आक्षेपित आदेश से पीड़ित व्यक्ति नहीं है। प्रतिवादी की ओर से यह आग्रह किया गया था कि याचिकाकर्ता को उसी तरह से पीड़ित नहीं किया जा सकता है जैसे कि एक कंपनी या उसके निदेशकों को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ निरीक्षण किए जाने के बाद उसके द्वारा प्रस्तुत रिटर्न से व्यथित नहीं किया जा सकता है। यह तर्क इस साधारण कारण से भ्रामक है कि जिन दस्तावेजों का कंपनी अधिनियम के तहत अधिकार के मामले के रूप में निरीक्षण किया जा सकता है, वे केवल नियम 93 (2) में उल्लिखित दस्तावेजों के बराबर हो सकते हैं, न कि नियम 93 (1) के लिए जिसमें

[39] A.I.R 1971 S.C 385

निरीक्षण के खिलाफ एक सामान्य निषेध शामिल है।

73. तब एक तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि आक्षेपित आदेश के परिणामस्वरूप कोई स्पष्ट अन्याय नहीं हुआ है। प्रतिवादी संभवतः सर्टिओररी की प्रकृति में रिट देने के मामलों के बारे में सोच रहा है, जहां अक्सर टिप्पणियां की गई हैं कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय से राहत प्राप्त करने के लिए याचिकाकर्ता को पात्र बनाने के लिए उसे यह दिखाना होगा कि अधिकार क्षेत्र के दोष या रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि के अलावा, आक्षेपित आदेश के परिणामस्वरूप अन्याय हुआ है। इस मामले में एकमात्र हमला इस आधार पर आदेश की वैधता पर है कि इसे कानून के अनुसार पारित नहीं किया गया है। जोगिंदर सिंह और अन्य बनाम ***डिप्टी कस्टोडियन जनरल, इवैक्यूप्रॉपर्टी, मसूरी और अन्य***[40] मामले में सुप्रीम कोर्ट के उनके न्यायमूर्ति द्वारा इसे आधिकारिक रूप से निर्धारित किया गया ***है***।कहा कि जहां एक हीन न्यायाधिकरण अपने अधिकार क्षेत्र से परे काम करता है, तो उसकी कार्रवाई से उस पक्ष के साथ अन्याय होता है जिसके खिलाफ कार्रवाई की गई है, क्योंकि न्याय कानून के अनुसार किया जाना चाहिए। एक बार जब यह पाया जाता है कि लागू आदेश कानून के अनुसार पारित नहीं किया गया है, तो हमें यह मानना चाहिए कि इस तरह किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ है जो या तो प्रभावित है या उससे पीड़ित है। यदि हम इस संबंध में श्री सांघी द्वारा कही गई बातों को स्वीकार कर लें, तो निरीक्षण की अनुमति देने के अपने निर्णय के कारणों को दर्ज करना आयोग के लिए अनिवार्य बनाने का उद्देश्य पूरी तरह से विफल हो जाएगा क्योंकि नियम 93 के तहत पारित पूरी तरह से अवैध आदेश भी अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी कार्यवाही में सवाल उठाने योग्य नहीं होगा। जब हमने प्रतिवादी के वकील से पूछा कि क्या वह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हमले से बचने के कारणों से निरीक्षण और पुन: उपयोग की अनुमति देने वाले आयोग के आदेश पर विचार करेंगे, तो वह स्वाभाविक रूप से हां में जवाब नहीं दे सका।

74. सामान्य नियम अच्छी तरह से तय है, जैसा कि जगन नाथ बनाम ***जसवंत सिंह और अन्य***[41] ***में माना गया*** है। कि चुनाव कानून की वैधानिक आवश्यकताओं का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और यह कि एक चुनाव मुकाबला इक्विटी में एक मुकदमा नहीं है, बल्कि एक विशुद्ध रूप से वैधानिक कार्यवाही है जो सामान्य कानून के लिए अज्ञात है और अदालत के पास कोई सामान्य कानून

[40] CIA No. 4ST Of 1958 decided on 26th march, 1962.
[41] A.I.R 1954 S.C 210

शक्ति नहीं है। जगन ***नाथ मामले*** (41) में सुप्रीम कोर्ट द्वारा "प्राकृतिक न्याय के अच्छी तरह से स्थापित ठोस सिद्धांत" का भी उल्लेख किया गया था कि चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार की सफलता को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए और इस तरह के हस्तक्षेप की मांग करने के लिए शुरू की गई किसी भी कार्यवाही को संबंधित वैधानिक प्रावधानों की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। *भारत संघ बनाम भारत-अफगान एजेंसियां* (42) में, उच्चतम न्यायालय की न्यायमूर्ति ने यहां तक कहा कि "नियमों द्वारा वस्त्र आयुक्त में निहित अधिकार, भले ही चरित्र में कार्यपालिका अपनी प्रकृति से मामले (आयात कोटा के) से निपटने के लिए एक प्राधिकरण था, जो न्याय और निष्पक्ष खेल की मूल अवधारणा के अनुरूप था। और यह कि "यदि उन्होंने एक ऐसा आदेश दिया जो न्याय और निष्पक्ष खेल की मूल अवधारणा के अनुकूल नहीं था, तो उनकी कार्यवाही अदालतों (अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों) द्वारा जांच और सुधार के लिए खुली थी। *इंडो अफगान* एजेंसियों (42) में, यह आगे कहा गया था कि भले ही किसी प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति प्रकृति में कार्यकारी थी, उच्च न्यायालयों के पास उचित मामलों में विभागीय अधिकारियों पर संबंधित नियमों (उस मामले में आयात योजनाओं) द्वारा लगाए गए दायित्वों के प्रदर्शन को मजबूर करने की शक्ति है।

75. नियम 93 चुनाव कानून का हिस्सा है। इसके परंतुक की आवश्यकताएं अनिवार्य हैं और कारण न बताना उप-नियम (1) के तहत निरीक्षण की अनुमति देने के लिए आयोग के अधिकार क्षेत्र की जड़ पर हमला करता है। वैधानिक आवश्यकता का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए जैसा कि *जगन नाथ के मामले* में कहा गया है । निषिद्ध दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति देना निश्चित रूप से चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार की सफलता को कानून द्वारा अनुमति नहीं देने वाले तरीके से खतरे में डालना होगा। यहां तक कि अगर निषिद्ध दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति देने वाला आदेश एक कार्यकारी है, तो यह न्यायालय का कर्तव्य होगा कि वह इसे रद्द करे (i) यदि यह परंतुक (ए) की अनिवार्य आवश्यकता के सख्त अनुपालन में कमी है या (ii) यदि इसे इस तरह से पारित किया गया है जो न्याय और निष्पक्ष खेल की मूल अवधारणा के अनुरूप नहीं है, जिसमें से ऑडी *अल्टरम पार्टम प्राथमिक* आधार है। इसलिए, मैं इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निहित असाधारण शक्ति से वंचित करने में असमर्थ हूं।

76. सांघी ने आधे-अधूरे मन से दलील दी कि याचिका खारिज की जानी चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता ने चुनाव में अन्य उम्मीदवारों को प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किया है। जाहिर है कि चुनाव में अन्य उम्मीदवार इस मामले में न तो आवश्यक हैं और न ही उचित पक्ष हैं। उन्हें इस याचिका के परिणाम में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह तर्क बिना किसी तथ्य के प्रतीत होता है।

77. श्री सांघी द्वारा दिया गया एक अन्य निवेदन यह था कि यदि हम पाते हैं कि मतदाता सूची की चिह्नित प्रति के निरीक्षण की अनुमति देने के आदेश से गोपनीयता के नियम का उल्लंघन होने की संभावना है, तो हमें आदेश के केवल उस हिस्से को रद्द कर देना चाहिए जो बाकी आदेश से अलग है। इस विवाद के गुण-दोष को ध्यान में रखते हुए मैंने जो विचार किया है, उसमें काल्पनिक प्रस्ताव के इस बंधन में पड़ना अनावश्यक है।

78. एस ए डी स्मिथ (दूसरा संस्करण) द्वारा प्रशासनिक कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा में इस निवेदन के समर्थन में दिए गए अंश का भी उल्लेख किया गया था कि भले ही हम पाते हैं कि आक्षेपित आदेश बुरा है क्योंकि यह कारणों से समर्थित नहीं है, हमें निम्नलिखित शब्दों में उस पाठ्य पुस्तक में सुझाए गए पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए -

"जहां क़ानून द्वारा कारण देना आवश्यक है, वहां न्यायाधिकरण को पर्याप्त रूप से समझदार कारण देने के लिए मजबूर करने के लिए ***परमादेश*** को झूठ बोलना चाहिए। इस तरह का कोई आदेश जारी करना अनावश्यक है क्योंकि लागू आदेश को कानूनी कारणों से समर्थित नहीं होने के कारण रद्द किया जा रहा है, और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना इसे पारित किया गया है।

79. याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए तर्क संख्या (4), (5), और (6) पर मेरे द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, मैं इस याचिका को स्वीकार करता हूं और लागत के बारे में किसी भी आदेश के बिना आयोग के आक्षेपित आदेश को रद्द करता हूं।

न्यायमूर्ति डी. के. महाजन

80. मुझे अपने विद्वान न्यायमूर्ति नरूला और तुली, द्वारा तैयार किए गए निर्णयों को पढ़ने का लाभ मिला है, मैं नरूला, जे द्वारा तैयार किए गए निर्णय से पूरी तरह से सहमत हूं। तुली, जे. के प्रति अत्यंत सम्मान के साथ, मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन संचालन नियमावली, 1961 के नियम 93 के अनुसार अपेक्षित कारण दिए हैं। मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि चुनाव आयोग का आदेश पूरी तरह से प्रशासनिक आदेश है।

न्यायमूर्ति बी.आर. 'तुली

(81) दिसम्बर, 1970 में लोक सभा को भंग कर दिया गया और नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया गया। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी 3 ने चुनाव लड़ा

वह कुछ अन्य उम्मीदवारों के साथ फाजिल्का संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए। मतदान 5 मार्च, 1971 को हुआ, वोटों की गिनती 10 मार्च, 1971 को शुरू हुई, और परिणाम 12 मार्च, 1971 को घोषित किए गए। याचिकाकर्ता को सफल घोषित किया गया क्योंकि उसने 1,52,653 वोट हासिल किए थे, जबकि प्रतिवादी 3 को 1,47,277 वोट मिले थे, जो उसके निकटतम प्रतिद्वंद्वी थे। यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि याचिकाकर्ता, सफल उम्मीदवार, पंजाब के मुख्यमंत्री का भाई है, जबकि प्रतिवादी 3 भारत सरकार का उप मंत्री था जब उसने चुनाव लड़ा था। प्रतिवादी 3 ने चुनाव के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कथित तौर पर किए गए कदाचार के संबंध में भारत के चुनाव आयोग को विभिन्न शिकायतें कीं। इस तरह का पहला पत्र 20 फरवरी, 1971 को लिखा गया था, और अंतिम टेलीग्राम 11 मार्च, 1971 को भेजा गया था। 8 मार्च, 1971 के पत्र में, प्रतिवादी 3 ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के लिए कहा ताकि यह देखा जा सके कि कोई कदाचार नहीं था और चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतगणना की प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया गया था। उस दिन, उन्होंने एक अन्य पत्र भी लिखा, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा कथित तौर पर किए गए कुछ कदाचारों और मतदान के दौरान विभिन्न अधिकारियों के अनुचित आचरण को गिनाया गया। प्रतिवादी 3 के अनुरोध पर, भारत के चुनाव आयोग ने श्री आरडी शर्मा को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया, जिन्होंने मतगणना के दिनों के दौरान विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा किया। परिणाम की घोषणा से पहले, प्रतिवादी 3 ने पुनर्मतगणना के लिए रिटर्निंग अधिकारी को एक आवेदन दिया, जिसे 12 मार्च, 1971 को अस्वीकार कर दिया गया था। परिणाम घोषित होने के बाद, प्रतिवादी 3 ने 15 मार्च, 1971 को अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित चुनाव पत्रों के निरीक्षण के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को एक आवेदन दिया और उसी दिन श्री एसपी सेन वर्मा, चुनाव आयोग ने उस पर निम्नलिखित आदेश पारित किया: –

> "एस. इकबाल सिंह द्वारा आवेदन में लगाए गए आरोप, यदि सही हैं, तो निस्संदेह गंभीर हैं। मैं समझता हूं कि निर्वाचन संचालन नियमावली, 1961 के नियम 93 के उप-नियम (1) में उल्लिखित दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति दी जाए। सर्वप्रथम, प्रयुक्त और अप्रयुक्त मतपत्रों का निरीक्षण किया जा सकता है और इस तरह के निरीक्षण के बाद यदि आवेदक निर्वाचक नामावली की अंकित प्रति के निरीक्षण की मांग करता है, तो उस दस्तावेज के निरीक्षण की भी अनुमति दी जा सकती है। नियम 93 (1) के परंतुक और विस्तृत निर्देशों के अनुसार एक औपचारिक आदेश तैयार किया जा सकता है।

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(तुली, जे।

और निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए जा सकते हैं।

फाजिल्का संसदीय क्षेत्र में मतपत्रों की गिनती के समय आयोग से कला पर्यवेक्षक के रूप में भेजे गए अवर सचिव श्री आरडी शर्मा फिरोजपुर जा सकते हैं और निरीक्षण के समय उपस्थित रह सकते हैं।

थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा:

उन्होंने कहा, 'आगे विचार करने पर मुझे लगता है कि चूंकि श्री आरडी शर्मा मतगणना के समय पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद थे, इसलिए आयोग के एक अन्य अधिकारी को नियम 93 के तहत दस्तावेजों के निरीक्षण के समय पर्यवेक्षक के रूप में फाजिल्का संसदीय क्षेत्र भेजा जाना चाहिए। इसलिए, श्री केवी विश्वनाथन, अवर सचिव, पराजित उम्मीदवार सरदार इकबाल सिंह द्वारा दस्तावेजों के निरीक्षण के समय फिरोजपुर के लिए रवाना हो सकते हैं। श्री आर डी शर्मा को जाने की आवश्यकता नहीं है। दोनों अधिकारियों को तदनुसार सूचित किया जा सकता है।

विभाग में कार्यरत अवर सचिव श्री केवी विश्वनाथन द्वारा एक औपचारिक आदेश तैयार किया गया था, जिसे 16 मार्च, 1971 को निर्वाचन आयोग के सचिव द्वारा अनुमोदित किया गया था और उस आदेश से जिला निर्वाचन अधिकारी, फिरोजपुर को अवगत कराया गया था, ताकि चुनाव संचालन नियमों के नियम 93 के अनुसार प्रतिवादी 3 को पी - एपर्स के निरीक्षण की अनुमति दी जा सके। 1961 (इसके बाद नियमों के रूप में संदर्भित)। जिला निर्वाचन अधिकारी ने निरीक्षण के लिए 31 मार्च, 1971 की तारीख तय की और सभी उम्मीदवारों को इसकी सूचना दी ताकि यदि वे चाहें तो वे अस्पताल के चूने पर उपस्थित हो सकें। इस आदेश के बारे में पता चलने पर, याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका दायर की, जिसमें चुनाव आयोग द्वारा पारित निरीक्षण के आदेश को चुनौती दी गई थी, जैसा कि जिला निर्वाचन अधिकारी को बताया गया था। यह याचिका 30 मार्च, 1971 को मेरे लॉर्ड महाजन, जे. और गोपाल सिंह, जे. की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आई और इसे पूर्ण पीठ द्वारा सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार इस याचिका को इस पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए रखा गया है।

82. याचिका के प्रतिवादी भारत निर्वाचन आयोग, फिरोजपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त और हारे हुए उम्मीदवार एस. इकबाल सिंह हैं। प्रतिवादी 1 और 2 द्वारा कोई रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, जबकि प्रतिवादी 3 ने अपना रिटर्न दाखिल किया है, जिस पर याचिकाकर्ता द्वारा एक प्रतिकृति दायर की गई है।

83. प्रतिवादी 3 द्वारा एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि निरीक्षण के आदेश से याचिकाकर्ता के किसी भी कानूनी या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया गया है। विद्वान

वकील ने उड़ीसा *राज्य बनाम मदन गोपाल रूंगटा पर भरोसा किया* है

"उच्च न्यायालय द्वारा रिट या निर्देश जारी करना केवल उसके फैसले पर आधारित है कि संविधान (मौलिक अधिकार) के भाग 3 के तहत पीड़ित पक्ष के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। यह रिट भी जारी कर सकता है या किसी अन्य उद्देश्य के लिए समान निर्देश दे सकता है। अनुच्छेद 226 के अंतिम शब्दों को उसी संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जो उससे पहले है। इसलिए, अधिकार का अस्तित्व इस अनुच्छेद के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग का आधार है।

सुप्रीम कोर्ट के उनके न्यायमूर्ति के एक और फैसले पर प्रतिवादी 3 के विद्वान वकील ने दृढ़ता से भरोसा किया, वह है *कलकत्ता गैस कंपनी (प्रोप्रेटरी) लिमिटेड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य,* जिसमें यह आयोजित किया गया था-

"अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को भाग एमआई द्वारा या किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए उसमें उल्लिखित प्रकृति के निर्देश और रिट जारी करने के लिए बहुत व्यापक शक्ति प्रदान करता है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि मौलिक अधिकारों का दावा करने वालों के अलावा अन्य व्यक्ति भी इसके तहत राहत पाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अनुच्छेद के संदर्भ में इसके तहत आवेदन करने के हकदार व्यक्तियों के वर्गों का वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन यह असाधारण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में निहित है कि मांगी गई राहत कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए होनी चाहिए। *उड़ीसा राज्य* versus *मदन गोपाल*, इस न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि अधिकार का अस्तित्व संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के प्रयोग का आधार है। में

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(तुली, जे।

चरणजीत लाल चौधरी versus *भारत संघ,*[42], इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 32 के तहत लागू किया जा सकने वाला कानूनी अधिकार आमतौर पर याचिकाकर्ता का अधिकार होना चाहिए जो इस तरह के अधिकार के उल्लंघन की शिकायत करता है और राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाता है। हमें ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाकर्ता के मामले में एक अलग सिद्धांत क्यों लागू होना चाहिए। अनुच्छेद 226 के तहत लागू किया जा सकने वाला अधिकार आमतौर पर याचिकाकर्ता का व्यक्तिगत या व्यक्तिगत अधिकार भी होगा, हालांकि बंदी *प्रत्यक्षीकरण* या *यथास्थिति वारंट* जैसी कुछ रिट के मामले में इस नियम में ढील या संशोधन करना पड़ सकता है।

उड़ीसा राज्य बनाम *राम चंद्र देव* में उच्चतम न्यायालय के उनके न्यायमूर्ति की निम्नलिखित टिप्पणियां पर भी भरोसा किया गया है: –

"संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निस्संदेह बहुत व्यापक है। उक्त अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए भी उचित रिट जारी की जा सकती है और इस अर्थ में, एक पार्टी जो अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के विशेष अधिकार क्षेत्र को लागू करती है, वह केवल अपने मौलिक अधिकारों के अवैध अतिक्रमण के मामलों तक ही सीमित नहीं है। लेकिन यद्यपि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र इस अर्थ में व्यापक है, अनुच्छेद के अंतिम शब्द स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि इससे पहले कि किसी पार्टी के पक्ष में एक रिट या उचित आदेश जारी किया जा सके, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि पार्टी के पास अधिकार है और उक्त अधिकार पर अवैध रूप से आक्रमण या धमकी दी गई है। इस प्रकार एक अधिकार का अस्तित्व अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका की नींव है।

84. विद्वान वकील ने तब मगनभाई ईश्वरभाई पटेल बनाम *भारत संघ और दूसरा* मामले में *उच्चतम न्यायालय के उनके न्यायमूर्ति के फैसले को हमारे ध्यान में लाया* है। जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियां होती हैं: -

पीठ ने कहा, ''सुनवाई शुरू होने से पहले हमने प्रत्येक याचिकाकर्ता से उसके दावे की बुनियाद के बारे में पूछताछ की। हमने पाया कि अधिकांश याचिकाकर्ताओं की इसमें कोई वास्तविक या स्पष्ट हिस्सेदारी नहीं थी।

(43) ए.टी.आर. 1951 एस.सी. 41= (1950) एस.सी.आर. 869.

अब इन इलाकों को पाकिस्तान का हिस्सा घोषित कर दिया गया है। इन व्यक्तियों का दावा है कि उनके पास अनुच्छेद 19 (एल) (डी), (ई) और (एफ) के तहत उन्हें गारंटीकृत मौलिक अधिकार थे, अर्थात, इन क्षेत्रों में यात्रा करने, निवास करने या बसने, या संपत्ति प्राप्त करने और रखने का अधिकार है। उनमें से किसी ने भी अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है लेकिन उनकी आशंका यह है कि भविष्य में वे इन अधिकारों से वंचित रह जाएंगे। यह, हमारे फैसले में, कानून के प्रशासन में अदालत द्वारा ध्यान देने के लिए बहुत कमजोर अधिकार है और मौलिक अधिकारों को लागू करने में अभी भी कम है। जब हमने पहले की सुनवाई में अपने विचार से अवगत कराया, तो कुछ और याचिकाकर्ता सामने आए। श्री मधु लिमये ने इस समर्थन में दलील दी कि उन्होंने इस क्षेत्र में बसने की संभावनाओं को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें वापस कर दिया गया। इस तरह वह दावा करता है कि उसने अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने का प्रयास किया था और उनका उल्लंघन किया गया था। एक अन्य पक्ष का दावा है कि इस क्षेत्र में लगभग दस साल पहले घास की भूमि का पट्टा था और अब वह इसी तरह के पट्टे प्राप्त करने के अधिकार से वंचित > है। अंत में, एक पक्ष ने दलील दी कि वह निकटवर्ती क्षेत्र में रहता है और इस प्रकार पाकिस्तान को सौंपे जाने वाले प्रस्तावित क्षेत्रों में उसकी रुचि है। इन याचिकाकर्ताओं के पास भी बहुत कम अधिकार हैं। एकमात्र व्यक्ति जो मौलिक अधिकारों से वंचित होने का दावा कर सकता है, वह श्री मधु लिमये हैं, हालांकि उनके मामले में भी संबंध अस्थायी और लगभग अल्पकालिक था। हालांकि, हमने उनकी बात सुनने का फैसला किया और जैसा कि हमें सवाल पर फैसला करना था, हमने अन्य लोगों से भी पूरक दलीलें सुनीं ताकि यथासंभव सहायता मिल सके। लेकिन हम बी नहीं कर रहे हैं। इसे इस न्यायालय के लिए एक मिसाल कायम करने के रूप में लिया जा रहा है जो ***किसी ऐसे पक्षकार के कहने को छोड़कर जिस पर प्रत्यक्ष और व्यापक रूप से आक्रमण किया गया हो या जिस पर आसन्न खतरा*** हो , उस पर परमादेश जारी करने से इनकार कर दिया जाए . इस पर हमला किया गया। इस दृष्टिकोण से हम शायद श्री मधु लिमये को छोड़कर सभी याचिकाओं को खारिज करने के लिए उचित होते। अब हम प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

यह निर्णय विद्वान वकील की मदद नहीं करता है क्योंकि उनके न्यायमूर्ति के समक्ष निर्णय के लिए याचिकाएं संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत थीं।

संविधान जो केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है।

85. दीनबंधु साकू *बनाम जदुमोनी मोंगराज और अन्य* के मामले में न्यायमूर्ति का फैसला *।विद्वान वकील द्वारा उद्धृत ,* उनके लिए कोई मदद नहीं करते हैं क्योंकि यह निर्णय इस बिंदु से संबंधित नहीं है। विद्वान वकील ने आखिरकार आदि फिरोजशाह गांधी बनाम *एच. एम. सीरवई महाराष्ट्र, बॉम्बे के एडवोकेट-जनरल* सुप्रीम कोर्ट के अपने न्यायमूर्ति के फैसले पर भरोसा किया है।, जिसमें 'पीड़ित व्यक्ति' वाक्यांश का अर्थ समझाया गया है। उस मामले में, महाधिवक्ता ने महाराष्ट्र राज्य की बीएआई परिषद की अनुशासनात्मक समिति के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि अधिवक्ता ने शिकायत की थी कि वह पेशेवर या अन्य कदाचार का दोषी नहीं था। अपील अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 37 के तहत दायर की गई थी, जिसके तहत पीड़ित व्यक्ति को अपील का अधिकार दिया गया है। यह उस संदर्भ में था कि उनके न्यायमूर्ति ने कहा कि राज्य के महाधिवक्ता को अनुशासनात्मक समिति के आदेश के खिलाफ 'असंतुष्ट व्यक्ति' नहीं कहा जा सकता है, जिसमें वकील को पेशेवर कदाचार के आरोप के खिलाफ शिकायत की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 226 में इस तरह के किसी वाक्यांश का उपयोग नहीं किया गया है। यह तय करने के लिए कि क्या याचिकाकर्ता के पास याचिका दायर करने का अधिकार है, यह देखा जाना चाहिए कि क्या आक्षेपित आदेश के परिणामस्वरूप उसे कोई चोट लगने की संभावना है। यह स्पष्ट है कि निरीक्षण का उद्देश्य, जैसा कि प्रतिवादी 3 ने चुनाव आयोग को अपने आवेदन में कहा है, उसे मतपत्रों से सामग्री इकट्ठा करने में सक्षम बनाना था ताकि याचिकाकर्ता के चुनाव को अनुचित अस्वीकृति या कुछ मतपत्रों की स्वीकृति के आधार पर रद्द करने के लिए चुनाव याचिका दायर की जा सके, जिसे धारा 100 (एल) (डी) (iii) में प्रदान किए गए चुनाव याचिका में लिया जा सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है)। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यदि निरीक्षण की अनुमति दी जाती है, तो प्रतिवादी 3 सामग्री एकत्र करने में सक्षम होगा, यदि यह मौजूद है, जिसका उपयोग चुनाव याचिका में याचिकाकर्ता के नुकसान के लिए किया जा सकता है और इसलिए, मेरी राय में, याचिकाकर्ता को निरीक्षण के आदेश से छुटकारा पाने के लिए इस याचिका को दायर करने में पर्याप्त रुचि है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने नियम 93 की *वैधता* को चुनौती दी है, जिसके तहत निरीक्षण की अनुमति दी गई है, विभिन्न आधारों पर, *अन्य बातों के साथ-साथ, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 324,* 327 और 329 (बी) और गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में अधिनियम की धारा 94 और 128 का उल्लंघन है । यह भी किया गया है

$2

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(तुली, जे।

कहा गया है कि आदेश उस नियम के अनुसार नहीं है क्योंकि कोई कारण दर्ज नहीं किया गया है। इस नियम द्वारा चुनाव आयोग में निहित निरीक्षण की अनुमति देने के अधिकार क्षेत्र को भी संविधान और अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत बताते हुए चुनौती दी गई है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निरीक्षण के आदेश का परिणाम यह होगा कि प्रतिवादी 3 को लोकसभा के लिए याचिकाकर्ता के चुनाव को चुनौती देने के लिए सामग्री इकट्ठा करने में सक्षम बनाया जाएगा और इस प्रकार उसे चुनावों में उसकी सफलता के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा जो उसने हासिल किया है। इस प्रकार याचिकाकर्ता के जीवन काल में लोकसभा के सदस्य के रूप में बने रहने के अधिकार को खतरा है, जिसमें से उसे केवल अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसरण में दायर चुनाव याचिका के माध्यम से वंचित किया जा सकता है। नियम 93 के परंतुक में निर्वाचन आयोग द्वारा निरीक्षण की अनुमति देने से पहले कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता यह भी इंगित करती है कि उस आवश्यकता का उद्देश्य यह है कि चुनाव आयोग द्वारा दर्ज किए गए कारणों को इस न्यायालय द्वारा न्यायोचित ठहराया जाना चाहिए यदि उस आदेश को इस आधार पर चुनौती दी जाती है कि कारण चुनाव कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं और उन कारणों के आधार पर, निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकी। नियम 93(1) के परंतुक (ख) के तहत सभी उम्मीदवारों या उनके विधिवत प्राधिकृत एजेंटों को किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी के समक्ष चुनाव पत्रों के उद्घाटन, निरीक्षण या उत्पादन के समय उपस्थित होने का यथोचित अवसर दिया जाना चाहिए, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि अन्य उम्मीदवारों को निरीक्षण के आदेश से व्यक्तिगत रूप से या अपने प्राधिकृत एजेंटों के माध्यम से निरीक्षण के समय उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त होता है। इस प्रावधान का एकमात्र उद्देश्य अन्य उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाना प्रतीत होता है कि निरीक्षण चुनाव आयोग के आदेश और गोपनीयता के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है और किसी भी तरह से मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ या गुप्त नहीं किया जाता है। निरीक्षण के समय उपस्थित अन्य उम्मीदवार भी उन सभी कागजातों को देख सकेंगे जिनके निरीक्षण के लिए आवेदक द्वारा निरीक्षण की मांग की गई है और वे उन मतपत्रों के संबंध में अपने स्वयं के नोट्स बनाने में सक्षम होंगे जिन पर आवेदक द्वारा निरीक्षण के लिए आपत्ति किए जाने की संभावना है। निरीक्षण का आदेश अन्य उम्मीदवारों के निरीक्षण के समय उपस्थित रहने के अधिकार को अस्तित्व में लाता है और वे अच्छी तरह से शिकायत कर सकते हैं कि उन्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और निरीक्षण में भाग लेने में खर्च नहीं करना चाहिए क्योंकि निरीक्षण का आदेश वैध नहीं है या यह नियम 93 के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। इस प्रकार नियम 93 में निहित है कि

लौटा हुआ उम्मीदवार संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका को बनाए रख सकता है जिसमें चुनाव आयोग द्वारा पारित निरीक्षण के आदेश को इसकी अयोग्यता या अवैधता के आधार पर चुनौती दी गई है। इसलिए, मुझे प्रतिवादी 3 की ओर से उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति में कोई दम नहीं लगता है और इसे हटा दिया जाता है।

86. एक अन्य प्रारंभिक आपत्ति यह है कि चुनाव आयोग द्वारा पारित निरीक्षण का आदेश एक प्रशासनिक आदेश है और इसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती है। यह आपत्ति फिर से बिना किसी बल के है। अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी प्राधिकारी द्वारा पारित किसी भी आदेश को चुनौती दी जा सकती है बशर्ते याचिकाकर्ता को इसके परिणामस्वरूप कुछ चोट लगने की संभावना हो। मैंने पहले ही कहा है कि याचिकाकर्ता को इस याचिका को बनाए रखने का अधिकार है और इस कारण से भले ही लागू आदेश एक प्रशासनिक हो, याचिका सुनवाई योग्य है।

87. याचिकाकर्ता के वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि नियम 93 संविधान के अनुच्छेद 324, 327 और 329 (बी) के प्रावधानों के विपरीत है। तर्क यह है कि अनुच्छेद 324 के तहत, चुनाव आयोग को संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों और संविधान के तहत आयोजित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति के साथ निहित किया जा सकता है। और आयोग में कोई और शक्तियां निहित नहीं की जा सकती हैं। मुझे खेद है कि मैं उस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता। अनुच्छेद 324 एक निर्वाचन आयोग का सृजन करता है जिसे संसद और राज्यों के विधानमंडलों के निर्वाचनों का समग्र प्रभारी होना है और उसे निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और उसके सभी निर्वाचनों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग करना होता है। ये शक्तियां संविधान द्वारा चुनाव आयोग में निहित की गई हैं और इन्हें किसी अन्य प्राधिकरण में निहित नहीं किया जा सकता है। तथापि, यह अनुच्छेद संसद को निर्वाचन आयोग में कोई अन्य शक्ति प्रदान करने से नहीं रोकता है। यह तर्क कि परिणाम की घोषणा के साथ चुनाव समाप्त हो जाते हैं और उसके बाद चुनाव आयोग का चुनावों से संबंधित कागजात या चुनावों आदि के संबंध में विवादों पर कोई नियंत्रण नहीं हो सकता है, किसी भी आधार से रहित है क्योंकि उल्लिखित चुनाव पत्र

नियम 93 में उस चुनाव से संबंधित है जो आयोजित किया गया है और उचित आदेश पारित किया जाना है शिर हिरासत, निरीक्षण और उत्पादन और अंततः विनाश। संसद के लिए यह खुला है कि वह निर्वाचक नामावलियों की तैयारी सहित संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी भी सदन के निर्वाचनों से संबंधित या उसके संबंध में सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकती है, संविधान के अनुच्छेद 327 के तहत ऐसे सदन या सदनों के उचित गठन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और अन्य सभी मामले। निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने का उल्लेख अनुच्छेद 324 में भी किया गया है और यह शक्ति केवल निर्वाचन आयोग में निहित की जा सकती है। इसके अलावा, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के चुनावों से संबंधित कोई अन्य शक्ति चुनाव आयोग को प्रदान की जा सकती है यदि संसद ऐसा निर्णय लेती है। अनुच्छेद 324 में उल्लिखित के अलावा चुनाव आयोग में कोई अन्य शक्ति निहित नहीं की जा सकती है, अनुच्छेद 327 "इस संविधान के प्रावधानों के अधीन" शब्दों से शुरू होता है, जिसका अर्थ है कि अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को विशेष रूप से प्रदान की गई शक्तियों को अनुच्छेद 327 के तहत संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून द्वारा छीना या हटाया नहीं जा सकता है और न ही इसके लिए कोई प्रावधान किया जा सकता है। अनुच्छेद 325 में निर्दिष्ट मामले। धारा 326 और 329 जो उसमें दी गई बातों के विपरीत हो सकती है। अनुच्छेद 324 और 327 के प्रावधानों का यह अर्थ नहीं निकाला जा सकता है कि अनुच्छेद 324 में विशेष रूप से उल्लिखित शक्तियों के अलावा चुनाव आयोग को कोई अन्य शक्तियां प्रदान नहीं की जा सकती हैं। अत, मैं उस नियम 93 को मानता हूं। जो चुनाव आयोग को उसमें उल्लिखित चुनाव पत्रों के निरीक्षण और उत्पादन के संबंध में शक्ति प्रदान करता है, वह *संविधान के अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 327 के* विपरीत नहीं है।

88. नियम 93 को संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) के प्रावधानों के *विपरीत* भी नहीं कहा *जा सकता है* क्योंकि निरीक्षण के लिए आवेदन संसद के किसी सदन, या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन या किसी भी सदन के चुनाव पर सवाल नहीं उठाता है, जो केवल ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत चुनाव याचिका द्वारा किया जा सकता है, जैसा कि उसके द्वारा या उसके तहत प्रावधान किया जा सकता है। उपयुक्त विधायिका द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जैसा कि अनुच्छेद 329 (बी) में प्रावधान किया गया है। जब निर्वाचन आयोग को निरीक्षण के लिए आवेदन किया जाता है, तो मतपत्रों की वैधता या अन्यथा के बारे में कोई निर्णय नहीं मांगा जाता है, चाहे वह स्वीकार किया गया हो या अस्वीकार, या चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित कोई अन्य मामला। *एन. पी. पोन्नुस्वामी* बनाम *निर्वाचन अधिकारी, नमक्कल निर्वाचन क्षेत्र और अन्य* (1), उनके न्यायमूर्ति ने कहा कि "चुनाव" शब्द का उपयोग किसमें किया गया है?

संविधान का भाग XV व्यापक अर्थों में, अर्थात्, किसी उम्मीदवार को विधायिका में वापस करने के लिए अपनाई जाने वाली पूरी प्रक्रिया का उल्लेख करना, जिसका अर्थ है कि प्रक्रिया निर्वाचन क्षेत्रों को अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए बुलाने वाली अधिसूचना के साथ शुरू होती है और परिणाम की घोषणा के साथ समाप्त होती है। केवल इसलिए कि मतगणना में की गई अनियमितताओं और मतपत्रों की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में निरीक्षण के लिए आवेदन में आरोप लगाए गए हैं, एक लौटे हुए उम्मीदवार के चुनाव पर सवाल उठाने के बराबर नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग लगाए गए आरोपों की सच्चाई या अन्यथा का निर्धारण नहीं कर सकता है और न ही हुए चुनाव के संबंध में कोई राहत दे सकता है। परिणाम घोषित करते समय डाले गए और गिने गए या अस्वीकार

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।

(तुली, जे।

किए गए मत। चुनाव आयोग के पास एकमात्र शक्ति यह है कि वह नियम 93 में उल्लिखित चुनाव पत्रों के निरीक्षण की अनुमति देता है, यह संतुष्ट करने के बाद कि आवेदक द्वारा *प्रथम दृष्टया* मामला बनाया गया है और निरीक्षण की अनुमति देने से पहले अपने कारणों को दर्ज करना होगा। वह निरीक्षण के परिणाम से संबंधित नहीं है और न ही इस तथ्य से कि निरीक्षण के लिए आवेदक अधिनियम की धारा 100 (एल) (डी) (iii) के तहत लौटे उम्मीदवार के चुनाव पर हमले के आधार का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री खोजने में सक्षम होगा या नहीं। चुनाव पत्रों के निरीक्षण से उसे केवल ऐसे आधार के समर्थन में सामग्री मिल सकेगी और यह हो सकता है कि निरीक्षण के बाद निरीक्षण के लिए आवेदक संतुष्ट हो जाए कि उस आधार में कोई तथ्य नहीं है जिसे वह लेना चाहता है और इसे अपनी चुनाव याचिका में आधार के रूप में नहीं ले सकता है और इस प्रकार न्यायालय का समय और स्वयं और लौटने वाले उम्मीदवार के खर्च को बचाता है। यदि वह मतपत्रों का निरीक्षण किए बिना उनकी अनुचित अस्वीकृति या स्वीकृति के संबंध में आरोप लगाता है। इस प्रकार, निरीक्षण के आदेश का चुनाव की प्रक्रिया से कोई लेना-देना नहीं है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि नियम 93 में उल्लिखित चुनाव पत्रों के निरीक्षण के लिए आवेदन वापस आए उम्मीदवार के चुनाव पर सवाल उठाने के बराबर है और इस कारण से संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) के तहत प्रतिबंधित है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा *एनपी पोन्नुस्वामी के मामले* (1) (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के उनके न्यायमूर्ति के फैसले पर बहुत भरोसा किया गया है, जिसमें तथ्य यह था कि पोन्नुस्वामी ने सलेम जिले के नमक्कल निर्वाचन क्षेत्र से मद्रास विधान सभा के चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर की।

मद्रास उच् च न् यायालय ने निर्वाचन अधिकारी के नामांकन पत्र ो ं को खारिज करने के आदेश को रद्द करने और प्रकाशित होने वाले वैध नामांकनों की सूची में अपना नाम शामिल करने का निर्देश देने के लिए एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका इस आधार पर खारिज कर दी कि संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) के प्रावधानों के कारण निर्वाचन अधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। अपील को खारिज करते हुए, उनके न्यायमूर्ति ने कहा -

> "अब सवाल उठता है कि क्या इस देश में चुनाव का कानून इस बात पर विचार करता है कि चुनावी कार्यवाही से संबंधित मामलों पर दो हमले होने चाहिए, एक जबकि वे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू करके चल रहे हैं (न्यायालयों के सामान्य अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है)। और दूसरा चुनाव याचिका के माध्यम से पूरा होने के बाद। मेरी राय में, इस बात की पुष्टि करने के लिए, ऐसी स्थिति संविधान के भाग XV की योजना और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के विपरीत होगी, जो, जैसा कि मैं बाद में बताऊंगा, ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी मामला जिसमें चुनाव को प्रभावित करने का प्रभाव पड़ता है, उसे केवल उचित स्तर पर एक विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष उचित तरीके से लाया जाना चाहिए और इसे मध्यवर्ती स्तर पर नहीं लाया जाना चाहिए। किसी भी न्यायालय के समक्ष, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव कानून के तहत। नामांकन पत्र की अस्वीकृति का एकमात्र महत्व इस तथ्य में निहित है कि इसका उपयोग चुनाव को प्रश्न में बुलाने के लिए एक आधार के रूप में किया जा सकता है; अनुच्छेद 329 (बी) को स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करने के लिए अधिनियमित किया गया था कि किस तरह से और किस चरण में यह आधार, और अन्य

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(तुली, जे।

आधार जो कानून के तहत उठाए जा सकते हैं, चुनाव बुलाने के लिए आग्रह किया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इस उपबंध की भाषा से इसका आवश्यक निहितार्थ निकलता है कि उन आधारों को किसी अन्य तरीके से, किसी अन्य स्तर पर और किसी अन्य न्यायालय के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है। जिन आधारों पर चुनाव कराया जा सकता है, यदि उन्हें पहले चरण में उठाया जा सकता है और त्रुटियां, यदि कोई हों, को ठीक किया जाता है, तो अनुच्छेद 329 (बी) जैसे प्रावधान को लागू करने और एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना करने का कोई मतलब नहीं होगा। अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्दों को दिया गया कोई अन्य अर्थ

विसंगतियां, जिन्हें संविधान स्वीकार नहीं कर सकता था, उनमें से एक यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा चुनाव पूर्व चरण में और चुनाव न्यायाधिकरण, जो एक स्वतंत्र निकाय है, द्वारा परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए जा सकते हैं, जब मामला उसके समक्ष लाया जाता है।

इन टिप्पणियों से, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि उनके न्यायमूर्ति ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव के संबंध में कोई भी विवाद, व्यापक अर्थों में उपयोग किया जाता है, केवल एक चुनाव याचिका द्वारा तय किया जा सकता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि पोन्नुस्वामी ने उनके नामांकन पत्र को खारिज करने के निर्वाचन अधिकारी के आदेश को रद्द करने या रद्द करने के लिए राहत मांगी थी, इसलिए उनके न्यायमूर्ति ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका सक्षम नहीं थी। उस मामले में, पोन्नुस्वामी ने चुनाव के दौरान किए गए रिटर्निंग अधिकारी के आदेश की वैध 1 ता के संबंध में निर्णय लेने और उसके आधार पर राहत देने के लिए प्रार्थना की। इस उद्देश्य के लिए, उनकी याचिका को संविधान के अनुच्छेद 329 (बी) के प्रावधानों के कारण सुनवाई योग्य नहीं माना गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चुनाव याचिका दायर करना उचित तरीका है क्योंकि चुनाव से संबंधित इस तरह के मामले पर दो बार फैसला नहीं किया जा सकता है, एक बार संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक आवेदन पर और दूसरी बार चुनाव याचिका पर चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा। यदि पोन्नुस्वामी ने अपने नामांकन पत्र को खारिज करने या रिकॉर्ड के निरीक्षण के लिए आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन दिया था ताकि वह नामांकन पत्र और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा पारित आदेश का निरीक्षण कर सकें ताकि वह बाद में चुनाव याचिका दायर कर सकें, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता था कि उस आवेदन को करके वह 'मद्रास विधान सभा' के चुनाव पर सवाल उठा रहे थे। जब नियम 93 के अंतर्गत निर्वाचन पत्रों के निरीक्षण के लिए निर्वाचन आयोग को आवेदन किया जाता है तो स्थिति भिन्न नहीं होती है क्योंकि, मैं इस बात पर जोर देता हूं कि निर्वाचन आयोग मतपत्रों अथवा अन्य निर्वाचन पत्रों जिनकी जांच की अनुमति है, की वैधता अथवा अन्यथा के संबंध में निर्णय नहीं ले सकता है। यदि कोई मामला दायर किया जाता है, तो उन मामलों को चुनाव याचिका में उत्तेजित किया जाना होगा, ताकि लौटाए गए उम्मीदवार के निर्वाचन को निर्वाचन याचिका पर विचार करने के लिए सक्षम न्यायालय में रिक्त घोषित किया जा सके। मतपत्रों की गिनती करते समय या निरीक्षण के लिए आवेदन में इन मतपत्रों की अनुचित अस्वीकृति या स्वीकृति के बारे में की गई अनियमितताओं के संबंध में आरोपों की केवल रिकॉर्डिंग

यदि आवेदन करने वाले प्राधिकारी के पास उन आरोपों की सच्चाई या अन्यथा निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है और न ही आवेदक को चुनाव के संबंध में कोई राहत दे सकता है, जैसा कि नियम 93 के तहत चुनाव आयोग को निरीक्षण के लिए आवेदन किया जाता है, तो यह वापस आए उम्मीदवार के चुनाव पर सवाल उठाने के बराबर नहीं हो सकता है। यह स्पष्ट करने के लिए, मैं मानता हूं कि "प्रश्न में कॉल" वाक्यांश का अर्थ यह है कि चुनाव से संबंधित किसी भी मामले के बारे में निर्णय उस प्राधिकारी से आमंत्रित किया जाना चाहिए जिसके पास आवेदन किया गया है और चुनाव की किसी भी प्रक्रिया के संबंध में उस आधार पर राहत मांगी जानी चाहिए। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग द्वारा पारित निरीक्षण की अनुमति देने वाले आदेश का चुनाव को खराब करने का प्रभाव है या अलग-अलग चरणों में दो अलग-अलग अधिकारियों द्वारा एक ही मामले पर परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए जाने की संभावना है। अत, मैं मानता हूं कि नियम 93 संविधान के *अनुच्छेद* 329 (ख) के दायरे से बाहर नहीं है।

89. याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया है कि अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो नियम 93 में उल्लिखित चुनाव पत्रों के निरीक्षण या उत्पादन के संबंध में चुनाव आयोग को किसी भी शक्ति के साथ निवेश करता है और इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त नियम अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। टायर अधिनियम की धारा 169 द्वारा केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति दी गई है, जिसका प्रासंगिक भाग निम्नानुसार है:

169. नियम बनाने की शक्ति

1. केन्द्रीय सरकार, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राधा तैयार कर सकती है।

2. विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता के पूर्वाग्रह के बिना, ऐसे नियम सभी या किसी के लिए प्रदान कर सकते हैं। निम्नलिखित मामले, अर्थात् :-

(क) * * * * *

(ख) * * * * ♦

(ग) * * * *

(घ) * * * * *

(उ)

(ऊ)* * * * * * *

(ऋ) * * * * * *

8. मतपेटियों, मतपत्रों और अन्य चुनाव पत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा, जिस अवधि के लिए ऐसे कागजात संरक्षित किए जाएंगे और ऐसे पत्रों का निरीक्षण और उत्पादन;

* * * * * *

3. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम को संसद के प्रत्येक सदन

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(तुली, जे।

> के समक्ष बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र रखा जाएगा, जबकि वह सत्र में है, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए, जिसमें एक सत्र या दो क्रमागत सत्रों में सम्मिलित किया जा सकता है, और यदि, उस सत्र की समाप्ति से पहले, जिसमें इसे रखा गया है या उसके ठीक बाद का सत्र, दोनों सदन इस बात पर सहमत हैं कि नियम को या तो संशोधित या रद्द किया जाना चाहिए, नियम उसके बाद केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या इसका कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो; इसलिए, हालांकि, इस तरह का कोई भी संशोधन या निरस्तीकरण उस नियम के तहत पहले किए गए किसी भी काम की वैधता के पूर्वाग्रह के बिना होगा।

यह धारा विशेष रूप से केंद्र सरकार को चुनाव पत्रों के निरीक्षण और उत्पादन के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देती है और इसी शक्ति के तहत नियम 93 बनाया गया है। धारा 169 की उपधारा (3) के तहत संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष नियमों को रखने का महत्व यह है कि यदि नियम को तीस दिनों के भीतर संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता है, तो यह लागू हो जाता है और इसका वही प्रभाव होता है जो अधिनियम में ही अधिनियमित किया जाता है। इस तरीके से बनाए गए इस नियम में वैसा ही बल है जैसे इसे संसद द्वारा अधिनियम में ही अधिनियमित किया गया था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह नियम अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नहीं बनाया गया है जब विधायिका ने स्वयं अधिनियम के उद्देश्यों में से एक के रूप में चुनाव पत्रों के निरीक्षण और उत्पादन का उल्लेख किया है। मेरी यह भी राय है कि मतपेटियों, मतपत्रों और अन्य चुनाव पत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा, जिस अवधि के लिए उन्हें संरक्षित किया जाना है और ऐसे पत्रों के निरीक्षण और उत्पादन का चुनावों के संचालन और मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखने के साथ घनिष्ठ संबंध है। इन चुनाव पत्रों को नष्ट करने के संबंध में प्रावधान भी उसी श्रेणी में आता है। मामले के इस दृष्टिकोण में, मुझे प्रतिवादी 3 के विद्वान वकील की इस दलील में कोई बल नहीं मिलता है कि नियम 93 की **वैधता को धारा 169 की** वैधता **को चुनौती दिए बिना चुनौती नहीं दी जा सकती** है, जिसके तहत इसे बनाया गया है। नतीजतन, मैं मानता हूं कि नियम 93 एक वैध नियम है जिसे अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है।

90. याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा है कि नियम 93 उन उद्देश्यों को निर्धारित नहीं करता है जिनके लिए और जिस तरीके से चुनाव आयोग को उस नियम में उल्लिखित चुनाव पत्रों के निरीक्षण की अनुमति देनी है। इसलिए, वह इस बात पर जोर देते हैं कि इस संबंध में चुनाव आयोग की शक्ति उस न्यायालय या न्यायाधिकरण की शक्ति से अधिक व्यापक नहीं हो सकती है, जिसे यह शक्ति मूल रूप से 1961 में नियम बनाते समय दी गई थी। यह नियम, जैसा कि मूल रूप से 1961 में अधिनियमित किया गया था, निम्नानुसार पढ़ा गया है:-

93. चुनाव पत्रों का उत्पादन और निरीक्षण

1. रिटर्निंग ऑफिसर की हिरासत में रहते हुए-

(अ) अप्रयुक्त मतपत्रों के पैकेट;

(आ) इस्तेमाल किए गए मतपत्रों के पैकेट चाहे वैध, निविदा या अस्वीकार किए

गए हों;

(इ) निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के पैकेट या, जैसा भी मामला हो, धारा 122 की उपधारा (1) या उप-धारा (2) के तहत रखी गई सूची; और

(ई) निर्वाचकों द्वारा घोषणाओं के पैकेट और उनके हस्ताक्षरों का सत्यापन;

किसी सक्षम न्यायालय **न्यायाधिकरण** के आदेश के अलावा किसी भी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा उनकी विषय-वस्तु का निरीक्षण नहीं किया जाएगा या उसके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

2. निर्वाचन से संबंधित अन्य सभी कागजात **ऐसी शर्तों के अधीन सार्वजनिक निरीक्षण के** लिए खुले रहेंगे और **ऐसे शुल्क, यदि कोई हो, के भुगतान के लिए, जैसा कि निर्वाचन आयोग निदेश दे।**

(3) नियम 64 के तहत या जैसा भी मामला हो, नियम 84 के उप-नियम (3) के तहत अग्रेषित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा रिटर्न की प्रतियां संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा ऐसी प्रत्येक प्रति के लिए दो रुपये के शुल्क के भुगतान पर प्रस्तुत की जाएंगी।

(1951 और 1956 में बनाए गए नियमों में समान शब्दों में एक नियम पहले मौजूद था)।

31 मार्च, 1962 को उप-नियम (1) में "चुनाव आयोग या सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण के" शब्दों को "सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। 7 सितंबर, 1962 को निम्नलिखित परंतुक जोड़ा गया:-

"बशर्ते कि-

(अ) जहां निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसा कोई आदेश दिया जाता है, वहां आयोग उसे बनाने से पहले निम्नलिखित कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा: और

(आ) चुनाव आयोग के ऐसे किसी भी आदेश के तहत ऐसे कोई पैकेट नहीं खोले जाएंगे और न ही उनकी सामग्री का निरीक्षण किया जाएगा या किसी व्यक्ति या प्राधिकरण के समक्ष पेश नहीं किया जाएगा, जब तक कि उस व्यक्ति या प्राधिकरण ने उम्मीदवारों या उनके विधिवत अधिकृत एजेंटों को इस तरह के उद्घाटन, निरीक्षण या उत्पादन में उपस्थित होने का उचित अवसर नहीं दिया है।

15 दिसंबर, 1966 को नियम 93 सहित नियमों के भाग VIII में निहित कुछ नियमों में "निर्वाचन अधिकारी" के स्थान पर "जिला निर्वाचन अधिकारी" को प्रतिस्थापित किया गया। इस प्रकार यथा संशोधित नियम 93 से यह स्पष्ट है कि निर्वाचन आयोग या कोई सक्षम न्यायालय या अधिकरण निर्वाचन पत्रों के उत्पादन और निरीक्षण का निदेश तभी तक दे सकता है जब तक वे जिला निर्वाचन अधिकारी

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(तुली, जे।

की अभिरक्षा में हों, ताकि जिस समय निरीक्षण की अनुमति दी जा सके वह इस नियम द्वारा विनिदष्ट हो। नियम 94 में यह अवधि अप्रयुक्त पैकेटों के संबंध में छह महीने बताई गई है।

नियम 93 के उप-नियम (1) के खंड (ए) में उल्लिखित मतपत्र और नियम 93 के उप-नियम (1) के खंड (बी), (सी) और (डी) में उल्लिखित चुनाव पत्रों के लिए एक वर्ष की अवधि, यदि चुनाव आयोग या सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा कोई विपरीत निर्देश जारी नहीं किए जाते हैं। इन पत्रों का निरीक्षण और उत्पादन विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिसमें चुनाव याचिकाएं और अपराधी अधिकारियों, या मतदाताओं, या उम्मीदवारों और उनके एजेंटों के आपराधिक अभियोजन शामिल हैं। चुनाव याचिकाओं के संबंध में, उस याचिका के दायर होने के बाद चुनाव याचिका की सुनवाई करने वाले सक्षम न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है और चुनाव अपराधों से संबंधित आपराधिक अभियोजन या ऐसी अन्य कार्यवाही के लिए, उन मामलों से निपटने वाले सक्षम न्यायालय या ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र को उसके समक्ष कार्यवाही शुरू होने के बाद ही लागू किया जा सकता है। जब तक किसी भी अदालत या ट्रिब्यूनल में कोई कार्यवाही शुरू नहीं होती है, तब तक चुनाव आयोग को चुनाव पत्रों के उत्पादन और निरीक्षण की अनुमति देने की शक्ति दी गई है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग की शक्ति सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण की शक्ति के साथ सह-समाप्त है या एक ही उद्देश्य के लिए है और समान सीमाओं द्वारा संरक्षित है। निर्वाचन आयोग, या सक्षम न्यायालय या अधिकरण की शक्ति की सीमा और कार्यक्षेत्र आवश्यक रूप से उनमें से प्रत्येक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कार्यों और शक्तियों के आधार पर निर्धारित किया जाना है। दूसरे शब्दों में, चुनाव पत्रों के निरीक्षण और उत्पादन की अनुमति देने की शक्ति उस प्राधिकरण के कार्यों से रंग लेना है जिसे वह शक्ति सौंपी गई है। जिन परिस्थितियों में उस शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, वे भी समान नहीं हो सकते हैं। इसलिए, मेरा विचार है कि रिट-याचिकाकर्ता सही नहीं है जब वह कहता है कि चुनाव पत्रों के निरीक्षण और उत्पादन की अनुमति देने की चुनाव आयोग की शक्ति सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण के साथ सह-टर्मिनस है और उसी सिद्धांत पर प्रयोग किया जाना चाहिए।

91. याचिकाकर्ता के वकील ने चुनाव पत्रों के निरीक्षण की अनुमति देने के लिए अदालतों की शक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के अपने न्यायमूर्ति के चार फैसलों का उल्लेख किया है और दृढ़ता से आग्रह किया है कि चुनाव आयोग को उन कारणों और उन निर्णयों में उल्लिखित तरीके से निरीक्षण की अनुमति देने या अस्वीकार करने की शक्ति का भी उपयोग करना चाहिए। हमारे ध्यान में लाया गया पहला निर्णय जबर *सिंह* बनाम *गेंदा लाल* है /

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(तुली, जे।

। मैंने इस निर्णय का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया है और पाया है कि चुनाव पत्रों के निरीक्षण का मामला; जैसा कि नियम 93 में उल्लेख किया गया है; उनके न्यायमूर्ति द्वारा बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया था और न ही यह कोई सवाल था। इसलिए यह फैसला प्रासंगिक नहीं है।

92. हमारे संज्ञान में लाया गया दूसरा फैसला राम सेवक यादव बनाम *हुसैन कामिल किदवई* है। *हुसैन कामिल किदवई और अन्य,* (4), जो इस मामले से संबंधित है और जिस पर विद्वान वकील द्वारा बहुत भरोसा किया गया है। उस फैसले में, उनके न्यायमूर्ति द्वारा यह बताया गया था कि नियम 93 "मतपत्रों और अन्य चुनाव पत्रों के बीच स्पष्ट अंतर करता है; मतपत्रों का निरीक्षण केवल सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश के तहत किया जा सकता है, लेकिन अन्य दस्तावेज, कुछ शर्तों के अधीन, सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले हैं। तब यह देखा गया था:

"एक चुनाव याचिका में उन भौतिक तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण होना चाहिए जिन पर याचिकाकर्ता अपने मामले के समर्थन में भरोसा करता है। यदि ऐसे भौतिक तथ्य निर्धारित किए जाते हैं, तो ट्रिब्यूनल के पास निस्संदेह उन दस्तावेजों की खोज और निरीक्षण का निर्देश देने की शक्ति है, जिनके साथ एक सिविल कोर्ट निहित मुकदमे की सुनवाई करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत है।

* * * * ♦

* * *. एक उचित मामले में जहां न्याय के हित इसकी मांग करते हैं, ट्रिब्यूनल रिटर्निंग ऑफिसर को मतपत्र प्रस्तुत करने के लिए बुला सकता है और मतपत्रों के पहले पार्टियों द्वारा निरीक्षण की अनुमति दे सकता है। यह स्पष्ट रूप से चुनाव संचालन नियम, 1961 की धारा 100 (एल) (डी) (iii), 101, 102 और नियम 93 में निहित है। धारा 94 और 128 (1) द्वारा निर्धारित मतपत्रों की गोपनीयता के बारे में वैधानिक प्रतिबंधों के अधीन, जो नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 11 से अलग है, मतपत्रों के निरीक्षण का आदेश देने की इस शक्ति का उपयोग किया जा सकता है।

निरीक्षण के लिए एक आदेश निश्चित रूप से नहीं दिया जा सकता है: मतपत्रों की गोपनीयता पर जोर देने के संबंध में, न्यायालय निरीक्षण के लिए आदेश देने में उचित होगा बशर्ते कि दो शर्तें पूरी हों:

1. कि चुनाव को रद्द करने की याचिका में उन भौतिक तथ्यों का पर्याप्त विवरण होता है जिन पर याचिकाकर्ता अपने मामले के समर्थन में भरोसा करता है; और
2. ट्रिब्यूनल *प्रथम दृष्टया* संतुष्ट है कि विवाद का फैसला करने और पार्टियों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए मतपत्रों का निरीक्षण आवश्यक है।

लेकिन याचिका में की गई अस्पष्ट दलीलों का समर्थन करने या ऐसी दलीलों का समर्थन करने के लिए मतपत्रों के निरीक्षण का आदेश नहीं दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता के मामले को भौतिक तथ्यों के कथनों द्वारा समर्थित सटीकता के साथ निर्धारित किया जाना चाहिए। इस तरह से पेश किए गए मामले को स्थापित करने के लिए, निस्संदेह, यदि न्याय के हितों की आवश्यकता हो, तो निरीक्षण के लिए एक आदेश दिया जा सकता है। लेकिन केवल एक आरोप कि याचिकाकर्ता को संदेह है या विश्वास है कि वोटों का अनुचित स्वागत, इनकार या अस्वीकृति हुई है, निरीक्षण के आदेश का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

थोड़ी देर बाद, न्यायमूर्ति ने देखा: –

पीठ ने कहा, ''इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि मतगणना की प्रक्रिया के हर चरण में उम्मीदवार या उसके एजेंटों के पास मतगणना के समय मौजूद रहने, निर्वाचन अधिकारी की कार्यवाही देखने, खारिज किए गए मतों का निरीक्षण करने और पुनर्मतगणना की मांग करने का अवसर होता है। इसलिए, एक उम्मीदवार जो इस आधार पर चुनाव को चुनौती देना चाहता है कि मतगणना के समय वोटों का अनुचित स्वागत, इनकार या अस्वीकृति हुई है, उसके पास मतपेटियों की जांच और खोलने के तरीके से खुद को परिचित करने का पर्याप्त अवसर है। उनके पास खारिज किए गए मतपत्रों का निरीक्षण करने, फिर से गिनती की मांग करने का भी अवसर है। यह धारा 8-3 (1) के प्रावधानों के प्रकाश में है, जिसमें उन भौतिक तथ्यों के संक्षिप्त विवरण की आवश्यकता होती है, जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है और उस अवसर के लिए जो एक हारे हुए उम्मीदवार के पास था। मतगणना के समय, पुनर्मतगणना का दावा करते समय कि निरीक्षण के आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए।

तब न्यायमूर्ति ने इस दावे के समर्थन में चुनाव में लगाए गए भौतिक आरोपों पर विचार किया कि वोटों का अनुचित स्वागत, इनकार या अस्वीकृति हुई थी और कहा: –

"वोटों की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति के आधार पर चुनाव को रद्द करने के लिए याचिका में ये कथन अस्पष्ट थे, और धारा 83 (एल) (ए) की वैधानिक आवश्यकताओं का पालन नहीं करते थे। पैराग्राफ 12 में भौतिक तथ्यों के पाठ में कमी है, जिसे याचिकाकर्ता के ज्ञान के भीतर माना जाना चाहिए, और केवल यह दावा करता है कि यदि याचिकाकर्ता के पक्ष में वास्तव में डाले गए वोटों की गणना की जाती है, तो उसके पक्ष में पाए गए वैध वोटों की कुल संख्या यादव द्वारा प्राप्त वोटों की संख्या से अधिक होगी। इस दुर्बलता को ध्यान में रखते हुए ट्रिब्यूनल ने मतपत्रों के निरीक्षण के लिए आदेश देने से इनकार कर दिया जब तक कि दावे के समर्थन में *प्रथम दृष्टया* मामला नहीं बनाया गया था। ट्रिब्यूनल को निस्संदेह अपने विवेक का प्रयोग करना होगा यदि यह न्याय के हित में प्रतीत होता है, लेकिन लगाए गए आरोपों की प्रकृति के संबंध में विवेक का उपयोग किया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल उस आदेश को अस्वीकार करने के लिए उचित होगा जहां याचिका में निर्धारित मामले में एक अस्पष्ट याचिका के समर्थन में सामग्री निकालने के उद्देश्य से निरीक्षण का दावा किया जाता है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इन टिप्पणियों पर बहुत जोर दिया है जो अधिनियम की धारा 83 के प्रावधानों के संबंध में एक चुनाव याचिका के संबंध में की गई थीं, जिसके लिए आवश्यक है कि

चुनाव याचिका में उन भौतिक तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण होना चाहिए, जिन पर याचिकाकर्ता भरोसा करता है और किसी भी भ्रष्ट अभ्यास का पूरा विवरण, याचिकाकर्ता का आरोप है कि इसे खारिज किया जाना चाहिए। यदि याचिका में भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण निर्धारित नहीं किया गया है, तो आरोपों को अस्पष्ट करार दिया जाता है और, जैसा कि उनके न्यायमूर्ति द्वारा निर्धारित किया गया है, अस्पष्ट आरोपों के समर्थन में सामग्री को पकड़ने के लिए निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन अगर भौतिक तथ्यों को बताया गया है, तो निरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है ताकि चुनाव-याचिकाकर्ता संबंधित मतपत्रों और अन्य चुनाव पत्रों के उत्पादन और निरीक्षण द्वारा इसे साबित कर सके। यह इस संदर्भ में था कि उनके न्यायमूर्ति ने बताया कि पराजित उम्मीदवार और उसके एजेंटों के पास मतगणना की प्रक्रिया के दौरान उपस्थित होने का पर्याप्त अवसर था और देखने का पर्याप्त अवसर था।
मतपत्रों की स्वीकृति और अस्वीकृति, चाहे वह उनके पक्ष में हो या उनके खिलाफ। इसलिए, उनसे अनुचित रूप से स्वीकार किए गए या अस्वीकृत मतपत्रों के संबंध में भौतिक तथ्यों का विवरण देने की अपेक्षा की गई थी और यदि वह चुनाव याचिका में विवरण देने या उनके संबंध में भौतिक तथ्यों को बताने में विफल रहे, तो उन्हें साक्ष्य निकालने के उद्देश्य से मतपत्रों का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी और फिर एकत्र किए गए सबूतों के परिणाम पर चुनाव को चुनौती देने की मांग की जा सकती थी। इस तथ्य के बावजूद कि चुनाव याचिका में लगाए गए आरोप अस्पष्ट थे, जिसके लिए लौटाए गए उम्मीदवार द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा सकता था। उनके न्यायमूर्ति की टिप्पणियों से, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि यदि प्रथम *दृष्टया* मामला न्यायालय या ट्रिब्यूनल की संतुष्टि के लिए बनाया जाता है और चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है, तो निरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है। यहां तक कि यदि चुनाव आयोग द्वारा इस सिद्धांत का पालन किया जाना है, तो उन्हें केवल यह देखना है कि क्या निरीक्षण के लिए आवेदन में भौतिक तथ्यों को संक्षिप्त रूप से बताया गया है और उन तथ्यों के प्रकाश में, नियम 93 में उल्लिखित मतपत्रों और अन्य चुनाव पत्रों के निरीक्षण की मांग के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था। यदि ऐसा किया जाता है, तो निर्वाचन आयोग द्वारा शक्ति का प्रयोग उचित होगा।

93. विद्वान वकील ने तब *डॉ जगजीत सिंह* बनाम *ज्ञानी करतार सिंह और अन्य*[43] *का उल्लेख किया।*, जिसमें ट्रिब्यूनल ने मतपेटियों के निरीक्षण और फिर से गिनती करने की अनुमति देने के बाद चुनाव याचिका स्वीकार कर ली थी। ट्रिब्यूनल के आदेश को उच्च न्यायालय ने अपील में रद्द कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट के उनके न्यायमूर्ति ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया था। न्यायाधिकरण के फैसले को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि चुनाव याचिकाकर्ता ने मतपेटियों के निरीक्षण और फिर से गिनती के लिए कोई मामला नहीं बनाया था। उनके न्यायमूर्ति द्वारा वास्तविक कानूनी स्थिति निम्नानुसार दोहराई गई थी: –

पीठ ने कहा, "इस मामले में सही कानूनी स्थिति अब संदेह के घेरे में नहीं है। अधिनियम की धारा 92, जो अधिकरण की शक्तियों को परिभाषित करती है, खंड (क) द्वारा उसे वे शक्तियां प्रदान करती है जो अन्य बातों के साथ-साथ खोज और निरीक्षण के संबंध में

[43] A.I.R 1966 S.C 773.

वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय में निहित होती हैं । इसलिए, एक उचित मामले में, ट्रिब्यूनल मतपेटियों के निरीक्षण का आदेश दे सकता है।

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(तुली, जे।

दक्षिणी*

और मतदान पत्रों की अनुचित स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में पार्टियों द्वारा उठाई गई आपत्तियों की जांच करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस शक्ति का प्रयोग करते समय अधिकरण को कतिपय महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होगा। अधिनियम की धारा 83 (1) (ए) के लिए आवश्यक है कि एक चुनाव याचिका में उन भौतिक तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण होना चाहिए, जिन पर याचिकाकर्ता निर्भर करता है; और हर मामले में, जहां एक याचिकाकर्ता द्वारा मतपेटियों के निरीक्षण के लिए अनुरोध किया जाता है, ट्रिब्यूनल को यह जांच करनी चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा उस संबंध में किए गए आवेदन में उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण है जिन पर वह भरोसा करता है। अस्पष्ट या सामान्य आरोप कि वैध वोटों को अनुचित रूप से खारिज कर दिया गया था, या अमान्य वोटों को अनुचित रूप से स्वीकार किया गया था, उस उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा जो धारा 83 (1) (ए) के दिमाग में है। मतपेटियों के निरीक्षण के लिए किए गए आवेदन में भौतिक तथ्य दिए जाने चाहिए जो ट्रिब्यूनल को यह विचार करने में सक्षम बनाएंगे कि न्याय के हित में, मतपेटियों का निरीक्षण किया जाना चाहिए या नहीं। प्रश्न से निपटने में, मतपत्रों की गोपनीयता के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और यह हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अधिनियम के तहत बनाए गए वैधानिक नियमों का उद्देश्य वोटों की वैधता या अमान्यता की जांच और उनकी उचित गणना के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना है। यह हो सकता है कि कुछ मामलों में, न्याय के अंत ट्रिब्यूनल के लिए यह आवश्यक बना देगा कि वह किसी पार्टी को मतपेटियों का निरीक्षण करने की अनुमति दे और किसी भी चुनाव में मतदाताओं द्वारा दिए गए वोटों की अनुचित स्वीकृति या अनुचित अस्वीकृति के बारे में उसकी आपत्तियों पर विचार करे; लेकिन न्याय की आवश्यकताओं पर विचार करते समय, यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि चुनाव याचिकाकर्ताओं को मतपेटियों में घूमने या मछली पकड़ने की जांच करने का मौका न मिले ताकि उनके दावे को सही ठहराया जा सके कि लौटा हुआ उम्मीदवार का चुनाव शून्य है। हम इस मामले में कोई कठोर और तेज नियम बनाने का प्रस्ताव नहीं करते हैं; वास्तव में इस तरह के नियम को निर्धारित करने का प्रयास अनुचित और अनुचित होगा।

94. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र बहादुर सिंह बनाम ***कृष्णा बिहारी***

और अन्य, (5), जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इससे पहले कि एक चुनाव न्यायाधिकरण मतपत्रों के निरीक्षण की अनुमति दे सके, निम्नलिखित बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए: -

1. चुनाव को रद्द करने के लिए याचिका में उन भौतिक तथ्यों का पर्याप्त विवरण होना चाहिए जिन पर याचिकाकर्ता अपने मामले के समर्थन में भरोसा करता है;
2. ट्रिब्यूनल को *प्रथम दृष्टया* संतुष्ट होना चाहिए कि विवाद का फैसला करने और पार्टियों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए, मतपत्रों का निरीक्षण आवश्यक है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि चुनाव-याचिकाकर्ता द्वारा मतपत्रों के निरीक्षण के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया था क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत ज्ञान पर कोई तथ्य नहीं बताया था और केवल यह कहा था कि उन्होंने उन तथ्यों को कुछ व्यक्तियों से सीखा था।

इस स्थिति में यह अभिनिर्धारित किया गया कि चुनाव-याचिकाकर्ता उन आरोपों को लगाने की जिम्मेदारी नहीं ले रहा था और केवल सुनी-सुनाई बातों पर लगाए गए आरोप उन भौतिक तथ्यों के बराबर नहीं थे जिन पर अदालत कार्रवाई कर सकती थी। यह फैसला *राम सेवक यादव के मामले* (सुप्रा) (4) में उनके न्यायमूर्ति द्वारा रखे गए फैसले में शामिल नहीं है।

95. जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, नियम 93 के तहत चुनाव पत्रों के निरीक्षण और उत्पादन की मांग करने के लिए चुनाव याचिका की सुनवाई करने वाले न्यायालय की शक्ति को चुनाव याचिका दायर किए जाने के बाद लागू किया जाता है और इससे पहले कि न्यायालय निरीक्षण की अनुमति दे, यह देखा जाना चाहिए कि क्या भौतिक तथ्यों को कहा गया है और यह नहीं कि केवल आरोप लगाए गए हैं और क्या उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उक्त कागजात ों की जांच के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। जब निरीक्षण के लिए निर्वाचन आयोग को आवेदन किया जाता है तो उसके समक्ष कोई चुनाव याचिका लंबित नहीं होती है और इसलिए अधिनियम की धारा 83 की आवश्यकता को लागू नहीं किया जाता है। निरीक्षण के लिए आवेदक को चुनाव आयोग को यह समझाने के लिए आवेदन में भौतिक तथ्यों को बताना होगा कि उसके पास चुनाव पत्रों के निरीक्षण की मांग करने के लिए एक अच्छा *प्रथम दृष्टया* मामला है और उस निरीक्षण का उद्देश्य चुनाव याचिका दाखिल करना या किसी भी अधिकारी या उम्मीदवारों द्वारा किए गए चुनाव अपराधों के संबंध में आपराधिक कार्यवाही करना हो सकता है। उनके एजेंट या मतदाता। इसलिए, मेरी राय में, चुनाव आयोग के लिए यह स्वीकार्य है कि वह आवेदक को निरीक्षण की अनुमति दे, यदि वह *प्रथम दृष्टया* संतुष्ट है कि वोटों का स्वागत या अस्वीकृति उचित नहीं थी या वोटों की गिनती ठीक से नहीं की गई थी। नियम के अनुसार उसे निरीक्षण की अनुमति देने से पहले कारणों को रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है जो

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(तुली, जे।

इसका मतलब है कि उन्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा और विवेकपूर्ण तरीके से आदेश पारित करना होगा। इस मामले में चुनाव आयोग द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति प्रशासनिक है न कि अर्ध-न्यायिक जिसे कारणों को दर्ज करने के बाद विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना है। निस्संदेह, इसके कारण चुनाव के सिद्धांतों और चुनाव कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए। चूंकि अधिनियम की धारा 83 के लिए आवश्यक है कि चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण दिया जाना चाहिए, यह एक वैध उद्देश्य है जिसके लिए अधिनियम की धारा 100 (1) (डी) (iii) में बताए गए आधार का समर्थन करने के लिए निरीक्षण की मांग की जा सकती है, अर्थात्, चुनाव का परिणाम, जहां तक वापस आए उम्मीदवार का संबंध है, किसी भी वोट के अनुचित स्वागत, इनकार या अस्वीकृति या किसी भी वोट के स्वागत से भौतिक रूप से प्रभावित हुआ है जो शून्य है। यह इस तरह के आधार के समर्थन में सबूत निकालने के बराबर नहीं होगा यदि चुनाव आयोग, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि निरीक्षण के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है, निरीक्षण की अनुमति देता है ताकि आवेदक चुनाव याचिका में ऐसे आधार के समर्थन में विवरण ो को संक्षिप्त रूप से बता सके और यहां तक कि यदि ऐसा होता है, तो, मेरी राय में, चुनाव आयोग के लिए यह खुला है कि वह चुनावों की शुद्धता, निष्पक्षता और निष्पक्षता के हित में निरीक्षण की अनुमति दे, जिन पर निरपवाद रूप से जोर दिया जाता है और न्याय के हित में है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को वोटों की गलत गिनती या वोटों की अनुचित अस्वीकृति या स्वागत या शून्य वोटों के स्वागत के आधार पर विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता जारी रखने का कोई अधिकार नहीं है। यह उन आधारों में से एक है जिस पर लौटाए गए उम्मीदवार के चुनाव को प्रश्न में बुलाया जा सकता है और यदि साबित हो जाता है, तो उसे शून्य घोषित किया जा सकता है और एक उचित मामले में, यदि चुनाव आयोग संतुष्ट है, तो वह निरीक्षण की अनुमति दे सकता है ताकि आवेदक अपनी चुनाव याचिका में सटीकता के साथ उस आधार को ले सके। यह याद रखना होगा कि निरीक्षण की अनुमति देते समय चुनाव आयोग को आवेदन में लगाए गए आरोपों की प्रकृति और गुणवत्ता पर संतुष्ट होना पड़ता है और पोन्नुस्वामी के मामले (1) (सुप्रा) में फैसले के मद्देनजर यह निर्धारित करने के लिए सबूत नहीं मांग सकता है कि वे सच हैं या नहीं।

96. प्रतिवादी 3 के विद्वान वकील ने मतपत्र अधिनियम, 1872 की पहली अनुसूची में नियम 40 का उल्लेख किया है, जो निम्नानुसार है: –

> 40. हाउस ऑफ कॉमन्स के आदेश के अलावा, किसी भी व्यक्ति को चांसरी में क्राउन के क्लर्क की हिरासत में किसी भी अस्वीकृत मतपत्र का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। या महामहिम के उच्च न्यायालयों में से एक के आदेश के तहत, ऐसे न्यायालय द्वारा शपथ पर साक्ष्य द्वारा संतुष्ट होने पर अनुमति दी जाएगी कि मतपत्रों के संबंध में किसी अपराध के लिए अभियोजन शुरू करने या बनाए रखने के उद्देश्य से, या चुनाव या वापसी पर सवाल उठाने वाली याचिका के उद्देश्य से ऐसे मतपत्रों का निरीक्षण या उत्पादन आवश्यक है; और मतपत्रों के निरीक्षण या उत्पादन के लिए ऐसा कोई भी आदेश व्यक्तियों, समय, स्थान, और निरीक्षण या उत्पादन के तरीके जैसी शर्तों के अधीन किया जा सकता है, जैसा कि सदन या न्यायालय उचित समझ सकता है, और चांसरी में क्राउन

के क्लर्क द्वारा पालन किया जाएगा। इस नियम द्वारा किसी न्यायालय को दी गई किसी भी शक्ति का प्रयोग ऐसे न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा कक्षों में किया जा सकता है।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1949 द्वारा मतपत्र अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था, और संसदीय चुनाव नियम उस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निहित थे। दस्तावेजों के उत्पादन और निरीक्षण के आदेशों से संबंधित नियम 57 है, जो निम्नानुसार है: -

"57.— (1) एक आदेश-

(अ) क्राउन के क्लर्क की हिरासत में किसी भी अस्वीकृत मतपत्र के निरीक्षण या उत्पादन के लिए; नहीं तो

(आ)मतदान के दिन ड्यूटी पर रोजगार के बारे में काउंटरफॉइल और प्रमाण पत्र ोें का एक सीलबंद पैकेट खोलने या उसकी हिरासत में किसी भी गिने गए मतपत्रों का निरीक्षण करने के लिए।

बनाया जा सकता है -

(१) हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा; नहीं तो

(२) यदि शपथ पर साक्ष्य से संतुष्ट किया जाता है कि उच्च न्यायालय या काउंटी कोर्ट द्वारा मतपत्रों के संबंध में अपराध के लिए या चुनाव याचिका के उद्देश्य से मुकदमा चलाने या बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश की आवश्यकता है।

3. काउंटरफॉइल और प्रमाण पत्र के एक सीलबंद पैकेट को खोलने या किसी भी गिनती के उम निरीक्षण के लिए एक आदेश

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(तुली, जे।

उक्त हिरासत में मतपत्र एक चुनाव न्यायालय द्वारा किए जा सकते हैं।

3. इस नियम के अधीन आदेश ऐसी शर्तों के अधीन किया जा सकता है जो व्यक्तियों, समय, स्थान और निरीक्षण, उत्पादन या उद्घाटन के तरीके के अधीन हों, जैसा कि हाउस ऑफ कॉमन्स या आदेश देने वाला न्यायालय समीचीन समझे:

परन्तु यह प्रतिपत्तियों और प्रमाणपत्रों के पैकेट खोलने या गिने गए मतपत्रों के निरीक्षण के लिए आदेश बनाने और लागू करने के लिए, इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जिस तरीके से किसी विशेष निर्वाचक का मत दिया गया है, उसका खुलासा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि यह सिद्ध न हो जाए कि उसका मत दिया गया था और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा मत को अमान्य घोषित कर दिया गया है।

4. इस नियम के तहत किए गए काउंटी कोर्ट के किसी भी आदेश से उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।

5. इस नियम के तहत उच्च न्यायालय या काउंटी न्यायालय को दी गई किसी भी शक्ति को खुली अदालत के अलावा न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

6. जहां क्राउन के क्लर्क द्वारा किसी निर्दिष्ट चुनाव से संबंधित उसके पास किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए आदेश दिया जाता है, तो उसके या उसके एजेंट द्वारा ऑर्डर किए गए दस्तावेज़ को इस तरह से पेश करना, जैसा कि उस आदेश द्वारा निर्देशित किया जा सकता है, निर्णायक सबूत होगा कि दस्तावेज निर्दिष्ट चुनाव से संबंधित है; और इस तरह से प्रस्तुत मतपत्रों के किसी भी पैकेट का कोई भी समर्थन प्रथम दृष्टया सबूत होगा कि मतपत्र वही हैं जो उन्हें अनुमोदन द्वारा बताए गए हैं।

7. किसी भी चुनाव में इस्तेमाल किए गए मतपत्र की उचित अभिरक्षा से उत्पादन, और उसी मुद्रित संख्या के साथ चिह्नित एक काउंटरफॉइल और उस पर लिखित रूप से अंकित संख्या, प्रथम *दृष्टया* इस बात का प्रमाण होगा कि जिस निर्वाचक का वोट उस मतपत्र द्वारा दिया गया था, वह वह व्यक्ति था जिसने चुनाव के समय निर्वाचकों के रजिस्टर में अपने नाम के साथ उसी संख्या को जोड़ा था। काउंटरफॉइल पर नंबर लिखा है।

8. इस नियम के अनुसार, किसी भी व्यक्ति को क्राउन के क्लर्क के कब्जे में किसी भी अस्वीकृत या गिने गए मतपत्रों का निरीक्षण करने या काउंटरफॉइल और प्रमाण पत्र के किसी भी सीलबंद पैकेट को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इन दो नियमों से, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि खारिज किए गए मतपत्रों या किसी भी गिने गए मतपत्रों के निरीक्षण की अनुमति देने की शक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स या उच्च न्यायालय या काउंटी

कोर्ट द्वारा चुनाव याचिका के प्रयोजनों के लिए अनुमति दी जा सकती है। यदि इस शक्ति का प्रयोग उच्च न्यायालय या काउंटी न्यायालय द्वारा किया जाना था, तो इसकी संतुष्टि के लिए शपथ पर साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना था। जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स को निरीक्षण का आदेश देने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। निस्संदेह, यह प्रावधान कठोर है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से बताता है कि चुनाव याचिका के प्रयोजनों के लिए निरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है। यह चुनाव से अलग उद्देश्य नहीं है। इसलिए, मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग निरीक्षण की अनुमति देने का हकदार है ताकि निरीक्षण के लिए आवेदक अधिनियम की धारा 100 (एल) (डी) (iii) में उल्लिखित आधार के समर्थन में सामग्री एकत्र कर सके, लेकिन उसे इस शक्ति का उपयोग उन कारणों को दर्ज करने के बाद करना होगा जो उसके द्वारा मनमाने ढंग से किए गए अभ्यास के खिलाफ एक सुरक्षा उपाय है। वह कर सकता है। बेशक, किसी अन्य अच्छे कारण के लिए भी निरीक्षण की अनुमति दें। यह बताया जा सकता है कि इंग्लैंड में, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 194.9, धारा 107 के तहत, संसद के चुनाव पर केवल एक चुनाव याचिका के माध्यम से सवाल उठाया जा सकता है, जो अनुचित चुनाव या अनुचित रिटर्न की शिकायत करता है, जिसे उस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किया जाना है, ताकि चुनाव याचिका के माध्यम से चुनाव के प्रश्न में बुलाने के संबंध में आवश्यकता सामान्य हो। भारतीय और अंग्रेजी दोनों क़ानून।

97. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने तब आग्रह किया कि चूंकि नियम 93 में उस उद्देश्य का उल्लेख नहीं है जिसके लिए या जिस तरीके से चुनाव आयोग को उसमें उल्लिखित चुनाव पत्रों के निरीक्षण की अनुमति देने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना है, उसे निरीक्षण के लिए आदेश पारित करने से पहले प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए क्योंकि नियम स्पष्ट रूप से उनके आवेदन पर रोक नहीं लगाता है। वास्तव में, विद्वान वकील ने यहां तक कहा कि चुनाव आयोग को तथ्यों का निर्धारण करना चाहिए ताकि यह तय किया जा सके कि वापस आए उम्मीदवार को नोटिस के बाद निरीक्षण की अनुमति दी जाए या नहीं और खुद को संतुष्ट करने के लिए किसी प्रकार की जांच की जाए कि निरीक्षण के लिए *प्रथम दृष्टया* मामला बनाया गया है। इस तर्क के समर्थन में, विद्वान वकील ने भारत संघ बनाम *सिन्हा और एक अन्य* मामले में सुप्रीम कोर्ट के उनके न्यायमूर्ति के फैसले का उल्लेख किया है। । उस स्थिति में, मौलिक नियमावली का नियम 56 (जे) विचाराधीन था जो किसी सरकारी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति का प्रावधान करता है यदि उपयुक्त प्राधिकारी की राय है कि यह सार्वजनिक हित में है इसलिए सरकारी कर्मचारी को कुछ मामलों में 50 वर्ष और अन्य मामलों में 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त करना। उसे कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देकर या उसके बदले में तीन महीने का वेतन और भत्ते। उस मामले में प्रतिवादी द्वारा यह दावा किया गया था कि उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने से पहले एक नोटिस दिया जाना चाहिए था। उस दलील को अस्वीकार कर दिया गया था और प्राकृतिक न्याय के नियमों के पालन के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं -"मौलिक नियम 56 (जे) के

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(तुली, जे।

> संदर्भ में यह आवश्यक नहीं है कि संबंधित 'सरकारी कर्मचारी को उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति के खिलाफ कारण बताओ नोटिस देने का अवसर दिया जाना चाहिए। भारत संघ के अधीन सेवारत कोई सरकारी कर्मचारी संविधान के अनुच्छेद 310 में किए गए प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति की इच्छा नुसार अपना पद धारण करता है। लेकिन यह 'आनंद' सिद्धांत अनुच्छेद 309 के तहत बनाए गए नियमों या कानून के साथ-साथ अनुच्छेद 311 के तहत निर्धारित शर्तों के अधीन है। प्राकृतिक न्याय के नियम सन्निहित नियम नहीं हैं और न ही उन्हें मौलिक अधिकारों की स्थिति में बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि इस न्यायालय ने *क्रेपक बनाम भारत संघ,* मामले में कहा था।, 'प्राकृतिक न्याय के नियमों का उद्देश्य न्याय को सुरक्षित करना है या न्याय के गर्भपात को रोकने के लिए इसे नकारात्मक रूप से रखना है। ये नियम केवल उन क्षेत्रों में काम कर सकते हैं जो वैध रूप से बनाए गए किसी भी कानून द्वारा कवर नहीं किए गए हैं। दूसरे शब्दों में, वे कानून की जगह नहीं लेते हैं, बल्कि इसे पूरक करते हैं। यह सच है कि यदि किसी सांविधिक प्रावधान को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ लगातार पढ़ा जा सकता है, तो न्यायालयों को ऐसा करना चाहिए क्योंकि यह माना जाना चाहिए कि
>
> विधायिका और वैधानिक प्राधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने का इरादा रखते हैं। लेकिन, दूसरी ओर, यदि कोई सांविधिक प्रावधान या तो विशेष रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा प्राकृतिक न्याय के किसी भी या सभी नियमों या सिद्धांतों के आवेदन को शामिल नहीं करता है, तो न्यायालय विधायिका या वैधानिक प्राधिकरण के जनादेश की अनदेखी नहीं कर सकता है और संबंधित प्रावधान में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को पढ़ सकता है। प्रदत्त शक्ति का प्रयोग प्राकृतिक न्याय के किसी सिद्धांत के अनुसार किया जाना चाहिए या नहीं, यह शक्ति प्रदान करने वाले प्रावधान के व्यक्त शब्दों, प्रदान की गई शक्ति की प्रकृति, जिस उद्देश्य के लिए इसे प्रदान किया गया है और उस शक्ति के प्रयोग के प्रभाव पर निर्भर करता है।

मेरी राय में, ये टिप्पणियां याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ जाने में मदद करने के बजाय हैं। विद्वान वकील इस टिप्पणी पर दृढ़ता से भरोसा करते हैं कि "यदि एक वैधानिक प्रावधान को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ लगातार पढ़ा जा सकता है, तो न्यायालयों को ऐसा करना चाहिए क्योंकि यह माना जाना चाहिए कि विधायिका और वैधानिक प्राधिकरण प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने का इरादा रखते हैं" और तर्क देते हैं कि नियम 93 स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा किसी भी या सभी नियमों या सिद्धांतों के आवेदन को बाहर नहीं करता है। प्राकृतिक न्याय और इसलिए, चुनाव आयोग द्वारा ऐसे नियमों या सिद्धांतों का पालन किया जाना चाहिए। मुझे खेद है कि मैं इस निवेदन से सहमत नहीं हूं। यदि विधायिका का इरादा था कि निर्वाचन आयोग को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, तो उसने सितम्बर, 1962 में यह परंतुक जोड़े जाने पर इस आशय का कुछ प्रावधान किया होता, जिसमें

निर्वाचन आयोग को निरीक्षण की अनुमति देने और निरीक्षण के समय उपस्थित रहने के लिए अन्य सभी उम्मीदवारों को नोटिस देने से पहले कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता होती थी। इस परंतुक की भाषा से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विधायिका का इरादा यह नहीं था कि चुनाव आयोग निरीक्षण के लिए आदेश पारित करने से पहले लौटे हुए उम्मीदवार या किसी अन्य उम्मीदवार को सुने लेकिन अगर वह आदेश पारित करता है, तो चुनाव लड़ने वाले वापस आए उम्मीदवार और अन्य उम्मीदवारों को निरीक्षण के समय उपस्थित होने के लिए नोटिस दिया जाना था, अगर उन्हें ऐसा पसंद आया। जहां लौटाए गए उम्मीदवार और अन्य उम्मीदवारों की उपस्थिति वांछनीय पाई गई थी, यह इस तरह से निर्दिष्ट किया गया था, जो आवश्यक रूप से इस निष्कर्ष की ओर जाता है कि कोई सुनवाई नहीं की जानी है।

गाइडस सिंह बादल *बनाम* भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(टीयू, जे।

निरीक्षण के लिए आदेश पारित करने से पहले लौटे उम्मीदवार या अन्य उम्मीदवारों को। उस स्तर पर, मामला निरीक्षण के लिए आवेदक और चुनाव आयोग के बीच का होता है और कोई अन्य व्यक्ति इसमें नहीं आता है। चुनाव आयोग को वापस आए उम्मीदवार को नोटिस देने या सुनने या किसी प्रकार की जांच करने से वंचित नहीं किया जाता है यदि वह खुद को संतुष्ट करने के लिए ऐसा चाहता है कि निरीक्षण की अनुमति देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला है क्योंकि उसे इसके समर्थन में कारण दर्ज करना होगा, लेकिन इसे कानून के मामले के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। सभी मामलों में, लौटाए गए उम्मीदवार या किसी अन्य उम्मीदवार को नोटिस दें और निरीक्षण के लिए आदेश पारित करने से पहले उसकी बात सुनें या किसी प्रकार की जांच करें / इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किए गए अन्य फैसले भी उसकी मदद नहीं करते हैं। ये निर्णय इस प्रकार हैं :-

1. आर.वी. *मैनचेस्टर कानूनी सहायता समिति, पूर्व में आर.ए.* ब्रांड एंड कंपनी, लिमिटेड,
2. *न्यू प्रकाश ट्रांसपोर्ट कं, लिमिटेड* बहुत। *न्यू सुवर्णट्राम- पोर्ट कंपनी लिमिटेड,*
3. *ए. के. क्राइपक और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य,* , और
4. *चंद्र भवन बोर्ड और लॉजिंग, बैंगलोर मैसूर राज्य और दूसरा ।*

98. कानून का एक और सिद्धांत है जो अब तक अच्छी तरह से तय हो गया है कि अंतिम निर्धारण ो पर लागू प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं है, चाहे अपील के अधीन हो या नहीं, जब प्रारंभिक निर्णय किए जाते हैं जो आम तौर पर एकतरफा लिए जाते हैं / मैंने पहले ही कहा है कि चुनाव आयोग के पास स्वीकार किए गए या खारिज किए गए मतपत्रों की वैधता या अन्यथा के संबंध में कोई राय व्यक्त करने का कोई अधिकार क्षेत्र या शक्ति नहीं है और न ही वह इसके संबंध में कोई राहत दे सकता है। इसलिए, निरीक्षण की अनुमति 1 लौटे उम्मीदवार के चुनाव को प्रभावित नहीं करती है और न ही यह चुनाव की प्रक्रिया के किसी भी हिस्से के संबंध में किसी भी मामले का फैसला करती है जिसे केवल चुनाव याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है और इसलिए, लौटाए गए उम्मीदवार या किसी अन्य उम्मीदवार को यह दावा करने का कोई अधिकार नहीं है कि निरीक्षण के लिए आदेश देने से पहले उसे सुना जाना चाहिए। यदि चुनाव पत्रों के निरीक्षण के परिणामस्वरूप कोई सामग्री एकत्र की जाती है, तो उस पर चुनाव याचिका पर सुनवाई करने वाले न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा, यदि उस सामग्री के साथ चुनाव याचिका दायर की गई है और उस स्थिति में लौटाए गए उम्मीदवार के पास इसे रोकने या खंडन करने का पर्याप्त अवसर होगा। उन्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि चुनाव याचिका में आधार के समर्थन में सबूत इकट्ठा करने के एक निश्चित तरीके को चुनाव-याचिकाकर्ता को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें बस इतना ही हक है कि उनके चुनाव के संबंध

में मामले पर फैसला होने से पहले उनका पक्ष सुना जाना चाहिए। वह सुनवाई उन्हें तब मिलेगी जब चुनाव याचिका दायर की जाएगी। नियम द्वारा प्रदान किए गए तरीके से साक्ष्य एकत्र करने को किसी भी तरह से लौटे उम्मीदवार के चुनाव को पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता है। बेशक, यदि निरीक्षण की अनुमति देने वाला आदेश नियम 93 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, तो लौटाए गए उम्मीदवार को उस आदेश को चुनौती देने का अधिकार है, लेकिन उसे यह शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं है कि वह आदेश उसे नोटिस के बिना पारित किया गया था। इस कारण से भी मेरी राय है कि चुनाव आयोग नियम 93 के तहत निरीक्षण का आदेश पारित करने से पहले लौटे हुए उम्मीदवार या किसी अन्य उम्मीदवार को नोटिस जारी करने या सुनने के लिए किसी भी बाध्य नहीं है।

99. प्रतिवादी 3 के विद्वान वकील ने वाइसमैन और एक अन्य वी का उल्लेख किया। *बोर्नमैन और अन्य,* (28), जिसमें पृष्ठ 1048 पर डिप्लोक, एल.जे. के निर्णय में निम्नलिखित टिप्पणियां होती हैं: –

"हालांकि, मुझे यह बताना चाहिए कि *अनीस्मिनिक*[44] *मामले* में टिप्पणियों को एक न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र में निर्देशित किया गया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वर्णित स्थिति मौजूद है या नहीं; यह निर्णय जब किया जाता है, तो उससे प्रदान की जाने वाली किसी भी अपील के अधीन होने के कारण, टिप्पणियों का किसी भी तरह से प्रारंभिक निर्णय से कोई लेना-देना *नहीं था कि क्या प्रथम दृष्टया* मामला बनाया गया था कि एक वर्णित स्थिति मौजूद थी जो आगे की जांच के योग्य थी कि ऐसा हुआ या नहीं। जहां किसी व्यक्ति या न्यायाधिकरण को क़ानून द्वारा ऐसा अधिकार क्षेत्र प्रदान किया जाता है, मेरे विचार से किसी को यह देखने के लिए क़ानून को देखना चाहिए कि वे कौन सी सामग्री हैं जिन पर प्रारंभिक निर्णय आधारित होना है। प्रथम दृष्टया कोई अनुमान नहीं है कि संसद का इरादा था कि प्राकृतिक न्याय के नियम अंतिम निर्धारण पर लागू होते हैं, चाहे वे निम्नलिखित के अधीन हों

अपील करें या नहीं, इस प्रारंभिक निर्णय पर लागू किया जाना चाहिए। वास्तव में, किसी को यह देखने के लिए इस न्यायालय की प्रथा में दूर तक देखने की आवश्यकता नहीं है कि जिस तरह की जांच अक्सर एकपक्षीय होती है, और मुझे केवल आरएससी, आदेश 11, नियम 4 के तहत अधिकार क्षेत्र से बाहर रिट की सेवा करने के लिए अनुमति के लिए आवेदन या निषेध के आदेश के लिए आवेदन करने की आवश्यकता है। आर.एस.सी., आदेश 53, नियम 1 के तहत परमादेश या प्रमाणपत्र। आवेदक द्वारा पेश की गई सामग्री पर दूसरे पक्ष को सुने बिना इन सभी और इसी तरह के कई मामलों से निपटा जाता है।

इस फैसले के खिलाफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अपील की गई जिसे खारिज कर दिया गया और कोर्ट

[44] 1967 2 A.E.R 986

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(तुली, जे।

ऑफ अपील के फैसले की पुष्टि की गई। उस फैसले को वाइसमैन और एक अन्य वी के रूप में रिपोर्ट किया गया है। बोर्नमैन और अन्य,

100. कोर्ट ऑफ अपील का एक और निर्णय जिस पर प्रतिवादी 3 के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया है, वह *पैरी-जोन्स बनाम है*। *लॉ सोसाइटी और अन्य,* (29). उस मामले में, लॉ सोसाइटी ने वादी, एक वकील को लिखा, जिसमें उसे लॉ सोसाइटी के जांच लेखाकार के निरीक्षण के लिए इस कार्यालय में अपनी विभिन्न पुस्तकों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। लॉ सोसाइटी द्वारा यह कार्रवाई एक व्यक्ति द्वारा दायर शिकायत के आधार पर की गई थी कि सॉलिसिटर अपने ग्राहकों का उचित लेखा-जोखा नहीं रख रहा था। सॉलिसिटर ने आग्रह किया कि यदि लॉ सोसाइटी ने किसी तीसरे पक्ष द्वारा दर्ज की गई लिखित शिकायत पर सॉलिसिटर अकाउंट्स रूल्स, 1945 के नियम एच (एल) (सी) के तहत कार्रवाई की, तो उस शिकायत को उसे दिखाया जाना चाहिए और वह यह जानने का हकदार है कि शिकायत कौन कर रहा था और इसकी प्रकृति क्या थी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक न्याय के लिए यह आवश्यक है। विद्वान न्यायाधीशों ने बताया कि नियम 11 (4) के तहत, यह प्रावधान किया गया था कि –

"किसी तीसरे पक्ष द्वारा उनके पास दर्ज कराई गई लिखित शिकायत पर निरीक्षण शुरू करने से पहले, परिषद को प्रथम दृष्टया सबूत की आवश्यकता होगी कि शिकायत का आधार मौजूद है।....."

और देखा :-

उन्होंने कहा, 'इससे पता चलता है कि परिषद को केवल यह जांच करनी है कि क्या प्रथम दृष्टया सबूत हैं. जैसा कि हमने कुछ दिनों तक किया

वाइसमैन वी के मामले में पहले। बोर्नमैन (8), एक प्रथम दृष्टया मामला वास्तविक निर्धारण से बहुत अलग स्तर पर खड़ा है। जहां एकमात्र जांच यह है कि क्या प्रथम दृष्टया सबूत हैं, प्राकृतिक न्याय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पार्टी को इसका नोटिस दिया जाना चाहिए। न ही मुझे लगता है कि सॉलिसिटर को यह जानने का अधिकार है कि परिषद नियम 11 (1) के पैरा (ए), (बी) या (सी) के तहत काम कर रही है या नहीं। नियम को इसकी आवश्यकता नहीं है। परिषद अपने लेखाकार को जांच करने के लिए भेजने का हकदार है, बिना यह बताए कि वे किस आधार पर काम कर रहे हैं। सॉलिसिटर को शिकायत का विवरण बताने का अधिकार नहीं है।

101. विद्वान वकील ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले दीनबंधु साहू *बनाम जदुमोनी मंगराज और अन्य* पर भरोसा किया, जिसमें चुनाव आयोग ने वापस आए उम्मीदवार को नोटिस जारी किए बिना चुनाव याचिका दायर करने में देरी को माफ करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया था। ट्रिब्यूनल के समक्ष चुनाव याचिका के लिए दायर अपने लिखित बयान में, लौटे उम्मीदवार ने यह तर्क उठाया कि चूंकि याचिका समय से पहले प्रस्तुत की गई थी, इसलिए इसे अधिनियम की धारा 85 के तहत चुनाव आयोग द्वारा खारिज कर दिया जाना चाहिए और परिणामस्वरूप चुनाव ट्रिब्यूनल को इसे खारिज कर देना चाहिए क्योंकि यह विचार योग्य नहीं है। चुनाव न्यायाधिकरण उस आपत्ति से सहमत नहीं हुआ और गुण-दोष के आधार पर याचिका पर सुनवाई के लिए आगे बढ़ा। अंततः, चुनाव न्यायाधिकरण ने याचिका को स्वीकार कर लिया और संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने वाले वापस आए उम्मीदवार के चुनाव को रद्द कर दिया। अपील में यह तर्क दिया गया था कि चूंकि चुनाव याचिका अधिनियम की धारा 81 द्वारा आवश्यक समय के भीतर प्रस्तुत नहीं की गई थी, इसलिए इसे धारा 85 में अनिवार्य प्रावधान के तहत खारिज कर दिया जाना चाहिए। और यह कि जब मामला चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष आया, तो उसका अधिकार क्षेत्र केवल उस आदेश को पारित करने के लिए था जिसे चुनाव आयोग को पारित करना चाहिए था, और यह कि याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया जाना चाहिए था। न्यायमूर्ति ने अधिनियम की धारा 85 के परंतुक का उल्लेख किया जो निम्नानुसार है:-

"बशर्ते कि यदि याचिका दायर करने वाला कोई व्यक्ति चुनाव आयोग को संतुष्ट करता है कि निर्धारित अवधि के भीतर याचिका पेश करने में उसकी विफलता के लिए पर्याप्त कारण मौजूद हैं।

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(तुली, जे।

इसलिए चुनाव आयोग अपने विवेक से इस तरह की विफलता को माफ कर सकता है।

और देखा :-

"इस प्रावधान के तहत निहित विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए चुनाव आयोग ने 2 जुलाई, 1952 के अपने आदेश द्वारा देरी को माफ कर दिया। यह विवादित नहीं है कि यदि यह आदेश वैध है, तो देरी के आधार पर याचिका को खारिज करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। श्री कृष्णास्वामी अय्यंगार का तर्क यह है कि आदेश वैध नहीं है, क्योंकि यह पार्टी के किसी भी आवेदन पर पारित नहीं किया गया था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि देरी को माफ किया जा सकता है, बल्कि *स्वत: संज्ञान लिया* जाए, और इस तरह के आवेदन, यह तर्क दिया जाता है, उस परंतुक के तहत अधिकार क्षेत्र के प्रयोग के लिए एक शर्त है। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्णयों में इस तर्क के लिए समर्थन मांगा गया था, जिसमें कहा गया था कि यह प्रार्थना करने वाली पार्टी पर निर्भर थी कि देरी को उस धारा के तहत स्पष्ट रूप से आरोप लगाने और इसके आधार को सख्ती से साबित करने के लिए माफ किया जा सकता है। हम इस विवाद से प्रभावित नहीं हैं। जैसा कि इस न्यायालय ने *जगननाथ बनाम जसवंत सिंह* मामले *में उल्लेख किया* कि इन कार्यवाहियों में मुकदमेबाजी के तहत अधिकार सामान्य कानूनी अधिकार नहीं हैं, बल्कि ऐसे अधिकार हैं जो कानूनों के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी हैं, और उन अधिकारों की सीमा उन विधियों के संदर्भ में निर्धारित की जानी चाहिए जो उन्हें बनाते हैं। धारा 85 के परंतुक में चुनाव आयोग प्रतिवादी को देरी के लिए माफी मांगने के लिए याचिका का नोटिस देने या इसके तहत आदेश पारित करने से पहले उसकी उपस्थिति में आधार की पर्याप्तता के बारे में जांच करने पर विचार नहीं करता है। इस प्रावधान में निहित नीति में विलंब के प्रश्न को निर्वाचन आयोग और याचिकाकर्ता के बीच का प्रश्न माना गया है और प्रश्न पर निर्वाचन आयोग के निर्णय को अंतिम बनाया गया है और बाद के किसी भी चरण में प्रश्न के लिए खुला नहीं है। कार्यवाही। अधिनियम की धारा 90 (4) के तहत, जब याचिका धारा 81, धारा 83 या धारा 117 की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं करती है, तो चुनाव न्यायाधिकरण के पास इसे खारिज करने या नहीं करने का विवेकाधिकार है, 'धारा 85 में निहित कुछ भी होने के बावजूद'। धारा 90 (4) के तहत चुनाव न्यायाधिकरण को दी गई शक्ति का दायरा यह है कि यह ओवरराइड करता है

धारा 85 के तहत चुनाव आयोग को याचिका खारिज करने की शक्ति। यह आगे नहीं बढ़ता है और अधिनियम की धारा 85 के तहत चुनाव आयोग द्वारा पारित किसी भी आदेश की समीक्षा करने के लिए चुनाव न्यायाधिकरण में एक शक्ति शामिल है। धारा 90 (4) के शब्द हैं, इसे 'धारा 85 में निहित किसी भी चीज के बावजूद' चिह्नित किया जाना चाहिए, न कि 'धारा 85 या उसके तहत पारित किसी भी आदेश में निहित किसी भी चीज के बावजूद'। धारा 85 के तहत किसी याचिका को प्रतिबंधित करने वाला चुनाव आयोग का आदेश, अधिनियम की योजना के तहत, अंतिम होगा, और उसी परिणाम को धारा 90 (4) के तहत पालन किया जाना चाहिए, जब आदेश देरी को समाप्त करने वाला हो। धारा 90 (4) केवल तभी लागू होगी जब चुनाव आयोग धारा 85 के तहत कोई आदेश पारित किए बिना ट्रिब्यूनल पर याचिका पारित करेगा। यदि चुनाव आयोग इस प्रकार प्रतिवादी को नोटिस के बिना देरी को माफ करने वाला अंतिम आदेश पारित कर सकता है, तो कोई कारण नहीं है कि उसे इस तरह के आदेश को *स्वत: पारित* नहीं करना चाहिए।इस संबंध में, धारा 85 के परंतुक के तहत स्थिति परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत भौतिक रूप से भिन्न है, जिसके तहत देरी को समाप्त करने का आदेश अंतिम नहीं है और बाद के चरण में प्रतिवादी द्वारा पूछताछ की जा सकती है। (प्रिवी काउंसिल के निर्णय के अनुसार) *कृष्णास्वामी पणिकोंदर* बनाम *रामास्वामी चेट्टियार*[45]।

यह तर्क दिया गया था कि इस दृष्टिकोण में प्रतिवादी के पास कोई उपाय नहीं होगा, भले ही चुनाव आयोग देरी को माफ करने का विकल्प चुने - यह वर्षों का हो सकता है - और इसके परिणामस्वरूप बड़ी कठिनाई होगी। लेकिन इस परंतुक में चुनाव आयोग को इस मामले में व्यापक विवेकाधिकार प्रदान करने की सलाह दी गई है, और विधायिका का स्पष्ट इरादा यह था कि इसका प्रयोग सभी पक्षों के साथ न्याय करने की दृष्टि से किया जाना चाहिए। इसलिए, चुनाव आयोग पर भरोसा किया जा सकता है कि वह उचित आदेश पारित करेगा जब परिहार्य और अनुचित देरी हो। यह कि एक शक्ति का दुरुपयोग किया जा सकता है, इसे अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है, जब क़ानून इसे प्रदान करता है, और जहां वैधानिक निकायों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग होता है, तो पीड़ित पक्ष कानून के तहत पर्याप्त उपायों के बिना नहीं होते हैं।

[45] 45 I.A. 25
(46) 45 आईए 25।

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(तुली, जे।

उनके फैसले का पालन किया गया और भीकाजी केशाओ और एक अन्य बनाम *बृजलाल नंदलाल बियानी और अन्य*[46] *मामले* में इसकी फिर से पुष्टि की, न्यायमूर्ति की टिप्पणियों से, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक कानून की आवश्यकता नहीं होती है, तब तक चुनाव आयोग के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह किसी अन्य पार्टी को नोटिस जारी करे जो उसके आदेश से प्रभावित हो सकती है। न्यायमूर्ति ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव आयोग पर उनके समक्ष आने वाले मामलों में उचित आदेश पारित करने के लिए भरोसा किया जा सकता है। यह नहीं माना जा सकता है कि चुनाव आयोग, संविधान के तहत गठित सरकार का एक उच्च पदाधिकारी, कानून या सही प्रक्रिया का पालन नहीं करेगा। निरीक्षण के लिए आवेदनों को अनुमति देते या अस्वीकार करते समय उन्हें अपनी प्रक्रिया अपनानी होगी। अधिनियम की धारा 85 के तहत निर्वाचन आयोग की शक्तियों के संबंध में उनके न्यायमूर्ति द्वारा की गई टिप्पणियां नियम 93 के तहत निर्वाचन आयोग की शक्तियों पर पूरी ताकत से लागू होती हैं। इसलिए, मेरी राय है कि याचिकाकर्ता अधिकार के मामले के रूप में दावा नहीं कर सकता है कि चुनाव आयोग को चुनाव पत्रों के निरीक्षण के लिए प्रतिवादी 3 के आवेदन को अनुमति देने से पहले उसे नोटिस देना चाहिए था।

102. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि जहां कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं है और प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन किया जा सकता है, उचित प्राधिकरण या न्यायाधिकरण को प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुरूप कार्य करना चाहिए और इस मामले में वह इस बात पर जोर देते हैं कि जैसा कि निरीक्षण के लिए आवेदन 15 मार्च को दायर किया गया था, 1971, और चुनाव याचिका दायर करने की सीमा की अवधि 26 अप्रैल, 1971 को समाप्त होने वाली थी, चुनाव आयोग के पास याचिकाकर्ता को नोटिस देने और निरीक्षण के लिए आवेदन पर आदेश देने से पहले उसे सुनने के लिए पर्याप्त समय था। *भारत संघ और अन्य बनाम पी. के. रॉय और अन्य*[47] *मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा* हैं: –

उन्होंने कहा, 'आम तौर पर हमें सोचना चाहिए था कि प्रकाशित प्रारंभिक सूची के खिलाफ अभ्यावेदन देने का एक अवसर कानून की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा. लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की सीमा और अनुप्रयोग को एक कठोर सूत्र के सीधे जैकेट के भीतर कैद नहीं किया जा सकता है। सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रशासनिक प्राधिकरण को प्रदत्त अधिकार क्षेत्र की प्रकृति पर, प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों के चरित्र पर निर्भर करता है।

[46] A.I.R 1955 S.C 610

---

(47) ए.आई.आर. 1955 एस.सी. 610.

कानून की योजना और नीति और विशेष मामले में अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों का खुलासा किया गया।

इन टिप्पणियों के आलोक में, मैं यह कहते हुए दृढ़ महसूस करता हूं कि निर्वाचन आयोग निरीक्षण के लिए आवेदन पर निर्णय लेने से पहले लौटे हुए उम्मीदवार सहित अन्य उम्मीदवारों को नोटिस जारी करने के लिए प्राकृतिक न्याय के किसी भी सिद्धांत से बाध्य नहीं है, जब नियमों के नियम 93 (1) के परंतुक (ए) द्वारा उन्हें ऐसा अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। केवल इसलिए कि निरीक्षण के लिए आवेदन पर निर्णय लेने से पहले लौटे उम्मीदवार को नोटिस जारी करने के लिए पर्याप्त समय था, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को सुनने में चुनाव आयोग की विफलता उस आदेश को दूषित करती है। यह निर्वाचन आयोग का कार्य है कि वह इन मामलों के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया तैयार करे जब नियमों में कोई प्रक्रिया प्रदान नहीं की गई है और नियम के अनुसार यह आवश्यक है कि उसे निरीक्षण के लिए आवेदन की अनुमति देने के कारणों को बताना होगा। यदि वह आवश्यकता पूरी हो जाती है, तो आदेश हमले से प्रतिरक्षा है।

103. इस मामले का एक और पहलू है जिस पर याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा जोर दिया गया है और वह यह है कि चुनाव आयोग द्वारा निरीक्षण के लिए आदेश पारित करने से पहले तथ्यों के रूप में सामग्री होनी चाहिए। यह तर्क निरीक्षण की अनुमति देने के लिए न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में, ऊपर उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय के उनके न्यायमूर्ति के निर्णयों पर आधारित है। यह कहा गया है कि केवल आरोप तथ्य नहीं हैं और साक्ष्य या जांच के माध्यम से किसी और समर्थन के बिना निरीक्षण के आदेश पारित करने के लिए उचित सामग्री का गठन नहीं करते हैं। नियम 93 की भाषा से पता चलता है कि यह चुनाव आयोग की व्यक्तिपरक संतुष्टि पर निर्भर करता है, कि निरीक्षण के लिए एक मामला बनाया गया है, कि वह निरीक्षण की अनुमति देने वाला आदेश पारित कर सकता है। जब उसे ऐसी राय बनानी होती है, तो उसे अपने समक्ष रखी गई सामग्री पर विचार करना होता है, तथ्यों के बारे में आरोप, यदि उसके द्वारा अविश्वास नहीं किया जाता है, तो ऐसे आवेदन पर निर्णय लेने के लिए उचित सामग्री का गठन किया जा सकता है। बस यह देखा जाना है कि जिस सामग्री पर विचार किया गया है वह उस आदेश के लिए प्रासंगिक और जर्मन है जो पारित होने जा रहा है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि एक बार जब यह मान लिया जाता है कि नियम 93 ***अन्तर्निहित*** है और निर्वाचन आयोग के पास उसमें उल्लिखित निर्वाचन पत्रों के निरीक्षण की अनुमति देने की शक्ति है तो हमें केवल यह देखना है कि क्या निर्वाचन आयोग द्वारा पारित निरीक्षण की अनुमति देने वाला आदेश उस नियम की पुष्टि करता है और कोई अन्य प्रश्न यह नहीं उठता है कि उन्होंने स्वयं को कैसे संतुष्ट किया कि निरीक्षण का मामला बनाया गया है। हम याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए अन्य काल्पनिक सवालों से भी चिंतित नहीं हैं कि चुनाव आयोग किस समय निरीक्षण की अनुमति दे सकता है, कि चुनाव आयोग द्वारा निरीक्षण की

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(तुली, जे।

अनुमति देने की शक्ति का प्रयोग चुनाव न्यायालय को उस अधिकार से वंचित कर देगा या क्या होगा यदि कोई व्यक्ति चुनाव आयोग और चुनाव याचिका की कोशिश करने वाले न्यायालय दोनों को आवेदन करता है, आदि। इस मामले में, चुनाव याचिका दायर किए जाने से पहले आदेश पारित किया गया है और याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा भी इस बात पर विवाद नहीं है कि इस स्तर पर चुनाव आयोग नियम 93 के तहत चुनाव पत्रों के निरीक्षण की अनुमति दे सकता है। रिट याचिका के पैरा 11 में कहा गया है कि-

"यदि प्रतिवादी, श्री इकबाल सिंह को निरीक्षण आदि के संबंध में कोई शिकायत है, तो उचित प्रक्रिया यह होगी कि मतगणना के संबंध में अनियमितताओं को दिखाने या मतपत्रों की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में विशिष्ट तथ्यों के साथ चुनाव आयोग को लागू किया जाए। तब चुनाव आयोग कानून में कर्तव्य बद्ध था कि वह याचिकाकर्ता को सुने और उठाए गए बिंदुओं पर अपना दिमाग लगाने और बोलने का आदेश देने के बाद उचित आदेश पारित करे। हालांकि, चुनाव आयोग ने इकबाल सिंह की एक आम शिकायत पर श्री इकबाल सिंह को छोड़कर अन्य सभी उम्मीदवारों के मतपत्रों की जांच का आदेश दिया है।

यह आरोप लगाकर याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि चुनाव आयोग के पास निरीक्षण की अनुमति देने की शक्ति थी यदि उसके सामने उचित सामग्री रखी गई थी, लेकिन उसे याचिकाकर्ता को नोटिस देने और उसे सुनने के बाद आदेश पारित करना चाहिए था। इस दलील को ध्यान में रखते हुए, हमें अब यह देखना है कि क्या चुनाव आयोग के पास आदेश पारित करने को सही ठहराने के लिए सामग्री थी और क्या कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता को पूरा किया गया है।

104. चुनाव आयोग के समक्ष सामग्री में प्रतिवादी 3 द्वारा 15 मार्च, 1971 को किए गए आवेदन शामिल थे, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पिछले पत्रों का भी संदर्भ दिया गया था। उस आवेदन में उन्होंने कहा था -

1. कि रिट-याचिकाकर्ता पंजाब के मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल के भाई हैं, जिन्हें जेल में डाल दिया गया था।

अकाली दल के टिकट पर एक उम्मीदवार के रूप में और जब से वह चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए हैं, पंजाब सरकार की मशीनरी ने सभी संभव अनुचित साधनों को अपनाकर और मुख्यमंत्री के निपटान में सरकारी मशीनरी का अवैध रूप से उपयोग करके उनकी मदद करने के लिए काम किया था।

2. श्री प्रकाश सिंह बादल ने अपने भाई की मदद करने के लिए हर कदम उठाया और उक्त निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव में उनकी सफलता के लिए अपनी पसंद के ऐसे मतदान और पीठासीन अधिकारियों को नियुक्त करके अपने पास मौजूद सभी साधनों का उपयोग किया, जो उनकी पीठ पर खड़े हो सकते थे और श्री प्रकाश सिंह बादल की इच्छा के अनुसार कुछ भी कर सकते थे ताकि उनके भाई को निष्पक्ष या गलत तरीकों से लोकसभा में प्रवेश करने में मदद मिल सके।

3. 20 फरवरी, 1971 से 28 फरवरी, 1971 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिवादी 3 द्वारा बार-बार शिकायत किए जाने के बावजूद, श्री प्रकाश सिंह बादल ने लोकसभा के उक्त चुनाव में अपने भाई की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उक्त परिस्थितियों में पूरे निर्वाचन क्षेत्र में 5 मार्च, 1971 को मतदान हुआ।

4. 7 मार्च, 1971 को प्रतिवादी 3 ने भारत के चुनाव आयुक्त को एक शिकायत की, जिसमें चुनाव आयोग से मतगणना की निगरानी के लिए कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को तैनात करने का अनुरोध किया गया ताकि मतगणना चुनाव संचालन नियम, 1961 में निर्धारित नियमों और चुनाव आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार हो सके। उस आवेदन पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया था।

5. 8 मार्च, 1971 को मुख्य चुनाव आयुक्त को एक विस्तृत पत्र लिखा गया था, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल द्वारा अपने भाई श्री गुरदास सिंह बादल को किसी भी परिस्थिति में उक्त निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा में वापसी में मदद करने के उद्देश्य से किए गए कदाचार का विवरण दिया गया था।

6. मतगणना के दौरान यह पता चला कि सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मतपत्र पाए गए जिन पर किस के हस्ताक्षर नहीं थे।

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(तुली, जे।

या तो पीठासीन या मतदान अधिकारी, और/ या विधानसभा / मतदान केंद्र की मुहर या इसकी संख्या। इस तरह के मतपत्रों की संख्या लगभग 15,000 से अधिक थी। इसके अलावा, प्रतिवादी 3 के पक्ष में डाले गए 6,000 से अधिक वैध वोटों को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था और इस मामले को टेलीग्राफिक रूप से चुनाव आयोग और अन्य अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया था। रिट-याचिकाकर्ता के पक्ष में वैध वोटों के इस गलत स्वागत और प्रतिवादी 3 के पक्ष में डाले गए 6,000 वोटों की गलत अस्वीकृति ने चुनाव के परिणाम को प्रभावित किया था।

7. 12 मार्च, 1971 को नियमों के नियम 63 और 64 के तहत रिटर्निंग अधिकारी को एक लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें पुनर्मतगणना के लिए कहा गया था, लेकिन रिटर्निंग अधिकारी ने बिना कोई वैध कारण बताए उक्त याचिका को खारिज कर दिया।

8. याचिकाकर्ता को केवल 5,323 मतों के अंतर से विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया था।

9. यह कि निर्वाचन अधिकारी ने याचिकाकर्ता को सफल घोषित करने में दुर्भावनापूर्ण इरादे से काम किया ताकि वह पंजाब के मुख्यमंत्री का पक्ष ले सके, जबकि उन्होंने प्रतिवादी 3 की तुलना में अधिक वैध वोट हासिल नहीं किए थे और यह तथ्य रिकॉर्ड और मतपत्रों की जांच से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा।

10. प्रतिवादी 3 को उचित आशंका थी कि सभी चुनाव पत्र, जैसे अप्रयुक्त मतपत्रों के पैकेट, पैकेट या इस्तेमाल किए गए मतपत्र - चाहे वे वैध, निविदा या खारिज किए गए हों, मतदाता सूची की चिह्नित प्रतियों के पैकेट और सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न मतदान अधिकारियों को मतपत्र जारी करने से संबंधित रिकॉर्ड और पीठासीन और मतगणना पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट और उक्त से संबंधित अन्य कागजात और रिकॉर्ड। संबंधित अधिकारियों द्वारा की गई अवैधताओं और अनियमितताओं को कवर करने के लिए निर्वाचन क्षेत्र के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए और आवश्यक हेरफेर और परिवर्तन नहीं किए जाने चाहिए।

तथ्य के इन आरोपों के आधार पर, यह प्रार्थना की गई थी कि-

1. प्रतिवादी 3 को सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों में सभी मतपत्रों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों के निरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है जो इस तरह के निरीक्षण के लिए खुले हैं ताकि वह चुनाव याचिका के माध्यम से उचित न्यायालय में अपना कानूनी उपाय प्राप्त कर सकें;
2. यह निरीक्षण कृपया निर्वाचन आयोग के किसी अधिकारी की देखरेख में किया जाए। इस तरह के निरीक्षण के बाद, फाजिल्का संसदीय क्षेत्र से लोकसभा उम्मीदवार के चुनाव से संबंधित मतपत्रों और अन्य दस्तावेजों को एक उपयुक्त प्राधिकारी, चुनाव आयोग और उम्मीदवारों की मुहर के साथ सील कर दिया जाता है।
3. इन दस्तावेजों को निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कब्जे में लिया जाए और उपयुक्त न्यायालय द्वारा तलब किए जाने तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के तहत एक स्थान पर जमा किया जाए; और
4. वह तत्काल आदेश पारित किया जाए ताकि इस बीच कोई शरारत न की जा सके।

इस प्रकार चुनाव आयोग के समक्ष मौजूद सामग्री में 15 मार्च, 1971 को दायर निरीक्षण के लिए आवेदन में लगाए गए तथ्य के आरोप और प्रतिवादी 3 द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त या उस कार्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी को पहले भेजे गए पत्र और टेलीग्राम शामिल थे। यह भी याद रखना होगा कि पहले लगाए गए आरोपों पर चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती पर नजर रखने के लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। 8 मार्च, 1971 के पत्र में, जिसकी एक प्रति अनुलग्नक 'आर-IX' के रूप में दायर की गई है, प्रतिवादी 3 ने फाजिल्का पार्लियामेंट क्षेत्र से चुनाव में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ पैरा 5, 7, 15, 16, 26 और 27 में गंभीर आरोप लगाए थे, जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है?

5. मलोट विधानसभा क्षेत्र के गांव दानेवाला मतदान केंद्र में एक बड़ी घटना हुई। मेरे पोलिंग एजेंट को पोलिंग बूथ में बैठने की अनुमति नहीं दी गई, जबकि उसने सुबह अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया था। सरपंच और कुछ ग्रामीणों ने उसे मतदान केंद्र से बाहर धकेल दिया। यह हुआ था

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(तुली, जे।

पीठासीन अधिकारी की मिलीभगत। मुझे व्यक्तिगत रूप से मतदान केंद्र का दौरा करना पड़ा और हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके बाद ही एजेंट को वहां रहने की अनुमति दी गई।

7. मलोट विधानसभा क्षेत्र के गांव बाम में अकालियों ने हमारे पोलिंग एजेंट को धक्का देकर मतदान केंद्र से बाहर कर दिया और उन्होंने खुद मतपत्रों को चिह्नित करने के बाद उन्हें बॉक्स में डाल दिया। हरिजनों को धमकी दी गई कि अगर उन्होंने अकालियों को वोट नहीं दिया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

15. लांबी विधानसभा क्षेत्र के सिखवाला गांव में एसएचओ ने मेरे पोलिंग एजेंट को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। उन्होंने लांबी विधानसभा क्षेत्र के खुबास, फत्ता खेड़ा और अरनीवाला के मतदान केंद्रों पर भी ऐसा किया था।

16. लांबी विधानसभा क्षेत्र के खुदियान मतदान केंद्र में मेरे पोलिंग एजेंटों को बूथ में प्रवेश करने से रोक दिया गया।

26. मुक्तसर विधानसभा क्षेत्र के बांगेवाला गांव में मेरे पोलिंग एजेंटों को काम नहीं करने दिया गया। हरिजनों को भी मतदान करने से रोका गया।

27. फरीदकोट विधानसभा क्षेत्र के भागसिंगवाला गांव में, मेरे पोलिंग एजेंट को सुबह 9 बजे बाहर धकेल दिया गया था, लेकिन जब उसने कड़ा विरोध किया, तो उसे दोपहर 1 बजे बूथ में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। उस समय तक कई फर्जी वोट डाले जा चुके थे।

इस पत्र में बताए गए तथ्यों को प्रतिवादी 3 ने अपने व्यक्तिगत ज्ञान से बात की थी। तथ्य के इन आरोपों को चुनाव आयोग ने गंभीर माना और यह नहीं कहा जा सकता कि वह अपने अनुमान में गलत थे। चुनाव आयोग जानता था कि याचिकाकर्ता मुख्यमंत्री का भाई है और मानवीय स्वभाव को ध्यान में रखते हुए, जब तक कि भाइयों के बीच संबंध तनावपूर्ण नहीं होते, मुख्यमंत्री स्वाभाविक रूप से चुनाव में सफलता हासिल करने में अपने भाई की मदद करते। इसका मतलब यह नहीं है कि मुख्यमंत्री ने अनुचित साधनों का सहारा लिया होगा, लेकिन यह मानना अस्वाभाविक नहीं है कि अधिकारी विभिन्न चरणों में काम कर रहे हैं।

हो सकता है कि चुनाव में मुख्यमंत्री के भाई की मदद करने की इच्छा हो, क्योंकि इससे स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री खुश होते। उस बैक-ग्राउंड में, जब यह आरोप लगाया गया कि उत्तरदाता 3 के पोलिंग एजेंटों को मतदान के दौरान कुछ मतदान केंद्रों में या तो प्रवेश नहीं दिया गया था या उनमें से कुछ से बाहर धकेल दिया गया था, तो इससे यह वैध निष्कर्ष निकल सकता है कि कुछ मतदान केंद्रों पर कुछ अनियमितताएं की गई होंगी। यह भी कहा गया था कि प्रतिवादी 3 के पक्ष में डाले गए 6,000 वैध वोटों को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था, जबकि याचिकाकर्ता के पक्ष में डाले गए 12,000 अवैध वोटों को गलत तरीके से स्वीकार किया गया था और याचिकाकर्ता के पक्ष में गिना गया था। प्रतिवादी 3 ने अपने आवेदन में यह भी स्पष्ट किया कि वह याचिकाकर्ता के चुनाव को चुनौती देने के लिए चुनाव याचिका दायर करना चाहता है। यदि, इस सामग्री पर, चुनाव आयोग ने संतुष्ट महसूस किया कि प्रतिवादी 3 द्वारा मतपत्रों और अन्य चुनाव पत्रों के निरीक्षण के लिए एक मामला बनाया गया था, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उनकी संतुष्टि किसी भी सामग्री पर आधारित नहीं थी। इसलिए, मैं संतुष्ट हूं कि चुनाव आयोग ने प्रतिवादी 3 द्वारा उनके समक्ष रखी गई सामग्री के संबंध में मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विवेकपूर्ण दिमाग लगाने के बाद प्रतिवादी 3 को निरीक्षण की अनुमति देने का आदेश पारित किया था। उन्हें उस स्तर पर यह निर्धारित करने के लिए नहीं बुलाया गया था कि निरीक्षण के लिए अपने आवेदन में और पिछले संचार में प्रतिवादी 3 द्वारा लगाए गए तथ्य के आरोप सही थे या गलत। उन्हें बस इतना निर्धारित करना था कि क्या उन आरोपों के आधार पर, वह निरीक्षण की अनुमति देने में उचित थे, अर्थात, क्या तथ्य के उन आरोपों ने *उन्हें प्रथम दृष्टया* संतुष्ट किया कि निरीक्षण के लिए एक मामला बनाया गया था। जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, चुनाव आयोग की राय यह राय बनाने में सही थी कि निरीक्षण के लिए एक मामला वास्तव में प्रतिवादी 3 द्वारा बनाया गया था।

105. अब इस बात पर विचार किया जाना है कि क्या निर्वाचन आयोग के आदेश में निरीक्षण की अनुमति देने के लिए कोई कारण शामिल हैं और इस प्रकार नियम 93 (1) के परंतुक (ए) की आवश्यकता का अनुपालन करता है। चुनाव आयोग ने कारण दिया कि, प्रतिवादी 3 द्वारा लगाए गए आरोप, यदि सही हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है और इसलिए, उनकी राय थी कि निरीक्षण की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि एक औपचारिक आदेश तैयार किया जाना चाहिए। एक औपचारिक आदेश तैयार किया गया था जिसे 16 मार्च, 1971 को फिरोजपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रतिवादी 3 को निरीक्षण की अनुमति देने के लिए सूचित किया गया था और यह वह आदेश है जिसे याचिकाकर्ता ने अपनी रिट याचिका में चुनौती दी थी।

जब इसे दायर किया गया था। इसलिए, उस आदेश को निर्धारित करना उचित है। यह निम्नानुसार है -

चुनाव आयोग को 5 मार्च, 1971 को हुए लोकसभा के आम चुनाव में पंजाब राज्य के 1-फाजिल्का संसदीय क्षेत्र से चुनाव कराने वाले उम्मीदवार इकबाल सिंह से आचार संहिता के नियम 93 में उल्लिखित दस्तावेजों वाले सीलबंद पैकेटों की जांच के लिए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। (ग) उक्त निर्वाचन क्षेत्र के सभी आठ विधान सभा क्षेत्रों में

प्रयुक्त मतपत्रों सहित निर्वाचन नियम, 1961 के अंतर्गत विधान सभा के नियम 1961 का प्रावधान किया गया है।

और जबकि आवेदक ने कहा है कि इन दस्तावेजों का निरीक्षण आवश्यक है ताकि वह चुनाव याचिका द्वारा उचित अदालत में अपना कानूनी उपाय प्राप्त कर सके।

और जबकि उक्त आवेदन में, आवेदक ने विशेष रूप से आरोप लगाया है कि गिनती के दौरान बड़ी संख्या में मतपत्र पाए गए थे, जिन पर कानून के तहत आवश्यक पीठासीन अधिकारी का कोई विशिष्ट चिह्न या हस्ताक्षर नहीं था और 6,000 से अधिक वैध वोटों को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था।

अब, इसलिए, निर्वाचन संचालन नियमावली, 1961 के नियम 93 के उप-नियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग इस बात से संतुष्ट हो गया है कि आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार निरीक्षण आवश्यक है ताकि मतपत्र की गोपनीयता का उल्लंघन किए बिना न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सके जैसा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा *श्री एस सी दत्ता* बनाम *श्री कृष्ण बाजपेयी और अन्य*[48] *मामले में आदेश में कहा गया* और क्रम में *रघुबीर सिंह यादव* बनाम *गजेंद्र सिंह और अन्य* (7), इसके द्वारा निर्देश देते हैं कि-

1. पंजाब राज्य में फिरोजपुर जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी अप्रयुक्त मतपत्रों और चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों के पक्ष में डाले गए मतों वाले सीलबंद पैकेट खोलेंगे। फाजिल्का संसदीय क्षेत्र के उपयोग के सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों के संबंध में और खारिज किए गए वोटों के पैकेट और आवेदक या उसके विधिवत अधिकृत एजेंट को उनकी उपस्थिति में उनका निरीक्षण करने की अनुमति देते हैं। यदि लौटा हुआ उम्मीदवार जिला निर्वाचन अधिकारी को लिखित में आवेदन करता है या आवेदक के वोटों के साथ-साथ उद्घाटन और निरीक्षण करता है, तो इसे भी अनुमति दी जाएगी।

2. यदि आवेदक फाजिल्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी या सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों के संबंध में मतदाता सूची की चिह्नित प्रति के निरीक्षण की मांग करता है, तो उपर्युक्त के अनुसार पूर्वोक्त निरीक्षक पूरा हो जाता है और आईटी कागजातों वाले पैकेटों का उपयोग, निविदा या अस्वीकार कर दिया जाता है और अप्रयुक्त मतपत्रों वाले पैकेटों को सील और सुरक्षित कर दिया जाता है, यदि आवेदक फाजिल्का संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसी भी या सभी आठ विधानसभा क्षेत्रों के संबंध में मतदाता सूची की चिह्नित प्रति के निरीक्षण की मांग करता है। फिर उस दस्तावेज़ के निरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है,

3. यह कि जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों या उनके विधिवत अधिकृत एजेंटों को ऐसे उद्घाटन और निरीक्षण में उपस्थित होने का

[48] E.P NO. 7 of 1969 decided by Allahabad high court on 11th august 1969.

उचित अवसर देगा। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को लिखित में उचित सूचना दी जानी चाहिए जिसमें निरीक्षण होने के समय, समय और स्थान का उल्लेख हो। प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को इस तरह के उद्घाटन और निरीक्षण में उपस्थित होने के लिए केवल एक विधिवत अधिकृत एजेंट नियुक्त करने की अनुमति दी जा सकती है। इस तरह के निरीक्षण के दौरान, किसी भी व्यक्ति को मतपत्र को छूने या संभालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन जिला निर्वाचन अधिकारी उपस्थित व्यक्तियों में से किसी को भी मतपत्रों की संख्या को नोट करने की अनुमति दे सकता है, जिसे वह अनुचित रूप से स्वीकार या अनुचित रूप से अस्वीकार करता है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पैकेटों के ऐसे उद्घाटन और निरीक्षण के समय पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी प्रदान की जाएगी और निरीक्षण समाप्त होने के बाद, निविदा किए गए या अस्वीकृत किए गए सभी मतपत्रों, अप्रयुक्त मतपत्रों और मतदाता सूची की चिह्नित प्रति को संबंधित पैकेटों और ऐसे पैकेटों में बदल दिया जाएगा।

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(तुली, जे।

जिला निर्वाचन अधिकारी की मुहर के साथ उसकी उपस्थिति में और निरीक्षण के समय उपस्थित ऐसे व्यक्तियों की मुहर के साथ जो उन्हें चिपकाना चाहते हैं, उन्हें और निर्वाचन आयोग की गुप्त मुहर के साथ फिर से सील किया जाएगा। सभी पैकेटों को एक स्टील बॉक्स या अन्य कंटेनर में डाल दिया जाएगा, जिसे पूर्वोक्त तरीके से बंद और सील किया जाएगा और इसे सुरक्षित हिरासत के लिए ट्रेजरी में रखा जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ न की जाए।

आदेश के अनुसार,

एसडी/-

(ए. एन. सेन)।

भारत निर्वाचन आयोग के सचिव।

जब याचिका पर बहस हो रही थी; हमने देखा कि उक्त आदेश इन शब्दों के साथ समाप्त हुआ-

" आदेश द्वारा;

एसडी/-
(ए. एन. सेन)

भारत निर्वाचन आयोग के सचिव।

जिससे यह अनुमान लगाया गया कि यह आदेशचुनाव आयोग के सचिव के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पारित किया गया था, जिन्होंने केवल जिला निर्वाचन अधिकारी को इसकी सूचना दी थी। दोनों पक्षों के वकीलों के कहने पर हमने चुनाव आयोग से रिकॉर्ड भेजा और उसमें चुनाव आयोग का 15 मार्च, 1971 का आदेश मिला, जिसे इस फैसले के पहले हिस्से में निर्धारित किया गया है। यह प्रश्न उठाया गया है कि इनमें से कौन सा

आदेश को चुनाव आयोग का आदेश माना जाना है। याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर आग्रह किया है कि चुनाव आयोग का आदेश 15 मार्च, 1971 को उनके द्वारा पारित आदेश है और चुनाव आयोग के सचिव द्वारा 16 मार्च, 1971 को फिरोजपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित किया गया था; केवल उस आदेश को व्यक्त किया गया था और यह चुनाव आयोग के रूप में उनके द्वारा पारित आदेश नहीं था और इस कारण से, इसे चुनाव आयोग द्वारा पारित आदेश नहीं माना जा सकता है। दूसरी ओर, प्रतिवादी 3 के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा 19 ए के तहत, चुनाव आयोग के सचिव को संविधान, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत इजेक्शन आयोग के कार्यों को करने का अधिकार है। इस कारण 16 मार्च, 1971 के आदेश को भी चुनाव आयोग द्वारा पारित आदेश के रूप में माना जाना चाहिए, जो 15 मार्च, 1971 को पारित आदेश का पूरक है। मेरी राय में; सही स्थिति यह है कि चुनाव आयोग द्वारा 15 मार्च को पारित आदेश; 1971; यह मूल आदेश था जिसे कार्यालय द्वारा लागू किया जाना था। चुनाव आयोग के सचिव द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को 16 मार्च, 1971 को दिया गया आदेश एक पूर्ण आदेश था जो 15 मार्च, 1971 के उनके आदेश में निहित चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार तैयार किया गया था। इस आदेश में, चुनाव आयोग को निरीक्षण की अनुमति देने के लिए प्रेरित करने वाले कारण आदेश की प्रस्तावना में बताए गए थे और वही हैं जो चुनाव आयोग द्वारा 15 मार्च, 1971 के अपने आदेश में दर्ज किए गए थे, अगर हम उस आदेश को उस सामग्री के साथ पढ़ते हैं जो उनके समक्ष विचार के लिए रखी गई थी और जिसके आधार पर वह आदेश पारित किया गया था जैसा कि ऊपर बताया गया है। 16 मार्च, 1971 का यह आदेश चुनाव आयोग के 15 मार्च, 1971 के आदेश की पुष्टि करता है और इससे आगे नहीं जाता है। इसलिए, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, 16 मार्च, 1971 के आदेश को ऑपरेटिव ऑर्डर माना जाना चाहिए। यह आदेश स्पष्ट रूप से नियम 93 की आवश्यकताओं के अनुसार है और निरीक्षण की अनुमति देने के कारणों के साथ-साथ निरीक्षण के तरीके को निर्धारित करता है। इसलिए, ये दोनों आदेश सही हैं और इस आधार पर रद्द किए जाने योग्य नहीं हैं कि इसमें कोई कारण दर्ज नहीं है।

106. याचिकाकर्ता के वकील ने हालांकि कहा कि चुनाव आयोग ने जिन आरोपों को गंभीर माना है, उन्हें उनके आदेश में निर्धारित किया जाना चाहिए था।

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(तुली, जे।

दिनांक 15 मार्च, 1971 को, ताकि आदेश एक स्व-निहित आदेश होना चाहिए था और केवल उस आदेश से ही प्रथम दृष्टया यह पता चलना चाहिए था कि चुनाव आयोग द्वारा प्रतिवादी 3 द्वारा लगाए गए आरोपों में से क्यों और किन आरोपों को गंभीर माना गया था। मेरी राय में, यह इस मामले में चुनाव आयोग द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश की आवश्यकता नहीं है। केवल इसलिए कि क़ानून ने कारणों को दर्ज करने के लिए एक आवश्यकता निर्धारित की है, कारण बताते हुए पारित किया जाने वाला आदेश अर्ध-न्यायिक नहीं बन जाता है। यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति द्वारा *मोन-ग़ीर के कलेक्टर बनाम केशव प्रसाद गोयनका अन्य के मामले में आयोजित किया गया था*। जिस समय चुनाव आयोग द्वारा निरीक्षण के आवेदन पर विचार किया जाता है, उसके सामने एकमात्र पक्ष निरीक्षण के लिए आवेदक होता है और यह उसके और चुनाव आयोग के बीच का मामला होता है। निर्वाचन आयोग को निरीक्षण के लिए *प्रथम दृष्टया* मामले के संबंध में संतुष्ट होना पड़ता है जो संतुष्टि व्यक्तिपरक है। चुनाव आयोग संविधान, अधिनियम और नियमों के तहत एक प्रशासनिक प्राधिकरण है और इसे नियम 93 के तहत यह शक्ति प्रदान की गई है। इसलिए, उनका आदेश प्रशासनिक प्रकृति का है और केवल इसलिए अर्ध-न्यायिक नहीं बन जाता है क्योंकि नियम के अनुसार उन्हें निरीक्षण की अनुमति देने के अपने कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग के आदेश को इस आधार पर लागू नहीं किया जा सकता है कि यह प्रतिवादी 3 द्वारा लगाए गए तथ्य के आरोपों को निर्धारित नहीं करता है जिन्हें गंभीर माना गया था और जिसके विश्वास पर उन्होंने खुद को संतुष्ट किया था कि प्रतिवादी 3 द्वारा मांगे गए चुनाव पत्रों के निरीक्षण की अनुमति देने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था। इस संबंध में, इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें पांच न्यायाधीश शामिल हैं। पंजाब राज्य बनाम *भगत राम पतंगा*[49] उस मामले में लागू आदेश निम्नानुसार था -

> "जबकि पंजाब के राज्यपाल श्री भगत राम पतंगा, सदस्य, नगरपालिका समिति, फगवाड़ा को पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 की धारा 16 के परंतुक के तहत स्पष्टीकरण देने का अवसर देने के बाद, संतुष्ट हैं कि उक्त श्री भगत राम पतंगा ने उक्त समिति के सदस्य के रूप में अपने पद का दुरुपयोग किया है:
>
> अब, इसलिए, उपर्युक्त धारा 16 की उप-धारा (1) के खंड (ई) के तहत उन्हें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न ही पंजाब सरकार उक्त श्री भगत को हटाने की कृपा करती है।

[49] I.L.R (1969) 2Pb & Hr. 347

राम पतंगा को सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से फगवाड़ा नगर समिति की सदस्यता से हटा दिया गया है और उक्त श्री भगत राम पतंगा को उक्त तिथि से तीन साल की अवधि के लिए उक्त धारा 16 की उपधारा (2) के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है।

पीठ के समक्ष अपील में यह आग्रह किया गया था कि सरकार द्वारा पारित आदेश अर्ध-न्यायिक था और किए गए निर्णय के लिए आदेश में कारण बताए जाने थे और आदेश में श्री भगत राम पतंगा को फगवाड़ा नगर समिति की सदस्यता से हटाने और उन्हें अयोग्य ठहराने का कोई कारण नहीं था। पीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सरकार द्वारा पारित आदेश एक अर्ध-न्यायिक था और इसे एक मौखिक आदेश होना चाहिए, लेकिन इसमें कारण शामिल थे और इसलिए, यह सही था। उस निष्कर्ष पर आते समय, पीठ ने सरकार द्वारा प्रस्तुत फाइल को देखा और इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इस मामले पर गृह मंत्री द्वारा विचार किया गया था, जो पोर्टफोलियो के प्रभारी मंत्री और मुख्यमंत्री थे और उन्होंने प्रतिवादी के खिलाफ मामले में अपना दिमाग लगाया था। कानूनी स्मरणकर्ता की सलाह भी मांगी गई थी और यद्यपि प्रतिवादी के खिलाफ आरोप निर्धारित नहीं किए गए थे, आदेश में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रतिवादी के संबंध में गृह मंत्री अपने निर्णय तक पहुंचने की प्रक्रिया की रूपरेखा कार्यकारी फाइल में पाए जाने थे। आक्षेपित आदेश को वैध ठहराया गया था। तर्क की समानता पर, वर्तमान मामले में फाइल के संदर्भ से उस सामग्री का खुलासा होता है जो चुनाव आयोग के समक्ष थी, जिस पर उन्होंने संतुष्ट महसूस किया कि निरीक्षण की अनुमति देने में आसानी हुई थी और इस आशय का आदेश पारित किया। उस समय उन्हें यह निर्धारित करने के लिए बुलाया या अधिकृत नहीं किया गया था कि प्रतिवादी 3 के पक्ष में डाले गए वोट, जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया था, या याचिकाकर्ता के पक्ष में गिने गए वोट जो कथित रूप से अवैध थे, वास्तव में ऐसा था। जैसा कि प्रतिवादी 3 द्वारा आरोप लगाया गया है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि न्याय और चुनावों की शुद्धता के हित में, इस मामले को आगे देखने की आवश्यकता है और इसलिए, निरीक्षण न केवल वांछनीय था, बल्कि उचित भी था। याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादी 3 द्वारा अपने आवेदन में लगाए गए आरोपों की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए, चुनाव आयोग को प्रतिवादी 3 को निरीक्षण की अनुमति देने से पहले मतपत्रों को मंगाना चाहिए था और स्वयं उनका निरीक्षण करना चाहिए था। मेरी राय में, यदि इस पाठ्यक्रम को चुनाव आयोग द्वारा अपनाया गया होता, तो यह निरर्थक कवायद होती।

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग आदि
(तुली, जे।

क्योंकि मतपत्रों को देखने के बाद वह पोन्नुस्वामी के मामले (1) *में फैसले को देखते हुए एक या दूसरे तरीके से अपना फैसला नहीं दे सकते* थे। उस स्तर पर उन्हें निरीक्षण के लिए आवेदन में लगाए गए आरोपों तक खुद को सीमित रखना पड़ा और मामले में आगे कोई जांच नहीं कर सके। वह केवल आरोपों की प्रकृति, सार और गुणवत्ता पर अपना मन बना सकते थे और उसके आधार पर अपना आदेश पारित कर सकते थे। निरीक्षण की अनुमति देने का कारण लगाए गए आरोपों की गंभीरता या अन्यथा को संदर्भित करना था और यही कारण चुनाव आयोग के आदेश में बताया गया है। कोई भी यह समझने में विफल है कि चुनाव आयोग इस मामले में लगाए गए आरोपों की शुद्धता या अन्यथा के बारे में अपनी राय व्यक्त किए बिना किसी अन्य कारण को दर्ज कर सकता है। आदेश स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उन्होंने मामले के तथ्यों पर अपना दिमाग लगाया और पारित आदेश मनमाने ढंग से नहीं किया गया था, इसके समर्थन में रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं थी।

107. विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करता है कि चुनाव आयोग के लिए यह आवश्यक था कि वह याचिकाकर्ता को संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उस आदेश को चुनौती देने के लिए इस न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करने में सक्षम बनाने के लिए एक स्व-निहित आदेश पारित करे, जब तक कि आदेश स्व-निहित न हो। वह उसी को चुनौती देने में विकलांग है। यह अनुमान लगाना मेरे लिए नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति के लिए आवेदन दायर किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के उनके न्यायमूर्ति इस तरह के आदेश पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन जहां तक इस न्यायालय का संबंध है, यह मामले के रिकॉर्ड को मंगाने के लिए बाध्य है ताकि *सर्टिओरी* की रिट जारी की जा सके, जिसके लिए प्रार्थना की गई है और यह निर्धारित करने के लिए रिकॉर्ड को देख सकता है कि क्या आक्षेपित आदेश के समर्थन में सामग्री थी। जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, इस मामले में मूल रूप से जो आदेश लागू किया गया था, वह 16 मार्च, 1971 का आदेश था, और वह आदेश नियम 93 की आवश्यकताओं का पूर्ण रूप से अनुपालन करता है। प्रतिवादी 3 के विद्वान वकील ने हमारे ध्यान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो फैसले लाए, जिन्हें 16 मार्च, 1971 के आदेश में संदर्भित किया गया है। इन दोनों मामलों में, लागू आदेश 16 मार्च के आदेश की तरह था। 1971 में, इस मामले में और उन आदेशों की प्रस्तावना निर्वाचन क्षेत्र के नाम को छोड़कर समान शब्दों में थी। इसलिए, उन आदेशों में से एक नीचे निर्धारित किया गया है: –

"और जबकि आवेदक ने कहा है कि वह उक्त बिधूना विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित उम्मीदवार के चुनाव के खिलाफ चुनाव याचिका दायर करने का इरादा रखता है;

और जबकि लौटे हुए उम्मीदवार और अगले स्थान पर आने वाले उम्मीदवार के बीच वोटों के अंतर का अंतर

उक्त निर्वाचन क्षेत्र में वोटों की सबसे बड़ी संख्या बहुत कम है और मतपत्रों के निरीक्षण के बिना एक उचित याचिका दायर नहीं की जा सकती है।

इन आदेशों को नियम 93 के प्रावधानों के अनुरूप माना गया और इसलिए वे वैध हैं। ये निर्णय विभिन्न बिंदुओं पर मेरे द्वारा ऊपर लिए गए दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं।

108. यहां यह उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति ने कई मामलों में इस बात पर जोर दिया है कि जहां *सरकार के उच्च अधिकारियों के खिलाफ दुर्भावना का आरोप लगाया गया है, वहां रिट याचिकाओं को खारिज नहीं किया जाना चाहिए,* बल्कि स्वीकार किया जाना चाहिए और मामले की जांच की जानी चाहिए। कुछ रिट याचिकाओं को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, *हालांकि उनमें* दुर्भावना के आरोप थे और संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अपील में, उनके न्यायमूर्ति ने उन मामलों को स्वीकार करने के लिए इस न्यायालय को सौंप दिया और दोनों पक्षों को सुनने के बाद गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया, तर्क की समानता पर, यह मानना वैध है कि जब चुनाव से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ पक्षपात या मा-प्रथाओं *के आरोप* लगाए गए थे, जो सभी पंजाब सरकार के कर्मचारी थे, और मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल था, चुनाव आयोग ने यह पता लगाने के लिए चुनाव पत्रों के निरीक्षण की अनुमति देना उचित समझा कि प्रतिवादी 3 द्वारा लगाए गए आरोप चुनावों की शुद्धता, निष्पक्षता और निष्पक्ष संचालन के हित में सही थे या नहीं, जिसके लिए वह पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके द्वारा दर्ज किया गया कारण बहुत संक्षिप्त है और स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, लेकिन संदर्भ में यह बहुत कुछ कहता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त आदेश में कोई कारण नहीं है। इस न्यायालय को यह निर्धारित करने के लिए नहीं बुलाया जाता है कि चुनाव आयोग द्वारा दर्ज किए गए कारण पर्याप्त हैं या नहीं। यह हो सकता है कि उन्हें बेहतर भाषा में या अधिक विवरण में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन उस आधार पर आक्षेपित आदेश को तब तक रद्द नहीं किया जा सकता है जब तक कि यह नहीं पाया जाता कि इसका समर्थन करने के लिए कोई सामग्री नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग का 15 मार्च का आदेश जारी है। 1971, और 16 मार्च, 1971; इसे इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि उनमें कारण नहीं हैं।

109. यह जी वीरप्पा पिल्लई *बनाम रमन एंड रमन लिमिटेड*[50]उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति द्वारा किया गया था,संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिटों के संदर्भ में कि-

> "अनुच्छेद 226 में संदर्भित इस तरह की रिट स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय को उन्हें गंभीर रूप से जारी करने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से हैं। ऐसे मामले जहां अधीनस्थ न्यायाधिकरण या निकाय या अधिकारी पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना, या उससे अधिक, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए कार्य करते हैं, या उनमें

[50] A.I.R 1952 S.C 192.

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(तुली, जे।

निहित अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से इनकार करते हैं, या रिकॉर्ड के चेहरे पर एक त्रुटि स्पष्ट है, *और इस तरह के कार्य, चूक, त्रुटि या अधिकता के परिणामस्वरूप स्पष्ट अन्याय हुआ है।* हालांकि, क्षेत्राधिकार व्यापक हो सकता है, यह इतना व्यापक या बड़ा नहीं है कि उच्च न्यायालय खुद को अपील की अदालत में परिवर्तित कर सके और लागू किए गए निर्णयों की शुद्धता की जांच कर सके और यह तय कर सके कि उचित दृष्टिकोण क्या है या आदेश दिया जाना है।

जहां तक मैं जानता हूं, इन टिप्पणियों को उनके न्यायमूर्ति द्वारा उसके बाद दिए गए विभिन्न निर्णयों में दोहराया गया है और इससे असहमति नहीं जताई गई है। रिट याचिका में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि याचिकाकर्ता को किसी भी अन्याय का सामना करना पड़ा है, आक्षेपित आदेश के परिणामस्वरूप एक प्रकट अन्याय तो बिल्कुल भी नहीं। इस आशय का एक पैराग्राफ आमतौर पर प्रत्येक रिट याचिका में पाया जाता है, लेकिन यह वर्तमान रिट याचिका में काफी अनुपस्थित है ताकि भले ही लागू आदेश नियमों 93 की आवश्यकता का कड़ाई से या शाब्दिक रूप से अनुपालन न करे, लेकिन याचिकाकर्ता के परिणामस्वरूप स्पष्ट अन्याय होने की अनुपस्थिति में आदेश को उस आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। चुनाव आयोग के पास निरीक्षण की अनुमति देने का अधिकार है और इसलिए, आक्षेपित आदेश को अधिकार क्षेत्र के बिना या इससे अधिक में पारित नहीं कहा जा सकता है। जब हमने इस पहलू को याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के सामने रखा, तो उन्होंने जोरदार आग्रह किया कि याचिकाकर्ता के साथ स्पष्ट अन्याय किया गया है क्योंकि उसके मतपत्रों पर गौर किया जाएगा। याचिकाकर्ता द्वारा अपने पक्ष में डाले गए मतों को मतपत्र कहना गलत धारणा है। कोई भी उम्मीदवार यह दावा नहीं कर सकता कि उसके पक्ष में डाले गए वोट उसकी संपत्ति हैं और उस पर गौर नहीं किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा आयोजित चुनाव के रिकॉर्ड से मतपत्र और अन्य चुनाव पत्र और उसके द्वारा नामित या नियमों में बताए गए अधिकारियों के माध्यम से उसकी हिरासत में हैं। अधिनियम की नीति है कि धारा 94 और 128 में जोर दिया गया मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखी जाए, लेकिन किसी भी उम्मीदवार या मतदाता को यह कहने का अधिकार नहीं है कि मतपत्रों को नहीं देखा जाना चाहिए और यदि उन्हें देखा जाता है, तो यह किसी भी अधिकार का उल्लंघन करेगा। उसका। नियम 93 के तहत चुनाव आयोग या सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण के आदेश के बिना मतपत्रों और अन्य चुनाव पत्रों का निरीक्षण या किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति को उन कागजातों का निरीक्षण करने या यह आग्रह करने का अधिकार नहीं है कि उनका निरीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। यह जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग या सक्षम न्यायालय या अधिकरण की है। निरीक्षण की अनुमति देने वाला आदेश पारित करते समय, चुनाव आयोग, सक्षम न्यायालय या ट्रिब्यूनल को मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखने के समग्र सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा और उस शर्त के अधीन निरीक्षण की अनुमति दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा आगे आग्रह किया जाता है कि गिने गए और खारिज किए गए मतपत्रों और मतदाता सूची की चिह्नित प्रति के निरीक्षण की अनुमति दी गई है और यदि इन पत्रों का एक साथ निरीक्षण किया जाता है, तो मतपत्र की गोपनीयता का उल्लंघन होगा। मुझे खेद है, मैं उस निवेदन से सहमत नहीं हो सकता। यदि मतपत्र की गोपनीयता नहीं रखी जा सकती है तो जिला निर्वाचन अधिकारी किसी भी चुनाव पत्र के निरीक्षण की अनुमति नहीं देंगे। इस संबंध में एक स्पष्ट निर्देश 16 मार्च, 1971 को जिला निर्वाचन अधिकारी को सूचित किए गए आदेश में निहित है। न्यायालय में यह प्रदर्शित किया गया था कि गोपनीयता को बनाए रखा जा सकता है यदि। मतपत्रों का निरीक्षण करने

की अनुमति दी गई। आदेश के अनुसार, मतपत्रों का निरीक्षण और सील किए जाने के बाद मतदाता सूची की एक चिह्नित प्रति का निरीक्षण किया जाना है, ताकि मतपत्रों के साथ-साथ मतदाता सूची की चिह्नित प्रति का एक साथ निरीक्षण न हो। मतपत्रों के निरीक्षण की अनुमति देते समय, जिला निर्वाचन अधिकारी मतपत्रों की संख्या और 'पीठासीन अधिकारी' का समर्थन मतपत्र पर किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में लगाए गए निशान को दिखाए बिना अपनी पीठ पर दिखा सकते हैं। इस प्रकार यह खुलासा नहीं किया जाएगा कि विशेष वोट किसके पक्ष में डाला गया था। इसी तरह, मतदाता सूची की चिह्नित प्रति में, बाकी सब कुछ छिपाने के बाद, एक मतदाता को जारी किए गए मतपत्र की संख्या को यह बताए बिना दिखाया जा सकता है कि यह किसे जारी किया गया था। सीरियल नंबर और मतदाता का नाम छिपाया जा सकता है और अकेले जारी किए गए मतपत्र की संख्या दिखाई जा सकती है। प्रतिवादी 3 का आरोप है कि लगभग 15,000 मतपत्र मतदाताओं को जारी नहीं किए गए थे, लेकिन उन्हें चिह्नित करने के बाद कुछ अकालियों द्वारा मतदान किया गया है। उस आरोप की सत्यता को सत्यापित करने के लिए निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति से जो दिखाया जाना आवश्यक है, वह यह है कि मतपेटियों में पाए गए मतपत्र भुगतानकर्ता वास्तव में निर्वाचकों को जारी किए गए थे और यह अभी बताए गए तरीके से निरीक्षण की अनुमति देकर किया जा सकता है। किसी भी सफल उम्मीदवार को यह बनाए रखने का अधिकार नहीं है कि उसके पक्ष में डाले गए मतपत्रों का निरीक्षण नहीं किया जाना चाहिए, भले ही वे अमान्य या शून्य थे और गलत तरीके से स्वीकार किए गए थे क्योंकि उन्हें यह बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है कि वह निर्वाचित रहने के हकदार हैं, भले ही चुनाव निष्पक्ष रूप से आयोजित न किया गया हो। एक

इसलिए, निरीक्षण की अनुमति देने वाला आदेश, चुनावों के निष्पक्ष और निष्पक्ष संचालन के संबंध में किसी भी तरह से लौटे उम्मीदवार के किसी भी अधिकार या हितों को चोट नहीं पहुंचाता है। ऊपर उल्लिखित तर्कों के अलावा, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील यह दिखाने में सक्षम नहीं हैं कि आक्षेपित आदेश से याचिकाकर्ता के किस कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है- इसलिए, मेरी राय है कि याचिकाकर्ता उसके द्वारा मांगी गई राहत का हकदार नहीं है, भले ही कुछ तकनीकी आधारों पर यह कहा जा सकता है कि आक्षेपित आदेश नियम 93 के प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं करता है। हालांकि, मेरी राय है कि लागू आदेश नियम 93 की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और इसलिए, वैध है।

110. ऊपर दिए गए कारणों के लिए, इस याचिका को खारिज कर दिया गया है, लेकिन मामले में शामिल कानून के सवालों की जटिलता और कठिन प्रकृति को देखते हुए लागत के बारे में किसी भी आदेश के बिना, जिसके लिए दोनों पक्षों पर लंबी बहस की आवश्यकता थी।

न्यायमूर्ति पी.सी. पंडित,।

111. मैंने नरूला जे और तुली जे द्वारा तैयार किए गए दो निर्णयों का अध्ययन किया है, मैं तुली जे से पूरी तरह सहमत हूं, कि रिट याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए, लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है। हालांकि, मैं दो मुख्य बिंदुओं पर कुछ शब्द जोड़ना चाहता हूं, जिन पर हमें काफी तर्क संबोधित किए गए थे।

112. पहला मुद्दा यह है कि क्या चुनाव आयोग का आदेश प्रशासनिक है या अर्ध-न्यायिक है। निर्वाचन आयोग द्वारा पारित निर्वाचन संचालन नियमावली, 1961 के नियम 93 में उल्लिखित निर्वाचन पत्रों के निरीक्षण या उत्पादन का आदेश किसी भी पक्ष के अधिकारों का निर्धारण नहीं करता है, क्योंकि न तो किसी को इन पत्रों के निरीक्षण या उत्पादन का दावा करने का अधिकार है और न ही उक्त कागजात किसी व्यक्ति के हैं। आयोग के पास मतपत्रों की वैधता या अन्यथा पर फैसला सुनाने का कोई अधिकार नहीं है। वह केवल इतना कर सकता है कि प्रतिवादी को उन्हें देखने और निरीक्षण करने की अनुमति दे। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार, चुनाव आयोग को संसद के सभी चुनावों को आयोजित करने के लिए एकमात्र प्राधिकरण का गठन किया गया है और उसे यह देखना है कि वे निष्पक्ष और निष्पक्ष तरीके से आयोजित किए जाएं। यदि उनसे शिकायत की जाती है कि मतदान या मतगणना के दौरान गलत कार्य किए गए थे, जो कि उपयोग किए गए और अप्रयुक्त दोनों मतपत्रों के निरीक्षण और मतदाता सूची की चिह्नित प्रति से स्पष्ट होगा, तो यह उन्हें तय करना है कि उन्हें निरीक्षण की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। किसी भी पार्टी को नोटिस जारी करने के लिए उन पर कोई कर्तव्य नहीं डाला गया है या

किसी भी व्यक्ति को उसके निर्णय पर आने से पहले सुनें। नियम 93 द्वारा इस प्रकार की कोई जांच भी निर्धारित नहीं की गई है। उस स्तर पर उनके आदेश की तुलना दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 या 197-ए या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 6 के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा दी जाने वाली मंजूरी से की जा सकती है और किसी ने भी अभी तक यह सुझाव नहीं दिया है कि दोषी लोक सेवक या भारतीय शासक के अभियोजन को मंजूरी देने वाला आदेश एक अर्ध-न्यायिक है जिसे व्यक्ति के खिलाफ नोटिस के बाद पारित किया जाना चाहिए। जिन पर मुकदमा चलाने का प्रस्ताव है। केवल कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि चुनाव पत्रों के निरीक्षण की अनुमति देने वाला चुनाव आयोग द्वारा किया जाने वाला आदेश अर्ध-न्यायिक है और इसे प्राकृतिक न्याय के नियमों या अर्ध-न्यायिक आदेश बनाने के लिए आमतौर पर आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने के बाद पारित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, जब चुनाव आयोग की केवल *प्रथम दृष्टया संतुष्टि* का सवाल है , तो उनके आदेश को अर्ध-न्यायिक नहीं कहा जा सकता है। आदेश अर्ध-न्यायिक नहीं होने के कारण किसी नोटिस की आवश्यकता नहीं है। मेरा विचार है कि आयोग का यह कोई कर्तव्य नहीं है कि वह लौटाए गए उम्मीदवार या अन्य उम्मीदवारों को नोटिस जारी करे ताकि उन्हें निरीक्षण की अनुमति देने के विरुद्ध कारण दिखाने का अवसर मिल सके।

113. मामले पर दूसरे तरीके से विचार किया जा सकता है। इस बात पर सहमति है कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव अपराधों की जांच या परीक्षण के प्रयोजनों के लिए चुनाव पत्रों के निरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है। क्या यह कहा जा सकता है कि किसी जांच अधिकारी को निरीक्षण की अनुमति देने से पहले, आयोग को नोटिस जारी करना चाहिए या अपराधी को सुनना चाहिए, या निरीक्षण की अनुमति देने वाला उक्त आदेश अर्ध-न्यायिक होगा? फिर इसे अलग तरीके से कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि निरीक्षण का उद्देश्य एक चुनाव याचिका के लिए सामग्री इकट्ठा करना है? पार्टियों के विवादों को निपटाना चुनाव आयोग का काम नहीं है। चूंकि आयोग पार्टियों के बीच मुद्दे में किसी भी बिंदु पर फैसला नहीं करता है, इसलिए लौटने वाले उम्मीदवार को कोई नोटिस आवश्यक नहीं है। इसलिए, मेरा विचार है कि चुनाव आयोग द्वारा पारित निरीक्षण की अनुमति देने वाला आदेश प्रशासनिक चरित्र का है और यह अर्ध-न्यायिक नहीं है और इसे पारित करने से पहले लौटाए गए उम्मीदवार या किसी अन्य उम्मीदवार को कोई नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरण पर लागू मानक आयोग पर लागू नहीं होते हैं, जब वह नियम 93 के तहत आदेश पारित करता है। जिस तरह अभियोजन को मंजूरी देने वाले आदेश को उचित कार्यवाही में चुनौती दी जा सकती है, उसी तरह निरीक्षण की अनुमति देने वाले आदेश को भी चुनौती दी जा सकती है। लेकिन हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि लौटा हुआ उम्मीदवार अदालत के समक्ष सुनवाई के अधिकार का दावा कर सकता है आदेश जारी होने से पहले या आदेश अवैध या दूषित हो जाता है क्योंकि उसे सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था।

114. नोटिस या सुनवाई के अवसर पर, एक और विचार भी है जो इसके खिलाफ है। लोक सभा और विभिन्न राज्य विधानसभाओं की

विधानसभाओं के चुनाव में, यह उम्मीद की जा सकती है कि निरीक्षण के लिए आवेदन काफी बड़ी संख्या में हारे हुए उम्मीदवारों से प्राप्त होंगे और यदि उन आवेदनों पर सुझाव के अनुसार अन्य उम्मीदवारों को नोटिस के बाद निर्णय लिया जाता है, तो इसमें बहुत लंबा समय लगेगा और निरीक्षण के उद्देश्य को भी निराश कर सकता है। अगर अखबारों की खबरों पर यकीन किया जाए तो इस साल हुए मध्यावधि पोल में निरीक्षण के लिए बड़ी संख्या में आवेदन वास्तव में मिले थे और उन सभी का निपटारा बिना किसी अन्य व्यक्ति को नोटिस दिए कर दिया गया था। याचिकाकर्ता का यह मामला नहीं है कि कुछ मामलों में नोटिस जारी किया गया, जबकि अन्य में ऐसा नहीं किया गया। चुनाव आयोग ने किसी अन्य उम्मीदवार को नोटिस नहीं भेजने या सुनने का अवसर नहीं देने की एक समान प्रक्रिया का पालन किया।

115. दूसरा सवाल यह है कि क्या इस मामले में चुनाव आयोग के आदेश में कारण शामिल हैं और इस प्रकार नियम 93 (3) के परंतुक (ए) की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। चूंकि आदेश एक प्रशासनिक है, इसलिए इसे उस सामग्री को बताने की आवश्यकता नहीं है जिस पर विचार करते हुए इसे पारित किया गया है। इस उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड देखा जा सकता है जैसा कि पंजाब राज्य बनाम *भगत राम पतंगा* मामले में इस न्यायालय के पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया गया था। यह पता लगाने के लिए कि क्या आयोग द्वारा उचित दिमाग लगाया गया है और आदेश मनमाने ढंग से पारित नहीं किया गया है। कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता संभवतः चुनाव आयोग में निहित शक्तियों के मनमाने प्रयोग को खारिज करने के लिए निर्धारित की गई है। आवेदन या निरीक्षण में लगाए गए आरोपों के प्रकाश और पृष्ठभूमि में आदेश को पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि आयोग ने अपना दिमाग लगाया और आरोपों को गलत या तुच्छ नहीं पाया और इसलिए, निरीक्षण की अनुमति देने का फैसला किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जानबूझकर सधी हुई भाषा का इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्हें न तो बुलाया गया था और न ही यह तय करने के लिए अधिकृत किया गया था कि लगाए गए आरोप सही हैं या गलत। पुनर्मतगणना की अनुमति नहीं देने वाले निर्वाचन अधिकारी के आदेश का आवेदक ने निरीक्षण के लिए अपने आवेदन में विशेष रूप से उल्लेख किया था और बाद में अधिकारी के खिलाफ *दुर्भावना* का आरोप लगाया गया था।

आदेश में बाद में जोड़ा गया भी इंगित करता है कि पर्यवेक्षक की रिपोर्ट भी उनके ध्यान में लाई गई थी और जिसके आधार पर उन्होंने उस अधिकारी के संबंध में आदेश बदल दिया, जिसे निरीक्षण में उपस्थित होना था। चुनाव आयोग के आदेश की व्याख्या निस्संदेह उस आवेदन के साथ की जानी चाहिए जिसके आधार पर यह किया गया था। वर्तमान मामले में उस समय उनके समक्ष पर्याप्त सामग्री थी जब आक्षेपित आदेश पारित किया गया था। यहां तक कि ऑब्जर्वर की रिपोर्ट ने एक तरह से प्रतिवादी नंबर 3 के आरोपों का समर्थन किया कि मतगणना के अंतिम दिन पूर्व द्वारा जांचे गए 50 मतपत्रों के बंडल में कुछ नकली वोट थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक बंडल में एक या दो ऐसे वोट थे। आवेदन से पहले प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा भेजे गए सभी टेलीग्राम और अभ्यावेदन, जिस पर विवाद में आदेश पारित किया गया था, आयोग के समक्ष थे, सभी दस्तावेजों को एक साथ पढ़ने पर, निरीक्षण के आदेश को सही ठहराने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। चुनाव आयोग के आदेश में बताया गया कारण, मेरी राय में, उपर्युक्त परंतुक की आवश्यकताओं का पूरी तरह से अनुपालन करता है और आदेश को इस आधार पर अवैध या अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं ठहराया जा सकता है कि यह कारण को दर्ज नहीं करता है। आयोग और क्या कह सकता है? जब उन्हें यह तय नहीं करना था कि प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा लगाए गए आरोप सही हैं या नहीं, तो उनके बारे में जांच शुरू करने और सबूत लेने का कोई मतलब नहीं था।

116. केंद्र सरकार ने नियम 93 में संशोधन करने के लिए किसी उद्देश्य का उल्लेख नहीं किया जिसके द्वारा चुनाव आयोग को निरीक्षण की अनुमति देने का अधिकार दिया गया था। ऐसा लगता है कि उद्देश्य तुच्छ चुनाव याचिकाओं से बचना है और केवल एक गंभीर चुनाव याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका दायर करने के लिए सामग्री इकट्ठा करने की अनुमति देता है और इस प्रकार समय और खर्च बचाता है। आयोग के पास चुनाव की शुद्धता के हित में निरीक्षण का आदेश देने का अधिकार है। यदि उसके समक्ष रखे गए तथ्यों पर, वह संतुष्ट है कि इस तरह का निरीक्षण आवेदक को सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनावों की शुद्धता से संबंधित गंभीर मामलों को उठाने या न्याय के अंत को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है, तो उसके पास ऐसा करने की शक्ति है। जरूरत इस बात की है कि उनका आदेश मनमाना या अप्रासंगिक विचारों पर आधारित न हो। इस मामले में ऐसी स्थिति नहीं है।

117. वर्तमान जैसे मामले में, मेरा विचार है कि इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इस तरह चुनाव की अशुद्धता को प्रकाश में आने से रोकना चाहिए। मेरा यह भी विचार है कि यदि यह न्यायालय आक्षेपित आदेश को रद्द करने का निर्णय लेता है, तो भी उसे या तो जारी करना चाहिए।

चुनाव आयोग को कारण बताने या एक नया आदेश पारित करने के लिए उसे खुला छोड़ने का आदेश दिया गया है, जिसे कारणों से समर्थित किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति गुरदेव सिंह।

गुरदास सिंह बादल बनाम गुरदास निर्वाचन आयोग, आदि।
(गुरदेव सिंह, जे।

118. मैंने अपने विद्वान भाइयों द्वारा ऊपर दर्ज की गई राय को ध्यान से पढ़ा है, लेकिन याचिका को खारिज करने में पीसी पंडित और बीआर तुली जेजे के साथ सहमत होने में असमर्थता पर खेद है। इसके विपरीत, मैं नरूला जे, जिनके साथ महाजन जे ने सहमति व्यक्त की है, से सहमत हूं कि भारत के निर्वाचन आयोग के आक्षेपित आदेश में इसके कारण शामिल नहीं हैं और इस प्रकार चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93 के परंतुक (ए) की अनिवार्य आवश्यकता का उल्लंघन करना स्पष्ट रूप से अवैध है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। वास्तव में, मेरी यह राय है कि आयोग ने मतपत्रों और मतदाता सूची की चिह्नित प्रतियों के निरीक्षण की अनुमति देकर अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया ताकि श्री इकबाल सिंह एक चुनाव याचिका द्वारा उचित अदालत में अपना कानूनी उपचार प्राप्त कर सकें, जैसा कि 16 मार्च के औपचारिक आदेश में कहा गया है। 1971 (याचिका का अनुलग्नक डी) जिस पर प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा अपने तर्क के समर्थन में काफी भरोसा किया गया है कि आदेश वैध और पर्याप्त कारणों से किया गया है। इस संबंध में, मैं संबंधित प्रावधान के अंतर्गत निर्वाचन आयोग में निहित शक्तियों के दायरे और सीमा के संबंध में कुछ शब्द कहना चाहूंगा। '

119. नियम 93 के तहत, जैसा कि आज है, मतपत्रों के पैकेट ोंं को खोलने, निरीक्षण करने और प्रस्तुत करने का आदेश देने की शक्ति और इसके उप-नियम (1) के खंड (ए) से (डी) में निर्दिष्ट मतदाता सूची और अन्य दस्तावेजों की चिह्नित प्रतियां न केवल चुनाव आयोग को दी गई हैं, बल्कि एक सक्षम न्यायालय और ट्रिब्यूनल को भी दी गई हैं। जैसा कि मूल रूप से तैयार किया गया था, मतपत्रों आदि के निरीक्षण की अनुमति देने की यह शक्ति केवल एक सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण में निहित है। "एक सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण" शब्द चुनाव याचिका की सुनवाई करने वाले चुनाव न्यायाधिकरण या न्यायालय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें चुनाव अपराध की सुनवाई करने वाले न्यायालय भी शामिल हैं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत, जैसा कि मूल रूप से अधिनियमित किया गया था, एक चुनाव याचिका की सुनवाई एक चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा की जानी थी। चुनाव याचिका की सुनवाई के दौरान निरीक्षण की अनुमति देने के लिए एक चुनाव न्यायाधिकरण (अब उच्च न्यायालय द्वारा) को प्राप्त शक्तियों के दायरे और सीमा पर कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति द्वारा विचार किया गया है। सबसे पहले

इन मामलों में। *राम सेवक यादव बनाम हुसैन कामिल किदवई और अन्य,* यह निम्नानुसार देखा गया: –

"निरीक्षण के लिए एक आदेश निश्चित रूप से नहीं दिया जा सकता है: मतपत्रों की गोपनीयता पर जोर देने के संबंध में, न्यायालय > में उचित होगा। निरीक्षण के लिए आदेश प्रदान करना बशर्ते दो शर्तों को पूरा किया गया हो:

1. कि चुनाव को रद्द करने के लिए याचिका में उन भौतिक तथ्यों का पर्याप्त विवरण शामिल है जिन पर याचिकाकर्ता अपने मामले के समर्थन में भरोसा करता है; और
2. ट्रिब्यूनल *प्रथम दृष्टया* संतुष्ट है कि विवाद का फैसला करने और पार्टियों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए मतपत्रों का निरीक्षण आवश्यक है।

लेकिन मतपत्रों के निरीक्षण का आदेश याचिका में की गई अस्पष्ट दलीलों का समर्थन करने या ऐसी दलीलों के समर्थन में सबूत निकालने के लिए नहीं दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता के मामले को भौतिक तथ्यों के कथनों द्वारा समर्थित सटीकता के साथ निर्धारित किया जाना चाहिए। इस तरह *से पेश किए गए मामले को स्थापित करने* के लिए, निस्संदेह, यदि न्याय के हितों की आवश्यकता हो, तो निरीक्षण के लिए एक आदेश दिया जा सकता है। लेकिन केवल एक आरोप कि याचिकाकर्ता को संदेह है या विश्वास है कि वोटों का अनुचित स्वागत, इनकार या अस्वीकृति हुई है, निरीक्षण के आदेश का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रत्येक चरण में विभिन्न अवसरों का उल्लेख किया जो एक उम्मीदवार या उसके एजेंट के पास जांच और वोटों की गिनती की प्रक्रिया में यह जानने के लिए होते हैं कि क्या हो रहा है। इसी नियम को हाल ही में जितेंद्र बहादुर सिंह बनाम *कृष्ण बहन और अन्य मामले में भी दोहराया गया* था।, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि ट्रिब्यूनल को *प्रथम दृष्टया* संतुष्ट होना चाहिए कि चुनावी विवाद का फैसला करने और पार्टियों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए, मतपत्रों का निरीक्षण आवश्यक है। इस प्रकार, जहां तक किसी *चुनाव याचिका की सुनवाई करने वाले न्यायाधिकरण या न्यायालय* का संबंध है, यह अधिकारपूर्वक तय है कि वह साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरीक्षण की अनुमति नहीं दे सकता है या उन भौतिक तथ्यों को जोड़ने की दृष्टि से नहीं दे सकता है जिन्हें अधिनियम की धारा 83 के तहत एक चुनाव याचिका में शामिल करना आवश्यक है।

120. यह सच है कि निरीक्षण के प्रश्न से निपटने के लिए जिन स्थितियों में चुनाव आयोग, ट्रिब्यूनल की अदालत को बुलाया जा सकता है, वे अलग-अलग होंगी, और इस प्रकार निरीक्षण की अनुमति देने के लिए उनके अधिकार का दायरा और जिन उद्देश्यों के लिए इन अधिकारियों द्वारा ऐसा आदेश दिया जा सकता है, वे समान नहीं हो सकते हैं, लेकिन इससे हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं कि चूंकि चुनाव आयोग को मतपत्रों आदि के निरीक्षण के सवाल से निपटने के लिए बुलाया जा सकता है, जब कोई चुनाव याचिका स्थापित नहीं की गई है या लंबित है, तो इसकी शक्तियां अदालत या ट्रिब्यूनल की तुलना में व्यापक हैं और यह चुनाव याचिका के लिए सामग्री एकत्र करने और सबूत निकालने के लिए निरीक्षण की अनुमति दे सकता है। वह उद्देश्य जिसके आधार पर, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया है, एक चुनाव याचिका से निपटने वाला एक न्यायालय या न्यायाधिकरण निरीक्षण की अनुमति नहीं दे सकता है।

121. प्रतिवादी की ओर से यह तर्क दिया गया है कि चुनाव याचिका से

निपटने वाले न्यायालय की शक्ति पर यह प्रतिबंध जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83 की आवश्यकता के मद्देनजर लगाया गया है, कि एक चुनाव याचिका में भौतिक तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण होना चाहिए, और यदि भौतिक तथ्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं, तो अदालत उन्हें बनाने के लिए उन्हें जोड़ने के उद्देश्य से निरीक्षण की अनुमति नहीं देगी। सटीक है, जबकि चुनाव याचिका दायर करने से पहले चुनाव आयोग निरीक्षण की अनुमति देकर याचिकाकर्ता को अपनी चुनाव याचिका में शामिल करने के उद्देश्य से भौतिक तथ्यों को एकत्र करने का अवसर प्रदान करेगा। मेरी राय में यह तर्क तर्कसंगत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति, जो चुनाव को चुनौती देना चाहता है, नियम 93 के तहत मतपत्रों, मतदाता सूची की चिह्नित प्रतियों आदि का निरीक्षण करके अपनी चुनाव याचिका के लिए सामग्री एकत्र करने का हकदार है, तो मैं यह समझने में विफल हूं कि उसे इस तरह के निरीक्षण की अनुमति क्यों नहीं दी जानी चाहिए जब चुनाव न्यायालय पाता है कि उसके द्वारा अपनी चुनाव याचिका में दिए गए भौतिक तथ्य या तो सटीक नहीं हैं या अपर्याप्त हैं। क्या एक चुनाव-याचिकाकर्ता को पीड़ित होना चाहिए और उसे अपनी चुनाव याचिका के उद्देश्य के लिए आवश्यक सामग्री को निरीक्षण पर इकट्ठा करने के अवसर से वंचित किया जाना चाहिए, केवल इसलिए कि चुनाव अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले उसने मतपत्रों के निरीक्षण आदि के लिए चुनाव आयोग से संपर्क करने से इनकार कर दिया था? यदि उसे चुनाव याचिका के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से मतपत्रों आदि का निरीक्षण करने का अधिकार था, तो निश्चित रूप से याचिका बनाने पर उस अधिकार को हराया या खोया नहीं जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से चुनाव याचिका के लंबित रहने के दौरान किसी चुनाव याचिकाकर्ता को संबंधित मतपत्रों आदि का निरीक्षण करने का अवसर देने से इनकार करना अनुचित होगा, यदि उसे कार्यवाही शुरू करने से पहले ऐसा अधिकार था।

122. यह तर्क दिया गया है कि किसी व्यक्ति को चुनाव याचिका के लिए सामग्री एकत्र करने में सक्षम बनाने के लिए निरीक्षण की अनुमति देने की शक्ति कुछ नई नहीं है, लेकिन लंबे समय से कानून के लिए जाना जाता है। इस संबंध में मतपत्र अधिनियम 1872 की पहली अनुसूची में होने वाले नियम 40 में निहित अंग्रेजी कानून के प्रावधानों और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1948 की दूसरी अनुसूची में निहित संसदीय चुनाव नियमों के नियम 57 का संदर्भ दिया गया है। पूर्व निरीक्षण या मतपत्रों के उत्पादन की अनुमति दी जा सकती है यदि यह "मतपत्रों के संबंध में किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाने या बनाए रखने के उद्देश्य से या चुनाव या वापसी पर सवाल उठाने वाली याचिका के उद्देश्य से" आवश्यक हो। संसदीय चुनाव नियमों के नियम 57 के तहत, जिसे मेरे विद्वान भाई तुली जे द्वारा विस्तार से प्रस्तुत किया गया है, उच्च न्यायालय या काउंटी कोर्ट निरीक्षण की अनुमति देने के लिए अधिकृत है "यदि शपथ पर साक्ष्य से संतुष्ट हो कि आदेश मतपत्रों के संबंध में या चुनाव याचिका के उद्देश्य से अपराध के लिए मुकदमा चलाने या बनाए रखने के उद्देश्य से आवश्यक है।

123. अंग्रेजी कानून के ये प्रावधान, मेरी राय में, प्रतिवादी की ओर से उठाए गए तर्क को आगे बढ़ाने से दूर, इसके खिलाफ जाते हैं। यह स्पष्ट है कि वर्ष 1875 में अंग्रेजी कानून में एक चुनाव याचिका के उद्देश्य से निरीक्षण की अनुमति देने के लिए प्रावधान किया गया था, और तब से यह शक्ति उच्च न्यायालय और काउंटी न्यायालयों में निहित है। इसके बावजूद, जब 1951 में हमारी संसद द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम अधिनियमित किया गया था और इसके तहत नियम बनाए गए थे, तो चुनाव याचिका के उद्देश्य से मतपत्रों आदि के निरीक्षण की अनुमति देने के लिए ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया गया था, और नियम 93 ने केवल एक सक्षम न्यायालय या ट्रिब्यूनल को उस उद्देश्य को इंगित किए बिना निरीक्षण की अनुमति देने का अधिकार दिया था जिसके लिए निरीक्षण की अनुमति दी जानी थी। यह तर्क कि जिस उद्देश्य के लिए इस शक्ति का उपयोग किया जा सकता है, उसका इस प्रावधान में जानबूझकर उल्लेख नहीं किया गया था ताकि इसे व्यापक आयाम दिया जा सके और अंग्रेजी कानून के तहत उच्च न्यायालय या काउंटी न्यायालय द्वारा प्राप्त शक्ति की तुलना में अधिक व्यापक शक्ति प्रदान की जा सके। यदि नियम 93 का उद्देश्य उच्च न्यायालय या काउंटी न्यायालयों की शक्तियों को अंग्रेजी में व्यापक रूप से प्रदान करना था, तो निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव न्यायाधिकरण में निहित ऐसी शक्तियों से निपटते समय उन्हें खारिज नहीं किया होगा और कहा होगा कि सबूत निकालने के लिए चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

124. मतदान की गोपनीयता स्वयं संविधि द्वारा संलग्न है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 128 इसे किस पर अनिवार्य बनाती है?

ग्रुरदास सिंह बादल बनाम भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(गुरदेव सिंह, जे।

प्रत्येक अधिकारी, क्लर्क, एजेंट या अन्य व्यक्ति के लिए सजा का दर्द जो किसी चुनाव में वोटों की रिकॉर्डिंग या गिनती के संबंध में कोई कर्तव्य निभाता है, मतदान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए और किसी भी व्यक्ति को किसी भी जानकारी के संचार को प्रतिबंधित करता है जो किसी भी कानून द्वारा या उसके तहत अधिकृत उद्देश्यों को छोड़कर इस तरह की गोपनीयता का उल्लंघन करता है। नियम 93, जो कतिपय निर्वाचन पत्रों के उत्पादन और निरीक्षण का प्रावधान करता है, में ही यह निर्धारित किया गया है कि प्रयुक्त और अप्रयुक्त मतपत्रों के पैकेट, निर्वाचक नामावलियों की चिह्नित प्रतियां और निर्वाचकों द्वारा घोषणा के पैकेटों को चुनाव आयोग या सक्षम न्यायालय या अधिकरण के आदेशों के अलावा किसी व्यक्ति या प्राधिकारी के समक्ष खोला या प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। चूंकि बैलेट पेपर आदि को खोलने, निरीक्षण करने और प्रस्तुत करने की अनुमति देने का अधिकार चुनाव आयोग, एक सक्षम न्यायालय और ट्रिब्यूनल को उसी प्रावधान द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें चरण और तरीके को निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, जिसमें इन अधिकारियों को उस शक्ति का उपयोग करना है, जो क़ानून कानून (5 वें संस्करण) पर क्राइज के पृष्ठ 161 में उल्लिखित व्याख्या के नियम के अनुसार है। इन प्राधिकरणों द्वारा प्राप्त शक्तियों के दायरे को समान माना जाना चाहिए। यह सच है कि जिन परिस्थितियों में इन तीनों प्राधिकरणों को मतपत्रों आदि के निरीक्षण या उत्पादन की अनुमति देने के लिए बुलाया जा सकता है, उनकी कार्यवाही अलग-अलग होगी, लेकिन यह इस धारणा को सही नहीं ठहराएगा कि दस्तावेजों आदि को प्रस्तुत करने और निरीक्षण करने की अनुमति देने की चुनाव आयोग की शक्ति सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण में निहित शक्ति से अधिक व्यापक है। मेरी राय में, नियम 93(1) की सही व्याख्या यह है कि इस नियम में नामित इन तीन प्राधिकरणों, अर्थात् निर्वाचन आयोग, न्यायालय या अधिकरण, को मतपत्रों के निरीक्षण और उत्पादन आदि की अनुमति देने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए जिन सिद्धांतों और उद्देश्यों के लिए जाना है, वे उस कार्यवाही की प्रकृति पर निर्भर करेंगे जिसमें उनसे ऐसा आदेश देने के लिए संपर्क किया जाता है। किसी भी पक्ष के विद्वान वकील द्वारा हमारे समक्ष यह तर्क नहीं दिया गया है कि एक न्यायालय या न्यायाधिकरण मतपत्रों आदि के निरीक्षण की अनुमति देने के लिए सक्षम है, जब चुनाव से उत्पन्न कोई कार्यवाही उसके समक्ष लंबित नहीं है, और दोनों पक्षों के विद्वान वकील इस बात पर सहमत हुए कि यह केवल तभी होता है जब चुनाव के संबंध में कुछ मामला अदालत या ट्रिब्यूनल के समक्ष आता है कि ऐसा प्राधिकरण सक्षम होगा। नियम 93(1) के अधीन मतपत्रों आदि के उत्पादन और निरीक्षण की अपनी शक्ति का प्रयोग करना। यदि ऐसा है, तो यह तर्क देना अनुचित है कि चुनाव आयोग मतपत्रों आदि के उत्पादन और निरीक्षण का आदेश देने की अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है, जब कोई कार्यवाही जिसमें ऐसे पत्रों की जांच आवश्यक है, उसके समक्ष लंबित नहीं है और किसी भी समय चाहे वह चुनाव याचिका स्थापित होने से पहले हो या उसका निपटान हो जाने के बाद। इस निष्कर्ष से बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है कि चूंकि यह चुनाव के समान प्रावधान द्वारा है। आयोग, ट्रिब्यूनल और न्यायालयों को मतपत्रों के उत्पादन और निरीक्षण को खोलने की अनुमति देने का अधिकार है, और इस तरह की शक्ति का उपयोग ट्रिब्यूनल या कोर्ट द्वारा नहीं किया जा सकता है जब उनके समक्ष कोई कार्यवाही लंबित नहीं है, चुनाव आयोग के पास किसी भी समय निरीक्षण की अनुमति देने की कोई व्यापक शक्ति नहीं है, लेकिन यह केवल तभी ऐसा कर सकता है जब उसके समक्ष और उसके संबंध में कुछ कार्यवाही लंबित हो।

125. ii इस मामले से निपटने में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मूल रूप से मतपत्रों आदि के निरीक्षण और उत्पादन की अनुमति देने की शक्ति केवल एक सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण में निहित थी, और यह केवल 31 मार्च, 1962 को किए गए एक संशोधन द्वारा था; कि "चुनाव आयोग" को नियम 93 में जोड़ा गया था ताकि इसे निरीक्षण की समान शक्तियां प्रदान की जा सकें। आदि। चूंकि संशोधन एक सांविधिक आदेश द्वारा

किया गया था, इसलिए यह पता लगाना संभव नहीं है कि चुनाव आयोग को इस संशोधन या निरीक्षण आदि की शक्ति प्रदान करने की आवश्यकता क्यों थी, हालांकि, यह इंगित किया जा सकता है कि मार्च 1962 में इस संशोधन को लागू किया गया था; चुनाव याचिकाओं को निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, जिसके पास *अन्य बातों के साथ-साथ* कतिपय परिस्थितियों में इसे अस्वीकार करने की शक्ति थी। उस समय चुनाव याचिकाओं की सुनवाई निर्वाचन अधिकरणों द्वारा की जाती थी और निर्वाचन आयोग के समक्ष प्रस्तुत चुनाव याचिकाओं को ऐसे अधिकरणों द्वारा विचारण के लिए लेने से पहले कुछ समय बीत जाना पड़ता था। चूंकि निर्वाचन अधिकरण मतपत्रों के निरीक्षण और उत्पादन आदि के आवेदनों पर विचार कर सकते थे, इसलिए चुनाव याचिकाएं उनके पास पहुंचने के बाद ही मतपत्रों के निरीक्षण या उत्पादन के लिए निरीक्षण का कोई आदेश प्राप्त नहीं किया जा सकता चुनाव याचिका वास्तव में ट्रिब्यूनल तक पहुंचने से पहले, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यह चुनाव आयोग को चुनाव याचिका की प्रस्तुति और चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा इसके संज्ञान के बीच इस अंतर का प्रावधान करने के लिए था। निरीक्षण आदि की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारियों में "निर्वाचन आयोग" जोड़कर नियम 93 में संशोधन किया गया था। बाद में दिसम्बर, 1966 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में संशोधन किया गया और अधिनियम की धारा 80 में यह प्रावधान किया गया कि चुनाव याचिकाओं का विचारण उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा और धारा 81 के तहत किसी भी चुनाव पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं को सीधे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, न कि निर्वाचन आयोग को।

126. यह वर्ष 1964 में था, कि सुप्रीम कोर्ट को शक्तियों के दायरे और सीमा से निपटने के लिए बुलाया गया था।

गुरदास सिंह बादल - यू. भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(गुरदेव सिंह, जे।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के नियम 93 में निहित दस्तावेजों का निरीक्षण और प्रस्तुतीकरण राम सेवक यादव बनाम *हुसैन कामिल किदवई और अन्य* मामले में।, और *जबर सिंह* बनाम *गेंदा लाल*। यह सच है कि इन दोनों मामलों में जो प्रश्न उठे वे मतपत्रों को प्रस्तुत करने का आदेश देने के लिए चुनाव याचिका का परीक्षण करने वाले चुनाव न्यायाधिकरण की शक्तियों से संबंधित थे, फिर भी उनके न्यायमूर्ति ने नियम 93 (1) की व्याख्या की, जिसके तहत उस दिन चुनाव आयोग को भी वही शक्ति प्राप्त थी, और यह निर्धारित किया कि सबूत ोें को पकड़ने या जांच करने के उद्देश्य से निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

127. यद्यपि उन कार्यवाहियों की प्रकृति अलग-अलग होगी जिनमें दस्तावेजों के निरीक्षण या प्रस्तुत करने आदि की अनुमति देने के लिए अदालत, न्यायाधिकरण या चुनाव आयोग से संपर्क किया जा सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के उनके न्यायमूर्ति द्वारा निर्धारित इस बुनियादी नियम का पालन किया जाना चाहिए कि साक्ष्य प्राप्त करने या चुनाव याचिका के उद्देश्य से जांच करने के लिए निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अर्थात्, चुनाव आयोग, न्यायालय और अधिकरण, मतपत्रों के निरीक्षण आदि के लिए एक याचिका पर विचार करते समय। जब तक इस नियम का पालन नहीं किया जाता है, तब तक जांच का आदेश देने या सबूत ोें को बाहर निकालने के लिए जो शरारत की जाती है, वह की जाएगी। इस मामले पर गंभीरता से और सावधानीपूर्वक विचार करने पर, मैं पाता हूं-

1. कि दस्तावेजों के निरीक्षण और उत्पादन का आदेश केवल तभी किया जा सकता है जब चुनाव से उत्पन्न या उससे संबंधित कार्यवाही संबंधित प्राधिकरण के समक्ष लंबित हो, और
2. कि सुप्रीम कोर्ट के उनके न्यायमूर्ति द्वारा निर्धारित नियम *राम सेवक यादव मामला* में कि सबूतों का पता लगाना के लिए निरीक्षण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और रोविंग जांच करना न केवल चुनाव याचिका से निपटने वाले न्यायालय द्वारा देखा जाना चाहिए, बल्कि चुनाव से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले से निपटने वाले अन्य न्यायालयों, ट्रिब्यूनल या चुनाव आयोग द्वारा देखा जाना चाहिए, जैसे कि चुनाव अपराध और अयोग्यता। .....

128. वास्तव में, मुझे प्रतिवादी श्री इकबाल सिंह की ओर से उठाए गए इस तर्क का कोई समर्थन नहीं मिलता है कि चुनाव याचिका दायर करने के लिए साक्ष्य और सामग्री एकत्र करने की दृष्टि से मतपत्रों आदि का निरीक्षण चुनाव कानून के अनुसार ज्ञात है लंबे समय तक, और जब तक इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाने के खिलाफ कोई निषेध नहीं था, मतपत्रों के निरीक्षण के बाद एक सफल उम्मीदवार के चुनाव को चुनौती देने के लिए एक पीड़ित व्यक्ति के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव के समर्थन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ के दो अनछुए फैसलों को छोड़कर किसी भी प्राधिकारी का हवाला नहीं दिया जा सकता है, लेकिन मतपत्र अधिनियम, 1875 के तहत बनाए गए नियम 40 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1948 के तहत नियम 57 में निहित चुनाव

के अंग्रेजी कानून पर भरोसा किया गया है। तथापि, इन उपबंधों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने पर मैं पाता हूं कि इन नियमों की भाषा इस तर्क का समर्थन नहीं करती है कि चुनाव याचिका स्थापित करने के लिए सामग्री एकत्र करने के लिए मतपत्रों के निरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है। जहां तक इस मामले का संबंध है, इन दोनों नियमों में मतपत्रों के निरीक्षण और उत्पादन की अनुमति देने का उद्देश्य समान है और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1948 की दूसरी अनुसूची में निहित संसदीय निर्वाचन नियमों के नियम 57 का उल्लेख करना पर्याप्त होगा। इस नियम के प्रासंगिक भाग में यह प्रावधान है कि निरीक्षण का आदेश उच्च न्यायालय या सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।

"यदि यह शपथ पर साक्ष्य से संतुष्ट है कि आदेश की आवश्यकता है या मतपत्रों के संबंध में अपराध के लिए मुकदमा चलाने या बनाए रखने का उद्देश्य है, या चुनाव याचिका के उद्देश्य से।

129. यह तर्क कि अंग्रेजी कानून के इस प्रावधान के तहत निरीक्षण का आदेश उच्च न्यायालय या काउंटी कोर्ट द्वारा चुनाव याचिका बनाने के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से दिया जा सकता है, इस नियम में होने वाली "चुनाव याचिका के उद्देश्य से" अभिव्यक्ति के उपयोग पर आगे बढ़ता है। इस तर्क में भ्रम एक बार में स्पष्ट हो जाता है जब हम पढ़ते हैं कि इससे पहले क्या होता है। इस प्रावधान के अनुसार, उच्च न्यायालय या काउंटी न्यायालय द्वारा केवल दो उद्देश्यों के लिए निरीक्षण का आदेश दिया जा सकता है, जो कहा जाता है:

1. मतपत्रों के संबंध में अभियोजन शुरू करने या बनाए रखने के उद्देश्य से, और
2. चुनाव याचिका के प्रयोजन के लिए।

130. जिन उद्देश्यों के लिए उच्च न्यायालय या काउंटी कोर्ट द्वारा निरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है, उनका वर्णन करने में उपयोग किए जाने वाले दो अभिव्यक्तियां न केवल समान नहीं हैं, बल्कि काफी अलग हैं।

गुरदास सिंह बादल बनाम गुरदास सिंह बादल चुनाव: भारत का आयोग*, आदि।
(गुरदेव सिंह, जे।

जहां तक मतपत्रों के संबंध में अपराध का संबंध है, निरीक्षण की अनुमति न केवल अपराध के साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दी जा सकती है, बल्कि अभियोजन को स्थापित करने और बनाए रखने के उद्देश्य से दी जा सकती है, लेकिन चुनाव याचिका के संबंध में निरीक्षण की अनुमति देने के लिए याचिका से निपटते समय, "स्थापना और रखरखाव के उद्देश्य से" शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है। और इसके बजाय "चुनाव याचिका के उद्देश्य के लिए" अभिव्यक्ति का उपयोग किया जाता है। एक ही प्रावधान में इन दो अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि किसी अपराध के अभियोजन के संबंध में निरीक्षण की अनुमति देने की शक्ति का दायरा चुनाव याचिका के संबंध में निरीक्षण की अनुमति देने की शक्ति के समान नहीं है। यदि यह इरादा था कि चुनाव याचिका स्थापित करने के लिए सामग्री एकत्र करने के लिए मतपत्रों के निरीक्षण की अनुमति दी जाती और चुनाव याचिका के परीक्षण में इसका उपयोग किया जाता, तो "चुनाव याचिका के उद्देश्य के लिए" शब्द नहीं होते, और "मतपत्रों के संबंध में" अभिव्यक्ति के बाद "या चुनाव याचिका" जोड़ना पर्याप्त होता। उस स्थिति में नियम 57 का संगत भाग निम्नानुसार पढ़ा गया होगा -

> "यदि शपथ पर साक्ष्य से संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय या काउंटी कोर्ट द्वारा मतपत्रों के संबंध में अपराध के लिए चुनाव याचिका या अभियोजन शुरू करने या बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश को फिर से हासिल किया गया है।

131. इस प्रकार यह इस प्रकार है कि "चुनाव याचिका के उद्देश्य से" शब्द का अर्थ "चुनाव याचिका स्थापित करने या बनाए रखने के उद्देश्य से" के समान नहीं पढ़ा जा सकता है। मेरी राय में, इस नियम की सही व्याख्या यह है कि यदि मतपत्रों के संबंध में किए गए अपराध के संबंध में निरीक्षण की आवश्यकता है, तो इसे न केवल अभियोजन को बनाए रखने के लिए, बल्कि इसे स्थापित करने के लिए संबंधित पक्ष को सक्षम करने की अनुमति दी जा सकती है, बल्कि जहां तक चुनाव याचिका का संबंध है, इसे उच्च न्यायालय या काउंटी न्यायालय द्वारा केवल तभी अनुमति दी जानी है जब चुनाव याचिका लंबित हो और उसमें निहित आरोपों के लिए मतपत्रों, काउंटरफोइल आदि के उत्पादन या निरीक्षण की आवश्यकता हो, ताकि चुनाव याचिका में उत्पन्न होने वाले मामलों का निपटान किया जा सके। कानून के इस प्रावधान पर हमारे समक्ष किसी भी अधिकार का हवाला नहीं दिया गया है जिसमें चुनाव याचिका स्थापित करने के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से निरीक्षण की अनुमति दी गई हो। भले ही मैं अपने भाइयों आर. एस. नरूला और बी. आर. तुली, जे. जे. का सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे उनके साथ सहमत होना संभव नहीं लगता कि संविधान के नियम 93 के तहत।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत, चुनाव आयोग मतपत्रों आदि के निरीक्षण की अनुमति दे सकता है, ताकि कोई व्यक्ति चुनाव याचिका स्थापित करने के लिए सामग्री एकत्र कर सके। जैसा कि मैंने उच्चतम न्यायालय के उनके न्यायमूर्ति के प्रासंगिक निर्णय के आलोक में प्रावधान को पढ़ा, जिसका संदर्भ पहले दिया जा चुका है, न तो किसी सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण और न ही चुनाव आयोग के पास निरीक्षण की अनुमति देने का अधिकार है ताकि कोई व्यक्ति चुनाव याचिका के लिए सामग्री एकत्र कर सके, लेकिन दूसरी ओर, निरीक्षण की अनुमति केवल उन भौतिक तथ्यों को साबित करने या अस्वीकृत करने के उद्देश्य से दी जानी है जो पहले ही दलीलों में निर्धारित किए गए थे और नियम 93 (1) के खंड (ए) से (डी) में उल्लिखित मतपत्र आदि संबंधित प्राधिकारी के समक्ष लंबित कार्यवाही के लिए किस हद तक प्रासंगिक हैं।

132. यदि हम किसी अन्य कोण से जांच करते हैं तो एक ही निष्कर्ष पर पहुंच जाता है। नियम *93 (1)* के तहत मतपत्रों के निरीक्षण और उत्पादन आदि की शक्ति के दायरे के संबंध में व्याख्या पर विचार किया गया था और वर्ष 1964 में सुप्रीम कोर्ट के उनके न्यायमूर्ति द्वारा निर्धारित किया गया था, लगभग दो साल बाद, मूल नियम जो केवल सक्षम न्यायालयों और न्यायाधिकरणों को ऐसी शक्ति देता था, में संशोधन किया गया था। और चुनाव आयोग को उसमें शामिल किया गया था; इस प्रकार प्रावधान उसे वही प्राधिकार प्रदान करता है जो सक्षम न्यायालय और अधिकरण को प्राप्त है। संबंधित प्रावधान में इस्तेमाल की गई व्यापक भाषा के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव ट्रिब्यूनल की शक्तियों से निपटते हुए कहा था कि इसका उपयोग संकीर्ण सीमाओं के भीतर किया जाना था। इस सीमित व्याख्या के बावजूद, इन सभी वर्षों के दौरान नियम 93 में संशोधन करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है ताकि इसे प्रिय बनाया जा सके और इसे विवाद से परे रखा जा सके कि चुनाव आयोग में निहित शक्ति अदालत और ट्रिब्यूनल की तुलना में अप्रतिबंधित और व्यापक है, और न ही उच्च न्यायालय को चुनाव याचिका के जब्त होने से पहले निरीक्षण की अनुमति देने के लिए उस शक्ति का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए। इससे यह वैध रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस नियम पर सुप्रीम कोर्ट के उनके न्यायमूर्ति द्वारा रखी गई व्याख्या उस इरादे के अनुरूप है जिसके साथ यह नियम तैयार किया गया था।

यदि चुनाव आयोग को किसी व्यक्ति को चुनाव याचिका के लिए सामग्री एकत्र करने में सक्षम बनाने के लिए निरीक्षण की अनुमति देने के लिए अधिकृत करने के उद्देश्य से थी, तो कोई यह समझने में विफल रहता है कि चुनाव याचिका से निपटने वाले न्यायालय या न्यायाधिकरण को निरीक्षण देने से क्यों रोक दिया जाएगा ताकि चुनाव-याचिकाकर्ता को और विवरण एकत्र करने में सक्षम बनाया जा सके जो उसके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वह चुनाव याचिका स्थापित करने के समय तक प्राप्त नहीं कर सका।

134. जैसा कि पहले देखा गया था, वर्ष 1966 में चुनाव कानून में संशोधन किया गया था, लेकिन फिर भी नियम 93 में संशोधन करने का कोई

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(गुरदेव सिंह, जे।

प्रयास नहीं किया गया ताकि चुनाव न्यायालय को एक सफल उम्मीदवार के चुनाव पर सवाल उठाने के लिए आगे की सामग्री प्राप्त करने के उद्देश्य से निरीक्षण की अनुमति देने की शक्ति प्रदान की जा सके और इस तरह उसे अपनी याचिका के समर्थन में अतिरिक्त आधार लेने में सक्षम बनाया जा सके।

135. राम सेवक यादव के मामले (4), (सुप्रा) में चुनाव की प्रक्रिया की जांच करने के बाद शाह जे. (जैसा कि वह तब थे) ने राम सेवक यादव के मामले *(4), (सुप्रा)* में चुनाव की प्रक्रिया की जांच करने के बाद कहा कि -

पीठ ने कहा, ''इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि मतगणना की प्रक्रिया के हर चरण में उम्मीदवार या उसके एजेंटों के पास मतगणना के समय मौजूद रहने, निर्वाचन अधिकारी की कार्यवाही देखने, खारिज किए गए मतों का निरीक्षण करने और पुनर्मतगणना की मांग करने का अवसर होता है। इसलिए, एक उम्मीदवार, जो इस आधार पर चुनाव को चुनौती देना चाहता है कि मतगणना के समय वोटों का अनुचित स्वागत, इनकार या अस्वीकृति हुई है, उसके पास मतपेटियों की जांच और खोलने और वोटों की गिनती के तरीके से खुद को परिचित करने का पर्याप्त अवसर है। उनके पास खारिज किए गए मतपत्रों का निरीक्षण करने और पुनर्मतगणना की मांग करने का भी अवसर है। यह धारा 83 (1) के प्रावधानों के आलोक में है, जिसके लिए उन भौतिक तथ्यों का एक संक्षिप्त विवरण आवश्यक है, जिन पर याचिकाकर्ता निर्भर करता है और उस अवसर के लिए जो एक हारे हुए उम्मीदवार के पास मतगणना के समय, देखने और फिर से गिनती का दावा करने का अवसर था कि निरीक्षण के लिए आवेदन पर विचार किया जाना चाहिए।

«

136. डॉ. *जगजीत सिंह* बनाम *ज्ञानी करतार सिंह और अन्य* के मामले में उनके न्यायमूर्ति ने इस बात पर जोर दिया कि चुनाव के दौरान, उम्मीदवारों के पास मतदान पत्रों की जांच करने और यह जानने का पर्याप्त अवसर है कि वास्तव में मतदान में क्या हुआ था, और कहा: –

"चुनाव याचिकाकर्ता, जो एक हारे हुए उम्मीदवार हैं, के पास गिनती से पहले मतदान पत्रों की जांच करने का पर्याप्त अवसर है, और यदि उनके या उनके चुनाव एजेंट द्वारा उठाई गई आपत्तियों को अनुचित तरीके से खारिज कर दिया गया है, तो वह जानते हैं।

उनके द्वारा उठाई गई आपत्तियों की प्रकृति और मतदान पत्र जिनसे ये आपत्तियां संबंधित हैं।

137. ये टिप्पणियां चुनाव आयोग को निरीक्षण के लिए किए गए आवेदन पर भी पूरी तरह से लागू होती हैं, और उसी तर्क पर प्रतिवादी श्री इकबाल सिंह की मतपत्रों के निरीक्षण और मतदाता सूची की चिह्नित प्रति के लिए अनुरोध नहीं दिया जाना चाहिए था।

138. बहस के दौरान, प्रतिवादी के विद्वान वकील, श्री जीएल सांघी ने श्री एससी दत्ता बनाम *श्री कृष्ण राजपाल और अन्य*, *रघुबीर सिंह यादव बनाम गजेंद्र सिंह और अन्य* (इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो अनरिपोर्ट किए गए एकल पीठ के फैसलों पर भरोसा किया / जिसमें चुनाव याचिका के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से मतपत्रों के निरीक्षण की अनुमति देने के चुनाव आयोग के अधिकार को बरकरार रखा गया है। इन दोनों मामलों में, यह प्रश्न तब विचार के लिए आया जब विद्वान न्यायाधीश चुनाव याचिकाओं की सुनवाई कर रहे थे और यह आपत्ति ली गई थी कि याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनाव याचिका की स्थापना से पहले नियम 93 के तहत मतपत्रों के निरीक्षण आदि पर एकत्र की गई सामग्री का उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि चुनाव आयोग ऐसे उद्देश्य के लिए निरीक्षण की अनुमति देने के लिए सक्षम नहीं था और उसका आदेश खराब था। *एससी दत्ता के मामले* में, डब्ल्यू ब्रूम जे ने यह मानते हुए कि चुनाव आयोग के पास निरीक्षण की अनुमति देने का अधिकार क्षेत्र था और उनका आदेश वैध था, इस सवाल पर नहीं गए कि निरीक्षण पर एकत्र की गई सामग्री को चुनाव याचिका में शामिल किया जा सकता है। दूसरे मामले में (*रघुबीर सिंह यादव का मामला*, बीएन लोकुर जे. ने इन शब्दों में संकेत देने से पहले उठाए गए निरीक्षण के संबंध में एक प्रारंभिक मुद्दे पर अपने निष्कर्षों को संक्षेप में प्रस्तुत किया: –

"चुनाव आयोग द्वारा मतपत्रों के निरीक्षण के लिए दी जाने वाली अनुमति विवेकाधीन है और अनुमति देने वाला आदेश प्रकृति में कार्यकारी है, फिर भी आदेश को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि नियम 93 के स्पष्ट प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को दिया गया निरीक्षण पूरी तरह से कानूनी और वैध है। नियम 93 के तहत चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निरीक्षण के परिणामस्वरूप एकत्र की गई जानकारी का उपयोग चुनाव को चुनौती देने वाली चुनाव याचिका में किया जा सकता है, इस सवाल के बावजूद कि चुनाव आयोग द्वारा दिया गया निरीक्षण कानूनी था या अवैध।

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(गुरदेव सिंह, जे।

139. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों द्वारा नियम 93 के तहत चुनाव आयोग की शक्तियों के संबंध में व्यक्त की गई राय निश्चित रूप से प्रतिवादी की दलील का समर्थन करती है कि चुनाव आयोग चुनाव याचिका के लिए सामग्री एकत्र करने के लिए निरीक्षण की अनुमति देने में सक्षम है, लेकिन यह याद रखना चाहिए कि यह सवाल चुनाव याचिकाओं की कोशिश करते समय उनके न्यायमूर्ति के सामने आया था। चूंकि संबंधित विद्वान न्यायाधीशों के संबंध में नियम 93 के तहत निरीक्षण के लिए आवेदन की अनुमति देने या अस्वीकार करने के निर्वाचन आयोग के आदेश के खिलाफ कोई अपील प्रदान नहीं की गई है, इसलिए मुझे बहुत संदेह है कि क्या वे नियम 93 के तहत किए गए चुनाव आयोग के आदेश की वैधता या अन्यथा में जाने के लिए सक्षम थे। इसके अलावा, आदेश पहले ही किया जा चुका था, और ऐसा कुछ भी नहीं था जो चुनाव याचिका की कोशिश कर रहा न्यायालय इसके बारे में कर सकता था। नियम 93 के तहत चुनाव आयोग द्वारा दिए गए आदेश की वैधता केवल तभी समाप्त हो सकती है जब संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू किया गया हो। किसी भी मामले में, मेरे द्वारा पहले दर्ज किए गए कारणों के लिए, मैं उनके द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सम्मानपूर्वक असहमत हूं।

140. नियम 93 में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि किस समय या उस चरण में निरीक्षण की अनुमति दी जानी है जिस पर उसमें उल्लिखित विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा निरीक्षण की अनुमति दी जानी है या जिस उद्देश्य के लिए ऐसा आदेश दिया जा सकता है। एक बार जब यह माना जाता है कि इस नियम के तहत निरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है ताकि किसी पार्टी को चुनाव याचिका के लिए सामग्री एकत्र करने में सक्षम बनाया जा सके, तो यह होगा कि न केवल चुनाव आयोग, बल्कि एक अदालत जिसके पास इस तरह की चुनाव याचिका की सुनवाई करने का अधिकार है, उसके पास भी इस तरह के निरीक्षण की अनुमति देने का अधिकार होगा। हालांकि, राम सेवक यादव के मामले (4) में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति के आदेश के मद्देनजर यह स्पष्ट रूप से असमर्थनीय है , कि नियम 93 के तहत एक चुनाव ट्रिब्यूनल किसी पार्टी को सबूत निकालने में सक्षम बनाने के लिए निरीक्षण की अनुमति नहीं दे सकता है।

141. आइए हम दूसरे कोण से प्रश्न की जांच करें। एक पराजित उम्मीदवार चुनाव याचिका दायर करना चाहता और नियम 93 के तहत मतपत्रों के निरीक्षण के लिए चुनाव आयोग में आवेदन करता है । उन्हें अनुमति नहीं दी जाती है और इस प्रकार केवल उस जानकारी पर भरोसा

करने के लिए मजबूर किया जाता है जो पहले से ही उनके कब्जे में है, वह एक चुनाव याचिका दायर करते हैं। जब उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका लंबित होती है, तो लौटा हुआ उम्मीदवार मतपत्रों के निरीक्षण के लिए उसके पास आवेदन करता है ताकि वह उचित बचाव और एक साथ साक्ष्य प्रस्तुत कर सके, जो धारा 97 की उप-धारा (2) के तहत आवश्यक बयान और विवरण के साथ होना चाहिए।

चुनाव याचिका के मामले में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 83। *राम सेवक यादव के मामले*(4), (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट के उनके न्यायमूर्ति के आदेश को ध्यान में रखते हुए कि नियम 93 के तहत निरीक्षण की अनुमति सामग्री को बाहर निकालने के लिए अनुमति नहीं दी जा सकती है, यह स्पष्ट है कि चुनाव याचिका से निपटने वाली अदालत के रूप में उच्च न्यायालय निरीक्षण के लिए इस तरह के आवेदन को मंजूरी देने के लिए सक्षम नहीं होगा। यदि यह तर्क स्वीकार कर लिया जाता है कि चुनाव आयोग के पास व्यापक शक्तियां हैं और वह चुनाव याचिका के लिए सामग्री के साथ निरीक्षण की अनुमति देने में सक्षम है, तो उच्च न्यायालय द्वारा निरीक्षण के लिए उसके आवेदन की अस्वीकृति के बाद भी, प्रतिवादी-लौटा उम्मीदवार, जिसका निरीक्षण के लिए आवेदन न्यायालय द्वारा परिभाषित किया गया है, चुनाव आयोग से संपर्क करने और निरीक्षण प्राप्त करने का हकदार होगा। सीमित माना जाता है। यह एक विसंगतिपूर्ण स्थिति पैदा करेगा यदि चुनाव याचिका स्थापित करने के इच्छुक व्यक्ति को उस उद्देश्य के लिए सामग्री एकत्र करने के लिए मतपत्रों का निरीक्षण करने की अनुमति दी जाती है, जबकि निरीक्षण के लिए एक सफल उम्मीदवार के आवेदन को अदालत द्वारा खारिज कर दिया जाता है और *इसके विपरीत।*

142. पूर्वगामी चर्चा के परिणामस्वरूप, मैं पाता हूं कि नियम 93 के तहत निरीक्षण की अनुमति देने के लिए चुनाव आयोग की शक्तियों का दायरा उसी प्रावधान के तहत सक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण की तुलना में व्यापक नहीं है, और चुनाव आयोग सबूत निकालने और चुनाव याचिका के लिए सामग्री एकत्र करने के लिए निरीक्षण की अनुमति नहीं दे सकता है। यह तर्क दिया गया है कि किसी भी निर्वाचित उम्मीदवार को अपनी सीट बनाए रखने का अधिकार नहीं है यदि उसे अवैध वोटों पर या भ्रष्ट प्रथाओं का सहारा लेकर लौटाया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि लोकतंत्र की सफलता हमेशा चुनाव की प्रक्रिया की शुद्धता और चुनाव मशीनरी की अखंडता पर निर्भर करेगी, लेकिन कानून के अनुसार, जैसा कि आज है, एक लौटने वाले उम्मीदवार को अपनी सीट बनाए रखने का अधिकार है, और उसे विधायिका की सदस्यता से जुड़े सभी लाभों और विशेषाधिकारों का आनंद लेने से रोका नहीं जा सकता है, जिसके लिए वह चुना गया है। जब तक उनके चुनाव पर सवाल उठाने के लिए कोई चुनाव याचिका दायर नहीं की जाती है और सक्षम न्यायालय द्वारा उनके चुनाव को रद्द नहीं किया जाता है। हालांकि, अवांछनीय वे साधन हो

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(गुरदेव सिंह, जे।

सकते हैं जिनके लिए एक लौटे उम्मीदवार ने आवेदन किया हो सकता है। अपनी सफलता सुनिश्चित करते हुए, वह अपनी सीट बरकरार रखेंगे और कोई भी उन्हें हटा नहीं सकता है यदि कानून के अनुसार उनके चुनाव पर सवाल उठाने वाली कोई याचिका नहीं की जाती है।

143. हमारे समक्ष इस बात को गंभीरता से चुनौती नहीं दी गई थी कि नियम 93 के परंतुक (क) में निहित निर्देश अनिवार्य है और यदि निर्वाचन आयोग निरीक्षण के लिए आवेदन की अनुमति देता है तो उसे कारण दर्ज करना होगा। चूंकि निर्वाचन आयोग द्वारा निरीक्षण की अनुमति दी गई थी, इसलिए 15 मार्च, 1971 को उनके द्वारा दर्ज किए गए आदेश के अनुसार हमें यह पता लगाना चाहिए कि क्या उचित कारणों से निरीक्षण की अनुमति दी गई है। उनके आदेश को मेरे विद्वान भाइयों द्वारा *विस्तार से* प्रस्तुत किया गया है , और इसके अवलोकन पर इस निष्कर्ष से कोई बच नहीं सकता है कि यह निरीक्षण देने के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करता है। यह इस आदेश के शुरुआती वाक्य पर है कि प्रतिवादी के विद्वान वकील ने पूरी तरह से आदेश के कारणों के बयान के रूप में भरोसा किया है। इसमें लिखा है:-

— -स्त्री-विषयक

"एस. इकबाल सिंह द्वारा किए गए आवेदन में लगाए गए आरोप, यदि सही हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे गंभीर हैं। मुझे लगता है कि चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 93 के उप-नियम (1) में उल्लिखित दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति दी जा सकती है।

144. मुझे अपने पहले विद्वान भाई आर. एस. नरूला, जे. से सहमत होने में कोई संकोच नहीं है कि एस. इकबाल सिंह द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर हैं, यह केवल तथ्य का बयान है और निरीक्षण की अनुमति देने वाले आदेश के समर्थन में कोई कारण नहीं है, खासकर जब आदेश के शुरुआती वाक्य में "यदि सच है" शब्द का उपयोग स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि चुनाव आयोग ने यह पता लगाने के लिए भी अपना दिमाग नहीं लगाया था। यदि वे प्रथम दृष्टया सही या गलत थे। इसके अलावा, आरोपों की गंभीरता अपने आप में निरीक्षण की अनुमति देने के लिए एक प्रासंगिक कारण नहीं है। अन्यथा मतपत्रों आदि का निरीक्षण करने की अनुमति मांगने वाले व्यक्ति को केवल लापरवाह आरोप लगाने होते हैं, खासकर जब वह जानता है, जैसा कि चुनाव लड़ने वाले प्रतिवादी की ओर से तर्क दिया गया था, कि आरोपों के झूठे या अन्यथा पर चुनाव आयोग द्वारा गौर नहीं किया जाना है। चूंकि नियम 93 के उप-नियम (1) के परंतुक (ए) में चुनाव आयोग को कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता होती है, यदि वह निरीक्षण के

लिए अनुरोध करता है, और यह अच्छी तरह से तय है कि निरीक्षण को निश्चित रूप से या नियमित रूप से अनुमति नहीं दी जानी है, इसलिए यह इस प्रकार है कि चुनाव आयोग को आवेदक द्वारा लगाए गए आरोपों पर अपना दिमाग लगाना होगा और कम से कम खुद को संतुष्ट करना होगा कि प्रथम *दृष्टया* उनमें दम है। यद्यपि मैं प्रतिवादी के विद्वान वकील से सहमत हूं कि उस उद्देश्य के लिए उसके लिए विस्तृत जांच शुरू करना आवश्यक नहीं है, फिर भी उसे सौंपे गए कार्य के उचित निर्वहन के लिए और मतदान की अत्यंत गोपनीयता को शामिल करने वाली कानून की नीति को ध्यान में रखते हुए, चुनाव आयोग से यह अपेक्षा की जाती है कि वह खुद को संतुष्ट करने के लिए कदम उठाए कि आवेदक के पास *प्रथम दृष्टया* मामला है। निरीक्षण के लिए अपनी प्रार्थना देने से पहले मामला। यह सच है कि जहां एक सम्मानित और अच्छी स्थिति में व्यक्ति द्वारा आरोप लगाए जाते हैं, संबंधित प्राधिकारी किसी विशेष स्थिति में उसके हलफनामे या बयान पर शपथ लेकर पर्याप्त विचार कर सकता है कि प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है, लेकिन जहां संबंधित पक्ष का इस मामले में सर्वोपरि हित है, प्राधिकरण अकेले उसके बयान पर कार्रवाई करने और किसी अन्य सामग्री से आश्वासन लेने में संकोच कर सकता है। इस मामले में मतगणना में पर्यवेक्षक के रूप में स्वयं निर्वाचन आयोग के अधिकारी श्री आरडी शर्मा उपस्थित थे। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी मौजूद थे और पुनर्मतगणना के आवेदन को निर्वाचन अधिकारी पहले ही खारिज कर चुके थे। पर्यवेक्षक की रिपोर्ट और रिटर्निंग अधिकारी द्वारा श्री इकबाल सिंह द्वारा पुनर्मतगणना के लिए किए गए आवेदन को अस्वीकार करने के आदेश को निर्वाचन आयोग द्वारा लाभ के साथ विज्ञापन दिया जा सकता है क्योंकि इनमें से किसी भी अधिकारी की किसी विशेष उम्मीदवार के चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। यह सुझाव कि चूंकि उम्मीदवारों में से एक पंजाब के मुख्यमंत्री का भाई था, इसलिए यह माना जा सकता है कि चुनाव से संबंधित अधिकारी उसके हित में काम करेंगे, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस तथ्य के अलावा कि सभी आधिकारिक कृत्यों को नियमित तरीके से किया गया माना जाता है जब तक कि इसके विपरीत कोई संकेत न हो, यह नहीं भूलना चाहिए कि मुकाबले में शामिल दोनों पार्टियां अत्यधिक प्रभावशाली थीं: जबकि एक तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री के भाई थे, दूसरी तरफ उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी एस इकबाल सिंह प्रतिवादी ने संघ में उप मंत्री का महत्वपूर्ण पद संभाला था। सरकार, और वह अभी भी न केवल मतदान के दिन, बल्कि निरीक्षण के लिए आवेदन किए जाने के समय और उसके बाद कई दिनों तक इसे धारण कर रहे थे।

145. मेरे विद्वान भाई, नरूला जे ने यह विचार व्यक्त किया है कि निरीक्षण

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(गुरदेव सिंह, जे।

के लिए अनुरोध स्वीकार करने से पहले चुनाव आयोग के लिए यह आवश्यक है कि वह आवेदन का नोटिस जारी करे और याचिकाकर्ता के सफल उम्मीदवार होने की बात सुने। तथापि, मुझे खेद है कि मैं इस मुद्दे पर उनसे पूर्णत सहमत नहीं हो सका। नियम 93 चुनाव आयोग को लौटाए गए या किसी अन्य उम्मीदवार को निरीक्षण के लिए आवेदन की सूचना देने का अधिकार नहीं देता है। इस प्रकार, कानून के मामले के रूप में विपरीत पक्ष को नोटिस जारी करने की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा हाल ही में निर्धारित नियम के अनुसार, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण *बनाम क्षेत्रीय* परिवहन प्राधिकरण *गुरबचन सिंह* (32) ने 12 फरवरी, 1971 को फैसला किया कि इच्छुक लोगों को इस तरह का नोटिस जारी करने का समय कहां है।

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(गुरदेव सिंह, जे।

पार्टियों, विशेष रूप से लौटे या पराजित उम्मीदवारों को, आवेदक के अलावा, प्राकृतिक न्याय के नियमों के अनुसार ऐसा नोटिस जारी किया जाना चाहिए और निरीक्षण का आदेश देने से पहले संबंधित पक्ष को सुना जाए। यह इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए और भी आवश्यक है कि अंग्रेजी कानून के प्रावधान के विपरीत नियम 93 के तहत आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की जाती है, निरीक्षण की अनुमति प्रदान की जाती है, और एक बार निरीक्षण देने वाले आदेश को संबंधित अधिकारी को सूचित किया जाता है और वह निरीक्षण की अनुमति देता है, विरोधी उम्मीदवार, भले ही निरीक्षण के समय मौजूद हो, उनके पास आपत्ति करने का न तो अवसर होगा और न ही *अधिकार होगा,* जिसके परिणामस्वरूप निरीक्षण के अवैध आदेश का पालन करने वाली शरारत की जाएगी। फिर, चूंकि चुनाव आयोग को निरीक्षण की अनुमति देने पर कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता होती है, इसलिए यह ऐसी शक्ति के उचित प्रयोग के लिए अनुकूल होगा यदि वह अन्य उम्मीदवारों को सुनता है जहां उन्हें सूचित करने का समय होता है।

मैं

146. निरीक्षण के समय उम्मीदवारों को उपस्थित रहने का अवसर प्रदान करने के लिए नियम 93 के परंतुक (बी) में निहित प्रावधान नोटिस का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि एक उम्मीदवार के पास निरीक्षण शुरू होने के समय स्पष्ट रूप से अवैध आदेश पर आपत्ति करने का भी समय नहीं होगा क्योंकि निरीक्षण की अनुमति देने के लिए निर्देशित अधिकारी पूरी संभावना में निरीक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर देगा।

(147) ऊपर मैंने जो कहा है, उसे ध्यान में रखते हुए, इस निष्कर्ष से कोई नहीं बच सकता है कि चुनाव आयोग के आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और याचिका को स्वीकार किया जाना चाहिए। इस सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकता है कि एक परमादेश चुनाव आयोग को कारण बताने के लिए एक आदेश जारी कर सकता है और उसे एक नया आदेश पारित करने के लिए खुला छोड़ दिया जा सकता है, खासकर जब एक चुनाव याचिका पहले ही स्थापित की जा चुकी है और अदालत इस मामले को देख रही है और उसके पास मतपत्रों के निरीक्षण के लिए अनुरोध से निपटने का अधिकार है; आदि।

अदालत का आदेश

(148) बहुमत के निर्णय के मद्देनजर, इस याचिका को स्वीकार किया जाता है और चुनाव आयोग के आक्षेपित आदेश को लागत के बारे में बिना किसी आदेश के रद्द किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा । विश्वास खटक, प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) रेवाड़ी, हरियाणा।

गुरदास सिंह बादल ***बनाम*** भारत निर्वाचन आयोग, आदि।
(गुरदेव सिंह, जे।